छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025

(फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1946)

[अंक 16]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 2025

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इधर तो आज पूरा गोल है।

श्री जनक ध्रुव :- इधर सब लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वे आपके पास ही खड़े थे। प्रश्नकाल संख्या 1. श्री प्रबोध मिंज जी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत समस्त विभागों में पदों का चिन्हांकन

[समाज कल्याण]

1. (*क्र. 2463) श्री प्रबोध मिंज : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- **(क)** राज्य में समस्त विभागों हेतु दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगजन हेतु पदों का चिन्हांकन कब किया गया था? क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों का चिन्हांकन किया गया है? यदि नहीं तो कब तक कर लिया जायेगा? **(ख)** भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 अनुसार दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संवर्गवार पदों को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किये जाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) राज्य में समस्त विभागों हेतु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगजनों हेतु पदों का चिन्हांकन दिनांक 25.09.2014 द्वारा किया गया था। जी नहीं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पदों का चिन्हांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। अतः भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.01.2021 अनुसार दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित संवर्गवार

पदों को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूलन किये जाने की कार्यवाही हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री महोदय से दिव्यांगजनों की भर्ती पदोन्नति के संबंध में प्रश्न पूछा था। उनका जवाब भी आया हुआ है लेकिन मैं जवाब से थोड़ा संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, उन्होंने अपने जवाब में दिया है कि वर्तमान में दिव्यांजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत् पदों के चिन्हांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-33 के तहत् पदों का चिन्हांकन किया जाना है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जो वर्ष 2016 अधिनियम है और छत्तीसगढ़ का दिव्यांगजन अधिनियम 2023 है, वह कब से लागू की गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बना, यह अधिनियम प्रथम बार 1995 में बना था, उस समय 7 प्रकार के दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया था। उसमें प्रक्रिया इतनी लंबी चली, जब वह कम्प्लीट हुई तो दिनांक 25.09.2014 को उसमें पदों का चिन्हांकन किया गया। अब क्योंकि यह अधिनियम फिर से 2016 में लागू हुई है तो इसकी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि वर्ष 2016 के बाद इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं तो सभी विभागों से अभिमत लेना रहता है, अभी 24 विभागों से अभिमत आ गया है, 26 विभागों का अभिमत आ जाएगा तो फिर से पदों का चिन्हांकन होगा।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अधिनियम 2016 के बारे में बताया लेकिन ये भी सही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत् दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन क्या एक वर्ष के अंदर किया जाना था ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अधिनियम बनता है तो उसकी प्रक्रिया होती है। जब वर्ष 1995 में इतनी लंबी प्रक्रिया चली, वर्ष 2016 से इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है तो स्वाभाविक है कि वर्ष 2023 में अधिनियम की प्रक्रिया लंबी ही रहेगी।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया जवाब ठीक दे रही हैं लेकिन वर्ष 2016 से प्रक्रिया चालू हुई है, वर्ष 2023 में प्रक्रिया फिर से लागू की गई। वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2023 और वर्ष 2023 से लेकर अभी तक 7 वर्ष हो गये। 7 वर्षों तक केवल चिन्हांकन का कार्य हो रहा है। न दिव्यांगजनों की पदोन्नति हो पा रही है, न उनकी भर्ती हो पा रही है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। अगर हम इसमें देखें तो करीब 9 साल निकल गए, वर्ष 2025 आ गया है। इतने लंबे अंतराल तक केवल प्रक्रियाधीन है, उसकी कार्रवाई चल रही है, ये तो दिव्यांगजनों के साथ अन्याय है। मैं मंत्री महोदया से चाहूंगा कि इसमें यदि इतने लंबे वर्षों में किसी अधिकारी या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या आप उनके उपर कार्रवाई करेंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी भी वर्ष 2016 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मैं माननीय सदस्य को इस बात से पहले भी अवगत करा चुकी हूं कि अभी तक कुल 24 विभागों से अभिमत आया है और कुल 26 विभागों से अभिमत आना बाकी है। माननीय सदस्य जिस नियम की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2023 अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। मतलब, यह अधिनियम है ही नहीं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी तक यह अधिनियम लागू नहीं हुआ है जबकि इस प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई है कि वर्ष 2023 अधिनियम लागू किया गया है और उसकी कार्रवाई चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदया से एक जानकारी और चाहूंगा कि क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग को शपथ पत्र दिया गया था?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशील विषय है क्योंकि यह दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ विषय है। कहीं न कहीं भर्ती में दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन वर्ष 2016 के अधिनियम के अनुसार भर्तियां की जा रही हैं। रही बात शपथ पत्र की तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-34 में सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत से शून्य का प्रावधान है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.08.2018 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्रबोध जी का प्रश्न बहुत छोटा है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2025 आ गया है और 9 साल की पूरी कार्य अवधि निकल गई है। यदि पदों के चिन्हांकन जैसी प्रक्रिया में 9 साल लगते हैं तो दिव्यांगजनों के लिए विभाग को और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। यदि हम 9 साल तक सिर्फ उनके पदों का चिन्हांकन करते रहेंगे तो इतने महत्वपूर्ण विषय में बहुत पीछे हो जायेंगे। इसलिए उनका यही विषय है कि कृपा करके यह समय-सीमा में हो जाये। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी आप इसको कर सकती हैं तो जल्द से जल्द इसका चिन्हांकन हो जाये। प्रश्न क्रमांक-2, श्रीमती अनिला भेंडिया जी।

श्री प्रबोध मिंज :- धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें है ?

डॉ. चरणदास महंत :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो आपका प्रश्न कर लिया। मैं आपका ही प्रश्न कर रहा था।

डॉ. चरणदास महंत :- हां सर, मुझे आपके प्रश्न में थोड़ा जोड़ना है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषेश भर्ती अभियान किये जाने हेतु दिनांक 31 मई, 2024 को शासन द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। यह शासन आपका है तो क्या आपको पता है कि इस तरह से परिपत्र जारी किया गया है? यदि इतनी लापरवाही हो रही है और माननीय अध्यक्ष जी भी इस पर चिंतित हैं तो यह एक अमानवीय व्यवहार है, जो आपके अधिकारियों के द्वारा या आपके द्वारा या शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसे मैं सीधा-सीधा कहूंगा कि आप लोग दिव्यांगजनों के साथ [xx] कर रहे हैं क्योंकि माननीय नरेन्द्र मोदी जी का जो घोषणा पत्र वाला प्रोग्राम आया है, उसमें लिखा हुआ है। दिव्यांगजनों के साथ इस तरह से व्यवहार एक अमानवीय व्यवहार है। इसके लिए भी आपको कुछ न कुछ सजा निर्धारित करनी चाहिए। अभी तक मात्र 24 विभागों का अभिमत आया है और 26 विभागों का अभिमत नहीं आया है। यह कोई पचने वाली बात नहीं है। यह मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सी बात है कि आप दिव्यांगजनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आप समय-सीमा निर्धारित करवा दीजिए, ताकि उनको न्याय मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि इसमें विभिन्न विभाग जुड़े हुए हैं और सभी विभागों से उनके पदों का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। आपका प्रश्न बहुत व्यापक है, मुझे लगता है कि मुख्य सचिव को इसकी चिंता करनी चाहिए और 6 महीने के अंदर एक रास्ता निकालें। यह अंतिम उपाय हो सकता है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आज आप ही ओपनिंग बैट्समैन हैं। लगता है कि आज आपको ही पूरा संभालना पड़ेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- बिलकुल नहीं जनाब, आपकी कृपा हो तो आज ही हम बैट्समैन बन जायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज शुरूआत से ही आप ही बल्लेबाजी कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या-2 XX XX

महतारी वंदन योजना अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं

[महिला एवं बाल विकास]

3. (*क्र. 2456) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितनी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा

है? **(ख)** महतारी वंदन योजना प्राप्त करने की पात्रता क्या थी और किस अंतिम अवधि से विवाहित महिलाओं को आवेदन हेतु पात्र माना गया है? **(ग)** क्या शेष महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त होगा ? अगर होगा तो कब से होगा और नए आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में जनवरी 2025 की स्थिति में महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली कुल 6969399 महिलाएं योजना का लाभ लिए जाने हेतु पात्र थी, जिन्हें भुगतान अनुमोदित किया गया है। **(ख)** महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों के पात्रता एवं अपात्रता हेतु निर्धारित मापदंड **संलग्न प्रपत्र** अनुसारहै। 20 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए आवेदन के प्रकरणों में कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली तथा पात्रता एवं अपात्रता संबंधी मापदंड को पूरा करने वाली विवाहित महिलाओं को पात्र माना गया है। **(ग)** महतारी वंदन योजना से विभाग के आंकलन अनुसार सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। नए हितग्राहियों को शामिल किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी है, अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महिला बाल विकास विभाग अन्तर्गत महतारी वंदन योजना का लाभ किन-किन को मिल रहा है ? जिनको पहले से योजनाओं का लाभ मिलता था, जैसे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500/- रूपये, सुखद सहारा पेंशन 500/- रूपये, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 500/- रूपया मिल रहा था। आपने महतवारी वंदन योजना में एक हजार रूपया देने का कहा था, क्या इन लोगों को उस योजना का पैसा काटकर दिया जाता है या उन्हें पूरा 1,000/- रूपया दिया जाता है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार ही सदस्यों के द्वारा ही इस बात को उठाया गया था तो मैं इसमें बात रखी थी कि अंतर की राशि दी जा रही है। जैसे महिलाओं को किसी तरह का पेंशन जैसे राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या नि:शक्तजन पेंशन मिल रहा है तो इसमें अंतर की राशि दी जा रही है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना वर्ष 2007 में लागू हुई थी तो उस समय 350/- रूपया मिलता था, जिसमें 200/- रूपया शेयर केन्द्र सरकार की ओर से तथा 150/- रूपया राज्य सरकार की ओर से था। उसके बाद सन् 2023 में कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य ने अपना अंश बढ़ाकर 300/- रूपया कर दिया तो 500/- रूपया राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में मिलता है। आपने वादा किया था कि सबको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। वृद्धा, नि:शक्तजनों का पैसा क्यों काटा जा रहा है ? उनको पुरानी योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है। महतारी वंदन योजना आपकी नई योजना थी, उसमें एक हजार रूपये में से पांच सौ रूपया काटकर क्यों दे रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- उनका स्पष्ट जवाब आ गया है कि अंतर की राशि दी जा रही है, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अब इसमें आगे बढ़कर प्रश्न करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाह रही हूं कि आप अंतर की राशि दे रहे हैं, कह रही हैं वह किस प्रकार के अंतर की राशि है, थोड़ा समझा देंगे ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने इस योजना में जिन महिलाओं को चिन्हांकित किया है, उसमें पेंशनधारी महिलाएं भी आ रही थीं। हमने कहा था कि एक हजार रूपया देंगे। लेकिन इस योजना में कुछ पेंशनधारी महिलाएं भी हैं, दोनों मिलाकर एक हजार रूपया दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अंतर की राशि दे रहे हैं, साफ-साफ बता दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा कि अंतर की राशि दे रहे हैं। यह घोषणा-पत्र में नहीं था। हम तो एक हजार रूपया ही मांगेंगे, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको एक हजार रूपया मिलना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर एक बार और चर्चा हो गई है। फिर उसी विषय पर पूरा चर्चा करना सदन का समय खराब करना है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में एक छोटा सा प्रश्न है। जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए पोर्टल खोलने हेतु क्या कार्ययोजना है ?

अध्यक्ष महोदय :- जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके बारे में पूछा है। कुछ है तो बता दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) आने वाले समय में चिंता करेगी।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बिलकुल है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप चिंता नहीं कर रहे हो इसीलिए हमको चिंता करने की जरूरत हो रही है। आप समय तो बता दीजिये कि कब तक पोर्टल को खोलेंगी ?

श्री रिकेशन सेन :- आप 5 साल में समय नहीं बता पाये कि पांच सौ रूपया कब दोगे ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं भाई। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिन महिलाएं को राशि नहीं मिल रही है, वह बार-बार हमारे पास आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी सक्षम हैं। उनको जवाब देने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृपा करके पोर्टल खोलने का समय निर्धारित कर दीजिये ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपका प्रश्न आ गया। उन्होंने भी अच्छा दे दिया।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न आगे बढ़ गया।

बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रों के भण्डारण स्थल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 2403) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण (खाद्यान्न) प्रणाली के कितने केंद्र संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के सभी केन्द्रों में स्वयं के खाद्यान्न गोदाम हैं ? **(ग)** भवन-विहीन कितने केंद्र हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? **(घ)** भवन-विहीन खाद्यान्न वितरण केन्द्रों का खाद्यान्न भंडारण कहां-कहां, कौन-कौन से भवन में किया जाता है ? केन्द्रवार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 688 उचित मूल्य दुकान संचालित हैं, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश 'क' के उचित मूल्य दुकानों में से 206 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के दुकान-सह-गोदाम हैं। **(ग)** 482 उचित मूल्य दुकान में स्वयं के दुकान सह गोदाम भवन नहीं है, विकासखण्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।**

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिला बिलासपुर में सार्वजनिक वितरण प्राणाली के कितने केन्द्र संचालित हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा प्रश्न कुछ नहीं है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गंभीर विषय है। आप मजाक में मत लीजिये। कितने केन्द्र संचालित हैं और आप कितने केन्द्रों को किराये के माध्यम से संचालित कर रहे हैं? वह भवन कब तक बन जायेंगे? माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आप जिन भवनों को किराये में संचालित कर रहे हैं, इनको कितने पैसे से किराये में लिये गये हैं और यह पैसा किस मद से दिया जाता है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में ऐसे 482 स्थान हैं, जहां पर भवनविहीन हैं। जहां तक किराये की बात है तो जो समूह वाले हैं या जो राशन दुकान चलाते हैं, वह किराया देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो समूह वाले राशन दुकान चलाते हैं, वह किराया में दिया जाता है। उनको कितना पैसा में किराया दिया जाता है? उनके लिए अगल से पी.डी.एस. भवन नहीं बना है तो क्या उनके लिए कोई नया भवन बनाने का प्रावधान है? नया भवन कब तक बनाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय :- वह यह पूछ रहे हैं कि जो 482 भवनविहीन हैं, उनको आप कब तक बनायेंगे? क्या उसके लिए कोई योजना है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवनविहीन हैं, उसको बनाने के लिए रोजगार गारंटी से निवेदन करते हैं और कभी-कभी मंडी से भी निवेदन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अलग-अलग मदों से बनता है?

श्री दयालदास बघेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप प्रश्न पूछिये।

श्री दिलीप लहरिया :- जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम धनगंवा में पी.डी.एस. भवन बन चुका है, लेकिन वहां निजी जगह में उचित मूल्य दुकान संचालित हैं। कई बार ग्रामवासियों की ओर से आवेदन देने के बाद भी दुकान को पी.डी.एस. भवन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। आखिर किसके संरक्षण में यह काम हो रहा है? मेरा एक और प्रश्न है। अभी वहां नया सरपंच चुनाव जीत कर आये हैं। वहां कहीं राशन में कमी है या वहां एक-दो महीने का राशन का शार्टेज है, उसको आप तो उसको किस तरीके से मेकअप करेंगे? क्योंकि कई लोग जार्च लेने में कतरा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। अभी मेरे यहां एक गंभीर मामला सामने आया है। दो फूड इंस्पेक्टर को अटैच किया गया है, लेकिन पूर्व में जिस फूड इंस्पेक्टर को शिकायत के आधार पर हटाया गया था, उसको फिर से उसी के जगह में भेज दिया गया। क्या उसको वहां फिर से भ्रष्टाचारी करने के लिए भेजा जा रहा है? आम जनता के हित में जो राशन है, वह उनको मिलना चाहिए, लेकिन मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश में लगातार अफरा-तफरी की शिकायतें हैं। जो दो-दो महीने राशन का शार्टेज है और जो गलत तरीके से नया उचित मूल्य की दुकान संचालन करते हैं, वह उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप 300 क्विंटल, 700 क्विंटल चावल का मेकअप करिये। आप यह सिस्टम को कब तक दुरूस्त करेंगे या जो अधिकारी यह नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे? एक गंभीर विषय है कि हमारे यहां जो फूड कंट्रोलर है, वह एक भी दिन क्षेत्र में मॉनिटरिंग करने नहीं जाता है और न ही जानकारी लेता है। जब वह लगातार जानकारी लेता तब ऐसी घटना ही नहीं होती, किसी को जेल जाने का नौबत ही नहीं आता। आपका यह विभाग है, आप माननीय सक्षम मंत्री जी हैं, आप सीनियर हैं, आप पूरे प्रदेश में इसको थोड़ व्यवस्थित कराईये। इसमें कई लोग न चाहकर भी जबरन जेल जा रहे हैं, इसमें अफरा-तफरी का मामला हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, थोड़ा व्यवस्थित करिये। आप जल्दी से करेंगे बोल दीजिये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो धनगंवा गांव है, वहां पी.डी.एस. राशन दुकान बनकर तैयार है। आप जब चाहे तब उसका उद्घाटन कर के उसको प्रारंभ करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने कह दिया है, आप उद्घाटन करवा लीजिये।

श्री दयालदास बघेल :- या फिर हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उसको प्रारंभ करवा देंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- जी। आपको धन्यवाद। जो भवन नहीं बना है, उसको आप कब तक बनवा देंगे?

अध्यक्ष महोदय :- 482 भवनविहीन हैं। वह बता रहें कि धीरे-धीरे बनेगा। बालेश्वर जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री दिलीप लहरिया :- सर, एक मिनट। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि उनको जो किराये में भवन देते हैं, वह पैसा अपने जेब से देते हैं या उसी में कुछ इधर-उधर करते हैं? (हंसी)

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको कमीशन की राशि मिलती है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री बालेश्वर साहू जी।

श्री दिलीप लहरिया :- धन्यवाद।

शासकीय उचित मूल्य के दुकान संचालकों को कमीशन एवं बारदाना की लंबित राशि का भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 2352) श्री बालेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को एपीएल, अंत्योदय, निराश्रित एवं प्राथमिकता कार्ड और बरदाना में किस - किस दर से किस - किस आधार पर कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया जाता है ? कृपया, जानकारी दें? **(ख)** क्या यह सच है कि जिला-सक्ति में 2023 से प्रश्नांक "क" के अनुसार निर्धारित कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया जाना लंबित है ? यदि हां तो, 15.02.2025 की स्थिति में स्वीकृत कमीशन एवं अन्य राशि में से कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया और कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है ? कृपया, वर्षवार जानकारी प्रदान करेंगे? **(ग)** क्या यह भी सच है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक संघ सक्ती ने भी दिसंबर 2024, में कलेक्टर सक्ती को ज्ञापन देकर प्रश्नांक "ख" के अनुसार लंबित कमीशन एवं अन्य राशि की भुगतान का मांग की है ? यदि हां तो, इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? कृपया, जानकारी

दें? **(घ)** प्रश्नांक "क", "ख" एवं "ग" के अनुसार लंबित कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान संचालकों को सामान्य एपीएल, अंत्योदय, निराश्रित एवं प्राथमिकता राशनकार्डो पर चावल वितरण हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल वितरण हेतु 90 रूपये प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना के अंतर्गत चावल वितरण हेतु 30 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण सहायता की राशि 50 क्विंटल तक मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकान को ग्रामीण क्षेत्र में 8,000 रूपये, शहरी क्षेत्र में 9,000 रूपये, 51 से 100 क्विंटल मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 रूपये, शहरी क्षेत्र में 6,500 रूपये, 101 से 150 क्विंटल मासिक आबंटन वाली उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 रूपये शहरी क्षेत्र में 3,000 रूपये प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उचित मूल्य दुकानों से लिये जाने वाले पीडीएस बारदाना के लिए 25 रूपये प्रति नग का भुगतान किया जाता है। **(ख)** जी हां, उचित मूल्य दुकानों के कमीशन की भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र**[1] **अनुसार है। (ग)** जी हां, उचित मूल्य दुकान संघ सक्ती के ज्ञापन के संबंध में प्रश्नांकित अवधि तक उचित मूल्य दुकानों को चावल के कमीशन की राशि 1,01,30,975 रूपये तथा पीडीएस बारदाना की राशि 1,32,580 रूपये का भुगतान किया गया है। **(घ)** चावल के कमीशन की राशि एवं पीडीएस बारदाना की राशि भुगतान हेतु शेष 59 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण भुगतान की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष उचित मूल्य दुकानों को कमीशन एवं पीडीएस बारदाना की शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी पी.डी.एस. दुकान के विषय में चर्चा हो रही थी । मेरे क्षेत्र जैजेपुर विधान सभा में भी इस प्रकार के मामले हैं, जो शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को पी.डी.एस. अन्त्योदय निराश्रित एवं प्राथमिकता कार्ड और बारदाना में किस-किस दर से, कौन से आधार पर कमीशन एवं अन्य राशि का भुगतान किया गया है ? अध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ वर्ष हो गये हैं, पी.डी.एस. संचालित दुकान वालों को कमीशन नहीं मिला है, जैसे कि सदस्य महोदय जी ने बताया कि क्या भुगतान कमीशन की राशि से करना है या जैम से करना है, इसकी जानकारी मुझे भी चाहिये । माननीय मंत्री जी, कृपया विस्तार से जानकारी देंगे और अभी तक कमीशन क्यों नहीं मिला है, मैं यह भी जानना चाहता हूँ ?

[1] परिशिष्ट "तीन"

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 348 राशन दुकान में से 289 दुकान का भुगतान कर लिया गया है, वर्ष 2023 का पूर्ण भुगतान कर लिया गया है तथा 59 दुकानों का भुगतान शेष है । अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी जो पूछ रहे हैं, उसके यहां का 14 राशन दुकान है, इस 14 राशन दुकानों शार्टेज मिला है, इसलिये वहां का भुगतान नहीं हुआ है ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री महोदय जी, जो शार्टेज मिला हुआ था, उसके निराकरण के लिये एस.डी.एम. कार्यालय में लगा हुआ था कि सक्षम न्यायालय एस.डी.एम. कार्यालय द्वारा दुकान संचालक के पक्ष में आदेश पारित हुआ था और इस प्रकरण को नस्तीबद्ध भी कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं जब विधान सभा में प्रश्न लगाया और वह मेरे पास आया तो मेरे आने से पहले फुड इंसपेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, खाद्य अधिकारी, कलेक्टर को मैंने फोन भी किया कि इनका जांच करके कमीशन का भुगतान दिलवा दीजिए, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है । मैंने जब प्रश्न लगाया तो 17-3-2025 को फिर से प्रकरण दर्ज कर लिया और पुराना प्रकरण को अनदेखा कर लिया गया है । जब पुराने एस.डी.एम. के द्वारा जांच कर नस्तीबद्ध कर दिया गया है, उसके बावजूद भी आपको विश्वास नहीं है । अध्यक्ष महोदय, उसको भुगतान नहीं मिलेगा तो वह कैसे संचालित कर पायेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आज आपने लंबा-लंबा प्रश्न दिवस घोषित किया है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- फुड का है ना ? चलिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- उनको संतुष्ट करिये । डेढ़ साल से भुगतान नहीं मिल पाया है । 14 दुकानें नहीं था, 59 दुकान था ।

अध्यक्ष महोदय :- कब दे देंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जितना लंबा प्रश्न है, उतना ही लंबा आप उत्तर देना ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ दूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप संक्षिप्त में बताईये ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 दुकानें हैं, जो विधायक जी एस.डी.एम. कोर्ट में बता रहे हैं तो पुर्नअवलोकन के लिये कलेक्टर महोदय ने 14 दुकानों को पुन: एस.डी.एम. को भेजा है । निराकरण के हिसाब से भुगतान...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण एस.डी.एम. में नस्तीबद्ध हो चुका है । मैंने इसमें 6 महीने से प्रयास किया है कि इसका भुगतान मिल जाये । मैंने प्रश्न लगाया तो 17-3-2025 को प्रकरण दर्ज किया गया है । अब मानलो साल-डेढ़ साल फिर कमीशन नहीं पायेगा तो

पी.डी.एस. चावल को वितरण कैसे होगा, वह पैसा कहां से लायेगा, खेत बेचकर लायेगा कि ब्याज में पैसा उठायेगा, यह बतायें ?

श्री दयालदास बघेल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ कि 14 दुकानों का है, इसमें जो शार्टेट मिला है तो कलेक्टर ने पुर्नअवलोकन के लिये एस.डी.एम. के पास भेजा है, वह प्रकरण लंबित है । जैसे ही इस पर निर्णय होता है, जो फैसला आता है...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह मामला एस.डी.एम. कार्यालय में और दो-तीन साल लगेगा ? यह मामला बहुत छोटा है, इसमें निर्णय हो जाना चाहिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा नियम है कि यदि किसी के पास शार्टेज है तो उसका कमीशन रोक दिया जाये, अगर ऐसा नियम है तो पूरे प्रदेश का कमीशन रोका जाये ? अध्यक्ष महोदय, सभी दुकानों में कुछ न कुछ शार्टेज है । मैं यह चाहता हूँ कि कमीशन रोकना उचित नहीं है, आप उनको तत्काल भुगतान के लिये आदेश करिये । जब एस.डी.एम. कार्यालय में प्रकरण का निराकरण होगा, उसको शार्टेज भरना रहेगा तो भरेगा या जिस विभाग से शार्टेज हुआ है, उसको मात मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उनको जल्द से जल्द भुगतान 10-15 दिनों में कराइये ।

अध्यक्ष महोदय :- भुगतान कराईए । प्रश्न संख्या-6 विक्रम मण्डावी जी ।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ बोल दीजिए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि 14 प्रकरण एसडीएम कोर्ट में लंबित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी से जल्दी कराईए, यह माननीय विधायक जी चाहते हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- जी हां ।

पालना योजना अंतर्गत व्यय राशि

[महिला एवं बाल विकास]

6. (*क्र. 2398) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में पालना योजना कब से प्रारंभ की गई? योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य किए जाने थे? वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश एवं राज्यांश कितना प्रावधानित/स्वीकृत किया गया ? 15 फरवरी, 2025 तक कितना व्यय हुआ? किस-किस कार्य में व्यय हुआ? कितना शेष है? कृपया

बतावें ? **(ख)** क्या वर्ष 2024-25 में पालना घर संचालित किया जाना था ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना किया गया ? सम्पूर्ण जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : क) कंडिका 'क' के अनुसार-

- प्रदेश में पालना योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रारंभ की गई ।
- योजना अंतर्गत योजना प्रावधान के अनुसार कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पालना (आंगनबाड़ी सह-पालना) का संचालन किया जाना है।
- वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश 60 प्रतिशत के मान से 48251250/- रूपये का मदर सेन्शन प्राप्त है। 40 प्रतिशत राज्य का अंशदान उपलब्ध है।
- 15 फरवरी 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। उपलब्ध केन्द्रांश 48251250/- रूपये (60 प्रतिशत) तथा 40 प्रतिशत राज्य का अंशदान शेष है।

(ख) कंडिका 'ख' के अनुसार-

- जी हां, वर्ष 2024-25 में पालना घर संचालित किया जाना था।
- संचालित पालना केन्द्र का जिलेवार विवरण संलग्न प्रपत्र[2] अनुसार है।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पालना योजना के अंतर्गत 2024-25 के लिए 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2024-25 में केन्द्रांश और राज्यांश का भुगतान होना था, उस समय उसकी अनुमति वित्त विभाग से नहीं मिल पाई थी, परन्तु अभी वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है । वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद पैसा रिलीज़ कर दिया गया है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 15 फरवरी, 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है और केन्द्रांश और राज्यांश की राशि शेष है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब राशि शून्य है तो जो 175 पालना घर आप संचालित कर रहे हैं, उनका व्यय किस मद से किया जा रहा है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए राशि आई हुई है और इसमें केन्द्र का अंशदान 4,82,51,250 रूपए दर्शाया गया है । मैंने वही बात बताई कि 25 फरवरी के बाद फिलहाल में ही वित्त विभाग से अनुमति मिली और राशि रिलीज़ कर दी गई है ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कोई राशि व्यय नहीं हुई है, उसके बावजूद भी आप मेरे प्रश्न के उत्तर में बता रही हैं कि 175 पालना घर का संचालन हो रहा है, उसके बाद भी यह बता रही हैं कि 15 फरवरी, 2025 तक राशि

[2] परिशिष्ट "दो"

खर्च नहीं हुई है तो जो पालना घर संचालित हो रहा है, उसक खर्च किस मद से हो रहा है ? उसके खर्च की जानकारी तो आपने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि किस मद से खर्च हो रहा है । मद की जानकारी मिलते ही मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है । आपको जानकारी दे देंगी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के लिखित उत्तर में ही जानकारी दी कि 15 फरवरी, 2025 तक किसी तरह की कोई राशि व्यय नहीं की गई है तो क्या यह योजना साल भर संचालित नहीं थी ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना संचालित है । पालना योजना केन्द्र सरकार की योजना है और यह योजना संचालित हो रही है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार प्रश्न का उत्तर देख लीजिए । मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट जानकारी दी है कि 15 फरवरी, 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है । 15 फरवरी मतलब मार्च का अंतिम महीना है । अगर साल भर राशि व्यय नहीं हुई है तो योजना संचालित हुई ही नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पैसा रिलीज़ होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया अभी चल ही रही है और जैसे ही वह कम्पलीट हो जाती है तो राशि पहुंच जाएगी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर दिया है कि 15 फरवरी, 2025 तक किसी तरह की कोई राशि व्यय नहीं की गई है, यह गलत है। आप बता दीजिए, इसको स्पष्ट कर दीजिए ।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राशि खर्च ही नहीं हुआ है तो पूरे राज्य में पालना योजना कैसे चल रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एसएनए स्पर्श मॉडल के अंतर्गत आ रही तकनीकी दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। 31 मार्च, 2025 तक जिलों द्वारा राशि का आहरण कर लिया जाएगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब ही नहीं आ पा रहा है। मैंने दो बार पूछा कि इसमें जब खर्च ही नहीं हो रहा है, मंत्री जी स्वयं उत्तर दे रही हैं कि इसमें खर्च कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ ये बता रही हैं कि पूरे प्रदेशभर में 175 पालना घर चल रहे हैं। दोनों कैसे हो सकता है? या तो आप जो 175 पालना घर चला रहे हैं, वह नहीं चल रहा है या फिर ये असत्य है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप क्लीयर करा दीजिए या आप बता दीजिए क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि राशि व्यय नहीं हुई है, तो फिर ये संचालित ही नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पालना केन्द्र का संचालन हो रहा है। जो व्यय की बात कर रहे हैं, उसे स्पष्ट रूप से मैंने माननीय सदस्यों को बताया है कि एसएनए स्पर्श मॉडल के अंतर्गत आ रही तकनीकी दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। 31 मार्च, 2025 तक जिलों द्वारा राशि का आहरण कर व्यय कर लिया जाएगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किस मद की राशि खर्च की जा रही है?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी, इनको 12.00 बजे के बाद अपने चेम्बर में चाय पीने के लिए बुला लीजिए, वहीं बैठकर इसका निराकरण कर दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर तो मिलना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर लिया जाएगा मतलब? साल तो खत्म होने वाला है, 10 दिन बचा हुआ है, यह financial year तो खत्म हो जाएगा। यदि साल भर किसी योजना में आपने व्यय नहीं किया है, इसका मतलब योजना संचालित नहीं थी, आप इसको मान लें या आप ये मान लें कि आपने लिखित में जो उत्तर दिया है, वह गलत है? दोनों बातें कैसे सही हो सकती हैं? या तो आपने व्यय किया और ये जो योजना है, उसे संचालित किया या फिर इस योजना को संचालित ही नहीं किया, व्यय ही नहीं किया? आप आहरण कर लेंगे तो कब करेंगे क्योंकि year end हो गया?

अध्यक्ष महोदय :- इनका लिखित जवाब पूरा पढ़ेंगे तो वर्ष 2024-25 में केन्द्रांश 60 प्रतिशत के मान से 48251250 रुपए का मदर सेन्शान प्राप्त है। 40 प्रतिशत राज्य का अंशदान उपलब्ध है। इसके आप दूसरे जवाब में देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि ये राशि उपलब्ध है। तो जो काम चल रहा है, इस राशि से चल रहा होगा।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी बताए हैं कि इसमें वर्ष 2024 से पहले राशि नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप दूसरे पैरा का उत्तर पढ़ेंगे तो क्लीयर हो जाएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात समझ गया।

अध्यक्ष महोदय :-दूसरे पैरा को पढ़ लेंगे, जवाब संपूर्ण है और उसके बाद भी आपको कोई और स्पेशिफिक जानकारी चाहिए, तो मंत्री जी उपलब्ध करा देंगी।

श्री उमेश पटेल :- मैं तो आपसे पूछूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय :- मंजी जी, उपलब्ध करा देंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- मुझे उत्तर मंत्री जी से समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय:- समझ में आ गया। वे आपको पूरा उत्तर दे देंगी।

श्री उमेश पटेल :- एक संशय है आप इसे दूर करा दीजिए।

श्री विक्रम उसेंडी :- दोनों उत्तर में अंतर है।

श्री उमेश पटेल :- मेरा एक संशय है, इसमें इन्होंने कहा है कि राशि व्यय नहीं की गई है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि केन्द्रांश उपलब्ध है। तो केन्द्रांश की राशि खर्च की गई 60% और राज्य की कोई भी राशि इस योजना में खर्च नहीं की जाती, इसे मंत्री जी से स्पष्ट करवा दें?

अध्यक्ष महोदय:- चलिए, आप पूरी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कभी तो उत्तर आता नहीं है। आप सभी से पूछ लीजिए, मंत्री जी उपलब्ध कराते हैं?

श्री रिकेश सेन :- पूरा उत्तर तो आपको मिल चुका है।

अध्यक्ष महोदय:- आपको उपलब्ध करायेंगी। प्रश्न क्रमांक 07, अब आगे बढ़ गए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 2360) श्री इंद्र साव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत पेंशन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? इन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी, 2024 से लेकर दिनांक 15.02.2025 तक पेंशन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना था? कितना भुगतान किया गया? योजनावार जानकारी देंवे? समय पर भुगतान न होने के क्या कारण है तथा पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार उपरोक्त योजना में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत कितने हितग्राहियों को, किस-किस योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया, विकासखण्डवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं जनवरी, 2024 से दिनांक 15.02.2025 तक इन योजनाओं के तहत भुगतान किये जाने वाली राशि व की गयी भुगतान राशि की

योजनावार जानकारी निम्नानुसार है -

(राशि रुपये लाख में)

क्रमांक	**योजना का नाम**	**भुगतान किये जाने वाली राशि**	**भुगतान की गई राशि**
1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	693.95	693.95
2.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	404.81	404.81
3.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना	48.06	48.06
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1298.16	1298.16
5.	सुखद सहारा योजना	446.69	446.69
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	2274.72	2274.72
योग		**5166.39**	**5166.39**

पेंशन राशि का भुगतान समय पर किया गया है । पेंशन राशि का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा सीधे लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer (DBT)) के माध्यम से पेंशन राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा करायी जा रही है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र[3] अनुसार** है।

श्री इन्द्र साव :- माननीन अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय समाज कल्याण मंजी से बहुत छोटे-छोटे दो-तीन प्रश्न हैं कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कितने पेंशन की योजनाएं लागू हैं। इसके साथ ही वहां की भुगतान की स्थिति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी चाही गई है, कृपया बताएं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो इसे माननीय सदस्य को उत्तर में दे दिया गया है और विकासखंडवार उत्तर भी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया गया है। अगर चाहेंगे तो मैं इसे पढ़ दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- पढ़कर सुना दीजिये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला बलौदा-बाजार, भाटापारा के अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

[3] परिशिष्ट "पाँच"

योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजनाएं हैं। यह केंद्र की योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो राज्य की योजनाएं हैं, वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना है।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों के द्वारा पिछले 2023 के चुनाव में मोदी की गांरटी के तहत एक योजना की घोषणा की गयी थी। आपके घोषणा पत्र के पेज नंबर 12 के सरल क्रमांक-4 में है कि प्रदेश के हर नागरिक को अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करेंगे, जिसमें योजना का आधा भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। माननीय मंत्री जी के उत्तर में इस योजना का जिक्र नहीं है। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आप इस योजना को कब लागू करेंगी ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कभी-भी घोषणा पत्र में घोषित जो योजना संचालित है, उसकी तारीफ कभी नहीं करते लेकिन जो बची हुई घोषणाएं हैं, उनके बारे में बोलते हैं। आप चिंता मत करिये धीरे-धीरे सब काम हो रहे हैं। हमारी सरकार ने कम समय में ही बहुत सारी घोषणाओं को पूरा किया है और आने वाले समय में इन सब को भी पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वैसे 6 योजनाओं में शत् प्रतिशत पेमेंट हो चुका है। आप क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक का पढ़ेंगे तो उसमें शत् प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। एक योजना के बारे में मंत्री जी ने कहा कि हम आगे आने वाले समय में उस योजना को लागू करेंगे।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी योजनाएं तो पुरानी योजनाएं हैं, जो अभी वर्तमान में लागू है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप घोषणा पत्र या कई चीजों के ऊपर जो संकल्प लेकर आये थे क्या आपने पहले उसकी पूर्ती की थी ? प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है, आपने उसके बारे में जानकारी पूछी है और माननीय मंत्री जी ने आपको उन 6 योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करायी है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय मूणत जी, आपको जब हर बात में यह सूझता है कि आपके पांच साल, आपके पांच साल, तो जब हम लोग यह कहते हैं कि आपकी डबल इंजन, त्रिपल इंजन और चार इंजन, तो इसमें आपको क्यों तकलीफ होती है ? जब आप हमको सुनाते हैं तो आप भी सुनने का साहस रखा करिये।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जो प्रश्न है और आपने उस प्रश्न में जो पूछा, मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है। वह प्रश्न के बाहर का प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए मैंने उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपके प्रश्न का पूरा जवाब आ गया है।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी मेरा मूल प्रश्न नहीं आया है। मेरा सवाल समाज के अंतिम छोर से जुड़े अशक्त और बेसहारा लोगों से संबंधित है और यदि इसमें माननीय सदस्य के द्वारा पिछली सरकार की बात की जा रही है। यदि कोरोना काल को छोड़ दे तो हमारी सरकार मात्र तीन साल तक रही और उसमें जो इतना बेहतर काम हुआ है, आप लोग उस बात को भूल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं चाहता हूं कि पेंशन की जो संचालित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जो राशि का भुगतान है, वह हमेशा दो महीने, तीन महीने और कभी-कभी चार महीने देर से होता है। मैं इस पर माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यदि महीने की 1 से 5 तारीख के अंतराल में उनका भुगतान हो तो ऐसे गरीब हितग्राहियों को इससे बहुत लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- सदस्य का प्रश्न है कि समय में पेमेंट हो जाये और आप Direct Benefit Transfer (DBT) में कर रहे हैं या नहीं ? यह उनके खाते में सीधा पहुंच जाता होगा ? माननीय सदस्य की सिर्फ इतनी चिंता है कि समय पर पेमेंट हो जाये।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान शत् प्रतिशत हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप समय पर भुगतान करवा दीजिये।

जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत अनाथालय से गुम/लापता बच्चे

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 2357) श्री ब्यास कश्यप : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत कितने अनाथालय, वृद्धाश्रम, संचालित हैं? वर्ष 2021 से दिनांक 15.02.2025 तक विभिन्न अनाथालयों से कितने बच्चें गुम या लापता हुए हैं? वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के गुम या लापता बच्चों में से कितने बच्चों को वापस लाया गया एवं उन्हें कहां-कहां व्यवस्थापन में रखा गया? कितने बच्चें अभी भी लापता हैं? वर्षवार/विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कोई भी अनाथालय संचालित नहीं है, अपितु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला जांजगीर - चांपा में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों हेतु 01 बालगृह एवं 01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित है। उक्त बालगृह एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण से प्रश्नावधि में गुम या लापता हुए बालकों कीजानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसारहै। जिला जांजगीर-चांपा में समाज कल्याण

विभाग द्वारा 01 वृद्धाश्रम संचालित है, जिसमें कोई भी बालक निवासरत नहीं है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसारहै।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न किया था कि जांजगीर चांपा अंतर्गत कितने अनाथालय और कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं। उसका जवाब आया है लेकिन उसमें एक भी वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी नहीं है। एक जानकारी आयी है कि हेल्प एण्ड हेल्प समिति द्वारा बालगृह चलाया जा रहा है परंतु यह हेल्प एण्ड हेल्प समिति जांजगीर चांपा में कहां संचालित है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हेल्प एण्ड हेल्प समिति विकासखण्ड नवागढ़ में संचालित है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नवागढ़, जांजगीर में किस स्थान पर है ? आप स्थान बता दीजिए कि नवागढ़ विकासखण्ड में कहां पर संचालित है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां नैला में यह समिति संचालित है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नैला में संचालित है। मैं तो नैला में स्वयं रहता हूँ। मैंने आज तक इस समिति को नहीं देखा है। वहां पर मेरा निवास स्थान है। वहां पर यह समिति कहां पर संचालित है ? आप स्थान बता दीजिए कि नैला में यह समिति किस मोहल्ले, किस वार्ड पर संचालित है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जगह का नाम ही है। अगर यह नहीं होगा तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगी कि यह समिति कहां पर संचालित है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। देखिये। यह गंभीर विषय है। निश्चित रूप से जब यह प्रश्न आया है तो आप स्थान का नाम नैला बता रही हैं। मैं नैला में स्वयं रहता हूँ। मेरी उम्र 59 वर्ष है मेरी वही पैदाईश है और मैं वहीं रहा हूँ। आज भी वही निवास करता हूँ तो आप कम से कम जगह तो बता दीजिए। वह नैला में जगह तो बता देते कि यह समिति कहां पर संचालित है, जो चला रही है ? मैं केवल यही पूछ रहा था। आप यह बता दीजिएगा। नैला में और पूछ लूंगा। आपके द्वारा यह जो जानकारी आयी है। यहां पर एक तो अनाथालय और वृद्धा आश्रम की बात है तो जांजगीर-चांपा जिले में एक भी शासकीय वृद्धा आश्रम संचालित नहीं है। आपकी तरफ से इसकी जानकारी भी नहीं आ पायी है ? आपने जरूर वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक जानकारी दी है। वर्ष 2024 का एक प्रश्न आया था कि उस संस्था में एक लापता बालक को वापस लाने हेतु पतासाजी की जा रही है यानी अभी भी एक बालक गुम है, उसकी जानकारी नहीं हो पायी है। वहां 6 बालक में 5 प्राप्त हो गये हैं, अभी भी एक बालक लापता है। यह संस्था इस लापता बालक को अतिशीघ्र खोजे। और उसे खोजकर, उसके घर में

[4] परिशिष्ट "छः"

वापस पहुंचाये। जो आप संस्था चला रहे हैं अगर यह नैला में है तो मैं स्वयं इसकी खोजबीन करूंगा कि वहां किस संस्था के द्वारा संचालित है। यह एक गंभीर विषय है। निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर चिंतित है। जहां तक वृद्धा आश्रम और अनाथालय की बात है। किसी कारण से बच्चे चले जाते हैं और अनाथालय में रहते हैं। मैंने यह बचपन से ही देखा है कि जांजगीर में एक अनाथालय संचालित था। आज भी वहां बिल्डिंग बनी बनायी है, वह अच्छी स्थिति में है। वहां पर तो छत्तीसगढ़ के ही नहीं वरन् भारत देश के कई ऐसे बच्चे जो अनाथ होकर आते थे और वहां भर्ती रहते थे और शासन की ओर से उनकी पूरी व्यवस्था की जाती थी। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह चाहूंगा कि आज भी वहां बिल्डिंग बनी बनायी और व्यवस्था बनी बनायी है तो क्या भविष्य में अनाथालय या वृद्धा आश्रम के लिए उस संस्था, जगह का उपयोग करेंगे या प्राईवेट संस्था के ऊपर ही भरोसा करेंगे। सरकार इस विषय में जांजगीर-चांपा ही क्यों, हम पूरे प्रदेश में शासकीय स्तर पर क्या कर रहे हैं ? माननीय मंत्री महोदया, मैं यह थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है निश्चित तौर पर हम उस भवन का निरीक्षण कराकर, वह किस उपयोग में आ सकता है। हम उसका निरीक्षण करवायेंगे, फिर उसका उपयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय ब्यास कश्यप जी यही चाहते हैं कि उस बिल्डिंग का उपयोग हो जाए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। उस बिल्डिंग का उपयोग हो रहा है। वहां पर महिला एवं बाल विकास विभाग का स्थानीय कार्यालय लग रहा है। वहां पर जिला कार्यालय का भवन अलग है, परन्तु महिला एवं बाल विकास विभाग के जो सेक्टर प्रभारी लोग रहते हैं, वह वहां पर है। मैं माननीय मंत्री महोदया से इसमें एक बहुत अच्छी बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग इन बच्चों के लिए योजना बनाने और कार्य करने के लिए आई.सी.पी.एस. को कितना बजट उपलब्ध करवाते हैं ? कृपया करके यह बता देते । यह चिंता, आप सरकार की तरफ से उनके लिए कितना बजट उपलब्ध कराते हैं, वह जाता कहां है ? आपके विभाग के पास इतना बजट है, उसकी क्या उपयोगिता हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप माननीय सदस्य को बजट के बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्। आपने कह दिया तो मैं उनकी तरफ से उत्तर मान लेता हूँ। आप मुझे इनकी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

प्रश्न संख्या : 09 XX XX

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित चावल

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (*क्र. 2406) श्रीमती भावना बोहरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए प्रतिमाह कितना चावल राज्य को आबंटित किया जाता है? **(ख)** राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2025 तक इस योजना अंतर्गत कितने चावल का वितरण किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक प्रात्रता अनुसार वर्तमान में 1,15,338 टन चावल प्रतिमाह आबंटित किया जा रहा है । **(ख)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक 25,70,780 टन चावल का वितरण किया गया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्। मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में है। मैं इसमें इतना जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में कितने पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जो पात्र हितग्राही हैं, उनमें से कितने को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। आप एक बार फिर से प्रश्न पूछिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने पात्र हितग्राही हैं जिनको पात्रता होने के बाद भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो वितरण हो रहा है। माननीय विधायिका जी ने अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक का प्रश्न पूछा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य 55 लाख 78 हजार है और इनको लाभ मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने मात्रा पूछा है, संख्या नहीं। आपके प्रश्न में मात्रा है तो आप मात्रा तक सीमित रहिये। संख्या बताना संभव नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा दूसरा सवाल यह था कि क्योंकि यह योजना कोविडकाल में शुरूआत हुई थी और कोविडकाल के समय की बहुत सारी शिकायतें अभी भी मिलती हैं कि कोविडकाल में इनको 5 किलो अतिरिक्त अनाज मिलना था, वह उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया था। क्या आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि चूंकि गड़बड़ियां बहुत बड़े स्तर पर हुई थीं तो

कोविड 19 के समय जो वितरण में कमी आई थी, क्या उसकी कभी जांच होगी ? क्योंकि यह बहुत बड़ी शिकायत थी और स्थल पर भी देखने से यह पाया गया कि 5 किलो चावल से लोग वंचित थे, क्या उसकी कभी जांच होगी ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए कि माननीय सदस्या का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारो के लिए प्रतिमाह कितना चावल राज्य को आबंटित किया जाता है ?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पूरक प्रश्न में यह पूछ रही हैं कि 5 किलो अतिरिक्त चावल मिलता था, क्या गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच करा लेंगे ? यदि जांच करा लें तो अच्छा है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी गड़बडी की शिकायत नहीं है। जो भी जानकारी है, माननीय सदस्या बता दें, उसकी जांच करा देंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत आई है, इसलिए मैं पूछ रही थी। यह 2019 कोविड के टाइम का केस है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी को कोई बता दे, वह जांच करवाने में बहुत उदार हैं। यदि उनको कोई अवगत भर करवा दे तो जांच करवाने में दयालदास बघेल जी से उदार मंत्री कोई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- वह पूरी पारदर्शिता से करते हैं। राजेश मूणत ही, प्रश्न करिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब क्या आया, मैं नहीं समझ पाई। इसमें जांच होगी या नहीं होगी ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताया हूं कि इस योजना का लाभ 97 प्रतिशत लोगों को मिल रहा है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सवाल को एक बार रिपीट कर देती हूं। कोविड 19 के समय जो पात्र हितग्राही थे जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो चावल का लाभ नहीं मिल पाया। क्या अब उसकी जांच होगी ? मैं कोविड 19 के समय की 2019-20 की बात कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पुरानी बात पूछ रही हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। यह 2019-20 का प्रश्न पूछ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता। चलिये, राजेश जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या भावना बोहरा जी ने जो प्रश्न पूछा है कि केन्द्र सरकार से गरीब परिवार के लिए जो अनाज मिला था। आपको प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल आबंटित किया गया था, आपको वितरण करना था। जो वंचित व्यक्ति रहे हैं, जिस परिवार में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति थे, उन परिवार को केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को चावल आबंटित किया था। आप यह स्पष्ट कर दें कि वह वंचित क्यों थे और कितने परिवार वंचित हैं?

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जवाब की उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा केस था। अगर हमें यहां से जवाब नहीं मिलेगा तो फिर हमारे लिए प्रश्न पूछने का अन्य कोई माध्यम नहीं है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 का प्रश्न है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 कोविड काल के समय का है।

अध्यक्ष महोदय :- असल में आपके प्रश्न का संदर्भ अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 का है, आप 2019 में पहुंच गई हैं। मंत्री जी को 2019 में पहुंचने में समय लगेगा। आपका प्रश्न पढ़िए न । यह वर्ष 2023 से 2025 का है और आप वर्ष 2019 में पहुंच गये तो 3-4 साल पुरानी घटना की इनको सूचनी रहेगी तभी तो जानकारी दे पायेंगे, मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, तो अवगत करा देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अवगत करवाने में जांच करवा देंगे ? (हंसी)

श्री दयालदास बघेल :- नहीं, प्रश्न का ही तो बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । पर्याप्त है, उसका इतना ही जवाब होता ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या अभी भी केंद्र सरकार से मिल रहा है और क्या आप उन परिवारों को दे रहे हैं ? आप केवल इतना ही बता दीजिये । मैं वर्ष 2019 का पुराना नहीं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, नया पूछिए ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में केंद्र सरकार से आज भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल आपको केंद्र सरकार से मुफ्त में वर्ष 2028 तक केंद्र सरकार दे रही है तो क्या आप उन सभी परिवारों को दे रहे हैं ? आप कृपया यह स्पष्ट कर दें ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अतिरिक्त आवंटन अभी नहीं मिल रहा है । जो कॉर्ड है उसके साथ ही मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं मिल रहा है, चलिये । प्रश्न क्रमांक- 11, श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं मिल रहा है, अब जवाब तो आ गया । पुन्नूलाल जी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों में अनियमितता की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (*क्र. 2261) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) क्या2 प्रदेश में विगत दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राशन दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को प्रदान किये जाने वाले गुड़, चना, नमक, शक्कर के क्रय हेतु निविदा आंमत्रित की गई? यदि हां तो निविदा में किन-किन निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई तथा किस निविदाकार को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिया गया, पृथक-पृथक बतावें? गुड़, चना, नमक, शक्कर का क्रय कितनी मात्रा में, कितनी राशि का किया गया तथा किन-किन जिलों में, कितने हितग्राहियों को, कितने के मान से, किस दर पर वितरण किया गया? जिलावार बतावें? (ख) क्या प्रश्नांक (क) अनुसार क्या गुड़, चना, नमक, शक्कर के गुणवत्ता अथवा वितरण में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त हुई तो उन शिकायतों के अधार पर क्या कार्यवाही की गई क्या गुणवत्ताहीन सामग्री सप्लाई में शिकायत प्राप्त होने के कारण संबंधित सप्लायर/ठेकेदार के विरुध्द कोई कार्यवाही की गई? यदि हां तो क्या सप्लायर/ठेकेदार के नाम सहित जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रदेश में विगत 02 वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु गुड, चना, नमक क्रय निविदा संबंधी जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। शक्कर का क्रय निविदा के माध्यम से नहीं किया जाता है। शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 69,718 टन शक्कर राशि 241.57 करोड़ रूपये का तथा वर्ष 2023-24 में 67,433 टन शक्कर 233.65 करोड़ रूपये का क्रय किया गया। प्रश्नांकित अवधि में नमक, शक्कर, गुड एवं चना वितरण के लिए प्रचलित राशनकार्डो की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब[5] अनुसार है। नमक का वितरण अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह निःशुल्क किया जाता है। शक्कर का वितरण अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को 01 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 17 रूपये प्रति किलो की दर पर किया जाता है। चना का वितरण अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को 02 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 05 रूपये प्रति किलो की दर पर किया जाता है। गुड का वितरण बस्तर संभाग के अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को 02 किलो प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह 17 रूपये प्रति किलो की दर पर

[5] परिशिष्ट "आठ"

किया जाता है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में चना की गुणवत्ता के संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत जांच में सही नहीं पायी गयी। नमक, शक्कर एवं गुड में गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चना, नमक, शक्कर, गुड वितरण में अनियमितता की 268 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें से जांच में 221 शिकायत सही नहीं पायी गयी, 30 शिकायत सही पायी गयी। शेष 17 शिकायत लंबित है। सही पाये गये शिकायत में 02 उचित मूल्य दुकान निलंबित तथा 01 उचित मूल्य दुकान निरस्त किया गया । 02 उचित मूल्य दुकान को चेतावनी दिया गया, 07 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) न्यायालय में प्रक्रियाधीन, 18 प्रकरण में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कराया गया।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न चना खरीदी, गुड़ के विषय में था तो माननीय मंत्री जी ने चना खरीदी का नहीं बताया है और चना खरीदी की निविदा नहीं हुई है तो जब निविदा नहीं हुई तो किसके माध्यम से 40 लाख मीट्रिक टन जो चना है वह कहां से खरीदा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिना निविदा के केंद्रीय कृषि मंत्रालय से वर्ष 2024 में जो 40 टन चना को खरीदा गया था ?

अध्यक्ष महोदय :- सिर्फ चना पूछ रहे हो न ?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सिर्फ चना ।

श्री दयालदास बघेल :- जी, चना पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, चना तक ही है ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक का बैकलॉग का चना फरवरी, मार्च 2025 में वितरण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब दूसरा ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वितरण की बात ही नहीं कर रहा हूं । आप यह बता दीजिये कि बिना निविदा के चना खरीदी कहां से हुई ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि बैकलॉग से चना खरीदा गया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- कहां से ?

श्री दयालदास बघेल :- बैकलॉग से । जो चना मिलता है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप यह भी बताईये न कि कहां मिलता है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, ये स्वयं खाद्य मंत्री रहे हुए हैं ।

श्री दयालदास बघेल :- मालूम है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- खाद्य मंत्री भर नहीं, एक-बार इनके प्रभारी मंत्री वे रहे और उनके प्रभारी मंत्री ये रहे और फूड इनके पास भी और अब उनके पास है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, पड़ोसी हैं तो पूछ लिया करिये न ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह ठीक है । माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आप ही कहेंगे कि क्यों नहीं पूछ रहे हैं इसलिये मैं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोटा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मेरा सामान्य है ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई बात नहीं, आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री दयालदास बघेल :- मैं बता रहा हूं न ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अच्छा तो बता दीजिये ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से 40 हजार टन और शेष निविदा से । भारत सरकार से 40 हजार टन नाफेड से...।

अध्यक्ष महोदय :- नाफेड से लिया ।

श्री दयालदास बघेल :- और शेष निविदा से ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आगे प्रश्न करिये । नाफेड क्लियर हो गया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने चना खरीदा, उसके मिलिंग-पैकेजिंग की क्या प्रक्रिया थी ?

अध्यक्ष महोदय :- अब इतना बारीक में मत जाओ भई । (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों एक ही समाज से मंत्री हैं । पहले ये बने थे कि ये बने हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- दोनों फूड मिनिस्टर हैं । चलिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, मतलब चना-चावल सबका मामला तो फूड में समझ में आता है लेकिन यह हिसाब-किताब कैसे होता है या तो उनको समझाया नहीं होगा या हिसाब-किताब कैसे होंगे ? यह उनको नहीं समझाये हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको हिसाब-किताब चाहिए तो बता देना ।

डॉ. चरणदास महंत :- एक मिनट, दे देना । आपके मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा है, इसके पहले वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम पिछले साल ज्ञान के मार्ग पर चले थे, इस बार गति के मार्ग में आये हैं तो यह गति दिखा रहे हैं कि किस गति से इनकी सरकार चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको क्या पूछना है । पूछ लीजिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि रॉ मटेरियल खरीदा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि रॉ मटेरियल खरीदे हैं तो आप यह बता दीजिये कि उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कैसे की या कितने का किया? मेरा सामान्य प्रश्न है। प्रश्न में मेरा कोई आरोप नहीं है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चना वितरण पैकेट बनाकर ही..।

अध्यक्ष महोदय :- पैकैट बनाकर देते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 12, श्री संदीप साहू।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामग्री खरीदी में अनियमितता की शिकायतों की जांच

[महिला एवं बाल विकास]

12. (*क्र. 2424) श्री संदीप साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अतंर्गत वर्ष 2022-23 से फरवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत किन-किन तिथियों में, कहां-कहां पर एवं कितने जोड़ों का विवाह सम्पन्न हुआ है? **(ख)** विवाहित जोड़ों को शासन द्वारा क्या-क्या उपहार/सामग्री का वितरण किया गया है? जिलेवार एवं वर्षवार बतावें? क्या उक्त उपहार सामग्री की खरीदी निविदा के माध्यम से की गई है? यदि हां तो चयनित निविदाकारों का नाम, पता एवं संस्थान की जानकारी, वर्षवार एवं जिलेवार देवें? **(ग)** क्या उपहार सामग्री वितरण में ब्राण्डेड के स्थान पर लोकल सामग्री वितरण करने की शिकायतें शासन/प्रशासन को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों की जांच हुई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है? वर्षवार एवं जिलेवार विस्तृत जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी **संलग्न†**[6] **प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी निरंक है।

श्री संदीप साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा महिला बाल विकास मंत्री से सवाल है। बलौदाबाजार-भाटापारा एवं रायपुर के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत किन-किन तिथियों में, कहां-कहां एवं कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ? विवाहित जोड़ों को शासन द्वारा क्या-क्या उपहार/सामग्री का वितरण किया गया? जिलेवार एवं वर्षवार बतावें? क्या उक्त उपहार सामग्री की खरीदी निविदा के माध्यम से की गई है? यदि हां तो चयनित निविदाकारों का नाम, पता एवं संस्थान की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार मांगा थी। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सवाल है कि जो आपने निविदा से और बिना निविदा से सामान खरीदा है तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि आधा जो विवाह का

6 †परिशिष्ट "नौ"

सामान है, वह आप निविदा से लेते हैं और आधा समान बगैर निविदा से लेते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत खराब रहती है, स्तरहीन रहती है, जिसकी शिकायतें भी हुई हैं। आपने उसमें क्या कर्रवाई की?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जब आप मुख्यमंत्री थे, उस टाइम यह योजना प्रारंभ की थी और आज भी यह योजना चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस चीज के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, अभी तक हमारे पास ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं। अगर उनके पास आई होंगी तो हमें उपलब्ध करा दें। हम परीक्षण कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, कोई शिकायत हो तो बताइए।

श्री संदीप साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर शिकायतें हुईं, मुझे उसका जवाब प्रपत्र में भी नहीं आया, जबकि शिकायतें हुई हैं और जो स्तरहीन सामान खरीदी कर रहे हैं, क्या उसकी जांच मंत्री जी करवायेंगी?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, क्या आपने कोई शिकायत पत्र दिया है, जिसका जवाब नहीं आया है?

श्री संदीप साहू :- अभी इसी को मेरी शिकायत मान लें, मैं शिकायत दे दूंगा, लेकिन आज आप यहीं पर मेरी शिकायत दर्ज कर लें और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि ये योजना आपने चालू की थी और बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन आज यह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गयी है। बालोद की एक जगह में विवाह हुआ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- उनका होने दीजिए न।

श्री संदीप साहू :- कुंवर सिंह निषाद जी, एक जवाब आया है, उसी में एक सवाल है कि बालोद में 16 जोड़ो का विवाह हुआ। उन 16 जोड़ों के विवाह में जो खर्च हुआ वह 33 लाख रूपये है, जबकि प्रति जोड़े का जो खर्चा है वह 50,000 है और 8 लाख रूपये खर्च होना था, लेकिन इनका 33 लाख रूपये का जवाब आया है। तो ऐसे कौन से जोड़े की शादी हुई? क्या बाहर से पंडित आए थे, बाहर से सामान आए थे? क्या कोई ऐसी स्पेशल शादी थी, जो 16 जोड़ों में 33 लाख रूपये खर्च हुए?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनका हो जाये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक ही प्रश्न है। बालोद जिले का ही प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि बालोद में जब 16 जोड़े का बिहाव होता है तो 33,50,000 रूपये खर्चा होथे, गुरूर में 36 के होतिस तो एग्जेक्ट 18 लाख रूपया खर्च होथे। गुंडरदेही में 66 होती है तो 24 लाख रूपये खर्चा होथे। ऐसे करके राशि में अंतर आया। टोटल, 53 लाख रूपये का घाल-मेल हुआ

है। माननीय, आप अलग फिगर दे रहे हैं, आप खर्चा अलग बता रहे हैं, वास्तविक खर्चा से कहीं ज्यादा खर्चा टोटल बता रहे हैं। तो 53 लाख रूपये का अंतर आ रहा है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सम्माननीय विष्णु देव साय जी के सुशासन में पूरी पारदर्शिता के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन कराया जा रहा है, उसमें प्रति जोड़ा 50 हजार रूपये का खर्च है, जिसमें विवाह आयोजन व्यवस्था, परिवहन पर व्यय 8000 रूपये, वर-वधू के श्रृंगार पर उपहार सामग्री 7000 रूपये और जो हम वधू को..।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 53 लाख रूपये का अंतर आ रहा है। 33 लाख रूपये का हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 लाख रूपये खर्च हुए हैं। (व्यवधान)

श्री संदीप साहू :- 33 लाख रूपये खर्च हो रहे हैं और उसका जवाब आया है। (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आप गलत जानकारी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 53 लाख रूपये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा.

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16, सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024-2025 के संदर्भ में तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-2024

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4, सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखती हूं ।

समय

12.02 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) लोक जैव विविधता पंजी तैयार नहीं करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होना.

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- इसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है इसलिए जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, चाहे इस पक्ष के हों, चाह उस पक्ष के हों, मैं सबका ध्यान चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जो भी विषय उठाते हैं, पूरा सदन गंभीरता से सुनता है । आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इतने वरिष्ठ हैं कि आपकी बात को सब सुनते भी हैं और नए विधायक समझते भी हैं, इसलिए जारी रखें

डॉ. चरणदास महंत :- मैं विशेष रूप से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी बातों को समझने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष महोदय :- जो समझ नहीं आएगा, उसका जवाब भी आप देंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके रहते, यह जुर्रत मैं कैसे कर सकता हूं सरकार।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का यह प्रमुख दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत का लोक जैव विविधता पंजी तैयार करे। यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और इतना बड़ा कार्य आज तक कभी नहीं हुआ है। यह पहली बार हो रहा है कि प्रत्येक गांव को जैव विविधता का इतना व्यापक सर्वे तथा प्रतिवेदित करने का कार्य किया जा रहा है। इस बोर्ड ने इस कार्य को अत्यधिक विलम्ब से करना प्रारंभ किया था। अनेक विशेषज्ञ संस्थाओं को इम्पैनल्ड करके यह कार्य करवाया जाना प्रारंभ किया गया था। आज की स्थिति में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, परंतु आम जनता को इसकी प्रगति की जानकारी नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि खुद मुझे यह जानकारी नहीं है । मैंने अपना सफर 45 साल पहले शुरू किया है, 1980 में मैं एमएलए था और तब से आज तक यह जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको मैं रोकना नहीं चाहता, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, स्वतंत्र हैं किंतु ध्यानाकर्षण में सिर्फ ध्यानाकर्षण पढ़ा जाता है ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो ध्यानाकर्षण ही पढ़ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उसके बाद आप जितने प्रश्न करना चाहें, स्वागत् है ।

डॉ. चरणदास महंत :- जी । आज की स्थिति में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था परंतु आज जनता को इसकी प्रगति की जानकारी नहीं है । जिन ग्राम पंचायतों की लोक जैव विविधता पंजियां तैयार की

जाकर स्वीकृत की जा चुकी हैं उन पर आगे क्या किया जाना है और क्या किया जा रहा है और इस कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है, यह प्रश्न उठता है। यह पंजियां अनेक दृष्टियों से, जिसमें अनुसंधान तथा योजनाएं बनाया जाना शामिल है। इम्पैनल्ड संस्थाओं के द्वारा तैयार करके प्रस्तुत की गई पंजियों में से अनेक पंजियों को परीक्षण में उपयुक्त नहीं पाया गया था, जिसे सुधारकर प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना चाहिए। राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड के और भी अनेक दायित्व है जिसमें वेटलैंड से संबंधित कार्य भी शामिल हैं। इस दिशा में भी कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। अब तक राज्य के एक भी वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित नहीं किया गया है, जबकि भारत के 89 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। हमारे राज्य में इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, जिसकी अब तक कमी रही है। देश के 23 से अधिक राज्यों में रामसर स्थल घोषित किये जा चुके हैं। पी.बी.आर. तैयार करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने के कारण प्रकृति प्रेमियों तथा आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक महत्वपूर्ण दायित्व प्रत्येक स्थानीय निकाय का लोक जैव विविधता पंजी तैयार करना है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है। यह सही नहीं है कि इस कार्य को अत्यधिक विलंब से प्रारंभ किया गया था बल्कि बजट उपलब्ध होते ही जैव विविधता का व्यापक सर्वे एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बी.एम.सी) को लोक जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु बजट वर्ष 2015-16 से ही उपलब्ध कराना प्रांरभ कर दिया गया था। यह सही है कि विशेषज्ञ संस्थाओं को इम्पैनल्ड करके लोक जैव विविधता पंजी तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। आज की स्थिति में 12008 स्थानीय निकायों में (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्तर) में से 10540 स्थानीय निकायों की जैव विविधता पंजी तैयार हो चुकी है। यह कहना सही नहीं है कि आम जनता को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है बल्कि जैव विविधता पंजी तीन प्रतियों में बनाई जाती है जिसकी एक प्रति बी.एम.सी. को उपलब्ध कराई गई है।

ग्राम पंचायतों में लोक जैव विविधता पंजियां तैयार करने के उपरांत स्थानीय जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण एवं उन तक पहुंच का तरीका बी.एम.सी. द्वारा निर्धारित किया जाता है, तद्नुसार बी.एम.सी. द्वारा की जाने वाली कार्यवाही प्रगति पर है। लोक जैव विविधता पंजियां तैयार करने के कार्य में अब तक 105.40 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। यह कहना सही है कि इम्पैनल्ड संस्थाओं के द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गई पंजियों में से कुछ पंजियों को परीक्षण में उपयुक्त नहीं पाया गया था, जिसे सुधारकर प्रस्तुत करने के लिए वापस किया गया है। राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड के और भी अनेक दायित्व है जिनमें वेटलैण्ड से संबंधित कार्य प्रमुख रुप से सम्मिलित नहीं है। वेटलैण्ड से संबंधित कार्य

प्रमुख रुप से राज्य स्तर पर राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण के द्वारा संपादित किया जाता है जिसके सदस्य सचिव, राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड के सदस्य सचिव ही होते हैं। यह कहना सही नहीं है कि इस दिशा में कार्य की प्रगति संतोषप्रद नहीं है बल्कि जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की अनापत्ति प्राप्त कर भारत सरकार को कोपरा जलाशय बिलासपुर को रामसर स्थल नामांकित करने का प्रस्ताव राज्य शासन द्वारा नवंबर, 2024 में भेजा जा चुका है। इस प्रकार शासन ने इस दिशा में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अतः यह कहना सही नही है कि पी.बी.आर. तैयार करने तथा वेटलैंड स्थलों पर अपेक्षित कार्य नहीं होने के कारण प्रकृति प्रेमियों तथा आम जनता में रोष एवं आकोश व्याप्त है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान चाहूंगा और सभी साथियों का ध्यान चाहूंगा। जैव विविधता के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कौन-कौन से थलचर जानवर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली पाये जाते हैं और जलचर में मछली, मेंढक, कितने प्रकार की मछलियां, सांप पाए जाते हैं उसकी जनसंख्या को हमें एकत्रित करके बायोडायवर्सिटी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता है, उसको भेजना है, उसके अनुसार उसमें काम होना है। मैं सभी विधायक साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि कह रहे हैं कि इतनी पंजी बन चुकी हैं। मेरे गांव में पंजी बनी है या नहीं बनी है, यह मुझे पता नहीं है। यहां का एक भी विधायक यह बता दें कि उनके गांव में इस तरह से परीक्षण चल रहा है या हो रहा है? मेरे ख्याल से यहां सबसे विद्वान व्यक्ति वित्त मंत्री जी बैठे हैं तो वही बता दें कि उनकी कितनी पंचायतों में जैव विविधता के रजिस्टर तैयार किये जा रहे हैं या चंद्राकर जी भी बैठे हुए हैं, जो सबसे अनोखे कलाकार हैं तो वही बता दें कि उनकी पंचायतों में कितने जैव विविधता के काम हो रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जैव विविधता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को में सन् 1992 में चर्चा हुई थी, मगर भारत सरकार ने सन् 2002 में इसमें नियम बनाया और आपकी कृपा से सन् 2002 के बाद सन् 2015 में जब आपकी सरकार थी, तब आपने इसमें नियम बनाया और नियम बनाकर आगे काम करने के लिए इसको सौंपा। उसके बाद कुछ हुआ। वह नया-नया काम था। वह विचित्र काम था, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता था। वह धीरे-धीरे करके चलता रहा। हमारी सरकार आने के बाद 12 हजार PVR बने। जैसा कि रजिस्टर बता रहे हैं, उस रजिस्टर को तैयार किया गया। अभी धीरे-धीरे करके इनको भी वापस किया जा रहा है। कुछ वापस किये जा रहे हैं और कुछ को दूसरों को देने के चक्कर में है। मेरे पास अभी एक जानकारी आई है कि दिनांक 20.08.2024 को इस पर जितने भी काम किये गये थे। वैसे वह काम NGO ने ही किये हैं और उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि NGO से किसका क्या संबंध है। ये सब धीरे-धीरे वापस हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में इतना बड़ा काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि किसी भी विधायक को पता नहीं है कि हमारे गांव में कौन से कीड़े-मकोड़े, तितली, फंगस व दुनिया भर के स्थल में कितने जानवर हैं, उनकी गिनती होनी है कि वह कैसे-कैसे मिलते हैं? साथ ही पानी में रहने वाले सभी जानवरों

की भी गिनती होनी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा काम तो हमारी किसी भी पंचायत में नहीं चल रहा है। माननीय मंत्री जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यह बता दें कि आपको कहां से इसकी जानकारी मिल गई और क्या आपके किसी गांव में या किसी पंचायत में इस तरह से रजिस्टर बने हैं?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता जी को इसकी पूरी विस्तृत तौर पर जानकारी देना चाहूंगा। वर्ष 2015-2016 में जो PVR बने थे, वह लगभग 82 PVR बने थे। उसके बाद वर्ष 2018-2019 से लेकर वर्ष 2023-2024 तक 560 PVR बने। फिर उसके बाद 2675, 1034, 4211 PVR तथा वर्ष 2022-2023 में 1300 PVR और वर्ष 2023-2024 में 1382 PVR बने। इस तरीके से पूरे पूरे प्रदेश में PVR का निर्माण किया गया। हमको जो 12008 PVR बनाने थे, उसका मैंने आपको बताया कि उसमें से 10000 से ऊपर PVR बन चुके हैं। जिसके तहत हमको इस पंजी का संधारण करना है। मैं इस पंजी की 1 कॉपी भी आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से पूरी पंजी बनाकर उसको निर्मित किया गया है। इस पंजी में जो प्रावधान हैं, उसमें 1 से लेकर 32 तक प्रपत्र होते हैं। उसमें फसलीय पौधे, फलदार पौधे, चारा फसल, खरपतवार फसलों के कीट, पालतू प्राणियों के लिए बाजार जनदर्शिका, भू परिदृश्य, जल परिदृश्य, मिट्टी का प्रकार, फलदार वृक्ष, औषधि पौधे, शोभाकारी पौधे, इमारती पौधे, पालतू पशु, कल्चर मछलियां, हाट बाजार, वृक्ष झाड़ियां, जड़ी-बूटी व उसके साथ सभी प्रकार के जंगली प्रजातियों के भी हमारे उपयोगी पौधे हैं। आपने जो जलीय जैव विविधता के बारे में कहा है तो उसमें महत्वपूर्ण जंगली व जलीय पौधों की प्रजातियां, औषधि, उपयोग में जंगली पौधों से संबंधित इसकी विस्तृत जानकारी इसमें 1 से लेकर 32 प्रपत्र में हैं, उसमें हम लोग करते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, आप इसमें परेशान मत होइये। आपके विभाग वालों ने इसको कितने दिन में बनाया होगा, इसको मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं। आप यह बता दीजिए कि आपके पास ऐसे कितने रजिस्टर हैं? आपके पास छत्तीसगढ़ के गांव के इस प्रकार के कितने रजिस्टर हैं? मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के रजिस्टर बनाने के पैसे दे दिये जाते हैं। हमको पता नहीं है कि हमारे गांव में क्या गिन रहे हो। हमको जानकारी नहीं है कि क्या गिन रहे हो। पैसे आते हैं, पैसे से आर्डर हो जाते हैं, आर्डर से इस तरह से किताब बन जाते हैं और चला जाता है। आपके बाजू में बहुत विद्वान व्यक्ति राम विचार जी बैठे हैं। आप ही बता दो कि आपके गांव में इस तरह का परीक्षण हुआ है ? चन्द्राकर जी, आपके गांव में सर्वे हुआ है ? कौशिक जी, आपके गांव में सर्वे हुआ है ? मैडम भेंडिया, आपके गांव में सर्वे हुआ है ? सर, किसी के गांव में नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछने का दुस्साहस तो कर ही नहीं सकता हूं। मेरे पास ऐसा दुस्साहस नहीं है कि मैं आपको पूछूं कि आपके गांव में कितने सर्वे हुए हैं ? पैसे आ रहे हैं, मैं कहां बोल रहा हूं। आपके आर्डर जा रहे हैं, मैं कहां बोल रहा हूं। चलिये विद्वान मंत्री, वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी सलाह कर रहे

हैं, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपके पंचायत के बारे में ऐसी जानकारी है, जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, वैसा रजिस्टर बन रहा है ? आपके अध्यक्ष महोदय, किरण देव जी को जानकारी है क्या कि ऐसा रजिस्टर बन रहा है ? आपके सामने लखन लाल जी बैठे हैं, उनको जानकारी है ? छत्तीसगढ़ के किसी को भी किसी पंचायत की जानकारी है तो बता दीजिये, मैं उसके चरण छू लेता हूं, वैसे चरण तो मैं ही हूं, फिर भी छू लूंगा। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी दी कि इसमें जो पी.बी.आर. बनाया गया है, वह पिछली सरकार के समय में ही ज्यादा से ज्यादा बनाया गया है। यदि आपको किसी विषय पर आपत्ति है तो मैं आपको एक पूरी पंजी उपलब्ध करा देता हूं। यदि किसी चीज पर आपत्ति है तो उस आपत्ति पर जो भी कार्रवाई होगी, वह हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह कहना है कि पूरी तरीके से..।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप रजिस्टर बनाने का आदेश देते हैं तो बन रहे हैं न। मगर आपके बाजू बैठे हुए मंत्री जी से पूछ लो। वित्त मंत्री जी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, आज आपका विनियोग विधेयक है, मुझे पता है। मगर है ही नहीं। पूछा ही नहीं है, राम विचार जी का मुंह बंद हो गया। चन्द्राकर जी बोलना नहीं चाहते।

श्री राम विचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता जी का भ्रम दूर कर दे रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अभी पूछूंगा।

श्री राम विचार नेताम :- मैं अभी आपके भ्रम को दूर करता हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आप अपने शब्दों में मत करिये, वित्त मंत्री जी से मेरा भ्रम दूर कराईये। वित्त मंत्री जी, आप आई.ए.एस. आफिसर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके कार्यकाल में एक भी रजिस्टर बना ? क्या एक भी गांव में सर्वे हुआ ? क्या एक भी विधायक को इसके बारे में पता है कि उसके गांव में कितने प्रकार की मछलियां, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली है ? किसी को पता है क्या ? मुझे खुद ही नहीं पता।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया कि अभी हमने जो किया है, वह आपके सरकार के समय में हुआ है। अगर आपको कहीं पर आपत्ति है तो..।

डॉ. चरण दास महंत :- पिछली सरकार के समय ?

श्री केदार कश्यप :- हां, पिछली सरकार के समय। उस सरकार के समय में पी.बी.आर. बना है। यदि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, यदि आपको ऐसा लगता है तो बताईये, हम उसको भी दिखवा लेंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इसके biodiversity management committee हर पंचायत स्तर पर बना हुआ है। biodiversity management committee के माध्यम से जो कार्य करना है, उसका भी

कार्य निर्धारित है। यह जो पूरा जो दायित्व है, हम उसके तहत लगातार काम कर रहे हैं। हम अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे देश में हमारी स्थिति बेहतर है। आने वाले समय में इस दिशा में और क्या करना है, उस पर काम करेंगे। अब पी.बी.आर. बन गया। पी.बी.आर. का निर्माण हो गया तो अब हमको आगे और क्या काम करना है, मैं इसके सन्दर्भ में बताना चाहूंगा। पहला, स्थानीय वैद्यों को पहचान कार्य के तहत उनके ज्ञान के प्रमाणीकरण हेतु बस्तर के 43 एवं सरगुजा 44 वैद्यों का पहचान किया गया है। botanical service of india कोलकाता के माध्यम से स्थानीय शिक्षित युवाओं को Parataxonomy का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें कांकेर वृत्त के 40 और जगदलपुर वृत्त के 65 युवा सम्मिलित हैं। उसके तहत पी.बी.आर. में दर्शित जैव संसाधनों का मार्केट सर्वे जो कोचिया है, जो व्यापारी है, उससे जानकारी का एकत्रित करके उस व्यापार के माध्यम से जैव संसाधनों ए.बी.एस. की राशि बी.एम.सी. द्वारा वसूल किये जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, हम यह भी कर रहे हैं। पी.बी.आर. के माध्यम से बी.एम.सी. क्षेत्र के सम्पूर्ण जैव विविधता संसाधनों का डेटा एकत्रीकरण किया गया है, जिसमें जैव संसाधनों तक पहुंचकर विनाश विहीन विदोहन की पद्धत्ति से जैविक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण किया जा सके। इस बाबत आवश्यक प्रशिक्षण बी.एम.सी. को दिया गया है। बायोडायवर्सिटी हैरिटेज साइट को चिन्हिंत कर संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मंत्री जी को सुझाव दीजिये। आप प्रश्न क्यों कर रहे हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुझाव दीजिये कि रामसर साइट कैसे हो, रतनपुर को और कैसे डेव्हलप करके रामसर साइट बेहतर किया जा सकता है। रामसर साइट के लिए छत्तीसगढ़ के अलग-अलग 40 स्थान चिन्हांकित हुए हैं, जहां जैव विविधता है, उसके लिए विशेषज्ञों का पैनल बनता है, पैनल ही आईडेंटिफाई करके उस चीज का सर्वे करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि यह प्रोसेस कितना चल रहा है, लेकिन मैं उस बैठक में as a chief minister था, जब पूरे हिन्दुस्तान की 140 विशेषज्ञों को बुलाकर हमने लगातार दो दिन तक मंत्रालय में चर्चा किया था और उसका एक्शन प्लान बनाया। मंत्री जी पूरा जवाब देंगे, मगर अब आप इसमें आगे बढ़ कर सुझाव दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बताने की कोशिश की कि आप उस बैठक में थे, जिसमें 40 अधिकारियों एवं आप मुख्यमंत्री जी के रूप उपस्थिति थे।

अध्यक्ष महोदय :- अधिकारी नहीं, विशेषज्ञ थे।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने विशेषज्ञ के बातों को सुना होगा और समझा होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण कार्य है?

अध्यक्ष महोदय :- जी-जी।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं। मैं न ही मंत्री जी पर आरोप लगा रहा हूं, मैं वन विभाग पर आरोप लगा सकता हूं, लेकिन यहां से खड़े होकर आरोप लगाना उचित नहीं है। यह काम हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ था, इसको भी मैं मान लेता हूं। क्योंकि अभी तक शायद यह कार्य हमारे कार्यकाल का ही है। हमने पिछले पांच साल में हमारे कार्यकाल में इस कार्य को शुरू किया था। अभी वह कार्य रूक गया है। अब इस कार्यकाल में इसमें आप जो सोच रहे हैं तो आप यह सोच रहे हैं कि इसको जैम्स पोर्टल के माध्यम से कैसे कराया जाये। आप यह समझते होंगे कि आपने 40 विशेषज्ञों के साथ बैठक की है तो इसको जैम्स पोर्टल के साथ काम करा सकते हैं। यह कोई खरीदी का काम है? यह कोई बिक्री का काम है? यह परसेंटेज का काम है?

अध्यक्ष महोदय :- यह विशेषज्ञों का काम है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, अब इसको जैम्स पोर्टल से कैसे काम करायें और जो वनवासी केन्द्र बने हैं, उसको कैसे चमकाये, इस पर यह सरकार विचार कर रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिये, इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर दीजिये, हम लोग बैठ कर इस पर चर्चा कर लेंगे और छत्तीसगढ़ के हित में कोई बेहतर से बेहतर चीज सोच लेंगे। मुझे कुछ और आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे किसी भी दिन, आज नहीं, अगले वाले दिन में आधे घंटे, एक घंटे, डेढ़ घंटे या दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि जो आपका विषय है, वह रूचि का विषय है, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में विविधता से पूर्ण कुटुमसर की गुफाएं हैं, जहां अंधी मछलियां हैं और ऐसे ही अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत अध्ययन हुआ है, उसकी मेरे पास डिटेल जानकारी है, उसको आपको देने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी, अभी उनका सुझाव को मानकर क्या आप इसमें आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, आप चर्चा करा लीजिये तो बेहतर होगा। हम किसी के ऊपर आरोप लगाने के चक्कर में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। यदि आप सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चर्चा नहीं, बल्कि हम एक अलग से workshop करा देंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें भी तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इससे सहमत हूं। workshop होने से ही इसकी व्यापकता को और विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है। उसमें से मैं आपको बहुत सारे नाम दे सकता हूं, जिनको बुलाया जा सकता है। 25-30 नाम के विशेषज्ञ मेरे संपर्क में रहते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जब अलग विधान सभा सत्र होगा, उसमें एकाध दिन सबको बुलाकर विधायकों को बैठाकर workshop करा दीजिये। आधे घंटे की चर्चा में कुछ नहीं होगा। मंत्री जी, इसलिए उसमं एक करा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वह सबके समझ में भी आएगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी workshop के लिए तैयार हैं। वह अच्छी बात है कि इसमें विशेषज्ञ ही बात करते हैं। इसमें हम और आप सुनेंगे, बाकी लोग बात करेंगे। अब आप कुछ बोलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, मैं इनके बाद और बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- हाँ, बोल लीजियेगा। आप पहले पढ़ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय वन मंत्री महोदय, आपने अभी कहा कि पंचायत स्तर में बायोडावर्सिटी की कमेटी बनी है। इसी सत्र में बायो वेटलैंड विषय पर मेरा प्रश्न था। अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं। हमने जिला पंचायत में स्थायी समिति बनाई है। आप लोगों ने कांग्रेस शासन में एक अतिरिक्त समिति, गौठान समिति बनाई थी। जिला पंचायत में बायोडायवर्सिटी की ऐसी कोई समिति होगी, जनपद पंचायत में होगी या पंचायत में समिति बनती है, उसमें उल्लेख नहीं है, हमने उसमें गठन नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि हर पंचायत स्तर में समिति है, वह पंचायत के बाहर गठित है? किसके द्वारा गठित है? वह जिला पंचायत, जनपद पंचायत की समितियों में शामिल है? यह कहां पर गठित है, आप स्पष्ट नहीं हैं? यदि आप स्पष्ट हैं तो हमें स्पष्ट कर दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बायोडायवर्सिटी के लिये मैनेजमेंट कमेटी तय किया है, उसके तहत सदस्य की प्राथमिकता हमारे सभी जनपद में, जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगमों में, ग्राम पंचायत स्तर पर इन सभी स्थानों में है । स्थानीय निकायों द्वारा नाम निर्देशित 7 स्थानीय जानकार व्यक्ति इस कमेटी में रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें एक तिहाई महिला या न्यूनतम दो महिलायें होंगी । अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और जो अन्य सदस्य हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप इसको हाईपोथेटिकल बोल रहे हैं कि ऐसा होगा । मैंने आपसे पूछा है, अभी थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न में कहा कि हर पंचायत में गठित है । मैंने उसकी अभी जानकारी दी है कि हमने समिति, उप समिति का सभी जिला पंचायतों में गठन किया है । उसमें बायोडायवर्सिटी नाम की कोई कमेटी नहीं है, यह प्रस्तावित है कि इस तरह के महिला विशेषज्ञ रहेंगे कि गठित हो गई है, यह नहीं बतायें । मैंने इससे पहले गठित हो गई है, यह कहा था । अध्यक्ष महोदय, यह अंतिम प्रश्न है, आप जिस दिन वर्कशॉप करें, जैसा करें, अभी जो वर्तमान में वेटलैंड के अंदर अवैध कब्जा है, उसे वर्कशॉप तक हटवायेंगे क्या, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- इतना व्यापक प्रश्न का इतना व्यापक जवाब ? (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा प्रश्न कर लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा कर सकते हैं, मगर ..।

डॉ.चरणदास महंत :- वह तो...।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष महोदय, वेटलैंड तो एण्डलेस प्रोसिजर है । अभी आईडेंटिफाईड हुआ नहीं है, बहुत सारे आईडेंटिफाईड हो रहे हैं...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत जगह आइडेंटिफाईड कर लिया है । मुझे जो बताया गया कि 2.75 हेक्टेयर से ऊपर का आइडेंटिटीफाईड 11 हजार कुछ हेक्टेयर बताया था, मुझे याद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसका उद्येश्य यह है कि रामसर साईड के लिये, सॉल्यूशन के लिये, रिकमंडेशन जाता है, फिर रामसर साईड डिक्लेयर होता है । हमारे ही छत्तीसगढ़ में जैव विविधता के ऐसे 30-40 सेंटर हैं, कुटुमसर, रतनपुर से लेकर बाकी जगह में, जहां रामसर के लिये बेहतर हो सकता है और आपकी जानकारी में है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये कोई सुझाव दे सकते हैं, इसमें प्रश्न-उत्तर का सवाल नहीं है । इसमें मंत्री को जवाब देने के लिये परेशानी भी होगी । आपको जो बोलना है, सुझाव के रूप में बोलिये ना ? आप इतना अच्छा विषय लिये हो, उसे सुझाव के रूप में लीजिए, तब इसमें सार्थक रूप से आगे बढ़ाने का काम होगा ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कठिन विषय लिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- कठिन नहीं, अच्छा विषय है ।

डॉ.चरणदास महंत :- मगर आप सब समझदार है, आप इसमें 40 विशेषज्ञों के साथ बैठ सकते हैं । मैं समझ के लिया हूँ कि कम से कम आप तो समझेंगे ?

अध्यक्ष होदय :- बिल्कुल ।

डॉ.चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी तो सदन को फंसाने के चक्कर में कुछ भी पूछते रहते हैं । वह चाहता है कि मंत्री उलझ जाये । मैं यह बात कह देता हूँ कि जानकारी में यह आ गया है कि एक बढ़िया विशेषज्ञों की बैठक करा दें । हमारे सभी विधायक समझेंगे कि सचमुच में गांवों में क्या होना चाहिये ? आप इसके लिये जैम पोर्टल में काम देना चाहते हैं और जैम पोर्टल के माध्यम से आप वनवासी आश्रम को देना चाहते हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ । बहुत हो गया है, बढ़ा देते हैं ।

डॉ.चरणदास महंत :- एक सेकण्ड सर । मैं मानता हूँ कि वन क्षेत्र में बहुत सारे वन आश्रम हैं, मगर जब उसके पास विशेषज्ञ नहीं होंगे, काम तो कर ही नहीं सकते । आप रजिस्टर बनाने, छपाने, प्रिंटिंग कराने, प्रेस में जाने, यह सब को छोड़िये । बहुत मोटी-मोटी किताबें बनती है । वह नहीं देख पा

रहे हैं, जो आपके पीछे देख रहे हैं, वित्त मंत्री बने बैठे हैं, कलेक्टर भी रहे हैं । उनके पास तक तो जवाब नहीं है तो बाकी के पास जवाब होने का सवाल ही नहीं है । अध्यक्ष जी के पास जवाब है, मैं आपको प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगले सत्र में एक घण्टे का, दो घण्टे का, जितना देर आप ज्ञान का वर्धन कर सकेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी । यह देश का ही नहीं, बल्कि विदेश का और अंतराष्ट्रीय विषय है । कृपया इस पर आप चिंता करिये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण लाया है, इसे विषय विशेषज्ञों के साथ में, जैसा कि आपने कहा है, उनके साथ बैठकर वर्कशॉप भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ? एक लाईन में बोल दीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है, जो सबसे जुड़ा हुआ है । चूंकि सवाल से ज्यादा सुझाव की जरूरत है । इसमें कोई व्यवस्था यह भी आ जाये कि जो रजिस्टर बन गए हैं, जैसा कि समझ में आ रहा है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो क्या उसका अवलोकन किया जा सकता है कि पब्लिक के लिए उपलब्ध हो, हम लोगों के लिए उपलब्ध हो और क्या उसमें त्रुटि सुधार की जा सकती है, इस पर मंत्री जी प्रकाश डाल दें ।

अध्यक्ष महोदय :- सुझाव बहुत आ गए हैं । माननीय मंत्री जी, अब इसमें निर्णय यही है कि आने वाले समय में सुविधानुसार आप एक वर्कशॉप करें, ताकि सारे विधायक उसमें सम्मिलित हों और उनका ज्ञानवर्धन हो ।

श्री केदार कश्यप :- बिल्कुल । माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसका नाम ही पीबीआर है । पीबीआर मतलब पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर होता है । आप भी उसका अवलोकन कर सकते हैं, आप भी सुझाव दे सकते हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इनके विभाग से जितने रजिस्टर आए होंगे, उसे यहां रखवा दें, ताकि जिन विधायकों को भी देखना है, वे मेरे कक्ष में आकर देख लें ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम अपना ध्यानाकर्षण पढ़ेंगे ।

(2) बस्तर एवं सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्रों में नियम विरूद्ध वन भूमि को आवंटित किया जाना.

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- राज्य की ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत वन क्षेत्र के वन भूमि प्रदाय में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके कारण जगह-जगह पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है । कुछ ग्राम सभाओं को बहुत कम एवं कुछ ग्राम सभाओं को बहुत ज्यादा वन भूमि मनमाने ढंग से आवंटित कर दी गई है। वन भूमि के आवंटन में गांव की आवश्यकता, जनसंख्या एवं

वनों तक पारंपरिक पहुंच का ध्यान नहीं रखा गया है एवं न ही इस हेतु विभाग के द्वारा कोई गाईडलाईन जारी की गई है । कई स्थानों पर समीप के ग्रामों की निस्तारी वन भूमि को दूसरी ग्राम सभा को आवंटित कर दिया गया है । मनमाने एवं पक्षपात पूर्ण तरीके से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार बांटा गया है । वन क्षेत्र के वितरण में ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया गया है । बस्तर अंचल के माचकोट व सरगुजा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी तरीके से ग्राम सभाओं का आयोजन एवं वन क्षेत्रों का आवंटन किया गया है । इस प्रकार विगत 5 वर्षों से मनमाने एवं पक्षपात पूर्व तरीके से ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वितरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है एवं आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है । वन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही से पूरे राज्य के वन अंचलों में निवास करने वाली जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय :
12:33 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय सभापति महोदय, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत धारा 3(1)(i) में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के अनुसार वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के सामुदायिक रूप से वन भूमि पर ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनरूज्जीवित या संरक्षित या प्रबंध करने का अधिकार होगा, जिसका वे सतत् उपयोग के लिए परम्परागत रूप से संरक्षा और संरक्षण कर रहे हैं । ये अधिकार ग्राम सभा को प्रदाय किये जाते हैं । इन अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया ग्राम स्तर पर प्रारंभ की जाती है । इससे ग्राम सभा की ओर से वन अधिकार समिति को अधिकृत किया जाता है । वन अधिकार समिति परम्परागत सीमा का ग्राम के बुजुर्ग एवं अनुभवी लोगों के साथ मिलकर नजरी नक्शा तैयार करती है और इसके पश्चात् इसका स्थल सत्यापन करती है । स्थल सत्यापन के समय लगे हुए ग्रामों वन अधिकार समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को भी सूचित किया जाता है, ताकि वे भी उपस्थित रहें । साथ ही शासकीय कर्मचारियों जैसे बीट गार्ड, पटवारी आदि भी उपस्थित रहते हैं । इनकी उपस्थिति में परंपरागत सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ग्राम सभा में वन अधिकार समिति द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे ग्राम सभा द्वारा पारित करने के उपरांत अभिलेखों तथा नक्शे सहित उपखण्ड स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाता है । उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा इसका परीक्षण कर पात्र पाये जाने पर जिला स्तरीय समिति को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं वन अधिकार पत्र जारी किया जाता है ।

अतः ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति पश्चात् ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि मनमाने ढंग से वन भूमि वितरित की गई है। वन भूमि के आबंटन में ग्राम की आवश्यकता, जनसंख्या एवं वनों पर पारंपरिक पहुंच का ध्यान रखा गया है। विभाग द्वारा सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रकिया के प्रवाह चार्ट (Flow Chart) सहित संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर्स को जारी किया गया है। इसके साथ ही समय-समय पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण/ दिशा-निर्देश जिलों को जारी किया जाता है। वन अधिकार अधिनियमों एवं नियमों के जागरूकता के संबंध में विभाग द्वारा उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर समय-समय पर कार्यशाला/ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। राज्य में ग्रामों की निस्तारी वन भूमि को दूसरी ग्रामसभा को वितरित नहीं किया गया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु दावा प्रक्रिया करते समय सीमावर्ती ग्रामों की अनापत्ति भी ली जाती है। वन अधिकार अधिनियम एवं नियमों में निहित प्रावधानों के तहत् सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। मनमाने एवं पक्षपात पूर्ण तरीके से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित नहीं किये गये हैं। वन क्षेत्र के वितरण में ग्रामीणों को विश्वास में लेकर ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। फर्जी ग्रामसभा के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बस्तर अंचल के माचकोट क्षेत्र में स्थल परीक्षण, पारंपरिक सीमा निर्धारण, समीप के ग्रामों से सहमति के पश्चात् नियमानुसार ग्रामसभा का आयोजन किया जाकर उपखण्ड स्तरीय तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के विचारण एवं अनुमोदन उपरांत वन क्षेत्रों को आवंटित किया गया है। ग्रामसभाओं का आयोजन फर्जी तरीके से नहीं किया गया है।

सरगुजा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी तरीके से वन क्षेत्रों का आवंटन नहीं किया गया है। ग्रामसभा, उपखण्ड स्तर की समिति एवं जिला स्तर की समिति द्वारा ग्राम की पारंपरिक सीमा के आधार पर नियमानुसार अनुमोदन उपरांत ही सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विवाद अथवा आपसी सौहार्द्र बिगड़ने की स्थिति नहीं है। वैधानिक तरीके से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जाने के कारण वन अंचलों में निवास करने वाली जनता में किसी प्रकार का असंतोष व्याप्त नहीं है।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

समय

12.39 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, ये अधिकार जब वर्ष 2006 में लोगों को दिया गया, तो सबसे पहले व्यक्तिगत मान्यताएं मिलीं और उसके बाद फिर सुझाव आए, संशोधन हुए, नियम बने और ये सामुदायिक उपयोग के लिए उस गांव के जंगल में लोगों को जाकर उनके निस्तार का, जानवर चराने का, महुआ-टोरी इत्यादि बीनने का अधिकार लोगों को दिया गया, लेकिन गांव की सीमा निर्धारित करने की जब बात आई, उसमें वहां की जो परंपरा है और वहां के जो प्राचीनकाल से चले आ रहे तरीके हैं, जो उनके परंपरागत रास्ते हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए, उस गांव के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कम्पार्टमेंट बने हुए हैं, जो कि सन् 1874 में, सन् 1935 में, सन् 1927 में बनाए गए थे, जो टोपोग्राफ तैयार किए गए थे, उसे ध्यान में रखकर जो वहां पर एक सीमा चिन्ह अवगत कराया गया है, उससे हर गांव में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जहां पर आये दिन एक गांव के व्यक्ति द्वारा जानवर चराने ले जाने पर दूसरे गांव के लोग उन पर हमला कर देते हैं। यदि वह महुआ बिनने जाते हैं तो उसमें लड़ाई हो जाती है। मछली पकड़ने जाते हैं तो उसमें लड़ाई हो जाती है।

सभापति महोदय :- टेकाम साहब, आप इसी सिलसिले में प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे पूरे क्षेत्र में, हर गांव के लिये जो वनाधिकार मान्यता समिति बननी चाहिए थी क्या वह आज की तारीख में क्रियाशील है ? यदि माननीय मंत्री महोदय जी इस समय उनकी संख्या भी उपलब्ध करा देंगे तो कृपा होगी।

सभापति महोदय :- आप पूरे प्रदेश का पूछ रहे हैं या अपने क्षेत्र का पूछ रहे हैं ? आप कहां की संख्या पूछ रहे हैं ?

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि जैसे केशकाल विधान सभा क्षेत्र है, तो केशकाल विधान सभा क्षेत्र में कितने वनाधिकार मान्यता के लिये ग्राम स्तरीय सिमति बनायी गयी है और क्या आज की तारीख में सभी समितियां क्रियाशील हैं ?

श्री राम विचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, जो वनाधिकार समितियां हैं, वह सभी गांवों में हैं और सभी जगह बनी हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि वह आपके केशकाल में भी बनी होंगी। रही बात पूरे प्रदेश की जानकारी की, तो पूरे प्रदेश की जानकारी अभी मेरे पास आयी है।

सभापति महोदय :- वह प्रदेश का नहीं पूछ रहे हैं। वह एक क्षेत्र विशेष का पूछ रहे है।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, सभी जगहों पर समितियां बनी हुई हैं। मैं संख्या दे दूंगा।

सभापति महोदय :- आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया है कि सीमा को लेकर एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह कैसे संभव हो सकता है ? जबकि मेरे साथ अनेक विधायक ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, जहां वे जब भी जनसंपर्क में जाते हैं तो लगातार यह बातें आती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोनगुड़ और बारदा, जो कभी नक्सलाइटों का गढ़ हुआ करता था। आज वहां से नक्सलाइट चले गये तो गांव के लोग आपस में सीमा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गोविंदपुर और कोसमी में यदि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में लकड़ी काटने चला जाता है, तेंदूपत्ता संग्रहण करने चला जाता है तो पूरे गांव के लोग दौड़ाकर उसको वहां से बाहर कर देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हातमा और मानिकपुर, दो ऐसे गांव हैं, जहां पर लोग एक-दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, वहां इतनी ज्यादा विवाद की स्थिति बन गई है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिये ना।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी फिर से विचार करें।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न के रूप में पूछ लीजिये कि आप क्या चाहते हैं।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि गांव के लोगों को परंपरागत तरीके से जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों तक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेव्हलप करके, जैसा पुराने समय से चलता आ रहा है, उनको लिखित में वैसी व्यवस्था दे देनी चाहिए, जैसा वह चाहते हैं।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य वहां पर स्वयं एक प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर के रूप में रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो बहुत सारे प्रकरण हैं, वह उनके समक्ष भी आते रहे होंगे। यहां पर तत्कालीन सरकार के मुखिया बैठे हुए हैं और उस समय बहुत सारे लोगों को इस तरह के वनाधिकार पत्र के साथ-साथ सामूहिक पट्टे भी दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपने उत्तर में जो उल्लेख किया कि वहां की जो प्रक्रिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय मंत्री जी, आपने मेरे नाम का उल्लेख किया और हमने सामुदायिक पट्टा दिया। आपने उसके पहले प्रश्नकर्ता का भी उल्लेख किया। वे वहीं पर कलेक्टर थे और उन्होंने

पट्टा बांटा है और उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी थी और आज विवाद हो गया तो वही प्रश्न भी कर रहे हैं। इसमें विवाद की जड़ तो वही हैं और उत्तर आपसे चाह रहे हैं।

श्री राम विचार नेताम :- सभापति महोदय, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का आदेश फरमान जाता था कि कल मुझे इतने लोगों का पट्टा बांटना है। अधिकारी वहीं बैठे-बैठे ग्राम सभा की बैठक कागजों में, खण्ड स्तरीय समिति की बैठक पेपरों में और जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन भी पेपरों में होता था। यह विवाद तो अब समझ में आ रहा है। गांव वालों को मालूम नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। यह केवल पेपरों में नहीं हुआ। पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग हुई। इसकी संभाग स्तर पर ट्रेनिंग हुई। सभी कलेक्टरों, जो वन विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उन सब की ट्रेनिंग हुई कि यह किस प्रकार से करना है ? मुझे इस बात की खुशी है कि यदि सबसे पहले सामुदायिक पट्टा बांटा गया तो यह कोण्डागांव जिला में बांटा गया। तब वह मेरे बगल में बैठकर खुद पट्टा बांटते थे, टेकाम जी, मुझे देते थे और मैं पट्टा बांटता था।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जवाब दे दीजिए।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य और काफी अनुभवी हैं। इस बारे में उनकी काफी संवेदना भी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का विवाद आम हैं, जहां-जहां पट्टे का वितरण होता है, सामुदायिक पट्टा का वितरण होता है, उसमें सीमा को लेकर विवाद होता ही है। अब इसका हल तो एक ही है कि आपसी सहमति से हो। वहां पर अगल-बगल के जो भी कम्पार्टमेंट के गांव आते हैं, आसपास के जो बगल के गांव हैं, उनके साथ सहमति बनाकर, इसमें प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ कि आपसी तालमेल के आधार पर जो भी विवाद है, उस विवाद का निराकरण हो जाएगा।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह सरगुजा से भी संबंधित है। माननीय नीलकंठ टेकाम जी ने बस्तर और सरगुजा के विषय में बात रखी है। अभी चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं, पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, इसमें उनके कार्यकाल के समय गड़बड़ी हुई है।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने पट्टा बांटा है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने पट्टा बांटा है।

सभापति महोदय :- आप मेरी बात सुनिये। आप अपनी सीधी बात करिये। आप किसी को कोड मत करिये।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इस तरह के वन अधिकार पट्टों में जो वर्ष 2005 से लागू है। हमारा सरगुजा, बस्तर जिला पांचवी अनुसूची क्षेत्र में है। वहां वनों और

पट्टों का बहुत बड़ा है। वहां पर आदिवासी बहुत वर्षों से उसमें काबिज हैं और वर्ष 2005 के पहले काबिज थे, उनको पट्टे देने की बात है। उसमें जो गड़बड़ियां हुई हैं तो यदि उसके आधार पर इस तरह से उन पट्टों को वन अधिकार समिति, ग्राम सभा के बगैर दिया गया है और फर्जी पट्टे बना दिये गये हैं तो उसको निरस्त करने की कार्यवाही होगी ? उसकी क्या प्रक्रिया होगी ? उसमें एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि इस वन अधिकार पट्टे के संबंध में एक विषय चर्चा में आया। चूंकि शहरी क्षेत्रों में यह वन अधिकार पट्टा देने का मामला लागू नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- आप यह गलत बोल रहे हैं।

श्री प्रबोध मिंज :- क्या यह शहरी क्षेत्रों में लागू है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र है। जो वर्ष 2005 का अधिनियम है..।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय,उसके पहले।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, यह वर्ष 2006 का अधिनियम है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह वर्ष 2006 का अधिनियम है। उसमें यह स्पष्ट है कि वहां वर्ष 2005 से जो काबिज हैं,

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, वह वहां वर्ष 2005 के पूर्व काबिज हैं और वर्ष 2006 से यह अधिनियम लागू है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2006 से यह अधिनियम लागू हुआ। चाहे शहर में हो या गांव में हो, चाहे वह मकान बनाकर रह रहे हों या खेती कर रहा हो। उनको यह अधिकार है।

सभापति महोदय :- आपकी बात का जवाब दे देंगे।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मैं उसी विषय में आ रहा था। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र है, वह वर्ष 2005 में बना। वहां पर वर्ष 2005 में नया परिसीमन हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, वह शहरी क्षेत्र में शामिल हो गये। जगदलपुर का क्षेत्र है, उसमें शामिल हो गये। कई नगर पंचायत बन गये। कई नगर निगम बन गये, लेकिन आज भी उन शहरों में वन अधिकार और वन क्षेत्र हैं तो अभी तक क्षेत्रों के लोगों का पट्टा नहीं बनाया जा रहा है। जो आदिवासी लोग है..।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, पहली बात यह है कि हमारे समय में नगरीय क्षेत्रों में पट्टे बंटा था।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय विक्रम जी सुनिये। माननीय सभापति महोदय, यदि वर्ष 2005 के पूर्व जो शहरों में भी लोग रह रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। यहां पर एक माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने आपकी बात सुन ली। आप मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, जो इनका कहना है, उसके बारे में बताईये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, देखिये। माननीय सदस्य महोदय जी ने जो पहला प्रश्न पूछा है कि उन क्षेत्रों में, आपके विधान सभा क्षेत्र में गलत तरीके से वन अधिकार पत्र का वितरण हुआ है। दूसरा आपने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के बारे में पूछा है। चूंकि आज का यह प्रश्न दूसरा है। यह सामुदायिक वन अधिकार पत्र का है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक इस तरह की शिकायतें हैं, आप हमें शिकायत दे सकते हैं और उसमें प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप माननीय मंत्री जी को शिकायत दे दीजिए। वह दिखवा लेंगे।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, इसी से संबंधित का प्रश्न है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्रों के लिए..।

सभापति महोदय :- वह बात सबके लिये लागू है न। जो बात उनके लिए बोले हैं, आपके लिए भी लागू है। आपको जो शिकायत है, मंत्री जी को दीजिये। बस हो गया।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति जी, शहरी क्षेत्रों में वन अधिकार पट्टे देने का विषय है, उसके बारे में मंत्री जी बोल दें।

सभापति महोदय :- वह आप मिलकर बात कर लेना।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का सदन में जवाब आ जाता तो उचित था। जो नियम मे है, इनको पट्टा दिये जायेंगे।

सभापति महोदय :- देखिये, इस ध्यानाकर्षण में शहर के पट्टे का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए कृपा करके इस बात को इसमें जबरदस्ती मत डालिये।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण में जो अंतिम प्रश्न है, वह माचकोट क्षेत्र को लेकर के है। जहां पर बड़े ही भोले-भाले आदिवासी और अन्य वर्ग के लोग रहते हैं। केवल कागजी कार्रवाई की वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। उसको एक विशेष टीम भेजकर के या फिर जिला प्रशासन से कोई टीम जाकर वहां पर इसका इसका निराकरण करे जिसमें फॉरेस्ट विभाग के, राजस्व विभाग के लोग रहें।

सभापति महोदय :- आपका यही प्रश्न है न। माननीय मंत्री जी बताईये।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह की जहां भी विवाद की स्थिति होगी, वहां आपसी सूझबूझ, तालमेल के आधार पर आसपास के जो भी गांव

प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ बैठकर, समिति के साथ-साथ और भी जो मैदानी अमला है, उनकी उपस्थिति में इस तरह के विवाद का निराकरण करने का विभाग ने भी आदेश दिया है और मैं भी इसमें व्यक्तिगत रूचि लेते हुए इस समस्या के निराकरण के लिये निर्देश जारी कराऊंगा।

सभापति महोदय :- ठीक है। नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं।

समय
12.51 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

सभापति महाहेदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री संदीप साहू
2. श्रीमती अनिला भेंडिया,
3. श्री विनायक गोयल
4. श्री कुंवर सिंह निषाद
5. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

समय
12.52 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुती एवं पारण

सभापति (श्री विक्रम उसेण्डी) :- सभापति महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-10)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-14)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक-11)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-33)	श्री धर्मजीत सिंह	30 मिनट

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय
12.53 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्रीमती कविता प्राण लहरे
2. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा
3. श्री लालजीत सिंह राठिया
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. सुश्री लता उसेण्डी
6. श्री संदीप साहू

समय
12.54 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025)

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

सभापति महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1. छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) — 30 मिनट
2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) — 15 मिनट

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी.

(3) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- अब इस पर श्री भूपेश बघेल जी चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, अब बजट सत्र समापन की ओर है । आज विनियोग विधेयक माननीय वित्तमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है लेकिन हम लोग पहले भी देखते थे कि विनियोग विधेयक पर पूरा सदन खचाखच भरा रहता था लेकिन ट्रेजरी बेंच मुख्यमंत्री सहित, उपमुख्यमंत्री और सारे सीनियर मिनिस्टर नदारद हैं । विनियोग पर चर्चा है और अभी दो अधिकारी आये हैं, बचत पहली लाईन जो है चीफ सेक्रेटरी से लेकर फाईनेंस सेक्रेटरी सब गायब हैं । (शेम-शेम की

आवाज) तो हम लोग सामने वाली कुर्सी को ही सुना देते हैं, हमको तो बोलना है। आपने आमंत्रित कर दिया है और हमको आसंदी का सम्मान भी करना है । कितनी गंभीरता से सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं यह इसी बात का परिचायक है । इनको अपने बजट पर या मंत्री ओ.पी. चौधरी पर विश्वास नहीं है क्योंकि उसका कारण भी है कि यह अनायास नहीं होता । आपने बजट प्रस्तुत किया, सभी विभागों में चर्चाएं हुईं, ओ.पी.चौधरी जी ने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया, उनकी सारी भावनाएं इसमें हैं । मैंने थोड़ी सी बात कह दी थी कि हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी में लिखे हैं तो थोड़ी सी कुछ भावना आहत हुई लेकिन आप विधानसभा की कार्यसंचालन प्रक्रिया को देख लें या चूंकि वह कलेक्टर रहे हैं तो उनको पता है कि आप कोई भी नोटशीट तैयार करते हैं, आप कोई भी योजना बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं तो उसकी भाषा और उसकी लिखावट सुस्पष्ट होनी चाहिए, उसका अर्थ है, वह भी सुस्पष्ट होना चाहिए, लेकिन हमने इस बजट की कॉपी को देखा।

समय :

1.00 बजे

सभापति महोदय, इसमें इस प्रकार से लिख दिया गया है जो हम लोग चालू भाषा में बात करते हैं, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अब उसकी भावना आहत हुई है तो हो, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है, उसका तो पालन करने के लिए सदन में कहेंगे, क्योंकि यह सदन नियम, प्रक्रिया, संचालन और परंपराओं से चलती है। मैंने इसका उल्लेख किया था। यह जो बजट है, उसमें तो विस्तार से बता दिया गया कि हमने 18 प्रतिशत स्थापना व्यय के अतिरिक्त वृद्धि की है। खूब मेज थपथपाई गई, लेकिन स्थिति क्या है? मैं कुछ आंकड़े पढ़कर सुना देता हूं। बजट प्रावधान में जो व्यय है, आपकी स्थिति क्या है? ये आप ही के विभाग खाद्य विभाग से शुरू करता हूं, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय योजना हेतु बजट में आपने 400 करोड़ रूपये रखा। दिसंबर तक क्या आपका व्यय जीरो है? गुड़ वितरण योजना हेतु बजट में 81 करोड़ रूपये रखा, पिछले साल दिसंबर तक वयय जीरो है। रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक के लिए 139 करोड़ है, दिसंबर तक व्यय जीरो है। आपने शक्कर वितरण में 150 करोड़ रूपये रखा। व्यय जरूर 31.72 करोड़ रूपये हुआ। राइस फोर्टिफिकेशन हेतु 100 करोड़, दिसंबर तक व्यय जीरो है। राइस फोर्टिफिकेशन पहले राज्य का था, ये केंद्र का 109 करोड़, व्यय जीरो है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण में जरूर आपने 7 करोड़ रूपये की बजाय 16 करोड़ रूपये खर्चा किया? माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से आप देखें तो स्वच्छ भारत मिशन नगरीय प्रशासन में आपकी स्थिति क्या है? स्वच्छ भारत मिशन हेतु 7 करोड़ 26 लाख रूपये रखा। जनवरी तक व्यय जीरो है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 146 करोड़, जनवरी में व्यय जीरो है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट हेतु 206 करोड़ रूपये, जनवरी तक व्यय जीरो है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट नॉलेज मैनेजमेंट हेतु 10 करोड़ 81

लाख रूपये, व्यय जीरो। नगरीय निकाय में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग, जिसका आदरणीय ओ.पी. चौधरी ने अपने भाषण में बहुत जोर दिया, लेकिन उसमें 148 करोड़ रूपये का बजट रखा, जनवरी तक व्यय जीरो है। माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान में भी आपने बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दिया। हम पूरा 1 लाख जितना है, सबको हम कंप्लीट कर देंगे। आपने पिछले साल 50 करोड़ रूपये का बजट रखा, लेकिन जो प्रतिपूर्ति अनुदान देना है, वह जोरो है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में साढ़े 3 करोड़ रूपये रखा, उन्होंने 66 लाख रूपये खर्च किया। फूड पार्क स्थापना में 50 करोड़ रूपये का बजट रखा, आपने 23 करोड़ रूपये खर्च किया। माननीय सभापति महोदय, श्रमिकों का मामला है। श्रमिक बाहुल्य प्रदेश है। अजय जी, बिल्कुल तैयार बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अब आपने बोल दिया तो खड़े ही हो जाता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उनके भाषण को नियमत: interrupt नहीं करना चाहिए, गरिमा के विपरीत होगा। उन्होंने सदन के नियम, प्रक्रिया, परंपराओं से बात शुरू की। विनियोग पर उपस्थिति, अनुपस्थिति में बात की। आप नियम प्रक्रिया देख लीजिए। विनियोग में उन बातों का उल्लेख नहीं होता, जिनकी चर्चा पूर्व में सदन में की जा चुकी है। शुरुआत में ही उन्होंने जिन बिन्दुओं को उठाया, अनुदान मांग में उन बिन्दुओं की चर्चा हो चुकी है। मैं इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ले रहा हूं । मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सरकार की आलोचना के लिए विषय नहीं हैं तो औपचारिकताएं क्यों पूरी कर रहे हैं ? ये बातें तो बोली जा चुकी हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- वैसे, सरकार की आलोचना करने के लिए अजय चन्द्राकर जी पर्याप्त हैं । (हंसी)

सभापति महोदय :- आप बोलिए ।

श्री भूपेश बघेल :- बाल श्रमिक सर्वेक्षण, जीरो । श्रम कल्याण निधि स्थापना, 33 परसेंट । बंधक मजदूरों को लाने में 1 करोड़ 35 लाख आपने रखा लेकिन उसमें से मात्र 48 हजार खर्च किया । सभापति जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग देखेंगे । मैं तो बजट पर ही बात कर रहा हूं । कुल मिलाकर पिछला जो बजट है उसमें आपने 50 परसेंट से भी कम खर्च किया है । आप देखेंगे, दिसम्बर तक आपने केवल 44-45 परसेंट खर्च किया, बचत आपने कोई खर्च नहीं किया । मैंने तो केवल उदाहरण के लिए कहा कि आपको बजट क्यों चाहिए ? आपने पिछले साल जो बजट प्रस्तुत किया उसका 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाए, इस साल बजट का केवल आकार ही बढ़ा है । आकर बढ़ गया, पेपर में छप गया, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है और इस कारण से इनके मंत्रिमंडल के साथियों को भी विश्वास नहीं है, अधिकारियों को भी विश्वास नहीं है क्योंकि खर्च तो होना ही नहीं है । सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, जो पुरानी योजनाएं थीं, आप देखेंगे, सबसे ज्यादा महिला एवं बाल विकास विभाग, हमारे बच्चे ही भविष्य के नागरिक बनेंगे लेकिन आपने पुरानी जितनी योजनाएं हैं, उनमें से बहुत सारी योजनाओं को

बंद कर दिया । मैं केवल उल्लेख करना चहूंगा - महिला कल्याण क्षेत्र में कार्यरत संस्था महिला मंडलों, विपत्तिग्रस्त महिलाओं तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान, आपने बंद कर दिया । समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, बंद कर दिया । राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, बंद कर दिया । राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलती थी, बंद कर दिया । राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, बंद कर दिया । क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बंद कर दिया । परियोजना कार्यालय-सह-संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण, वह भी बंद कर दिया । जिला प्रशिक्षण-सह-संस्थान केंद्र हेतु भवन निर्माण, वह भी बंद कर दिया । दहेज प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत प्रकोष्ठ का गठन, बंद कर दिया। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, क्योंकि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हमारे हैं और यदि बच्चे कुपोषित रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा ? उस योजना को आपने बंद कर दिया । यूनिफाइड डिजिटल एप्लीकेशन योजना उदय, उसको आपने बंद कर दिया । न्युट्रिशियन सर्विलेंस योजना बंद कर दिया, कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय हमने बढ़ाया, आपने नहीं दिया । अनैतिक व्यापार के रोकथाम के कार्यक्रम को आपने बंद कर दिया । आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के आवास गृह कार्यक्रम हमने चलाया था, उसको आपने बंद कर दिया । किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण को बंद कर दिया । महिला पुलिस स्व-सेवक योजना बंद कर दिया । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के जो हितलाभ हैं उसको आपने बंद कर दिया । किशोर न्याय निधि बंद कर दिया । नारी निकेतन भवन निर्माण बंद कर दिया । घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण, वह भी आपने बंद कर दिया । कार्य स्थल में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के रोकथाम हेतु कार्यक्रम, उसको भी बंद कर दिया । रेडी-टू-ईट की प्रयोगशाला की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण भी रूका हुआ है । एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी बंद कर दिया । निराश्रित महिला गृह सिलाई केन्द्र महिलाओं के लिए संस्थान, वह भी आपने बंद कर दिया । महिला जागृति शिविर भी बंद कर दिया । यह स्थिति है सभापति महोदय और आप देखिए समाज कल्याण विभाग में, नगरीय क्षेत्र में उचित मूल्य सह दुकान सह गोदाम निर्माण, आपने वह भी बंद कर दिया। एकीकृत प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने वह भी बंद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में दुकान सह गोदाम निर्माण योजना, आपने वह भी बंद कर दिया। सभापति महोदय, हमने सी मार्ट शुरू की थी, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी हो, चाहे रीपा में हो, हमारे वनांचल में जो निर्माण हो रहे हैं, आदिवासी भाई बहन जो भी निर्माण कर रहे हैं, उसका विक्रय शहरों में होना चाहिए, सी मार्ट बदहाली में है, उस बिल्डिंग को किसी और योजना में देने की बात चल रही है आपने उसको भी बंद कर दिया। श्रम विभाग में बाल श्रमिक सर्वेक्षण है, आपने वह भी बंद कर दिया। असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल, आपने वह भी बंद कर दिया। ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिलाएं एवं हमाल कल्याण मंडल, आपने वह भी बंद कर दिया। आपने डॉ. खूबचंद बघेल

योजना का नाम बदल दिया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, आपने उसको भी बंद कर दिया, सी.पी.एस. योजना भी बंद कर दिया। मुख्यमंत्री मेडिकल फेलोशिप योजना, आपने वह भी बंद कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उसको बंद कर दिया। गन्ना के बारे में चर्चा हुई, बालोद में जो सहकारी शक्कर कारखाना है, गन्ना परिवहन में जो अनुदान देते थे, आपने वह भी बंद कर दिया। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन करना है, आपने रोक रखा है। राज्य जिला सहकारी केन्द्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सहकारी बैंकों में विलय ये भी नहीं हो पा रहा है। आपने विपणन सहकारी समिति का सुदृढ़ीकरण रोक रखा है। कौशल विकास में, प्रधानमंत्री कौशल योजना इसकी क्या स्थिति है। जीवन निर्वाह प्रशिक्षण, उसकी क्या स्थिति है। औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण उसकी क्या स्थिति है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, बजट में रखे हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, पिछले साथ बजट में था, इस साल तो वह भी नहीं है। आपने वह भी रोक रखा है। मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना, आपने वह भी बंद रखा है, मुख्यमंत्री अति विशिष्ट उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देते थे, यहां के बच्चे बाहर पढ़ने जाए, उसको मदद मिलती, आपने वह भी बंद करके रखा है, आजीविका विकास हेतु नवीन कार्यक्रम, वह भी बंद है, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, वह भी बंद है, शिक्षित बेरोजगार गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण, वह भी बंद है। सरगुजा से मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, आप भी आते हैं, वहां जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, कम से कम उसको मिला लीजिए, वह भी नहीं हो पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिसमें कहा जा सकता है। खासकर शिक्षा में, हम लोगों ने शिक्षा के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू किए थे, शालाओं के सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण, नवीनीकरण, नया निर्माण कार्य, वह सब बंद है, चॉक योजना, वह भी बंद है, प्राथमिक शालाओं के लिए 2 हजार करोड़ रूपए दिए थे, वह सब रूका हुआ है। ई-लर्निंग योजना, वह भी बंद है। विश्व बैंक योजना, मैंने जो चॉक के बारे में कहा, वह भी बंद है। प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा, वह भी बंद है। चूंकि कोटा में यहां से बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, हमने वहां छात्रावास बनाने का फैसला किया था, उसको आपने बंद करके रखा है, उसको देते, वहां छात्रावास बनता, बच्चे पढ़ाई करते। शैक्षणिक विकास सहायता भी बंद है। जो सारे कार्य हैं, जो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केवल उससे ही नहीं बल्कि पशुधन से भी जुड़ा हुआ मामला है। पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, वह भी बंद। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ में आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप केवल गुजरात मॉडल ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मॉडल तो लाईए, छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल कैसे हो सकता है। एक स्वागत विहार है, आज तक अटका पड़ा है। गुजरात मॉडल, पूरा देश देख रहा है, गुजरात मॉडल क्या है, 11 साल से गुजरात मॉडल खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको आपने बंद कर दिया है। कृषकों में मैं पहले भी बोल चुका हूं, राजीव गांधी किसान

न्याय योजना जिसमें किसान बरसात में दूसरी फसल लेते थे, उसको भी आपने बंद करके रखा है, आप उनको कोई सहायता नहीं दे रहे हैं। उसके कारण सब लोग धान में ही डायवर्ट हो रहे हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति भी बंद कर दिया। फाइटोसेनेटरिक प्रयोगशाला संचालन, वह भी बंद है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वह भी बंद है। आपने सारी चीजें बंद करके रखी है, जिन योजनाओं से किसानों को लाभ मिलता। आप तेंदूपत्ता का बड़ा गुणगान कर रहे हैं, लेकिन तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसे हमने शहीद महेन्द्र कर्मा जी के नाम से शुरू किया था, उसको आपने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को भी आपने बंद कर दिया। मुख्यमंत्री बांस विकास योजना को भी आपने बंद कर दिया। जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। चाहे गरीब लोग हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, उनके जीवन में यदि हम थोड़ी सी आर्थिक सहायता कर दें तो वह आगे बढ़ सकते हैं। उन सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। सभापति महोदय, आखिर हम इनको बजट में पैसे क्यों दें? किसलिए दें? क्योंकि आपसे कोई चीज संभल नहीं रही है। यदि हम पुलिस की बात करे तो आप देखेंगे कि सीधे गृहमंत्री जी स्वयं घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वह रात में पहुंच जाते हैं। वह भी अच्छी बात है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है ? चाहे आप लोहारीडीह की स्थिति की बात करे तो पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है ? कचरू साहू के लिए कह दिया गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन जब जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबार उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि वह आत्महत्या नहीं, हत्या है जबकि आप एस.पी. का बयान देख लीजिए। आप उसकी वीडियो देख लीजिए। आप जबरदस्ती के मीडिया हाइट क्रियेट कर रहे हैं, सेंसेशन बढ़ा रहे हैं जबकि स्थिति यह है कि उसने आत्महत्या की है। अब स्थिति यह है कि जब यह प्रमाणित हो गया कि वह हत्या है तो उस एस.पी. के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ? यदि आप उसको इस प्रकार से बढ़ावा देंगे तो क्या होगा ? लोहारीडीह में 3-3 घटनाएं हो गईं। प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई, उसका दोषी कौन है ? उसको आज तक यह सरकार नहीं बता रही है तो आखिर हम गृह विभाग को पैसे क्यों दें ?

माननीय सभापति महोदय, बलौदा-बाजार जिले की घटना से पूरा देश हतप्रभ है। देश के इतिहास में पहली बार कोई कलेक्टोरेट, एस.पी. और आबकारी कार्यालय जलें। लेकिन क्या हुआ ? जो निर्दोष थे, उनको आपने जेल में ठुस दिया। मैं आपको एक ही उदाहरण बताना चाहूंगा कि वहां 2 मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने 10 दिनों तक वहां मलबा हटाया और ग्यारहवें दिन बोला गया कि तुम उसको जलाने में शामिल थे क्योंकि तुम्हारा लोकेशन मिल रहा है तो जो मजदूरी करेगा, उसका कलेक्टोरेट में ही लोकेशन मिलेगा। जो वहां मजदूर था, वह 6 महीने बाद जमानत में छूटा है। क्या ऐसे काम करने के लिए हम आपको पैसे दें ? फिर आपने कलेक्टर व एस.पी. को बिल्कुल कह दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है तो आखिर वह कलेक्टोरेट जला तो उसका दोषी कौन है ? आखिर उन लोगों के द्वारा जो आंदोलन हो

रहा है, उसे रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया ? आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। यदि आप कलेक्टोरेट को नहीं बचा सक रहे हैं तो सरकार क्या चलाएंगे ? हम आपके गृह विभाग में पैसे क्यों दें ? आज स्थिति क्या है ? कल ही मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ अनाचार होता है और उसको हॉस्टल में रखते हैं तो वह बच्ची आत्महत्या कर लेती है। जब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक बालिका सुरक्षित नहीं है, आपके शासकीय आवास में सुरक्षित नहीं है तो हम आपको पैसे क्यों दें ? हम आपको किसलिए पैसे दें ?

सभापति महोदय, आप उसी प्रकार की स्थिति दूसरे विभागों में भी देख लीजिए। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए कि किस प्रकार से घेराबंदी हो रही है। शहरी क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है। आप एक भी विकास का काम बता दीजिए। क्या आपने पिछले 1 साल में अपने बजट से कहीं पर एकाध ईंट रखी है ? विधायक तरस गये हैं कि पत्थर में हमारा भी नाम हो जाए, लेकिन उसका भी अता-पता नहीं है। सभापति महोदय, सवाल इस बात का है कि क्या आप यहां पर केवल आरोप लगाने के लिए, षडयंत्र करने के लिए बैठे हैं या जनता का हित करने के लिए बैठे हैं ? विपक्ष को बदनाम करो, खूब बोलो, जमकर बोलो, जोर-जोर से बोलो और उनको बदनाम करो। सभापति महोदय, इसी सदन में रामकुमार जी के प्रश्न में आपने क्या किया ? आपने कहा कि 8 दिसम्बर को केडिया डिस्टलरी का एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें नकली होलोग्राम था और उसमें कार्रवाई हुई। उसको पकड़ा गया और 8 दिसम्बर को जब आपने शपथ नहीं ली थी, उसका लायसेंस एक महीने के लिए निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उसको बहाल कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को शपथ लेते हैं और 8 दिसम्बर को उसका निरस्ती वापस होता है। यह अदृश्य शक्ति कौन है ? यह उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से हसदेव का जंगल काटा गया। मुख्यमंत्री शपथ नहीं लिए थे, अदृश्य शक्ति है, जो कटाई कर रही है उसको आदेश दे दिया गया। यह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस प्रदेश को संचालित कर रही है ? मुख्यमंत्री जी, आप शपथ भी नहीं लिए हैं और सारी कार्रवाई हो रही है। सभापति महोदय, खूब आरोप लगाया गया कि धान में 20/- रूपया कमीशन लिया जा रहा है। कितने की वसूली हो रही है ? 30/- रूपये की वसूली हो रही है। पूरे प्रदेश में हल्ला है कि प्रदेश में 30 रूपया प्रति क्विंटल ले रहे हैं। कोई कोयला लेव्ही ले रहा है। कोयला में 25/- रूपया लेने का आरोप लगाया गया। आपने किसी को पकड़ा ? पैसा देने वाला भी अपराधी है और लेने वाला भी अपराधी है। आपने देने वाले को कहां पकड़ा है ? ए.सी.बी. का नियम क्या है ? एक्ट में क्या है ? पैसा देने वाला और लेने वाला दोनों अपराधी है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने 25/- रूपये लेने का आरोप लगा दिया, वसूली कितने की हो रही है, पूरे बाजार में 50/- रूपये वसूली की चर्चा है। होलोग्राम नकली, लेकिन कितनी वसूली ? सीधा 30 प्रतिशत ऊपर वसूली हो रही है, यह स्थिति है। आप आरोप लगा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, शराब के प्रत्येक घटनाक्रम अच्छे या बुरे जो

भी घटे हों, उनके बिलकुल विशेषज्ञ वक्ता की तरह बोलते हैं। सुनने में मजा आता है। आपकी विशेषज्ञता हो गई है।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने आज कोयला में भी बोला है, धान में भी बोला है, वन कटाई के बारे में भी बोला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- परन्तु आप इसमें ज्यादा अधिकार से बोलते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- किसमें ?

श्री अजय चन्द्राकर :- दारू में।

श्री भूपेश बघेल :- वह आपको लगता है, आपको वही सुनाई देता है। अजय जी, क्या है कि पुरानी संगत, पुरानी आदत कहां छूटती है ? (हंसी) भले ही सिगरेट पीना छोड़ दे, लेकिन अभ्यास रहता है। उसका स्मेल आ ही जाता है। कहीं अचेतन मन में रहता है, वह उभर आता है।

श्री राम विचार नेताम :- इनकी क्या-क्या आदते हैं, मालूम है ? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- मेरा पड़ोसी है, भाई। हम लोगों का घर लगा हुआ है। हम लोग एक साथ सावन में कौही जाकर महादेव में जल अभिषेक करते हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- केवल महादेव में जल अभिषेक करते हैं या और भी कुछ करते हो ? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अब वह अजय जी ही बतायेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ोसी हैं और रायपुर के घर में भी पड़ोसी हैं। समझ रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, उनको बोलने दीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आज पूरे प्रदेश में सब लोग चिंतित हैं कि इस प्रदेश का क्या होगा ? इसके पहले भी, जब आप यहां बैठते थे, रामचन्द्र सिंहदेव जी यहां बैठते थे, बड़े-बड़े विद्वान यहां बैठेते थे और प्रदेश के विकास के बारे और जो दिशा पकड़ रही है, उसके बारे में लगातार चिंता व्यक्त करते थे। आज क्या हो रहा है ? 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आयेंगे। सीपत में जो पावर प्लाण्ट लगा हुआ है, उसके अतिरिक्त और पावर प्लाण्ट लगना है, उसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रदेश में 20 हजार मेगावाट का पावर प्लाण्ट लगने वाला है। जब 20 हजार मेगावाट का पावर प्लाण्ट लगेगा तो आपको कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, केवल एस.ई.सी.एल. के खदान के कोयले से आपूर्ति पूरी नहीं होगी। एस.ई.सी.एल. में जितना कोयले का उत्पादन हो रहा है उसके कारण यात्री ट्रेनें बंद है, गुड्स ट्रेन चल रहीं हैं, माल वाहक गाड़ियां चल रही हैं। जब आप 20 हजार मेगावाट का पावर प्लाण्ट और लगायेंगे तो एस.ई.सी.एल. खदान का कोयला पर्याप्त नहीं होगा। फिर और खदानें खोली जायेंगी तो जंगल उजाड़े जायेंगे। वहां से आदिवासियों को हटाया जायेगा। वहां गडढा होगा और उसके साथ-साथ पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सीपत में प्लाण्ट

लगने के बाद सरकार ने कहा कि हम आखिरी बार हसदेव बांगों से पानी देने की अनुमति दे रहे हैं। उस समय आप उपाध्यक्ष थे। उस समय यह फैसला हुआ था। उसके बाद जितने पावर प्लाण्ट बने, महानदी में जितने एनीकट बने, वह केवल पावर प्लाण्ट के लिए बने हैं। उस महानदी के पानी से एक चुल्लू पानी किसान नहीं ले सकता है। आपने यह स्थिति बनाकर रखी है। अब 20,000 मेगावाट पावर प्लांट और लगायेंगे। यहां रायपुर शहर में पानी की व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन आपके विधान सभा के बगल में जो पावर प्लांट है, उसका एक्सटेंशन करने के लिए आप अनुमति दे रहे हैं। उसमें और पानी लगेगा। 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए कितनी पानी की आवश्कता पड़ेगी, इसका आपने कोई हिसाब-किताब किया है? अभी गर्मी का मौसम शुरू नहीं हुआ है, उसके बावजूद समाचार-पत्रों में पानी की कमी और जल स्तर घटने की बात हो रही है। जब आप 20,000 मेगावाट पावर प्लांट लगायेंगे तो यहां की भूमिगत जल की क्या स्थिति होगी? यहां का तापमान क्या होगा? सीपत पावर प्लांट बनने के बाद बिलासपुर के temperature में 5°C की वृद्धि नहीं हुई है। क्या वृद्धि नहीं हुई है? वहां एयर कंडीशन हो रहा है, वहां बिल्कुल बयार चल रही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- 1°C बढ़ा है।

श्री भूपेश बघेल :- वहां temperature 1°C बढ़ा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- एक बार 49°C तापमान पहुंच गया था।

श्री भूपेश बघेल :- जब आप 4000 में 6000 मेगावाट और जोड़ देंगे तब कितना temperature बढ़ेगा? इसलिए आप पूरे प्रदेश का तापमान बढ़ा रहे हैं। आज यह स्थिति है कि आप चाहे जांजगीर-चांपा चल दीजिये, चाहे कोरबा चल दीजिये, आप कहीं भी जायेंगे तो सड़कों के किनारे जितने फ्लाई ऐश डंप करके जा रहे हैं, उसका सही मायने में डिस्पोजल नहीं हो रहा है, इसके कारण से सड़कों में धूल वगैरह बहुत जयादा हो गये हैं। अब तो गर्मी के दिन में सड़कों में बिना चश्चा के कोई मोटर-सायकल नहीं चला सकता है। यदि आप 20,000 मेगावाट पावर प्लांट से फिर बिजली का उत्पादन करेंगे तो यहां की पानी की क्या स्थिति होगी, यहां के खेतों की क्या स्थिति होगी? यहां की खेतों की जमीन बंजर होने वाली है। अभी 14 लोहा खदान नीलामी हुआ। 14 खदान का ई-ऑक्शन हो गया। एक तरफ ऊपर बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ के जंगल साफ होंगे, दूसरी तरफ आप 14 खदान का ई-ऑक्शन कर दिये तो फिर दंतेवाड़ा और पूरा नारायणपुर से लेकर कांकेर तक के सारे जंगल फिर से उजड़ेंगे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का नुकसान होगा। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है ताकि आदिवासियों का अहित किया जा सके, आदिवासियों को उजाड़ा जा सके और यह लोगों को कहेंगे कि हमने तो आदिवासी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। आदिवासी क्षेत्र में पूरा खदान खोल कर सबको निजी हाथ में दे दिया गया है। वहां किसी को कोई रोजगार नहीं मिलना है, जो खदान खुलेंगे उसमें कोई प्लांट नहीं लगेगा, उसमें जो सारे आयरन हैं, वह सब बाहर जाना है, इससे स्थिति यह होगी कि किसी को रोजगार नहीं

मिलेगा, जंगल उजड़ जायेंगे, आदिवासी बेघर हो जायेंगे, यह स्थिति आप बना रहे हैं। आपकी रोजगार देने की स्थिति है ही नहीं। यह स्थिति हम सबके लिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि हमारी प्राकृतिक संपदा को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहिए। आप सोना ऑक्शन का कर रहे हैं, आप लीथियम ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपने उससे संबंधित प्लांट लगाया गया है? जब आप इससे उत्खनन करेंगे, उसमें हैवी मेटल और दुनिया भर की जो चीजें निकलेंगी, उसका सीधा मानव शरीर पर क्या असर पड़ेगा? उस दिन मंत्री जी थे और हमारे भिलाई नगर के एक विधायक ने पर्यावरण के संबंध में प्रश्न उठाया था। आज वहां से जितने नाले निकल रहे हैं, वहां एक भी जलचर प्राणी नहीं है। एक तरफ आपने औद्योगीकरण बढ़ाया है, लेकिन आप उन उद्योगों को बढ़ाईये, जिससे लोगों को रोजगार मिलें, लेकिन उससे पर्यावरण न बिगड़े। इसीलिए हमने रीपा शुरूआत की थी कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलें, लेकिन आपने उसे बंद करके रखा है। यह जो बजट है, यह बिल्कुल निरस है। जब आपने पिछले साल खर्चा नहीं किया तो आप इस साल क्या खर्चा कर पायेंगे? मैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गया था, वहां पिछले कार्यकाल का पानी टंकी के लिए 43 करोड़ रूपये की स्वीकृति है। उसका टेण्डर हो गया, सब कुछ हो गया, उसका भूमिपूजन हो गया है, उस पर साल भर से काम ही नहीं चल रहा है। जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में काम नहीं चल रहा है तो बाकी जगहों में कहां से काम चलेगा? आज पेयजल की स्थिति यह है कि आप नलकूप खनन बंद कर दिये हैं। पूरे गर्मी में कहीं भी नलकूप खनन नहीं हो रहा है। अजय चन्द्राकर जी, धरमलाल कौशिक जी और हमारे पक्ष के लोग लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि टंकी बन गया है, जल स्त्रोत है ही नहीं। आखिर भूमि गत जल की भी कोई सीमा है? जब तक पुनर्भरण नहीं करेंगे तब तक पानी कहां से आएगा? वह टंकी बने ही रहेगी। जो हाल शौचालय का हुआ, वही हाल यह नलजल योजना का होने वाला है। आपने नरवा, गरवा का बहुत मजाक उड़ाया, वन मंत्री बैठे हैं, आप वह रिकार्ड निकलवाकर देख लें, आपने जितना नरवा कार्यक्रम लिया है, जब नरवा नहीं था तो वॉटर टेबल कितनी थी और आज कितना है ? आप उन जंगलों की देखिये, निकालकर देख लीजिए । जब तक जल पुनर्भरण का काम हाथ में नहीं लेंगे, यह सारे चाहे वह सिंचाई के लिये हो, चाहे निस्तार के लिये हो या पेयजल के लिये हो, पानी नहीं रहेगा । यह बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है । सभापति महोदय, आप लक्ष्य पूरा करने के लिये कर तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उपयोग के लायक पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी । सभापति महोदय, आप एक तरफ किसानों को टाईट कर रहे हैं, आप गरमी फसल में धान नहीं ले सकते हैं, धान नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? आप आर्डर निकाल रहे हैं कि 50 हजार आपको फाईन लगेगा, सरकार बोलती है कि हमने नहीं निकाला है, क्या कलेक्टर को सपना आया था जो अपने आप से निकाल देगा । चाहे बालोद का हो, चाहे राजनांदगांव का हो, चाहे महासमुंद का हो, अपने आप निकाल देंगे । इस प्रदेश में यह जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वह बेहद चिंताजनक है । सभापति महोदय, सरकार निर्णय ले, सारे सक्षम लोग हैं, लेकिन यह कहें कि दिल्ली से फोन आयेगा तो आपका

काम होगा, यह कहा जाता है । मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, हॉ दिल्ली से फोन आयेगा तो उसका काम करूँगा । मंत्री तो मंत्री, अधिकारी बोलना शुरू कर दिये । यहां दिल्ली की कृपा से पदस्थ हुये हैं तो बोलो कि मैं यहां के अंत्री-मंत्री, इधायक-विधायक की बात नहीं सुनता । आप एक नंबर, दो नंबर से बात करा दो, तुम्हारा काम हो जायेगा, आप ऐसे अधिकारी बिठा कर रखे हैं ? सभापति महोदय, मैंने अधिकारियों के बारे में पिछले सत्र में भाषण दिया था, सारे लोग पीड़ित थे । आप भाषण निकालकर देख लीजिएगा, उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन सत्ता पक्ष के सारे विधायकों ने बाहर लॉबी में कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है । आज फिर से वही शिकंजा कस रहे हैं, विवेक से काम लीजिए, केवल अधिकारियों के भरोसे मत चलिये । प्रदेश की जनता ने आपको चुना है । वह तो पढ़ाई करके पहुंचे हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है, लेकिन आपके एक निर्णय से प्रदेश के जनता के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता, लेकिन वह परिवर्तन लाने की कोशिश आप नहीं कर रहे हैं । आपकी जितनी योजनायें हैं, आप पिछली सरकार की योजनाओं से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं ? एक भी योजना बता दो, जो आपकी अपनी योजना हो ? आप महतारी वंदन की बात कह रहे हैं, उसके अलावा कोई योजना बता दो जिससे बाहर निकलकर आये हैं ? सभापति महोदय, पिछले समय मंत्री जी ने कहा कि कर्नाटक में नहीं मिल पा रहा है, आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में बजट कम हो गया है, मध्यप्रदेश में बजट कम कर दिये हैं, आप धान की बात कर रहे हैं ? आज डबल इंजिन की सरकार में आपकी स्थिति क्या है, आपको 40 लाख मीट्रिक टन बाजार में बाजार में नीलामी करना पड़ रहा है, इसका भार किस पर पड़ेगा ? यदि डबल इंजिन की सरकार है तो उसका भार छत्तीसगढ़ की जनता पर नहीं पड़ना चाहिये, यह जो आप नीलामी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि आपकी योग्यता...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने धान नीलामी की थी कि नहीं की थी ? आपको आज किस बात की आपत्ति है ?

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैंने किया था । आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है । आप कृपा करके बैठ जाईये । सभापति महोदय, तत्कालीन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी, तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी को लेकर केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से मीटिंग की थी । मेरे साथ अधिकारी गये थे । मैंने कहा कि आप सेंट्रल पुल में हमारा चावल लीजिए, हमारा कोटा क्यों कम कर रहे हैं ? उन्होंने कहा कि आप 25 सौ रूपये में धान खरीद रहे हैं, यह बोनस है और यदि बोनस दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे । (शेम-शेम की आवाज) सभापति महोदय, मैंने कहा कि आप चावल लें या न लें, मैंने किसानों से वादा किया है कि 25 सौ रूपये दूँगा, सरकार ने हमारा कोटा घटा दिया, उसके बाद हमने झुकना पसंद नहीं किये, किसानों के साथ खड़े रहे और 25 सौ रूपये में धान खरीदे, जो बचा उसे बाहर में नीलाम कर दिये । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, आपकी आज डबल इंजिन है, आप 3100 रूपये दे रहे हैं, आपको तो मना नहीं कर रहे हैं, अब वह नियम बदल गया है, जो वर्ष 2014 से लागू

था, अब वह नियम क्यों बदल गया है ? भारत सरकार आपको 3100 रूपये देने की अनुमति क्यों दे रही है ? जब 3100 रूपये देने की अनुमति दी है तो चावल भी पूरा खरीदना चाहिये । यदि चावल नहीं खरीद रहे हैं तो डबल इंजिन सरकार का कोई औचित्य नहीं है । आपके डबल इंजिन सरकार का नुकसान राज्य की जनता क्यों उठाये, आपके लिये भारत सरकार ने नियम तो बदल दिया है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा भी खरीदेंगे तो आपका चावल लेंगे ? उसमें शिथिलता बरत दी है और हमारे समय कड़ाई किया था । आप तो उस समय मंत्री थे, जब अमित शाह के पास गये थे कि हमको अनुमति दो तो दो साल के लिये आपको रिलीफ दिया था । दिया था न ? तब आपने एक साल बोनस भी बांटा था, चुनाव के साल में बोनस बॉटे थे । दूसरे साल भी बोनस दिये, लेकिन उसके बाद रोक लगा दी गई । तब हमने यह किया । ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ।

श्री लखेश्वर बघेल :- आजकल चौथा इंजन की सरकार बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न, वे बोल रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं डबल इंजन की बात करूंगा, अभी तीसरा और चौथा इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है । सभापति महोदय, इसी पवित्र सदन में महानदी के जल विवाद के बारे में कितनी चर्चाएं हुईं । महेश तिवारी यहां थे, तब से उन्होंने शुरूआत की थी । वे विपक्ष के उप नेता थे । आप सभापति थे, उस समय की बात है । तब से महानदी जल विवाद पर चर्चा शुरू हुई थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसी पवित्र सदन में महानदी जल विवाद में जब चर्चा हुई, उस विवाद में आपने वकील नहीं खड़ा किया था ।

श्री भूपेश बघेल :- गलत बात ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गलत बात नहीं है, यह हाऊस के रिकार्ड में है । यह हाऊस रिकार्ड में है, आपके मिश्री भैया की स्वीकारोक्ति है ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए न । बघेल साहब, आप बोलिए।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, अब तो आप सरकार में हैं । कोर्ट में किस समय वकील खड़ा नहीं हुआ, यह आप सामान्य प्रशासन विभाग से निकालकर देख लीजिए, जल संसाधन विभाग से निकालकर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ । आपने जो वकील तय किया था, उसी वकील को हमने कॉन्टीन्यू किया क्योंकि उसको जानकारी थी । वह वकील भी उड़ीसा का था, लेकिन अब मैं यह कह रहा हूं कि चाहे महानदी जोड़ने की बात, चाहे अरपा-भैंसाझार में नदी जोड़ने की बात की सारी योजनाएं बनी थीं, लेकिन उड़ीसा सरकार की आपत्ति के बाद वह सारी परियोजनाएं धरी की धरी रह गईं । हमने उसके खिलाफ भी आपत्ति की थी । यदि आप हमारा स्ट्रक्चर नहीं बनाने देते तो आप भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन आज तो वहां भी भाजपा की सरकार है, यहां भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है तो अब क्यों तकलीफ हो रही है ? अब तो निपटारा हो

जाना चाहिए । महानदी जल विवाद समाप्त होना चाहिए, अब वह पैरी की बात हो, चाहे अरपा-भैंसाझार की बात हो, चाहे इंद्रावती की बात हो, वह सारी समस्या निपट जाना चाहिए, तब तो डबल इंजन का फायदा है । आप नहीं कर रहे हैं तो समझा जाएगा कि यह आपकी नाकामी है, नाकाबिलियत है । आप इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहे हैं । वैसे भी प्रदेश में सिंचाई दर कितनी है ? प्रदेश में सबसे ज्यादा है । यदि आप देश का टोपोग्राफी देखेंगे तो यदि हिमालय की तराई में जितने नदी-नाले हैं, उसके बाद सर्वाधिक नदी-नाले यदि पठारी हिस्से में देखा जाएगा तो केवल छत्तीसगढ़ में 30 हजार नाले हैं, इतने नाले किसी प्रदेश में नहीं है । बड़े-बड़े प्रदेशों में ये आंकड़े नहीं मिलेंगे । हमारे पास इतना पानी है, लेकिन हम रख नहीं पा रहे हैं। यदि जल विवाद का निपटारा करेंगे तो महासमुन्द जिला हो, रायपुर जिला हो, चाहे बलौदाबाजार जिला हो, दुर्ग जिला हो, बेमेतरा जिला हो, सब जगह पानी हो सकता है, बिलासपुर में पानी की व्यवस्था हो सकती है । आप पावर प्लांट के लिए पानी ला रहे हैं, लेकिन ये पानी किसानों के लिए भी ले आईए । पावर प्लांट भी चलें, लेकिन यह जल विवाद समाप्त हो जाएगा, यहां स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, इन्द्रावती में नीचे में आंध्रप्रदेश ने स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन हमारे यहां नहीं बन पा रहा है क्योंकि विवाद है। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है । अभी आपको सरकार में आए सवा साल हुए हैं, अभी टेक-अप करेंगे तो हो सकता है कि साल डेढ़ साल में रिजल्ट मिले, यह विवाद निपट जाएगा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ा योगदान होगा । ऐसे कुछ काम करिए, लेकिन उस दिशा में आपका कोई प्रयास नहीं हो रहा है । यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है ।

सभापति महोदय, मैं धान के लिए फिर से कहना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री जी के पास चलिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे और कहेंगे कि आप 40 लाख मेट्रिक टन धान मार्केट में बेचेंगे, उससे छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य के लिए नुकसानदायक है, हमको घाटा होगा । आप पूरा चॉवल लीजिए, जब दूसरे प्रदेशों का चांवल ले सकते हैं तो छत्तीसगढ़ का चॉवल क्यों नहीं ले सकते ? जबकि इंजन आपका है । आप समय लीजिए, पूरा सदन आपके साथ चलेगा । क्योकि यह छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है । क्योंकि आज इस साल नहीं खरीदेंगे और जितना भी घाटा होगा, आप 40 लाख मेट्रिक टन में प्रति क्विंटल 2000 रूपए नुकसान नहीं होगा तो 1000 रूपए का नुकसान होगा और 1000 रूपए प्रति क्विंटल का नुकसान होगा मतलब हमारे प्रदेश को 4000 करोड़ का नुकसान होगा । यदि 35 लाख मेट्रिक टन की गणना करते हैं तो साढ़े 3 हजार करोड़ का नुकसान होगा । यह नुकसान होगा तो छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान होगा, आपके विकास कार्य इससे बाधित होंगे और अगले साल आपको धान खरीदने में दिक्कत आएगी । यदि आप अभी लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों का भी भला होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी से समय लीजिए, पूरा सदन चलेगा और बात करेंगे कि यहां का धान खरीदा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं

होना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ की बात होगी, तो हम दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ [xx] नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यहां के निवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बजट का विस्तार आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस विनियोग विधेयक में, आप जो विनियोग विधेयक लाए हैं, उसका विरोध करता हूं कि इसमें पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने एकाध वि□ष्य को छोड़कर काल्पनिक चित्रण किया। उनको किसी ने लिखकर दे दिया कि ये बंद-वो बंद-वो बंद और वह बंद में ही रहे। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के लिए साथ हैं, बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो नया घट रहा है, उसको स्वीकारने की, समझने की, उसके साथ चलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। पांच साल हम आपके साथ चले थे। कैसे चले थे, वह अभी आएगा। आप तो बजट क्यों मिलना चाहिए, उसे सुनिए। वि□नियोग में 1 लाख 79 हजार 540 करोड़, जिसमें कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 1 लाख 65 हजार 100 करोड़, बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि है। जिसमें ऋण अदायगी 14540 करोड़, सही है साहब? राजस्व प्राप्तियों में कहें, तो राज्य के राजस्व में 11 प्रतिशत की वृद्धि, केन्द्र से प्राप्तियों में 13 प्रतिशत की वृद्धि 1 लाख 41 हजार करोड़, ये भी एक साल में 12 प्रतिशत की वृद्धि है। राजस्व व्यय 1 लाख 65 हजार करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 26341 करोड़, 18 प्रतिशत की वृद्धि। देश के किसी भी प्रांत के बजट से पूंजीगत व्यय के लिए सबसे ज्यादा वृद्धि है। मेरे ख्याल से आप तो विद्वान आदमी हैं, इस बात को समझते हैं। ब्याज अदायगी के लिए इसमें 9515 करोड़ रुपए है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 12 प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। राजकोषीय घाटा 2.97 में स्थिर है। इससे अच्छा बजट प्रबंधन क्या होगा? अब इससे बड़ी संकल्पना क्या होगी कि हम जीएसडीपी को दुगुना करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, जीएसडीपी को दुगुना करने का आपका जो लक्ष्य है, आपको भागीरथ प्रयत्न करने होंगे। 12 प्रतिशत जो वृद्धि है, उसमें हम पांच साल में नहीं पायेंगे। आपका घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, उसे लगभग 14.5 प्रतिशत करने की जरुरत है। जिस तरह से आप दौड़ रहे हैं, मैं सोचता हूं कि 14.5 प्रतिशत का लक्ष्य भी आप पायेंगे। मैं ये शुभकामनाएं सबकी ओर से देता हूं कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को आप दुगुना करें। (मेजों की थपथपाहट) और इसके लिए आपकी आलोचना उसमें शामिल हो जाएगी, आपने नकारात्मक दृष्टि से सोचा, अपना धर्म निभाया। विनिर्माण क्षेत्र में आपने जितने पैसे बजट में दिए हैं, वे जल्द व्यय हों, समय पर व्यय हों, आप ही के पास वह विभाग है। रोजगार के अवसर की बात है, तो दुनिया में सब सरकारों ने स्वीकार कर लिया कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार का विषय नहीं है और रोजगार का विषय नहीं है क्योंकि आप जो बात कर रहे थे तो मैं

दस्तावेज के साथ दे सकता हूं कि वह पांच साल में बेरोजगारी की परिभाषा तय नहीं कर पाए कि बेरोजगार किसको मानेंगे।

श्री उमेश पटेल :- भईया, अब तो आप लोग आ गए हैं, बेरोजगारी की परिभाषा तय करवा दीजिए। ये पांच साल आप बोलते ही रहे, हमने भत्ता दिया, आपके वायद में है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठिये। देखिये, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बहुत जबर्दस्त।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुंबई में, दिल्ली में और यहां निवेश के लिये एक अच्छा वातावरण बना है।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, एक मिनट। यहां बहुत शानदार चर्चा हो रही है। कृपया सब कोई उसको सुनिये।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, कम से कम सभापति महोदय ला सुन लेवव।

सभापति महोदय :- आप भी बैठिये। मैं यह कह रहा हूं कि जो वक्ता हैं, उनका भाषण सुनिये। बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- 14.5 प्रतिशत तक ले जाये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, लेकिन यह बात ओला भी कह देवव। ओ हर हमेशा मोर गोठ ला नइ सुनय। बस ज्ञान बांटथस।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, अभी अक्ल के बात होत हे तो फिर तैं आ गिस।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, यह अक्ल ला तुंहर धर के रखे रहिबे, कोई काम नहीं आये। तोर गोठ ला कोई सुनत हे का ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप लोग खड़े मत होईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार यादव जी, तोर बर बजट में आई.व्ही.एफ. योजना है।

सभापति महोदय :- देखिये, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत लंबे समय तक भाषण चला। उन्होंने बहुत-सी बातें कही और सबने सुना और अब वह बोल रहे हैं तो उनकी बात भी सुनिये। आप बीच-बीच में डिस्टर्ब मत करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति माहेदय, आप विनिर्माण को, रोजगार को और निवेश को 14.5 प्रतिशत तक ले जाइये। आप समझते हैं। मैं एक-एक लाइन बोलकर आगे बढ़ता हूं। मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ तो बैठते नहीं है। अब क्यों नहीं बैठते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। मैं ज्यादा देर वित्त विभाग में नहीं बोलूंगा। प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रूपये हुई है, जिसमें वर्ष 2023-24 की तुलना में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि है। माननीय भूपेश बघेल जी को यह शब्द समर्पित है। वर्ष 2023-24 की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जो कांग्रेस शासन में 8.27 प्रतिशत थी। साहब, सही है ? यह आंकड़े आप देख लीजिये,

वह 5 साल वित्त मंत्री रहे हैं। इसी में सारी चीजें निहित हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 7.51 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात्।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा सुन लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- आप यह बताईये कि यह तो अनुमान है। आपने पिछली बार भी वित्त प्रस्तुत किया। उसमें जो राजस्व प्राप्ति अनुमानित थी, उससे कितना प्रतिशत कम मिला ?

श्री रामकुमार यादव :- ओला ये हर वर्ष 2047 में बताही।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 3,06,712 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3,29,752 करोड़ रूपये हो गयी। वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पादन में विद्युत, गैस, जलापूर्ति का योगदान वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 9.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि उनके समय में कृषि क्षेत्र में सिंचाई और कृषि दोनों में कमी हुई है। मैं अभी उसको किसानों के तथाकथित मसीहा को बताऊंगा। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि, उद्योग खान सहित 6.47 प्रतिशत की वृद्धि, सेवाओं में 7.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माननीय वित्त मंत्री जी, जनसंख्या घनत्व के आधार पर शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास, नियोजन, सभी में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विकास के पैमाने पर बस्तर, सुकमा की प्राथमिकता कुछ हो सकती है और रायपुर, दुर्ग, भिलाई की प्राथमिकता कुछ हो सकती है। वहीं जहां जनसंख्या घनत्व है, उसमें और मजबूतीकरण करने की जरूरत है। आप जो जी.एस.डी.पी. की बात करते हैं, उसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, इन योजनाओं को और मजबूत करने की जरूरत है, वह आप समझते हैं। मैं उसमें ज्यादा प्रकाश नहीं डालता। अब मैं आपको कुछ चीजें समर्पित कर देता हूं। बजट में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में 119 प्रतिशत की वृद्धि, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 100 प्रतिशत की वृद्धि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 47 प्रतिशत की वृद्धि, महिला एवं बाल विकास विभाग में 45 प्रतिशत की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 43 प्रतिशत की वृद्धि, परिवहन विभाग में 37 प्रतिशत की वृद्धि, जनसंपर्क विभाग में 24 प्रतिशत की वृद्धि, उच्च शिक्षा विभाग में 21 प्रतिशत की वृद्धि, पशुपालन विभाग में 20 प्रतिशत की वृद्धि, जल संसाधन विभाग में 20 प्रतिशत की वृद्धि और लोक निर्माण विभाग में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, जब आप इतनी वृद्धि बता रहे हैं तो आप मछली पालन का भी बता दीजिये कि उसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि है ?

सभापति महोदय :- आप बोलेंगे ना ?

श्री दलेश्वर साहू :- आप पिछले साल से अब तक मछली पालन के क्षेत्र का भी बताईये।

समय
1.50 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब बजट में जो आयोजन है। लगभग सब में चर्चा हो चुकी है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमको कुछ चीजें जाननी चाहिए। आपको वित्त विभाग को छत्तीसगढ़ शासन को दिल्ली से बजट प्रबंधन में 4 हजार 400 करोड़ रूपये का Incentive मिला है।(मेजों की थपथपाहट) यह सबसे महत्वपूर्ण Indication में से एक है। माननीय भूपेश बघेल जी पर्यावरण और तापमान के बारे में बात कर रहे थे निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल मामला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के वनाच्छादन में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसको आप कम कर रहे हैं। आप जिन नियामक संस्थाओं के आधार पर बात करते हैं। मैं उन्हीं नियामक संस्थाओं के रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप भूमिहीन लोगों की जो बात कर रहे हैं। यहां 562 यानी 5.62 लाख जो भूमिहीन लोग हैं, उसको 10 हजार रूपये वार्षिक दिया जायेगा और पहली किश्त दी जा चुकी है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें एक चीज यह है कि जो सुशासन की बात हुई। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। मैंने आपके समय में एक प्रश्न किया था कि कोयला ऑक्शन को ऑफलाईन, परिवहन को ऑनलाईन से ऑफलाईन क्यों कर दिया गया, मैंने ऐसा प्रश्न किया था। तो उस समय मुझे यह उत्तर मिला था कि हमारी ऑफलाईन में इंकम बढ़ी है। पूरा देश ऑनलाईन होने जा रहा था, आपने उसको ऑफलाईन किया। कुछ और चीजें रिपिट तो मत हो। यहां पर सभी योजनाओं में चर्चा हुई है। मैं हमेशा नालन्दा परिसर, ट्राईबल कल्चरल कनवेन्शन सेंटर की बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। आपने फिल्म निगम बना दिया। आप 5 सालों में फिल्म सिटी के लिए जगह नहीं दे पाये। ठीक है आप उसके लिए जगह नहीं दे पायें तो आपको जनता ने उसका उत्तर दिया, लेकिन आपने अभी संकल्पना व्यक्त की है कि चित्रोत्पला के लिए 95 करोड़ रूपये समथिंग प्राप्त हो गये हैं। मैं यह सोचता हूँ कि यहां यह जल्दी क्रियान्वित हो जाएगा। यह Relise हो गया है। यह नवाचार है। अब एक सवा साल की अल्पावधि की बात है। सम्मानित छत्तीसगढ़ पांचवा पुरस्कार ग्राम पंचायत महसूल पानी जिला कांकेर, इसको दिल्ली से पुरस्कार। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी चांपा नगर पालिका आते हैं सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय का द्वितीय पुरस्कार, 4 नगरीय निकायों को स्पार्क वर्ष 2023-2024 पुरस्कार। चित्रकूट एवं घुड़मारास को बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार, यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे नंबर पर आया। जैव इंधन और जैव ऊर्जा के लिए किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए सी.वी.डी.ए. पुरस्कार, रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, इसमें कुम्हारी भी है। आरंग, पाटन को स्वच्छता के लिए पुरस्कार, खनिज ऑनलाईन पोर्टल को मिला एक्सीलेंट एवार्ड, सेरीकल्चर टूरिज्म टसर कृमि पालन, टसर धागा गतिविधियों के लिए बेस्ट Achiever एवार्ड, गैर कोयला मुख्य खनिजों की नीलामी के लिए द्वितीय पुरस्कार, मत्स्य पालन के लिए कांकेर को बेस्ट इंलैण्ड एवार्ड,जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिले हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। इसमें आपका योगदान क्या है? आप यह बताईये? उनने पुरस्कार जीता है चाहे कुम्हारी वाले हों चाहे चांपा वाले हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका योगदान क्या है, मैं यह बोलता हूँ। मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। आपने स्वच्छता में ईनाम की घोषणा की। आपने यहां बताया कि चाहे पाटन हो, कुम्हारी हो, चांपा हो, इसमें आपका योगदान क्या है ? और जहां तक के जो नरवा योजना के कारण, हमने काम किया। भारत सरकार के सारे अधिकारी, जितने फॉरेस्ट के अधिकारी, यहां आकर काम किये हैं। आप वहां से यह निकालकर देख लीजिए। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। उसमें आपने नाम लिया है तो यह बहुत अच्छी बात है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन जो हमने 3 साल काम किया, उसके कारण से आपको ईनाम मिला है। आपको 10 में से 8 जिलों में जो पुरस्कार मिला है, वह हमारे कारण से मिला है। आपकी कोई योजना बता दीजिए, जिसके कारण से आपको ईनाम मिला हो। हम तो नरवा योजना का बता रहे हैं, जिसके कारण से हमको यह लाभ, ईनाम मिला।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। कृषि कर्मण पुरस्कार कहां गया, वह भी बता दीजिए। वह हमेशा मिलता रहा है। हमें इस साल क्यों नहीं मिला ?

सभापति महोदय :- माननीय दलेश्वर जी, वह बता रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- का हो गे ममा।

सभापति महोदय :- यहां नेता जी न कहा, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसके बाद आप कहेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय भांजा जी, आपके द्वारा कही हुई बात को ही मैं बताने जा रहा हूँ। जब हमारे सरकार में केन्द्र सरकार से पुरस्कृत हुए। तब आपका इसी सदन में यह वक्तव्य था कि यह तो सेटिंग में मिल जाता है। आप रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नई औद्योगिक नीति पढ़िये। कल उसमें उद्योग मंत्री का उत्तर आया है कि कितने प्रबंधकीय क्षेत्र में, कितने कुशल, कितने अकुशल का नियोजन होगा। लेकिन उसमें नीतिगत निर्णय में सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला है जो आज की आवश्यकता है। hospitality sector दुनिया का सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बात की। कुपोषण की समस्या पर बात हुई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, उद्योग की बात किये हैं, आप बहुत सारे नये उद्योग खोल रहे हैं। मेरे विधान सभा में एकमात्र शक्कर कारखाना है, वह भी बंद होने जा रहा है। कल का समाचार है उसको निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात केबिनेट में हो गई है। उसकी

ओर पहले ध्यान दें। आप गन्ने के उत्पादन को बढ़ाईये, गन्ने का रकबा बढ़ाईये। आप उस ओर ध्यान दीजिए न। उसको बंद करने पर क्यों जा रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्मार्ट केन्द्रों में विकसित कर रहे हैं। कुपोषण की चिंता हुई। हमारे प्रदेश में 31.6 प्रतिशत के आसपास कुपोषण है, यह आपके समय मेंटेन था, लेकिन आपने उसमें कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन इसको multi activity केन्द्र के रूप में करने जिसमें कुपोषण को दूर करने के लिए बाकी गतिविधियों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण घटक है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति जी, यह कुपोषण का प्रतिशत कितना है? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कितने प्रतिशत कुपोषण है, यह भी बता दीजिए ? जब फिगर की बात कर रहे हैं तो कम से कम कुपोषण का प्रतिशत बता दें।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दलेश्वर जी, मेरी जानकारी में अभी तो आप बोलने वाले हैं, आप बोल लेना। उनको बोलने दीजिए न।

सभापति महोदय :- दोनों पक्ष के वक्तागणों का नाम यहां है, अपने-अपने समय में अपने पक्ष की बात रखें, बीच में किसी को अनाश्यक डिस्टर्ब न करें। उनको बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा बहुत चलता है। बस्तर ओलंपिक की बहुत चर्चा हो गई है। मैं तो स्पर्श करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया। (मेजों की थपथपाहट) यह एक रिमॉर्क है कि देश का मुखिया उस पहल को, नक्सली उन्मूलन के लिए जो पहल होती है, उसको appreciate करता है। आपने बस्तर पंडुम की योजना बनाई है। संस्कृति को सरंक्षित करना, कल मैं संस्कृति विभाग की चर्चा में माननीय भूपेश बघेल जी के योगदान को बताया था कि जो संस्था बनी है, वह क्या काम की और कैसे की ? उसको आज दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस माध्यम से नक्सली उन्मूलन की बात करना, मैंने कहा था कि एक प्रतिज्ञा हुई, कल की बात थी, 31 मार्च 2026 को नक्सली उन्मूलन करेंगे। आप काहे नकारेंगे, किस तरह से उसको नकारेंगे ? साल भर में 300 लोग मारे गये, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और उसमें से ज्यादा लोग सरेंडर किये। वही पुलिस, वही बस्तर, वही नक्सली, बस लीडरशिप भर का अंतर है। इसमें आरोप बनता है, लेकिन आज आरोप लगाने का समय नहीं है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और पहली नक्सली घटना हुई, गीदम का थाना लूटा गया तो कहा गया अजीत जोगी जिंदाबाद। छत्तीसगढ बनने के बाद गीदम के थाना को लूटने के बाद पहला नारा जो लगा, कांग्रेस से दोस्ती है या नहीं है, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन गीदम में यह नारा तो लगा था। सड़क ऊपर पहली बार थाना लूटा गया।

समय :

2.00 बजे

सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं। भूपेश बघेल जी शराब में बहुत अधिकारिता से बोलते हैं। माननीय नेता जी, टी.एस.सिंहदेव जी ने एक बात कही, हमारे विधायक साथी अनपढ़ हैं, नासमझ नहीं हैं, वे सब जानते थे कि दारू घोटाले में क्या हो रहा है । नासमझ नहीं थे, आज तथाकथित अनपढ़ होने को अपना एक कवच बनाए रखना चाहते हैं, सुरक्षा कवच । पी.एस.सी. भूपेश बघेल जी के शासन का एक नायाब उदाहरण । माननीय राम विचार जी, नायाब उदाहरण ऐसा है कि टामन सिंह सोनवानी जी तो गये, वसूली में साला-साली शामिल हो गये । साला-साली के बाद उसके दोस्तों का भी नाम आ गया कि वह भी उस धंधे में लगे थे अब इसके बाद यह कहां तक जाएगा, समझ में नहीं आता । यह रिश्ता क्या कहलाता है भई ? कहां से खोजकर लाये और यह आरोप है । उसके ऊपर सचिव स्तर की जांच थी । उसकी जांच को खत्म करवाया गया, केबिनेट ले जाया गया । मामूली शास्ती लगाई गई ताकि वह नियुक्त हो सके और नियुक्त किया गया और फिर आगे की कहानी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया । अब वह हमको सिखाते हैं कि बजट मिले न मिले, ऐसे कुशासन की मुक्ति के लिए और इस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो शब्द आपने उपयोग किया है न । अभी सदन में कौन सा शब्द उपयोग किया । इज लिविंग (ease living) सुगमता का जीवन हो, लोगों के लिए अवसर हो, आपने अवसर खत्म करने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना तोड़ा है । (शेम-शेम की आवाज) अब नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दे दिया कि अगला चुनाव टी. एस. सिंहदेव के नेतृत्व में होगा करके ।

श्री भूपेश बघेल :- आप मुझे यह बताईये कि यह अनुदान मांग से कहां जुड़ता है ? यह अनुदान मांग का हिस्सा कहां से आ गया ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप अच्छे से जानते हैं कि विनियोग विधेयक में क्या-क्या चर्चा होती है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, अजय जी बोल रहे हैं कि पी.एस.सी. में क्या हुआ । वास्तविक में पी.एस.सी. अभी का नहीं है, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू हैं । (शेम-शेम की आवाज) मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं । आपके शासन में क्या हुआ था ? वर्ष 2005 का आज तक सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, अभी तक और दूसरी बात आपने आरोप लगा दिया । सी.बी.आई. जांच में क्या निकला ? वह और उसका रिश्तेदार...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे तब पी.एस.सी. में क्या हुआ था ? जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस समय पी.एस.सी. में क्या हुआ था ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- उस समय तो कुछ नहीं हुआ था । वर्ष 2004 में क्या हुआ था ? वर्ष 2004 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में आज तक मामला अटका हुआ है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- दोबारा जब आप मुख्यमंत्री बने तब पी.एस.सी. में गड़बड़ी आयी, उसके बाद 15 साल हमारी सरकार रही कहीं गड़बड़ी नहीं आयी । (व्यवधान) जब-जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आयी है दोनों बार पी.एस.सी. में गड़बड़ी हुई है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके समय में आबकारी विभाग में भी घोटाला हुआ था । (व्यवधान) नशबंदी कांड भी हुआ था । नान घोटाला भी हुआ था, सभी घोटाले आपके समय हुए थे । नान घोटाला 4400 करोड़...।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013 के पी.एस.सी. की भी जांच करा लीजिये । वर्ष 2013 का पी.एस.सी. घोटाला । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह पी.एस.सी. घोटाले की बात करते हैं । इनके मध्यप्रदेश में तो वयापम घोटाले पर पिक्चर तक बन चुकी है, वह इतना नामी हो गया । (शेम-शेम की आवाज)

सभापति महोदय :- उमेश जी, धरमजीत जी आप सब वरिष्ठ लोगों के नाम हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूं ।

सभापति महोदय :- आपका वक्ताओं में नाम है । आप लोग अपने समय में अपनी बात रखियेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके पिता जी मध्यप्रदेश में थे और आपने छत्तीसगढ़ में राजनीति शुरू की है । वह मध्यप्रदेश की बात करते तो समझ में आता, वे लोग मध्यप्रदेश का बोलेंगे तो समझ में आयेगा, आप तो यहीं रहिए । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके तो उपकरण खरीदी में भी घोटाले थे । (व्यवधान) उपकरण खरीदी में भी आपके घोटाले हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आप मध्यप्रदेश की बात नहीं कर सकते क्योंकि व्यापम इतना बड़ा घोटाला था जिसमें आज तक आप जांच नहीं कर पाये ।

सभापति महोदय - संगीता जी, बैठिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक-एक चीज में, दवाई में भी घोटाले हैं । अगर हम गिनवायें न तो बहुत सारे घोटाले हैं ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप रतनजोत घोटाले के बारे में भी बता दीजिये । रतनजोत घोटाला ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नहीं मालूम कि नेता प्रतिपक्ष जी को धमकी क्या मिली कि क्या हो गया ? दूसरे दिन बोले कि साहब, उन्होंने बयान वापस ले लिया या मेरे बयान को इधर-उधर करके प्रस्तुत किया गया ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- जनाब, आप सरासर गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो जो समाचार-पत्रों में छपा है वह बोल रहा हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- वह गलत है, पेपर में गलत छपा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दहशत में क्यों हैं ? उभरिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, हम दहशत में बिल्कुल नहीं हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- लीडरशिप संभालिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- बिल्कुल, दहशत में नहीं हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल हैं तब तो आपने बयान बदल दिया ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर पूरा सबका नेतृत्व होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है । हमने कहा है, हम अभी स्वीकार करते हैं कि हम सबके सामूहिक नेतृत्व में होगा, उसमें टी. एस. बाबा साहब शामिल रहेंगे । आपको उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप मानहानि कीजिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- किस पर ?

श्री अजय चंद्राकर :- पेपर के ऊपर, समाचार-पत्रों के ऊपर । मैंने ऐसा कहा उसको गलत छापा करके ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, सदन में हमारे विपक्ष के नेता यहां उपस्थित हैं। हम सारे विपक्षी सदस्यों के नेता हैं । हम सबके नेता हैं। आपके नेता कहां हैं? आपके नेता कहां हैं? नेता वही हैं। असली नेता वही हैं। असली नेता वही हैं। जो नेता है, वही बैठेगा। लेकिन अब उनको यहां आ जाना चाहिए। ओ.पी. जी, इधर देखिए। इधर, इधर। उधर नहीं। इधर। अरे, देखिए भाई। ओ.पी. जी, इधर देखिए और इधर बैठिए। (हंसी)

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय भूपेश जी, आपके पूरे भाषण की ओपनिंग में नेता प्रतिपक्ष कहां थे? पहले यह बता दीजिए। सामूहिक नेतृत्व दिखाई देता है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- मैं अध्यक्ष महोदय के कक्ष में था। वहां मीटिंग चल रही थी।

श्री अमर अग्रवाल :- तो बाद में भी जा सकते थे। आप किस ढंग से सामूहिक नेतृत्व की बात करते हो? बाहर भागते हो।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय के यहां से बुलावा आया था। मैं उनके कक्ष में बैठा था। मैं उनके कक्ष में भाषण सुन रहा था। हम लोग साथ-साथ सुन रहे थे।

श्री अमर अग्रवाल :- सामूहिक नेतृत्व में बगल में बैठकर सुनना चाहिए न। आप बहुत तरीके से जब भी भाषण करते हो तो उठकर चले जाते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- हम लोगों के अगल-बगल में कोई अंतर नहीं है। ये हैं तो मैं हूं, मैं हूं तो ये हैं। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अमर जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आप लोगों की उठक बैठक चल रही है।

श्री भूपेश बघेल :-, भैया, आपने राजनीतिक चर्चा शुरू कर दी, इसलिए बोलना पड़ रहा है। नहीं तो बढिया आपकी बात सुन रहे थे। अमर जी, ये है कि इन्होंने कहा कि आपको ओपनिंग करना है। इनका निर्देश था। नहीं तो अक्सर हमारे चिरंजीवी हमारे उमेश पटेल जी करते हैं। लेकिन आज मुझे कहा कि आपको करना है। मैंने नेता जी के आदेश का पालन किया। लेकिन असली नेता तो वे हैं। (हंसी) वे वहां बैठे हैं। अब आ जाओ, संकोच मत करिए। (हंसी) आ जाओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के ऊपर छोड़ता हूं कि उन्होंने बयान वापस लिया, दबाव में लिया, स्वेच्छा से लिया, लेकिन यह तो सारे समाचार-पत्रों में छपा कि हम अगला चुनाव टी.एस. बाबा के नेतृत्व में लड़ेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसे कहां विनियोग में घुसा रहे हो। (हंसी)

सभापति महोदय :- अजय जी, अब आपकी ट्रेन आगे ले जाइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, मैं एक लाइन विनियोग से बाहर नहीं जा रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वे जानते हैं कि विनियोग में क्या चर्चा होती है। आपने कहा कि नहीं देना चाहिए, मैंने कहा कि देना चाहिए। इसलिए इनके आरोप वे अंतरद्वंद से लगाये गये हैं, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। इनकी जवाबदेही आपस के नेतृत्व के लिए है। इसलिए ये जो कहेंगे, वह सबकी नहीं है। इनकी जवाबदेही नहीं है और जब मैं बोलूंगा तो वह आगे और साबित हो जायेगा। अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं। बोले कि चपरासी कलेक्टर तो पार्टी से निकालने की नोटिस देगा। वहां अलग दंगा हो गया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ये विनियोग की चर्चा है क्या?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्योंकि ये वही अजय चन्द्राकर जी हैं, जो थोडे से हम सब्जेक्ट से बाहर होते हैं तो रूकवा देते हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए न। आज आप रामकुमार जी का रोल अदा कर रहे हैं। (हंसी) आप बैठिए। चलिए, अजय जी, आप बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- ये महाज्ञानी होगे हे, एला कहूं मेर जांच कराये जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, क्या हुआ? चलिए, अटल जी, क्या चपरासी, क्या कलेक्टर है, आप बोलेंगे तो बता दीजिएगा। इनको निकालने की विधायक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को एक आदमी पार्टी से निकालने की अनुशंसा करता है।

श्री अमर अग्रवाल :- निकाल दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- निकाल दिया और अभी हम जानना चाहते हैं कि इस सदन में 2 बार हमारे विधायक साथी रहे कुलदीप जुनेजा जी, वे कांग्रेस पार्टी में हैं या नहीं हैं, उनको भी निकालने का प्रस्ताव हो गया। तो इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। ये उस हार से उबर नहीं पाये हैं। ये बजट तक पहुंच नहीं पाये हैं। ये जनकल्याणकारी योजनाओं की चिंतन में लगे नहीं हैं। ये अंत:संघर्ष में फंसे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, अभी तक 3 मंत्री का चयन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाह रही है कि वे 3 मंत्री कब बनेंगे? पहले आप मंत्री तो डिसाइड कर लीजिए।

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं, मेरा दल, मेरे नेता, माननीय मंत्री सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, मेरे अति आदरणीय भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए कब कोर्ट में जा रहे हैं और कब सड़क में आंदोलन कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि वे भाषण देंगे तो तारीख, तिथि की घोषणा करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- हम कोर्ट में जायेंगे। हम आपके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखेंगे। हम आपके जो गडकरी जी हैं, उनको भी चिट्ठी लिखेंगे। अभी तक मैंने यह नहीं कहा कि आपके परिवार का नाम भी आ रहा है। अगर आ रहा है तो वह भी लिखेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल लिखिए। बिल्कुल, मेरे परिवार का होगा तो उसका नाम लिखकर करिए।

श्री अमर अग्रवाल :- लेकिन आदरणीय, उस भारतमाला के पीछे आपकी मंशा इधर नहीं, आपकी मंशा कहीं और है। आपकी मंशा कुछ और है। बगल में जो बैठे हैं, वे आपको सफल नहीं होने देंगे। यह आप ध्यान रखिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अग्रवाल साहब, आपसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हैं ना? गुड़ाखू के भी संबंध हैं (हंसी) । अगर आपके और हमारे बीच में समझौता हो सकता है तो हमारे और इसके बीच में नहीं हो सकता ? हमने पहले से ही पूछ लिया है कि वे शामिल हैं या नहीं हैं । फिर ऊपर से हमारा राजस्व मंत्री था जयसिंह, जिसको हमारे नाम से जानते हो तो मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं भाई, सब पूछकर किया है ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपकी नजर कहीं और है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, भारत माला के पीछे मैं जानता हूं कि आप किसको माला पहनाना चाहते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जब माननीय भूपेश बघेल जी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, चर्चा में रहना है, कहा कि मेरी जासूसी हो रही है । मेरे साथ कांस्टेबल लगा दिए गए हैं, कहां बजट

पढ़ेंगे ? ये कांग्रेस पार्टी है चंद्रशेखर सरकार से कांस्टेबल के नाम पर समर्थन वापस ले लिया । राजीव गांधी जी ने इसी आरोप के आधार पर चंद्रशेखर जी से समर्थन वापस ले लिया । रेकी तो आप लोगों का पुराना संबंध है । चर्चा में रहने के लिए ऐसे शब्द का उपयोग क्यों करते हैं ? आप पंजाब के प्रभारी हैं भाई, महसूस कीजिए, आप गांधी परिवार के निकट हैं । कहां चर्चा में रहने के लिए रेकी करने का आरोप लगा रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, मुझे चर्चा में रहने के लिए ऐसी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा होता है, यह मैंने पहले भी लिखकर दिया है । आपकी जब सरकार थी तब डीजी को लिखकर दिया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल कैसे राजनीतिक व्यक्ति हैं? यदि कोई नया आदमी आएगा तो उसको लगेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ भूपेश बघेल ही हैं, दूसरा नहीं है ।

श्री विक्रम मंडावी :- आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है या नहीं, यह बताइए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कल मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि प्रक्रिया के बाहर जितने गलत नामकरण हैं उसकी जांच कराकर, उसको यथास्थिति में लाएं, यह एक निक्रिष्ट राजनीति है । हम कुछ बना नहीं सकते, भाजपा के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं और जो चीजें हैं, 1054 स्मारक, सड़कों के नाम रखे गए या नाम बदल दिये गये, 1054, मेरे पास इतनी मोटी जानकारी है और जब तक मैं परिणाम तक नहीं पहुंचुंगा मैं लगा रहूंगा । कांग्रेस पक्ष के लोगों ने एक गलत राजनीति की शुरूआत की है । सभापति जी, अभी वक्फ बोर्ड का बयान आया है, वक्फ बोर्ड की 100 एकड़ जमीन में अवैध कब्जा है, यह नाम किसका है ? मैं जानता हूं तो भूपेश बघेल जी जरूर जानते होंगे कि किसका कब्जा है और किस समय हुआ, यह भी वे जानते हैं । किसका है और कब हुआ वह भी वे जानते हैं, खुला दस्तावेज है । किसने नियुक्त किया था न्यायमूर्ति, अब नाम यहां नहीं लूंगा । आप ही द्वारा नियुक्त लोग हैं । सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि वे कांग्रेस पक्ष के लोग ...।

श्री उमेश पटेल :- भईया, आपका भाषण बहुत गौर से सुन रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वे ही मुख्यमंत्री हैं और हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया है और आप बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- पांच साल के भूत नहीं उतरे हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नेता बन जाओ ना, पिछलग्गू बनना छोड़ दो तो मैं आपका नाम लेना शुरू कर दूंगा । अभी तो आप किसी की छाया से नहीं उबरे हैं । मैं वही अपील तो नेता जी से कर रहा हूं कि आप छाया से निकलिए, आप नेता हैं यह महसूस कीजिए, हम आपके साथ हैं । आप सदन के नेता हैं मैं वही बात कर रहा हूं । सभापति महोदय, किसानों की बात कर रहे थे । मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं । 2019 से 2022 तक भूपेश बघेल जी के राज में 570 किसनों ने आत्महत्या की, जिसमें एक सामूहिक आत्महत्या पाटन में हुई, हम लोग वहां जांच करने गए थे । पाटन में आत्महत्या क्यों हो

गई भई ? आपने क्या किया, आपने क्या कदम उठाया? आज जब कृषि में बजट बढ़ा, मैं अभी इरीगेशन में बात कर रहा हूं 5000 करोड़ रूपए जितनी अधूरी सिंचाई योजनाएं थी, उसके लिए दिया । आपने पांच साल में क्या किया यह बताइए ? पांच साल में एक अधूरी सिंचाई योजना पूरी हुई हो । मैं उसके आगे पढ़ देता हूं कि कृषि भूमि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 45 हजार हेक्टेयर घटा है, वर्ष 2021-22 में 50124 हेक्टेयर कृषि भूमि का रकबा घटा, इस बात को आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है। रबी फसल का उत्पादन, मैं रबी फसल को छोड़ देता हूं, नहीं पढ़ता। सिंचाई का रकबा पढ़ देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आगे चलकर किसानों की बात करना बंद कर देंगे, आलोचना करना बंद कर देंगे। इस सरकार में 5 हजार करोड़ रूपए मिले हैं, अब ये महसूस नहीं होता तो उसको कौन क्या करेगा ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय।

श्री अजय चंद्राकर :- एक लाईन सुन लीजिए मामा। ताहन मैं बईठ जहूं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कर्जा माफ नई कर सकव, किसान मन के का बात करहू।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, किसानों के हित में हमारी सरकार में क्या काम हुआ है, मैं बताना चाहता हूं। 15 साल से गांवों में ढाई लाख, तीन लाख, पांच लाख रूपए में जमीन बिकती थी, हमारी सरकार की देन कर्जामाफी हुई, जमीनों का दाम बढ़ा, अभी आपको 5 साल में 15 लाख में जमीन नहीं मिला। 10 एकड़ के किसान की पूंजी 1 करोड़ रूपए बढ़ गयी। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की देन है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार के आने के बाद महासमुंद में एक किसान ने आत्महत्या की है। आप इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते। आपकी सरकार आने के बाद आत्महत्या फिर शुरू हो गई। हमारे किसान भाई लोगों ने पिछले 15 साल में भी आत्महत्या की थी। उसको संज्ञान में लीजिए, किसान लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अभी शुरूआत हुई है, संभाल लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, 5 साल में हमर सरकार बने के बाद 10 हजार करोड़ कर्जा माफ करे रेहेन। आप मन किसान मन के कर्जामाफी करे हव का। अभी बतईहा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय रामकुमार जी, तुम्हारा जीवन धन्य है। आपका जीवन धन्य है, मैं तुम्हारा बोलकर गलत बोल दिया।

श्री रामकुमार यादव :- धन्य हे लेकिन तुंहर जीवन ला देखा।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी बात सुन लीजिए, क्यों धन्य है ? वह सुन लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- न पक्ष के हो न विपक्ष के हो, बीच में ढेला बरोबर माढ़े हो।

श्री अजय चंद्राकर :- क्यों धन्य है, वह सुन लीजिए, पांच जन्म ले लेते तो वह नोट की गड्डी नहीं देख पाते जो भूपेश बघेल जी के राज में देखे हो। (मेजों की थपथपाहट) ये तुम्हारा जीवन धन्य हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा सुन लीजिए,

श्री रामकुमार यादव :- नोट के गड्डी कहां हे, समय आही ता बताही। ई.डी. मन ला आवन तो दो।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप पांच जन्म ले लीजिए लेकिन आपको वे मंत्री नहीं बनाएंगे, ये भी सत्य है। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ऐ रामकुमार ल कतका कुछ कर लेव। घोड़ा के सिंग जागही त ले तुम मंत्री नई बनव। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 में वास्तविक सिंचाई क्षमता 16974 हेक्टेयर में कमी आई, वर्ष 2022-23 में 29762 हेक्टेयर में कमी आई, प्रशनोत्तरी दिनांक 13 मार्च, 2023 में है। आपके कार्यकाल में खेती का रकबा घटा, आपके कार्यकाल में सिंचाई का रकबा घटा। (शेम शेम की आवाज) आप क्या करते रहे ? किसान आत्महत्या करके मरते रहे। आप जिस शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे थे। मैं इन सभी में बैठे-बैठे टैग लगा रहा था, शिशु व मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, यदि हम वर्ष 2017 में शिशु मृत्युदर देखें 38 प्रति हजार थी, वर्ष 2020-21 में ये 40 हो गई, वह वृद्धि लगातार होती रही, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार मातृ मृत्युदर वर्ष 2015-16 में 1 से 41 प्रति लाख थी, वर्ष 2020-21 में वह 159 हो गई, ये आपकी सरकार में हुई। ये मैं आर्थिक सर्वेक्षण में बोल रहा हूं। जब आपने बात की तभी मैंने इसमें टैग लगाया।

माननीय सभापति महोदय, हमने सुगम जीवन की परिकल्पना की। आदमी का जीवन आसान हो, कर्मचारी का जीवन आसान हो, इस राज्य को उन्नत देखने वाले उस हर अवयव का जीवन आसान हो। छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को अब [xx] प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। यहां के कर्मचारियों ने भूपेश बघेल जी के राज में ही [xx] प्रदर्शन किया था, इससे पहले देश में कहीं भी नहीं हुआ था, एक बार मणिपुर की महिलाओं ने किया तो उन लोगों ने सामने बैनर रखा था, वैसे वस्त्रहीन नहीं थे। कर्मचारियों ने इसी राज्य में वस्त्रहीन प्रदर्शन किया, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, विधान सभा चल रही थी। ये जीवन सुगम नहीं था, ये बनाने का काम बजट कर रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- उसको उकसाने वाले आप थे, कलेक्टर, एस.पी. ऑफिस जलाने वाली सरकार आप हो, आप लोग इस बात को याद रखिए।

श्री अजय चंद्राकर :- 58वां विभाग जो बना, वह इसीलिए बना। माननीय सभापति महोदय, हर चीज में अवसर मिलता था, इसलिए सारी चीजें ऑनलाईन हो रही हैं। आप सुशासन और अभिसरण

विभाग को पढ़ियेगा। मुझे कभी नहीं बताया जा सका कि पैरादान कितना हुआ ? पैरादान हुआ या नहीं हुआ ? यह मालूम नहीं है, परंतु शेष लगाये गये। शेष में मैं हाई कोर्ट में गया हूं। अभी उसमें सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उसमें 18 करोड़ रूपये पैरा ढुलाई में खर्च किये गये। यह नहीं मालूम कि कितना पैरा दान हुआ ? लेकिन पैरा ढुलाई शेष के पैसे से हुई। पैरा ढुलाई के लिए शेष नहीं लगा था। ऐसा शासन चलता था, जो एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता शासन होता था। कानून का राज समाप्त हो गया था और वह हमको कहते हैं कि हम आपको बजट क्यों दें। हम बजट तो लेंगे। मेंडेट हमारे पास है। जनादेश हमारे पास है और भाजपा के पक्ष में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हमारे पास है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा जनोदश आपके पास नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आपके पास जनादेश है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ला जनादेश मिले हे ता का दारू भट्ठी खोले बर मिले हे का ? आप 67 ठन दारू भट्ठी खोल देहो। आप ला जनादेश मिल गेहे ता कुछु अच्छा काम करव। महाज्ञानी जी, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो। आप दारू भट्ठी खोलत हो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, नेता जी खड़े हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ते थोड़ा नेता जी के तो सम्मान कर।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, चंद्राकर जी की आदत है कि प्रथम वक्ता जितना बोलेगा, उससे वह 5-10 मिनट ज्यादा ही बोलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर देता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने आपको नहीं बोला है। मैं इनको बोल रहा हूं कि आप उनको बता दीजिए कि जितनी देर तक भूपेश बघेल जी ने बोला है, उनका समय उससे ज्यादा हो गया है। यदि वही-वही बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं जल्दी खत्म कर देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी को अधिकार है कि वह कभी भी, किसी भी मोशन में कहीं भी खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं। सदन के नेता को और नेता प्रतिपक्ष को टोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। आसंदी भी उनका सम्मान करती है। हम लोगों की आपके सामने क्या बिसात है ? आप मुझे क्षमा करियेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, आप आगे बढ़िये।

श्री अजय चंद्राकर :- जी। सभापति महोदय, भूपेश बघेल जी अभी नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी इधर-उधर के लिए बोल रहे थे। जल स्रोत उठा है। आप नाला देख लीजिए।

श्री अमर अग्रवाल :- शायद आपको जानकारी है या नहीं है कि नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी आजकल तेलंगाना चला गया है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, इसमें 5 साल में इस बजट से क्या 1 रूपया भी खर्च किया गया ? बजट से 1 रूपया का कोई बजट सपोर्ट इस योजना को नहीं दिया गया और केन्द्रीय योजनाओं से इनका अभिसरण किया गया। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि 1 हजार 342 करोड़ रूपये केन्द्रीय योजनाओं पर लगाये गये। जब मैं बस्तर ओलम्पिक व केन्द्रीय योजनाओं की अभिसरण की चर्चा कर रहा था। मैंने बस्तर ओलम्पिक की चर्चा की तो 1 साल में 4 बार ओलम्पिक हुए और बजट से उसको 1 पैसा नहीं दिया गया। बस्तर ओलम्पिक के लिए वित्त मंत्री जी ने साढ़े 7 करोड़ रूपये दिये हैं और इस साल और पैसे दिये हैं। (मेजों की थपथपाहट) जब आपमें से कोई वक्ता खड़े होंगे तो वह मुझे इस बात को बताएंगे कि जब बस्तर ओलम्पिक या छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक हुआ तो उसके लिए कितने पैसे का बजट आयोजन किया गया था ? हर चीज में अवसर था, हर चीज में संभावना थी। वह हमको आइना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बजट क्यों दें ?

सभापति महोदय, नवजवानों के सपने के लिए एक बड़ा काम करेंगे और कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड बनाएंगे। हमने सब योजनाएं बंद कर दीं तो आपने कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड बनाया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप कभी-कभी बोलते हैं तो वह कहते हैं कि हमारे समय का है। आपकी कोई भूमिका नहीं थी। यह भी हमारी सरकार का 5 साल का है, ऐसा बोलते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आप यह बात जरूर बताइयेगा कि कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड में बस्तर व सरगुजा से कितनी भर्ती हुई? झुनझुना पकड़ाने को आप राजनीति कहते हैं।

श्री विक्रम मण्डावी :- अजय भैया, बस्तर कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड में बस्तर संभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 1500 से अधिक लोगों की भर्ती हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। बिजली उत्पादन का ग्राफ देखिये। बिजली उत्पादन में लगातार कमी आई है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, जिसे आप कल पढ़ रहे थे। मैं आपको उसकी रिपोर्ट बता देता हूं। बिजली उत्पादन में जल विद्युत भी बनेगा। जिसका आप लोगों ने एम.ओ.यू. किया है। उसी सीट पर बैठकर माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं बोधघाट परियोजना बनाऊंगा। क्या वह ओस्काप लिमिटेड था ? उसको एडवांस में पैसे दे दिये गये। उसने वह कार्य किया या नहीं किया और वह पैसे कहां गये ? इसको भगवान जाने। लेकिन उनको साढ़े चार-पांच करोड़ रूपये दे दिये गये। हम लोगों ने कहा कि वह परियोजना नहीं बन सकती है तो आपने कहा कि आप नहीं बना सकते हैं, हम आपको बनाकर बताएंगे। जो भी वक्ता बोलेंगे तो वह मुझे बतायेंगे कि बोधघाट परियोजना का क्या हुआ ? ऐसे कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, बोधघाट परियोजना बन जाएगी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी में कैम्पा के पैसे लगा देंगे, कार्य योजना दूसरी है और दूसरा कर देंगे तो सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में ये जो चीजें हैं , मुझे इस बात से बहुत दुःख लगता है। नेता प्रतिपक्ष जी सुन नहीं रहे थे, बात कर रहे थे। मेरे विधायक साथी कवासी

लखमा जी हैं, और भी विधायक साथी हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किसकी भागीदारी है, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन अभी भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि निर्दोष लोग अंदर हो गए। अब वह अदालत की भूमिका भी निभाने लगे हैं। साहब, कुछ न कुछ तो है। जहां आग होती है, वहां ही धुआं उठता है। प्रदेश में 3-4 ऐसी घटनाएं घट गईं, वहां किस आदमी को जाने की जरूरत थी ? बलौदा बाजार में कौन से समाज का कार्यक्रम था ? कौन-कौन आदमी मंच पर उपस्थित था, कौन-कौन आदमी मंच के नीचे उपस्थित था ? उसको किसने फायनेंस किया ? जांच होगी, आप तक पहुंचेगी तो आप निर्दोष हो गए, दूसरे फंसे तो दोषी हो गए ? प्रदेश को अशांत करने का, भाई मेन्डेट को स्वीकार करो, मेहनत करो। 15 साल बाद आए हो, 15 साल बाद फिर आ जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को उस रास्ते में मत ले जाओ, जहां छत्तीसगढ़ ने कभी देखा नहीं है। यह आगजनी, लूटपाट, प्रशासनिक संस्थानों को ठप्प करना, छत्तीसगढ़ की राजनीति की फितरत नहीं रही है। अपराधियों को सरंक्षण देना फितरत नहीं रही है। अपराधियों के साथ राजनीति करना फितरत नहीं रही है। सुशासन विभाग भी इसीलिए बना है। गलती किसकी है, न्यायालय फैसला करेगा, मैं फिर से बोलता हूं। लेकिन जो जनता के क्षेत्र में काम करते थे, प्रशासन के क्षेत्र में काम करते हैं, वह आज उनको जिन जगहों में नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं उन जगहों में मौजूद तो हैं और लम्बे समय से हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय भी उनको बाहर नहीं आने दे रही है। कहीं न कहीं कोई बात तो है। इस प्रशासन को सुधारे बगैर, इस कार्यशैली को सुधारे बगैर, प्रशासन और राजनीति में स्वेच्छारिता को खत्म किए बगैर इस प्रदेश का भला नहीं होगा। बजट आया, जो अनुदान मांगें पारित हुईं, हम विनियोग पर बात कर रहे हैं। हम सकारात्मक दिशा में बात कर रहे हैं कि इस प्रदेश में कानून का राज चलेगा। कानून सर्वोपरि होगा, व्यक्ति की स्वेच्छारिता महत्वपूर्ण नहीं है। वह सर्वोच्च नहीं होगी, कानून के हिसाब से काम होगा। नियम-अधिनियम के हिसाब से काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा। साहब, आग्रह यह है कि मान लो 24-25 का बजट आया। अभी 2025-26 का बजट आया। कोई ऐसा रूल बनाईये कि मुख्य बजट की प्रशासकीय स्वीकृति प्रथम अनुपूरक आते तक हो जायेगी। प्रथम अनुपूरक की प्रशासकीय स्वीकृति द्वितीय अनुपूरक आते तक हो जायेगी। हम आरोप सुनते हैं, सरप्लस राशि होने के बाद भी राशि खर्च नहीं हो रही है। एक साल में जितनी चीजें होती हैं, एक 50 करोड़ की सड़क है, एक साल तो बनेगी नहीं। आप एक साल के लिए बजट देते हैं, सही है कि एक दिन में नहीं दे सकते, लेकिन अमर जी वित्त मंत्री थे तो भी, डॉ. साहब वित्त मंत्री थे तब भी सदैव इसी बात में झंझट होती रही कि प्रशासकीय स्वीकृति देने की गति धीमी है। जो भी वित्तीय परिस्थितियां हों, परन्तु आपके 14.5 के लक्ष्य को पाने के लिए जो विनियोजन का क्षेत्र है, जो आपके वर्किंग डिपार्टमेंटस हैं, उसमें तेजी की जरूरत तो है। इसको आलोचना के तौर पर मत लीजिये, सुझाव है। इसमें तेजी की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है।

श्री अमर अग्रवाल :- आप एक वित्त मंत्री को भूल गये क्या ? हमारा और डाक्टर साहब का नाम लिए हो, वहां भी तो वैसा ही होता था, वहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं। हम दोनों का नाम ले रहे हो, सबका नाम लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है। मंत्री, विधायक नहीं, जहां विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, वहां के विषय पर बात करता हूं। किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्रीय असंतुलन (regional imbalance) है, सुकमा, बस्तर, सरगुजा में कहीं भी बीजापुर, नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन इस तरह के प्राथमिक सेक्टर के क्षेत्र हैं, वह क्षेत्रीय असंतुलन (regional imbalances) खत्म हो, ये चीजें झलकनी चाहिए। अभी क्या होता है कि इससे पहले वाली सरकार में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के मंत्री बैठते थे, दुर्ग से अंडा तक सड़क बनाई गई। अंडा से गुण्डरदेही को नहीं जोड़ा। क्यों ? गुण्डरदेही उसके विधान सभा क्षेत्र में नहीं था। मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, माननीयगण से निवेदन करता हूं कि आप अभी जाकर पाटन की सड़कों को देखिये। जहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर भी डबल लेन, फोर लेन सड़क बनी है। यदि हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं तो जो प्रभावशाली है, वह असंतुलन हमेशा छत्तीसगढ़ में बना रहेगा। मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा था कि शिक्षा का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। आपके पास 33,000 पद रिक्तियां है या नहीं है, यह मैं नहीं जानता हूं। मैं राजनीति बात नहीं कर रहा हूं। आपने यह बात सदन में कही है कि हम 33,000 रिक्तियां भरेंगे। फिर हमने सदन में ही यह बात करेंगे कि हम भरेंगे नहीं, युक्तियुक्तकरण करेंगे। सवा साल हो गये, लेकिन हम न भर्ती की तरफ बढ़े हैं, न हम युक्तियुक्तकरण की तरफ बढ़े हैं। मैं उस बात को फिर से दोहरा देता हूं कि छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश है। कोई नौकरी करेगा तो उसे कोंटा क्षेत्र भी जाना पड़ेगा, उसको बलरामपुर, वाड्रफनगर भी जाना पड़ेगा। यह अब मध्य प्रदेश नहीं है कि यहां झाबुआ, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ है। यदि कोई उस धारणा से विरोध करते हैं तो उस दबाव से सरकार को मुक्त होना चाहिए। मैं आपसे तीसरी महत्वपूर्ण बात कहूंगा, जिस पर आप विचार कीजिये कि उच्च शिक्षा विभाग में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह रिक्त पदों की है, विशेषज्ञता की है, विषय है। जो नवाचार हो रहे है, उससे आप अपने आप को जोड़िये। आप विद्वान मंत्री हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो स्वास्थ्य की बात है। नेता जी, जांजगीर-चांपा के चार मेडिकल कॉलेज भवन के लिए इसी बजट में एक हजार करोड़ रूपये मिला है। आप उसकी प्रशंसा कर दीजियेगा। मैंने उसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसकी डिमांग मांग में चर्चा हो गई थी, लेकिन आप वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिएगा। जशपुर के स्वास्थ्य सेवाओं के तहत आप वहां मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, उसकी मैंने प्रशंसा की और मैंने उस दिन दंतेवाड़ा की भी प्रशंसा की थी। उसका कारण है कि इन सुविधाओं के अभाव में दूसरे तत्व, धर्मांतरण वाले लोग हावी होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं में जशपुर की जो डेमोग्राफी बननी थी वह बन गई, लेकिन बस्तर की डेमोग्राफी बहुत तेजी से अनबैलेंस हो रही है। यदि

हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो उस बात की कौन चिंता करेगा? खासतौर पर जब आप हैं तो यह डेमोग्राफी असंतुलित मत हो। किसी समय असंतुलित हो गई होगी तो हो गई होगी। हमें कोई आरोप की चिंता नहीं है कि हमको क्या बोला जाता है कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं, हम अतिवादी हैं, हम दक्षिणपंथी हैं, हम जितने भी रेड लिस्ट हैं, जितने प्रकार के आरोप है वह हमें लगा लें, लेकिन यह आरोप सुनते-सुनते हमको सौ साल हो गये हैं और राजनीति में आरोप सुनते-सुनते 51 से आज तक पहुंच गये और इस आरोप के साथ भा.ज.पा. शून्य से भारत व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे आरोप में दबाव में प्रशासन नहीं होता है। आप उन क्षेत्रों को ठीक करेंगे, यह आपके भाषण में आना चाहिए। मेरी एक छोटी सी विनती है, फिर मैं समाप्त करूंगा। आपने मेरे यहां एक अस्पताल दिया है। मैं कुरूद की बात नहीं करता, लेकिन मुझे थोड़ा त्रुटि महसूस हुई।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओ हर बार नई मांगव कइथे, लेकिन हर बार मांगथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय वित्त मंत्री जी, आपने 100 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया है। उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने जो बिल्डिंग के लिए पैसा दिया है, उसमें 100 बिस्तर लिखा है। आप उसको एक लाईन पढ़ देंगे कि उसको 200 बिस्तर माना जाये तो 200 बिस्तर का अस्पताल भी हो जाएगा और 200 बिस्तर की बिल्डिंग भी बन जाएगी। आप बोल देंगे तो वह त्रुटि सुधर जाएगी। एक और छोटी सी बात है कि साहब, हमारे जैसे लोग न मंत्री हैं, न कुछ हैं तो अनबैलेंसेस मत हो। आपने हम लोगों की तरफ कुछ कागज वगैरह छोड़ दिया था तो आप उस कागज को अनुपूरक में शामिल कर लीजिएगा। मैं यह आग्रह के साथ कहना चाहूंगा कि आपका बजट बहुत अच्छा है। आलोचना करने वाले लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। उनका जिस तरह से राजनीति शिक्षण-प्रशिक्षण हुआ है, देश व प्रदेश के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। उनकी निष्ठा परिवार के प्रति है। उनके समय सरकार नहीं चलती थी, ए.टी.एम. की सरकार चलती थी (मेजों की थपथपाहट) और अभी जो सरकार चल रही है, वह ए.टी.एम. सरकार नहीं बल्कि जनता की सरकार चल रही है। आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, माननीय विष्णु देव साय जी की सुशासन की जो परिकल्पना है, उस पर आप खरे उतरेंगे, (मेजों की थपथपाहट) इस सद्भावना के साथ मैं अपनी बात समापत करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल्ली में छत्तीसगढ़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच खुल गया है।

श्री रामकुमार यादव :- झारखण्ड के ठेका कोन ले हे रिहीस हे तेन ला मोला बतावौ तो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- दो गुजराती पूरे छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूट रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा?

सभापति महोदय :- दोनों पक्ष के प्रथम वक्ताओं ने अपनी-अपनी विस्तृत बात को रखी है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं सभी माननीय वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी बातों को संक्षेप में रखेंगे। श्री दलेश्वर साहू जी।

श्री राजेश मूणत :- दलेश्वर जी, अजय चन्द्राकर जी का 1 घंटा 3 मिनट भाषण हुआ है। competition कम नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय :- श्री उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- अजय जी, आयेंगे ना ? थोड़ा जल्दी आईये । माननीय सभापति महोदय, विनियोग पर चर्चा है, बजट में ...।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, यह पूर्ण उम्मीद है । अब आप सोचो कि आपके दोनों नेता उठकर चले गये ? अजय के लिये तो दोनो बैठे थे । अब देख लो यार, क्या स्थिति है, समझ लो बस ?

सभापति महोदय :- मूणत जी, बोलने दीजिए । उमेश जी, चलिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, विनियोग पर चर्चा होगी, मैं अनुदान मांगों और वित्त विभाग पर लंबी चर्चा कर चुका हूँ, विनियोग पर ही सीमित रखने की कोशिश करूँगा कि पूर्व वक्ताओं ने कुछ ऐसे विषय को रखा है, मैं उसमें भी आना चाहूँगा । सभापति महोदय, हम जिस विधान सभा में आज बोल रहे हैं, इसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत बोलते हैं, इसकी गरिमा को स्थापित करने का काम भी हमारा है और उसे यदि स्थापित किया जा सकता है, उसे आसंदी से किया जा सकता है । माननीय सभापति महोदय, क्या हो रहा है, इसी सत्र में विधान सभा की गरिमा को कैसे तार-तार किया जा रहा है, मंत्री लिखित में कुछ और जवाब दे रहे हैं, यहां कुछ और जवाब देते हैं । सभापति महोदय, विधान सभा चल रहा है, यहां नेता प्रतिपक्ष जी के एक सवाल पर मंत्री उत्तर दे रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि कमिश्नर से जांच होगी, क्या आसंदी से परमिशन ली गई, इस गरिमा को मैंटेन कौन करेगा या अगर ऐसा है तो इस विधान सभा का कोई औचित्य नहीं है ? सभापति महोदय, अगर विधान सभा चल रही है, हम लोग सब उपस्थित हैं, आप नियम प्रक्रिया को देख लीजिए, अगर यह चल रहा है तो क्या बिना आसंदी की अनुमति के, बिना अध्यक्ष की अनुमति के, इस तरह से जब नीतिगत निर्णय हो तो इस विधान सभा की क्या गरिमा बच पायेगी ? सभापति महोदय, हमें चुनकर इसलिये भेजा जाता है कि क्षेत्र के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में जाओ और बताओ, बात करो, चर्चा करो । हम लोग इस सदन को एक पवित्र सदन के रूप में देखते हैं, लेकिन इसकी गरिमा नहीं बचेगी तो इस बजट भाषण का, इन सारे वार्तालाप का कोई औचित्य ही नहीं है ? सभापति महोदय, हम सब की यह जिम्मेदारी है...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन की गरिमा में कहां पर संकट आ गया ? बजट में सब बैठकर रात भर चर्चा कर रहे हैं, बजट पारित कर रहे हैं, डिमांड मांग पर चर्चा हो रही है...।

श्री उमेश पटेल :- बाहर थे, नहीं सुन पाये । यहां नीतिगत निर्णय हो जाता है। यहां अलग घोषणा होती है और शाम तक कुछ दूसरा घोषणा हो जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वक्तव्य आ गया ।

श्री उमेश पटेल :- वक्तव्य आने से क्या होता है अजय जी, आप भी जानते हैं, इस गरिमा को मैंटेन करने की आवश्यकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय भईया बोल रहे थे कि आपकी सरकार में यह है, आपस में लड़ रहे हैं, आप ऐसी बोल रहे हैं ना, आपस में लड़ रहे हैं, इनको बस अपना धर्म पूरा करना है ? सभापति महोदय, आप क्या कर रहे हैं, तीन लोगों में मंत्री बनने की ऐसी होड़ लगी है...।

श्री राजेश मूणत :- उमेश भाई एक मिनट, आप बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हो, उसके लिये धन्यवाद । लेकिन वहां जो बैठ रहे हैं, उनसे कहो ना कि आपस में अच्छा रोल अदा कर लें । जब नेता जी बोलते हैं तो पड़ोसी नदारद हो जाते हैं और पड़ोसी बोलते हैं तो नेता जी नदारद हो जाते हैं । विपक्ष की भूमिका में कौन, कब बहिगर्मन करके चल दे, मैंने तो ऐसा हाऊस में कभी नहीं देखा । मैं भी कई साल से हाऊस में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं देखा हूँ । आपके नेता जी को पता नहीं लगता है कि कब कौन उठकर चल देता है । विपक्ष की राजनीति में जो तार-तार हो रहा है, उसमें एकरूपता लाये ।

श्री उमेश पटेल :- आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहां बैठे सभी सदस्यों से माननीय नेता जी ने यह कहा है कि कोई भी एक डिसीजन लेगा, उसको सब लोग मानेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- मतलब सभी नेता हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- आप मंत्री बने के होड़ में हो का ?

श्री राजेश मूणत :- यादव महाराज, मैं तुम्हारे साथ में हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- ह तो अब नहीं बोलवं ।

(पत्रकार दीर्घा में कुछ गिरने की आवाज आने पर)

श्री उमेश पटेल :- ऐसा लगा कि कुछ गिर गया । सभापति महोदय, मंत्री बनने की ऐसी होड़, ऐसी होड़ है। अमर भैया ।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप उधर देखकर मत बोलिए न, इधर देखकर बोलिए ।

श्री उमेश पटेल :- इधर ही बैठा रहूंगा तो शरीर भी टेड़ा हो जाएगा । आप समझिए न, यहां जगह नहीं है । थोड़ा हिलना-डूलना पड़ता है । अब तो नए विधान सभा में जाएंगे तो वैसे भी ठीक हो जाएगा, लग रहा है । सभापति महोदय, मंत्री बनने की ऐसी होड़ मची हुई है कि एक मंत्री के खिलाफ उसको हटाने के लिए षड़यंत्र कर रहे हैं । आपको नहीं पता ? आपके नगर पालिका का अध्यक्ष जिसको

आपने चुनाव लड़ाया, उस मंत्री के खिलाफ उसके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, पार्षदों को पैसा दिया जा रहा है ।

श्री राजेश मूणत :- यह सब बात विनियोग में कहां है ?

श्री उमेश पटेल :- आप बोलें तो ठीक ।

श्री विक्रम मण्डावी :- सबसे पहले अजय भैया बोल रहे थे, उनको आपने नहीं कहा ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन विदेश के बात करथौं तो एमा रहिथे । हमन कहिबो तो वो ह नहीं रहाय ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, इसके बाद आप ही का नम्बर है ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं इतना ही कह रहा हूं कि बजट के कुछ अच्छे सुझाव हो तो वे दें, उसमें कुछ कमीबेशी हो तो वह बताएं । उमेश भाई, आप जैसा पढ़ा-लिखा नौजवान और भविष्य है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं ।

श्री राजेश मूणत :- जिनको राजनीतिक भाषण देना है, वे अभी बैठे हुए हैं, वे दोनों-तीनों वही बात करेंगे ।

सभापति महोदय :- मूणत जी, आप बैठिए न । उमेश जी अच्छी बात रखेंगे। आप बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं इस विषय पर बिल्कुल टच नहीं करना चाहता, लेकिन ये उकसा रहे हैं ।

श्री राजेश मूणत :- आपका काम्पीटिशन कर रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- काम्पीटिशन की बात नहीं है, वे सारी बातें कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में बात न करें ।

श्री उमेश पटेल :- इनके नेतृत्व में क्या-क्या किया, वह भी बोलूंगा । सदन में मैंने कभी बोला नहीं था । 2013 में ये मंत्री थे, हम विधायक थे । हमको क्या-क्या झेलना पड़ता था, वह बात भी रखूंगा । राजेश जी, आपका तो अलग था, आप तो बढ़िया थे । सभापति महोदय, ऐसी होड़ है कि मंत्री के खिलाफ षड़यंत्र चल रहा है, क्या वह राजद्रोह नहीं होगा ? इस शासन के खिलाफ षड़यंत्र नहीं है ? अगर कोई शासन के खिलाफ षड़यंत्र करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह लगना चाहिए । आप राजद्रोह लगा सकते हैं क्या ? नहीं लगाएंगे ।

श्री राजेश मूणत :- जिसके ऊपर राजद्रोह लगाए थे, वह कोर्ट से बहाल होकर वापस सर्विस में आ गया । ऐसा राजद्रोह मत लगाया करो, आपको मुबारक हो ।

सभापति महोदय :- राजेश जी, उमेश जी, आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं । आप लोग सदन में आपस में बातें करते हैं, यह उचित नहीं लगता ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, अगर आपस में बात नहीं करेंगे, अगर एकतरफा ही चलता रहेगा तो फिर तो ऐसे ही कम लोग बैठे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे । सभापति महोदय, इस शासन का आचरण बताना चाहता हूं । हमारे आचरण के बारे में अजय जी बोल रहे थे, मैं इस शासन के लोगों से, जुड़े हुए लोगों की बात बताता हूं । यहां पर एक विधायक बैठे हैं । एक नौजवान लड़का जाकर इतना बात बोल दे कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम से बाहर का नाम क्यों रख रहे हैं तो उसका गला पकड़ लिया जाता है । अगर महिलाएं धरना दे रही हैं तो एक मंत्री द्वारा उनको बोला जाएगा कि तुम यहां से हटो, नहीं तो डंडा लगाकर तुम्हें उठाएंगे । एक विधायक अपने ही शासन के खिलाफ बोलता है कि पुलिस मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है ।

श्री रिकेश सेन :- उमेश जी, आप टिप्पणी कर रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- मैंने किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री रिकेश सेन :- आपने टिप्पणी की तो जवाब लेना पड़ेगा ।

श्री उमेश पटेल :- मैंने किसी का नाम नहीं लिया ।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप बैठिए न ।

श्री रिकेश सेन :- आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी बिना सत्यता जाने बिना सोचे-समझे टिप्पणी करते हैं । आप भी बिना सत्यता जाने बोल रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- मैंने किसी का नाम नहीं लिया ।

श्री रिकेश सेन :- आपने नाम नहीं लिया है, लेकिन आपने इंडायरेक्ट तो बोला न।

श्री उमेश पटेल :- मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप बैठिए ।

श्री रिकेश सेन :- बिना सत्यता जाने आप सदन में बयान दे देते हैं । आप लोग चाहते क्या हैं ? आप लोग लगातार जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- आपकी बात हो गई न, मैंने आपका नाम नहीं लिया ।
मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । सभापति महोदय, या तो मुझे बोलने दीजिए ।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप बैठिए ।

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका जवाब आप सुन लीजिए । आपके प्रदेश के संघटन के महामंत्री...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- सभापति महोदय, नहीं। आपको जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री उमेश पटेल :- आप अपने टाइम में बोल लीजियेगा। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- मेरा टाइम है ही नहीं। अब आप सुन लीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रिकेश जी, आप प्लीज बैठ जाईये।

श्री रामकुमार यादव :- ऐसे नहीं होये कि मंत्री जी कोई । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, उनको अलग से टाईम दे दीजियेगा। वह अपना पूरा जवाब दे देंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जब यहां एक विधायक अपने ही शासन के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ यह बयान दे कि वह मेरे खिलाफ काम कर रही है, गलत कर रही है। सभापति महोदय, इसको कैसा आचरण बोलेंगे ? आपके शासन के लोगों का यह आचरण चल रहा है।

श्री रिकेश सेन :- माननीय सभापति महोदय, आपके विधायक तो रेट लिस्ट।

श्री उमेश पटेल :- हो गया ना।

श्री रिकेश सेन :- नहीं, कैसे हो गया ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, आप इनको जवाब देने के लिये समय दे दीजियेगा।

श्री रिकेश सेन :- बिलासपुर में रेट लिस्ट लगायी गयी थी कि टी.आई. की कीमत कितनी होगी और सी.एस.पी. की कीमत कितनी होगी। ऐसा आपके विधायक ने कहा था।

सभापति महोदय :- रिकेश जी, बैठिये।

श्री उमेश पटेल :- हो गया ? माननीय सभापति महोदय, अजय जी कई बार बोलते हैं कि यह मंत्री रहा, वह मंत्री रहा। जब वह मंत्री थे, तब मैं और दलेश्वर साहू जी विधायक थे। दलेश्वर जी बता सकते हैं। यह पंचायत मंत्री थे। हम लोगों के पास दलाल लोग आते थे कि आप बस चिट्ठी लिख दीजिये, आपका 10 प्रतिशत में काम होगा। यह कहते थे। यह ऐसे ही बड़े-बड़े आरोप लगाते हैं। मैं बता रहा हूं। जितने विधायक उस समय थे, वह सब बता सकते हैं। ऐसी तो कार्रवाई हुई है। सभापति महोदय, मैं इन सब में नहीं जाना चाहता था, चूंकि यह बार-बार आरोप लगाते हैं, इसलिए मैंने यह सब कहा।

सभापति महोदय :- आप विनियोग पर आईये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, जी हां बिल्कुल। पुलिस विभाग की बात करते हैं। पुलिस का काम है सुरक्षा देना, इंटेलिजेंस गैदर करना और कोई बड़ी कार्रवाई को रोकना। आज पुलिस इन सब में फैल है। माननीय सभापति महोदय, सबसे खराब बात यह है कि हमारे गृहमंत्री जी के जिले में सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। चाहे साहू जी की मौत होना, उसके बाद गांव में बवाल होना, फिर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की मौत होना, फिर एक व्यक्ति की घर में जिंदा जला देने की बात होना, यह प्रकरण हैं। सभापति महोदय, कवर्धा में एक सीरिज ऑफ क्राईम होता गया। आप निकालकर देख लीजिये कि पिछले 6 महीने में क्या-क्या हुआ है। कवर्धा में लगातार क्राईम होता गया और पुलिस उसे रोकने में पूरी तरीके से अक्षम रही। माननीय सभापति महोदय, शासन-प्रशासन के एस.डी.एम., कलेक्टर के साथ घटनाएं हो

रही हैं। लोग एस.डी.एम. को मारने के लिये दौड़ेंगे ? जशपुर में एक एडिशनल एस.पी. को महिलाएं मार रही है। हमने छत्तीसगढ़ में यह स्थिति देखी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस को यह शासन कार्यकर्ता के रूप मे उपयोग कर रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? माननीय सभापति महोदय, हमने विडियो में देखा, यह सारी चीजें न्यूज में वायरल हुई थी। कवर्धा जिले में एक स्टेशन की बात है। वहां थाने के सामने डी.जे. बज रहा था। पुलिस वाले उस डी.जे. और नाच गाने को रोकने गये तो वहां झगड़ा झंझट हुआ। उसके बाद उस जिले का भाजपा जिलाध्यक्ष पुलिस थाना आता है और वहीं से किसी मंत्री को फोन लगाता है और तुरंत टी.आई. और सिपाही का ट्रांसफर हो जाता है और एक को निलंबित कर दिया जाता है। सभापति महोदय, इससे पुलिस का क्या मनोबल बढ़ेगा ? पुलिस की वर्दी की जो धमक है, वह तो समाप्त हो गयी। आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे और जब आपको पुलिस को मजबूत करने की मंशा ही नहीं है तो हम लोग ऐसे में पुलिस को पैसे क्यों दें ? लॉ एण्ड ऑर्डर इस सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी काम अलग है। माननीय सभापति महोदय, कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। आपके दो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें एक महतारी वंदन योजना और एक प्रधानमंत्री आवास योजना है। महतारी वंदन योजना में इसी सत्र में माननीय मंत्री जी का उत्तर आता है कि बस्तर में बॉलीवुड के किसी प्रसिद्ध अभिनेत्री के नाम से महतारी वंदन योजना से राशि निकल रही है। मैंने बार-बार पूछा कि महतारी वंदन योजना में यह हो सकता है कि ऐसे प्रकरण और हो। क्या आपने इसमें जांच की है? इसमें जांच नहीं हुई है। मैं यह आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ कि आपने यह जबरदस्ती कर दिया। वह कुछ न कुछ त्रुटि हो गई होगी, यह हुआ होगा क्योंकि सबने अपने हिसाब से फार्म भरा है, लेकिन जब यह विषय संज्ञान में आ गया तो यह संज्ञान में आने के बाद यह जरूरी नहीं था कि यह सरकार उसकी Thoroughly जांच कराये। इसमें पता तो चलें कि जो हितग्राही हैं उसमें कितने लोग सही हैं या गलत है? इसमें जांच ही नहीं हुई है। जब कोई बड़ी चीज निकलेगी तभी जांच होगी। यह तो जांच का विषय था। इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जब तक आप उसको पूरी तरीके से जांच नहीं करायेंगे, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, यह कितनी राशि का हो रहा है, यह आपको नहीं पता चलेगा। मैं फिर से यह कहूंगा कि यह सरकार गलत कर रही है। यह सरकार किन लोगों के साथ यह गलत कर रही है। यहां की परित्यकताओं, बुजुर्ग महिलाओं, विधवा महिलाओं के साथ गलत कर रही है। विधवा महिलाओं को पेंशन का 500 रूपये मिलता है और महतारी वंदन योजना से 500 रूपये काट दिया जाता है, वह बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें पेंशन की सर्वाधिक आवयश्यकता है, वह बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें सेवा की आवश्यकता है जिनको सरकार की उपस्थिति और हाथ की जरूरत है। उन लोगों के साथ यह सरकार धोखा कर रही है इसलिए मैं यह कहता हूँ कि यह जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट महतारी वंदन योजना है। यह पूरी तरीके से अधूरा है जब तक उन बुजुर्ग महिलाओं को सही से पैसा नहीं मिलेगा तो इनकी यह महतारी वंदन

योजना पर्याप्त नहीं है। न यह इसमें जांच कर रहे हैं। न उन बुजुर्ग महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। आप उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं। आप फिर से माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिएगा। उन्होंने यह माना है कि हम उन्हें अंतर की राशि को दे रहे हैं। यह अंतर की राशि मतलब पेंशन की राशि प्लस 500 रूपये महतारी वंदन योजना का है। आप उनकी आधी राशि काट रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री आवास पर कहना चाहूंगा। प्रधान मंत्री आवास योजना में 18 लाख रूपये का पोस्टर लगता है। इस शासन ने कितना दिया है ? मेरे ख्याल से 6 लाख, 7 लाख रूपये के आसपास दिया है। इसमें 6 लाख, 7 लाख रूपये के आसपास स्वीकृति हुई है। ठीक है, यह बढ़िया है। इसमें प्रधान मंत्री आवास योजना में जो मेरी समझ है, मैंने वहां इंजीनियर से बात की, मैंने वहां हितग्राहियों से बात की। राजेश भईया, आज के दिन में 1 लाख 20 हजार रूपये में घर नहीं बन रहा है। अगर आप 30 X 30 का लेंगे, एक साधारण ड्राईंग बनायेंगे तब भी 1 लाख 20 हजार रूपये में घर नहीं बन रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय उमेश भाई, प्रधान मंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को सरकार एक मुश्त पैसा दे रही है। आप मजदूरी कर सकते हैं। आप अपना पैसा भी लगा सकते हैं। जब अपना खुद का अंश लगाकर, लोगों ने अच्छे-अच्छे मकान बनाये, ऐसा नहीं है। आप यह सोचिये कि हम कम से कम 1 लाख 20 हजार रूपये नहीं, इसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो लाख और समथिंग पैसा जा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- नहीं। वह आपके शहरी क्षेत्र का है। मैं शहरी क्षेत्र का नहीं बोल रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रूपये में मिल रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय,25 हजार रूपये अर्थात्।

श्री उमेश पटेल :- सर, मैं यह मान गया।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, यह पहले 25 हजार रूपये था।

सभापति महोदय :- माननीय मूणत जी, आप बैठिए।

श्री उमेश पटेल :- अरे भईया, अगर आप इस तरह से इनफ्लेशन की बात करेंगे तो हम चलते हैं उस समय वर्ष 1947 में क्या था ? एक आना बराबर आज का एक लाख रूपये हो गया। अगर आप वैसा करेंगे और इनफ्लेशन को एडजस्ट करके बात करेंगे तो ..।

सभापति महोदय :- माननीय द्वारिकाधीश जी, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं है।

सभापति महोदय :- आप इसमें नाम नहीं है तो उनको नाम देना चाहिए था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने जितनी देर मुझे रोका मैं उतनी देर में अपनी बात कहकर बैठ जाता। सभापति महोदय :- उमेश जी, आपको 20 मिनट से ज्यादा हो गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संक्षेप में समाप्त करें।

उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी से।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। माननीय राजेश मूणत जी, आप लोक निर्माण मंत्री रहे हैं। इसमें एस.ओ.आर. बढ़ जाता है। जब से प्रधान मंत्री आवास योजना चालू हुई है, यह गरीबों का बढ़े, हम यह चाह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, का हो गये। उमेश जी, एक गूड न्यूज बता देता हूं, अभी आप गरिमा की बात रहे थे न, अभी बीजापुर में 18 नक्सली एनकाउंटर में मारे गये हैं।

सभापति महोदय :- अजय जी, उसको आप अलग से बता दीजियेगा।

श्री उमेश पटेल :- मैं मीडिया में बधाई दे चुका हूं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- 22 हो गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, 22 हो गये।

श्री उमेश पटेल :- आपको शायद नहीं पता मैं आलरेडी मीडिया में बधाई देकर आ गया हूं। आप पीछे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समझ रहे हैं, यह शासन है। अजीत जोगी जिंदाबाद वाला शासन नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- आप पीछे हैं, मैं बधाई दे चुका हूं। आप मीडिया में बाईट देख लीजियेगा। जो अच्छा काम करेंगे, उसके लिए बिल्कुल बधाई मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बधाई दीजिए न।

श्री उमेश पटेल :- मैं बधाई दे चुका हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां सदन में सुरक्षा बल को बधाई दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- चलिये, सुरक्षा बल को बहुत-बहुत बधाई।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप भी तो गुप्त बात को खुले आम बता रहे हैं। चलिये, आप आगे बढिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि है, वह वाकई में ही कम पड़ रही है। मेरी यह शंका है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरी यह शंका है कि कहीं यह स्थिति ऐसी न बन जाये, पहली किश्त, दूसरी किश्त, तीसरी किश्त इस तरह से पैसा मिलता है। जब आप एक certain level तक घर बना लोगे, तभी आपको किश्त मिलेगी। मेरी यह शंका है कि कहीं पहली किश्त, दूसरी किश्त इतनी कम हो जाये कि आदमी घर से लगाने के बाद भी उस लेवल तक

पहुंचा ही नहीं पाये और बहुत सारे लोगों का घर अधूरा रह जाये। हालांकि आपने एक योजना बनाई है जो जल्दी गृह प्रवेश करेगा उसको प्रोत्साहन देने की बारी है। हो सकता है कि उससे उनको फायदा भी मिले, लेकिन वह शहरी क्षेत्र का है। ऐसी ही योजना ग्रामीण क्षेत्र में भी बनाने की आवश्यकता है। यह मेरी शंका है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे घर छूट जायें। तो जो शहरी क्षेत्र के लिए योजना है, मेरा सुझाव है कि वह योजना ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लागू की जाये।

सभापति महोदय :- उमेश जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रोत्साहन है।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन वाली योजना नहीं है, शहरी क्षेत्रों में है। बजट के बारे में सभी ने मोटा-मोटी बात कर ली है। अजय जी, आखिरी में बोल रहे थे, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं। बजट में हमको दिखता है कि ये काम हो गया, ये काम हो गया और 02 साल तक दिखता ही रह जाता है और 02 साल के बाद वह बजट से गायब हो जाता है। ऐसा मत हो। प्रशासनिक स्वीकृति मिले। सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति की बात नहीं है, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद उस कार्य को प्रारंभ करने की वित्त विभाग की अनुमति भी जल्द से जल्द मिले। यह हो सकता है कि कुछ काम 3 महीने के लिए अटक सकें, कुछ महीने के लिये पैसे में अभी रिसीप्ट में कमी हो गई या पैसे नहीं आ पाये, यह हम लोग समझ रहे हैं। वह 3-4 महीने का हर आदमी समझता है। लेकिन वह दो साल तक बजट में रहते-रहते बजट से ही बाहर निकल जाता है। सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अमर भैया, शायद समर्थन करेंगे। खरसिया में रेलवे ओवरब्रिज 2022 से स्वीकृत है। उसका टेंडर भी हो गया है और पिछले डेढ़ साल से वित्त की अनुमति के लिए रूका हुआ है। मेरे ख्याल से वह ओवरब्रिज खरसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि उसके कारण से आज खरसिया दो हिस्से में बंटा हुआ है। ओवरब्रिज बनते ही दोनों हिस्सा जुड़ जायेगा। कई बार आधा, एक घंटा रूकना पड़ता है। उसमें वित्त की अनुमति तुरंत दी जाये।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति जी, एक भी मंत्री नहीं दिख रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- दयालदास बघेल जी हैं न। अकेले बघेल जी पूरे हैं। हम आपको एक और एक ग्यारह मान रहे हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री बैठे हैं। उमेश जी, समाप्त करेंगे। आप कुछ मांग रहे थे, उस पर बोलकर समाप्त करिये।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मांग नहीं करना है। आप बोलेंगे तो मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि लोकतंत्र में त्रिस्तरीय, लखनलाल देवांगन जी, आप नहीं थे, मैं आज आपके बारे में बोला। आपके खिलाफ षडयंत्र हो रहा है। मंत्री जी, यह षडयंत्र के खिलाफ हम लोग आपके साथ हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- क्या है कि पीछे में जो साथ में चाय पी रहे थे, उसका असर है। देवांगन जी और आप चाय पी रहे थे, उसका असर है।

श्री उमेश पटेल :- देवांगन जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि यह जो लोग आपको मंत्री पद से हटाना चाह रहे हैं।

समय :
3.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- उमेश बाबू एक बात सुनिए । माननीय दयालदास जी अति उदार मंत्री हैं, वे यहां बैठे हैं । आपके पास कोई कागज हो तो दे दीजिये वह तुरंत जांच करवा देंगे । (हंसी) आप भाषण बंद करो ।

श्री उमेश पटेल :- देवांगन जी, मैं आपको यह बता रहा था कि यह जो षड़यंत्र हो रहा है, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है । आपको मंत्री पद से हटाने के लिए यह षड्यंत्र हो रहा है और मैं तो कहता हूं कि शासन के मंत्री के खिलाफ अगर यह षड्यंत्र हो रहा है तो वह एक राजद्रोह हो रहा है और अगर इसमें सच्चाई निकलती है तो इसमें राजद्रोह की धारा लगनी चाहिए और आप इसमें पीछे मत हटिएगा, हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा था कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ । नगर-निगम, नगर पालिका सभी जगह हुआ ।
माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की जहां-जहां सदस्य संख्या ज्यादा थी । चाहे वह अनिला जी के क्षेत्र में हो, चाहे भानुप्रतापपुर में हो, चाहे कई ऐसी जगहों पर जहां पर भी संख्या बल ज्यादा थी । लगातार उसको कैंसिल किया गया, अभी कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल हो रहा है । आज 10 तारीख को गये तो कैंसिल, 12 तारीख को गये तो कैंसिल, 15 तारीख को गये तो कैंसिल । यह क्या है ? आप लोग केवल खरीदी-बिक्री करने के लिए लोकतंत्र को मजबूत कर रहे थे मतलब एक संख्या ज्यादा है, 13 है, वहां ऐसा । माननीय सभापति महोदय, इस लोकतंत्र को भी बचाने की आवश्यकता है अगर इसी तरह से सरकार बनती रही, इसी तरह से यह होता रहा । राजेश जी, मैं आपको इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बता दूं कि इसका कुछ असर नहीं होता है । जो विधानसभा-लोकसभा का चुनाव है न, वह अलग ही पैटर्न में होता है । यह आप भी जानते हैं, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं तो इसके जीत जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता । लेकिन यह हमारे गांव का चुनाव है, लोगों का चुनाव है और हमारे गांव के प्रतिनिधित्व का चुनाव है, हमें इसको बहुत अच्छे ढंग से कराने की आवश्यकता थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है इसलिए मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी भी तरह के रूपये इस विधानसभा से नहीं मिलना चाहिए, मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहत-बहुत

धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री राजेश मूणत जी ।

श्री उमेश पटेल :- भैया, अच्छे से ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी सदन में बोल रहे थे और पिछले पांच वर्षों में अपनी सरकार में रहते हुए इन्होंने हॉर्सट्रेडिंग की एक नई व्यवस्था दी थी और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे । स्थानीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो पिछले 5 साल पूर्व हुआ उसका भी अध्ययन करना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय । क्या इनका नाम है ? (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- उमेश जी, मैंने आपको टोका नहीं है । मैं आग्रह कर रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- अरे, आप बोल लीजियेगा । अलग से बैठाकर बोल लीजियेगा । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, नगर-निगम चुनाव में पार्षदों के माध्यम से लोकतंत्र की प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को रोककर इन्होंने छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था खड़ी की थी, इन्हें उसको भी तो बोलना चाहिए ।

सभापति महोदय :- चलिये, अब मूणत जी बोलेंगे । राजेश जी आप बोलिए ।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विनियोग के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ नया राज्य के साथ में हम पच्चीसवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं । छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो और इस राज्य की प्रगति-उन्नति के मार्ग में इस सदन के 90 विधायकों का उतना ही योगदान है । लगभग 3 करोड़ की आबादी वाला यह छत्तीसगढ़ दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के अंदर 42 परसेंट के लिए आरक्षित, शहरी पड़ाव से लेकर किसानों पर आधारित यह छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सरकार में विष्णुदेव साय की सरकार में आने के पहले 15 साल डॉ. रमन सिंह की सरकार रही । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से साल के शुभारंभ वर्ष 2025 में यह सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लगातार चरणबद्ध तरीके से योजनाएं बनायी हैं । सरकार ने 1 लाख 49 हज़ार मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और वह सुचारू रूप चली और यही नहीं किसान के खाते में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ठीक करते हुए 1 लाख करोड़ रूपये । यह कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है । कभी इस प्रदेश का बजट हुआ करता था, उतना पैसा वर्ष 2024 और 2025 के अंदर सरकार ने किसानों के खाते में पहुंचाया और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किसानों का उतना ही बड़ा योगदान हुआ है और ये पैसा पूरा मार्केट में आया। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो ट्रैक्टर बिक रहा है, हार्वेस्टर बिक रहा है, गाड़ियां बिक रही हैं। चारों तरफ तरक्की, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसलिए धान का

कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हमारी विष्णु देव साय सरकार ने और ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री ने एक कुशल नेतृत्व के साथ में प्रारंभ किया है, मैं उसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, राजनीति में कई आरोप-प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ आपका अपना है। आप इसको समृद्ध बनायें, इसको खुशहाल बनायें, इस सोच, इस कल्पना को मूर्तरूप देने के लिए विष्णु देव साय की सरकार ने कुछ कड़े कदम भी उठाये हैं और कुछ ऐसी योजना लेकर आयी है, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था का समाधान सब व्यक्ति के साथ में हो सके। सभापति महोदय, किसान को समृद्ध करने के लिए कुछ कार्य की योजनाओं के साथ में हमारी सरकार ने काम प्रारंभ किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कृषि पर आधारित यह प्रदेश, जहां दो तिहाई से ज्यादा 80 प्रतिशत कृषक लोग रहते हैं और धान पर आधारित छत्तीसगढ़ पूरे देश के अंदर चलता है तो इसकी इकोनॉमी के अंदर उसका भी उतना ही योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्नतिशील यह छत्तीसगढ़ आपका अपना है और कृषि के सेक्टर में चाहे हमने सिचाई पंप की बातचीत की हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। अपने आप में एक स्वागत योग्य है। हम गरीब परिवार को बिजली के लिए अब वह 50 प्रतिशत माफ कर दो, यह नहीं, हम सब्सिडी देकर सौर ऊर्जा के साथ में उसके घर में पैनल लगा ले और वहां पर वह अपने आप सरकार की लाइट का उपयोग करे, सरकार उसमें सब्सिडी भी दे रही है। यह दूरदृष्टि है, यह सोच है, यह कल्पना है, जिसको विजन के साथ में बजट में लेकर आना, यह महत्वपूर्ण दृष्टि है और इसलिए मैं इसका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम बहुत राजनीतिक बात करते हैं। जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बातचीत हुई, अजय चंद्राकर जी ने डिटेल में बहुत सारी बातें कीं, मैं उन सब चीजों को नहीं छूना चाहूंगा। लेकिन एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कार्यकारी योजना बनाकर भविष्य की चिंता जरूर करना पड़ती है। उन चिंताओं के ऊपर दूर दृष्टि के साथ में किसी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है तो स्टेट की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से रोडों का जाल बिछाने का काम पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से प्रारंभ किया है, यह कोई छोटा-मोटा विषय नहीं है साहब। अगर आप चिंता करें कि लगभग 22 प्रतिशत का बजट का प्रावधान बढ़ाकर सिंगल लाइन को टू लाइन में कन्वर्ट करना, टू लाइन को फोर लाइन में कन्वर्ट करना, ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय में कन्वर्ट करना, राजधानी को सुव्यवस्थित तरीके से बसाना और शहर के मार्गों को सुगम दृष्टि से ठीक करना, यह अपने आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी एक छोटी सी बात के लिए मेरे सहयोगी साथी उमेश जी सीनियर विधायक बोल रहे थे कि मेरे यहां खरसिया के फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया।

माननीय ओ.पी. चौधरी जी बैठे हैं, यहां पर वित्त के सेक्रेटरी भी बैठे हैं, उमेश भाई, इस सरकार में चिंता मत करिए, बिना मांगे काम पूर्ण होगा, यह सरकार की सोच है, विष्णु देव साय सरकार की गारंटी है। मुझे मालूम है कि यहां पर किस-किस चीज की मांग करते थे, कितनी मांग करते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अभी नेता जी बहुत सारा भाषण देकर गए। जितनी योजनाएं गिनायीं, आपने खुद ने तो कितनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया? आपने तो पैसे का स्वार्थपूर्ण बंटवारा किया है। आपने खेल तो बढ़ावा देने के लिए बातचीत की, छत्तीसगढ़ के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए आपने क्या किया? खेल विभाग के अंदर आप देखिए, 5 साल के अंदर जो टैलेंटेड बच्चे थे, उन बच्चों की कभी आपने चिंता नहीं की। आपने कभी पुरस्कार वितरण नहीं किया। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। क्यों भैया? आप 5 साल क्या करते रहे? क्या उनका हक नहीं था? कोई ओलंपिक के अंदर जीतकर आ रहा है, उसका हक नहीं था? कोई ओलंपिक में जीतकर आ रहा है, क्या उनका हक़ नहीं था ? वह वहां से सर्टीफिकेट लेकर घूम रहा था कि मुझे कब यहां पर नौकरी का मौका मिलेगा । पांच साल के अंदर खेल अलंकरण नहीं हो पाया, पूरे पांच साल । यह चिंतन का विषय है कि बड़ी-बड़ी बात करने वाले पांच साल अलंकरण नहीं दे पाए । राजीव मितान योजना, क्या थी राजीव मितान योजना ? आपने मोहल्ले के अंदर एनएसयूआई और युवक कांग्रेस के लोगों का क्लब बना दिया और अपने नेताओं को 25-25 हजार का चेक बांट दिया । उन्होंने क्या किया था, उनकी क्या उपलब्धि थी ? रायपुर शहर में एक कार्यक्रम किया जिसमें आपके युवराज पधारे, 3 करोड़ रूपए की टी-शर्ट, उनके 3 करोड़ रूपए के जैकेट, बिना टेंडर की खरीदी किसने की ? पांच साल में युवा ओलंपिक के लोगों को आपने प्रोत्साहन नहीं दिया । मैंने इसी सदन में बात उठाई, उनके चेयरमेन ने पूरी की पूरी टी-शर्ट खरीद ली, आर्डर दे दिया, चेक कर लिया, वर्क ऑर्डर इशू कर दिया लेकिन उस खाते में पेमेंट नहीं है, टेंडर तक नहीं किया । बिना टेंडर के माल की पूर्ति भी हो गई, वह आदमी दर-दर भटक रहा है, केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए, राजीव जी के नाम पर, वे बहुत श्रद्धेय नेता थे, वह नेता खुलकर बोलता था, उसका नाम बदनाम करने के पहले सोच तो लिया होता कि उसके नाम की टी-शर्ट हम छपा रहे हैं, कम से कम उसका पेमेंट तो कर दिया होता । केवल नाम के लिए काम करते हैं । यही एक चिंता का विषय रहा।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत सारे साथी महतारी वंदन के विषय में बोलते हैं, हमारी बहनें अनेक अवसरों पर इस नाम से बहिर्गमन करके चली जाती हैं । आपने भी तो घोषणा की थी, आप अपना पुराना जनघोषणा पत्र पढ़ लो, आपने कहा था 500 रूपए देंगे । उसमें कई चीजें पढ़ लो । ठीक है, कुछ कमीबेशी है, कुछ बात रखना है । विधायक होने के नाते अपनी जन समस्या को रखने के लिए यह सदन सबसे बड़ा स्थान है । लेकिन सदन में विषय रखना और उस विषय पर चर्चा करना, यह हर विधायक का कर्तव्य बनता है लेकिन आप हमेशा एक ही बात करते हैं । 300, 500 रूपए लेने के लिए बहनों को कितनी लम्बी लाईन लगानी पड़ती थी । सर्वे सूची में नाम खोजना

पड़ता था । उन बहनों के लिए कहीं उनका निराश्रित पेंशन बन जाए, विधवा पेंशन बन जाए, उस बहन के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की, अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने चिंता की । 70 लाख परिवार की बहनों को बिचौलियों को खत्म करके, उनके खाते में 1000 रूपए देकर, साल के 12 हजार रूपए उनको दे रहे हैं ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- सभापति जी, महतारी वंदन में से पेंशन की राशि काटकर ही दे रहे हैं, आप भी ।

श्री राजेश मूणत :- अरे सुन तो लो बहिनी । आपकी सरकार ने भी 500 की घोषणा की थी लेकिन कुछ नहीं किया ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- अभी तो आपकी सरकार है ।

श्री राजेश मूणत :- हमारी सरकार है हम करेंगे, आप चिंता मत करो ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- कब करोगे, अभी तो आपकी सरकार है, करो ना ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति जी, मैंने पहले ही कहा कि 300, 500 रूपए की पेंशन के लिए उस समय बहनें भटकती थीं, उस समय क्या करते थे ? देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश में राज किया । गरीबों का नारा लगाती रही लेकिन गरीबों की चिंता नहीं की । अभी उमेश भाई चिंता कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी होना चाहिए । यह सरकार सुझावों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है । लेकिन आप लोगों ने तो गरीबों का पूरा हक़ छीन लिया था । उन गरीबों की इस लिए चिंता नहीं की कि प्रधानमंत्री आवास योजना, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ? अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा कि इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उन्होंने राजनीति नहीं की है, आप तो गांधी नेहरू परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाए, सिर्फ उनके नाम की योजनाएं चलाए । क्या फर्क पड़ता है ? छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे जिनके नाम पर वोट मांगकर यहां आए हो, गांव, गली, मोहल्ले में घूमकर उनकी बात करते थे, लेकिन पांच साल उनको वंचित क्यों रखा । क्यों, गरीब परिवार का हक़ नहीं था क्या कि उस गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले ? कांग्रेस का उद्देश्य केवल वोट की राजनीति करना रहा है और राजनीति की दिशा में..।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप हमारे उपर सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं कि हमने गरीबों का आवास नहीं दिया। उसको आपकी दिल्ली की सरकार ने रोका है, यही सच है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट-एक मिनट। किसने रोका, किसने नहीं रोका, आप लोग इसमें मत पड़ों। आपको जनता ने यहां आने से रोक दिया, आपको वहां बैठाया न। (मेजों की थपथपाहट) आप साल दो साल थोड़ा तसल्ली से बैठिए, सरकार को काम करने दीजिए। आप तो पहले ही सत्र से सरकार

ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है बोल रहे हो, ऐसा करोगे तो बंगाल जैसा हाल होगा या दिल्ली जैसे जीरो में रहोगे। यहां आप लोगों को नॉमिनेट करना पड़ जाएगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने भी कहा था, आप भी इधर आए थे, हम तो 35 आए हैं। धर्मजीत भैया, 15 साल की हुकूमत के बाद 15 थे 15. आपकी ही भाषा बोल रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमने जनादेश को स्वीकारा, हमारी सरकार बन गई। आप लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से सोचिए। (व्यवधान) पहले सरकार को काम करने दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- विनियोग में बात हो रही है, ये बातें आनी चाहिए न। हमारे राजेश भैया ने आवास की बात की है, आप पिछले सत्र का देख लीजिए, केवल 6 आवास के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। आपने 10-10 लाख की बात की है।

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, एक मिनट। जैसे कल सुनीता विलियम्स का 18 हजार किलोमीटर की स्पीड से प्लेन आया, उसी तरीके से सांय-सांय सरकार काम कर रही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एलन मस्क को धन्यवाद दीजिए। आपकी लापरवाही के कारण सुनीता विलियम्स वहां 9 महीने अटकी रही।

सभापति महोदय :- मूणत जी, विनियोग पर आईए।

श्री राजेश मूणत :- हमको यहीं रहना है। माननीय सभापति महोदय, मैं विनियोग पर ही बोल रहा हूं, जिन लोगों को विनियोग पर बोलना था, वे आरोप-प्रत्यारोप लगाकर चले गये, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्या हुआ ? चलिए मैं उदाहरण देता हूं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, आप रायपुर शहर घूम लीजिए, आप लोगों ने भूमिपूजन किया, बजट में प्रावधान नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, भूमिपूजन की बात आई, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। गुंडरदेही विधान सभा में भूमिपूजन हुआ, प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी, आपके सांसद थे, मैं भी था, उस पैसे को वित्त विभाग ने वापस मंगा लिया, उसका क्या हुआ ?

श्री राजेश मूणत :- अभी रूकिए, साहब, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जिसमें आप और हम सब रहते हैं। लोग आएंगे, चले जाएंगे, पार्टी आएगी, चली जाएगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रहेगी और रायपुर रहेगा तो रायपुर की उन्नति, तरक्की और प्रगति के मार्ग को आगे पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता को केवल रायपुर से मतलब नहीं है। जशपुर वालों को जशपुर से मतलब है, बस्तर वाले को बस्तर से मतलब है, अंबिकापुर वालों को अंबिकापुर से मतलब है, भिलाई वालों को भिलाई से मतलब है, आप केवल रायपुर की बात मत करिए।

श्री राजेश मूणत :- 5 साल रायपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। खाली बात करना, भाषण देना अच्छा लगता है, कांग्रेस पार्टी रायपुर शहर में रह करके पूर्व महापौर से ले करके, एक काम नहीं कर पाए, आप रायपुर राजधानी की क्या बात करते हैं ? नया रायपुर, फोटो छपाना अच्छा लगता है, चांद सुहाना लगता है। वाह भई वाह। नया रायपुर 21वीं सदी का है। उस शहर को बर्बाद कर दिया, 5 सालों के अंदर क्या किया ? मंत्रालय की बिल्डिंग का पूरा सत्यानाश करके रख दिया। वह छत्तीसगढ़ की धरोहर है, आप और हम रहे या न रहें, नया रायपुर है। मेरे बाप सोनिया गांधी जी ने भूमिपूजन किया था, आप लोग 5 साल तक उसकी भी लॉज नहीं रखे, क्या बात करोगे ? (शेम शेम की आवाज) पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। मैं आवास एवं पर्यावरण मंत्री को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने नया रायपुर की सुध ली, नया रायपुर के विकास के लिए एक विजन के साथ, एक योजना के साथ काम करना प्रारंभ किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- मूणत जी, राजनीति में दो प्रकार के नेता होते हैं। एक जबर्दस्त नेता होते हैं, एक जबर्दस्ती नेता होते हैं। हमारे जबर्दस्त नेता यहां बैठे हैं, जबर्दस्ती के नेता आप लोग उधर हो। (हंसी) आप लोगों को जबर्दस्ती नेतागिरी मत करो बोल रहा हूं भाई, नहीं तो टेलीविजन में दिल्ली जैसे जीरो जीरो आएगा अच्छा नहीं लगता, जितने भी हो ठीक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कुछ नेता ऐसे होते हैं जो वहां जबर्दस्ती जाकर नेतागिरी करते हैं। ऐसे यहां भी हैं।

सभापति महोदय :- चलिए मूणत जी।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, जब नया रायपुर की बातचीत करता हूं तो एक विजन है, कल्पना है। 21वीं सदी का नया रायपुर है। जहां हम जाकर देखते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं, आप कल्पना करिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी भी वक्त है, अगर आप लोग आओगे तो हम विचार कर लेंगे आ जाईए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- खून में गद्दारी नहीं है। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- बाबू, गद्दारी की परिभाषा अलग-अलग होती है। हम उसके उपर चर्चा न करें तो अच्छा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जो करते हैं, वह जाने।

श्री राजेश मूणत :- मैंने कहा न कि राजनीति में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप औरंगजेब के लिए वफादारी रख रहे हो और उसके बाद गद्दारी का पाठ पढ़ाते हो। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट)

समय :

3.21 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई)

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदया, नया रायपुर एक सोच, एक दृष्टि, एक नया शहर है। जिसकी कल्पना को हम मूर्त रूप देकर उसको साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज वहां पर इस शहर के अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से रेलवे की लाइन बिछ चुकी है, उसके गार्डन का सौदर्यीकरण हो रहा है, आप वहां पर छत्तीसगढ़ के लिए सोचिये और कल्पना कीजिए। आपको भी अवसर मिला था। मैंने आपको इसलिए कहा कि उंगली उठाने से पहले आप यह सोचिये। निफ्ट जैसी संस्था लाकर उसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आने वाले बच्चों का भविष्य बनाने की दृष्टि से चाहे वह फैशन डिजाइनिंग की बातचीत हो, चाहे वह टेक्निकल की बातचीत हो, चाहे वह हमारे कोसा की साड़ी, चद्दर व किसी की भी डिजाइनिंग करने की बात हो, यदि वहां पर उसका कोर्स प्रारंभ होगा तो उससे छत्तीसगढ़ के बच्चे ही आगे बढ़ेंगे और कहां के बढ़ेंगे? (मेजों की थपथपाहट) यह विजन है, यह सोच है। आपने कहा कि हम एक ऐसा एम.ओ.यू. चलायेंगे, रायपुर में मेट्रो चलायेंगे। मैंने भी उस पर आश्चर्य किया। समाचार पत्रों में सुर्खियों में छपा कि रायपुर से मेट्रो चलेगी। मैंने कहा कि कौन चलाएगा? रायपुर के मेयर साहब घूमने चले गये। किसी के पर्सनल निमंत्रण में वहां पर एम.ओ.यू. खोल दिया गया। हम लोग आश्चर्यचकित हो गये। हम लोगों ने शासन-प्रशासन से पूछा, नगरीय प्रशासन विभाग से पूछा कि क्या सरकार ने ऐसा कोई एम.ओ.यू. किया है कि रायपुर में मेट्रो चलाने के लिए वहां से कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है? बिना निमंत्रण के आप किसी कॉन्फ्रेन्स में चले गये और आपने एम.ओ.यू. भी कर लिया। एक कागज की कोई वेल्यू ही नहीं है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो चलेगी तो कौन चलायेगा? किसने सर्वे किया? कौन लैण्ड इक्वेशन करेगा? फण्डिंग कहां से आएगा? आपको किस चीज की चिंता है? केवल चाल सुहाना लगता है और नेता के आगे गुलाब की पंखुड़ियां बिछती हैं। यह क्या है? आप यह सोचिये। सभापति महोदय, इसीलिए मैं भविष्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप रायपुर से लेकर राजनांदगांव तक मेट्रो की योजना लेकर आये और उसके सर्वे के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां आपके, मेरे व सबके लिए एक दूरदृष्टि के साथ काम करेंगी। हमारी यह सोच है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री रहे हैं, वह क्या करते थे? मैं आपको कितने उदाहरण दूं? आप नगर पालिका, नगर निगम के लोगों से पूछिये कि कैसे स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदरबांट किया गया। न दूरदृष्टि, न सोच, न कल्पना, न विजन था। पैसे का बंदरबांट कैसे हो, कार्य योजना के विरूद्ध जाकर

काम कैसे करे। आपने अपनी धर्मपत्नी के लिए सोसायटी के अंदर एक बढ़िया सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लिया और बिना स्वीकृति के उसमें ढाई करोड़ रूपये खर्च कर दिये। गजब। वही नहीं, जो आपके व मेरे घर में आधुनिक फर्नीचर नहीं होगा, वहां पर वह फर्नीचर लग गया। उसके अंदर क्या-क्या नहीं लगा? शानदार सोफा, 76 इंच स्क्रीन की 4 बड़ी-बड़ी LED TV लगी। वह आज तक विधायक निवास में भी नहीं लगी होगी। बढ़िया फर्नीचर व मॉड्यूलर कीचन बना। अंधा बांटे रेवड़ी, चुन-चुन के दे। आपकी क्या सोच थी, क्या विजन था? राजधानी के विकास के लिए 800 करोड़ रूपये मिले। आप रायपुर में घूमकर मुझे एक काम बता दीजिए कि 800 करोड़ रूपये का जनहित के अंदर उपयोग हुआ हो। स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदरबांट किया गया। आप जिस भवन में बैठ रहे हैं, वह भाजपा की सरकार की देन है। ऑडिटोरियम भाजपा सरकार की देन है। इंडोर स्टेडियम भाजपा सरकार की देन है। आप यहां आरोप लगाते हैं कि दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कैसे बना है? आज मैं इस बात को गर्व के साथ कहता हूं कि ''हमने बनाया है, हमने ही संवारा''। (मेजों की थपथपाहट) मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं होता है।

श्री रामकुमार यादव :- आपमन जे देश मा हवो, ओ देश ला आजाद कराने वाला कांग्रेस पार्टी अउ हमर पुर्खा हे। जेन देश में लोकतंत्र में हवो, ओखर कानून बनाने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अउ महात्मा गांधी जी हें। न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी। हमन अगर ए देश ला आजाद नहीं करातेन ता आपमन मंत्री कहां बनतेव। ए देश ला आजाद कराने वाला कांग्रेस पार्टी हे। ए बात ला आप याद रखिहुं। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- कांग्रेस पार्टी नहीं कराई है। यह देश आजाद हुआ है। जातिगत वोट के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम लेना बंद कर दो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- क्या बात कर रहो हो। तुम तो उस जमाने के लोग हो, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, देश का बर्बाद किया। अपनी रोजी-रोटी सेंकने के लिए जाति और समाज में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज बात करते हो।

श्री राम कुमार यादव :- बांटने वाला कोन ए, पूरा देश अउ विश्व जान गय हे। सब जान गय हे कि कोन पार्टी बांटने वाला हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, जाति और समाज को बांटने की बात बोले हैं। आप लोग जो सार्वजनिक स्थल पर नारा देते हो।

श्री राजेश मूणत :- क्या देते हैं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जो हिन्दू-मुस्लिम की बात करते हैं।

श्री राजेश मूणत :- हम कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बंटे रहोगे तो दूसरे राज करेंगे। (व्यवधान)

श्री राम कुमार यादव :- हम दो, हमारे दो।

एक माननीय सदस्य :- आप अपने बड़े नेता को समझाईये, काम पूछकर चाय पीते हैं।

श्री राम कुमार यादव :- क्या बात करत हो, यह देश आजाद नहीं होता तो आप मंत्री नहीं बनते।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- अहाहा। सही बात है भाई, गांधी जी बोलकर गये थे कि अब कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भंग नहीं किया तो कब तक उसके नाम की रोटी सेकोगे ? इसीलिए भरोसा टूटा, विश्वास टूटा, लोकतन्त्र के चारों चक्कें फिट हो जाते हैं, तो कईयों को तकलीफ होना स्वाभाविक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, यह वही कांग्रेस पार्टी है, जिसने अटल जी और आडवानी जी को सम्मान दिया। आज ये उनके नाम का खा रहे हैं और आज उनकी स्थिति देखिये, क्या स्थिति है ?

श्री सुशांत शुक्ला :- सीताराम येचुरी जी, नरसिम्हाराव जी।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, कृपया बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैंने कहा न कि मैं उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहता हूं, मित्र। मैं आज एक समाचार-पत्र में पढ़ा हूं। मैं इस सदन में 3-4 बार कह चुका हूं। आज फिर पूरी कांग्रेस पार्टी से आग्रह करता हूं, खासकर के बस्तर के पूरा नेताओं से आग्रह करता हूं। आज के समाचार-पत्र में फिर वही समाचार छपा है। जगदलपुर के अंदर झीरमघाटी के शहीद हमारे नेताओं का चित्रण, वह स्मारक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। एक समाचार के मुख्य पेज में छपा है। आपने वहां भी नहीं छोड़ा है। वह छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे, वह मेरी आपकी पार्टी से ऊपर उठते थे। वे एक घटना में शहीद हो गए, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों को वंदन करता हूं। वाह रे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, उनके नाम पर स्मारक बनाये और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया। (शेम-शेम की आवाजें) पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव में देखते-देखते, वहां जगदलपुर में मेरा भाई बैठा है, मैं जब वहां पहली बार यात्रा में गया था तो मैं कहकर आया था कि क्या किए हो भाई, कम से कम यहां तो छोड़ देते। इसीलिए मैंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप पर न चले, तो अच्छा है। आपने क्या किया है ? 5 साल पहले सड़क विकास निगम का गठन किया। आपपे एक्सप्रेस हाइवे 3 साल बंद करके रखा और क्या किया ? आप लोग रायपुर में राजधानी की दृष्टि से सिंगल काम नहीं खड़ा कर पाये, न यातायात को सुगम कर पाये। कमल विहार जैसी योजना लेकर आते है तो शहर का डेवलपमेंट होता। जब शहर चारो तरफ बस जाता है, कहां से रोड आयेगी, कहां नाली होगा, कहां से पीने का पानी आयेगा, कौन पहुंचायेगा। वह एक

योजनाबद्ध तरीके से अच्छी सड़क निर्माण करने की बात चलती है तो वहां भ्रष्टाचार की बात आती है। दूरदृष्टि नहीं है, न आपकी सोच है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब विजन के साथ काम करना पड़ेगा तो आलोचना करने वाले करते रहें, हम तो विजन के साथ काम करेंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, सबके साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही भा.ज.पा. की पहचान है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, ..।

श्री राजेश मूणत :- आपका भी नंबर आयेगा तो बोलियेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मेरा नाम नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- नाम नहीं है क्या ? मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि आपका भाषण हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी एक प्रश्न लगा था।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप बार-बार बीच में मत बोलिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लेगशीप योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो खुले आम भ्रष्टाचार हुआ है, इसके बारे में भी बात कर दीजिये। केवल बालोद जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 53 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी प्रदेश का छोड़ दीजिये।

श्री राम कुमार यादव :- मूणत भईया, आप बढिया बोलत ह। आपके भाषण बहुत अच्छा लगत हे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के काम लच्छेदार भाषण देना काम हे। काम करना, नइ करना, अलग बात हे। तु ओ समय रायपुर मा आडा-बाड़ा बनाय हा, मरीन ड्राइव, ओ ऊपर मा आड़ा-बाड़ा कस बनाय ह, मैं आज तक नइ समझ पाय कि येमा आदमी रेंगही, गाड़ी चगही, कुकुर-बिलाइ रेंगही, आज तक समझ नइ आईस। तुंहर हाथ जोड़त ओ समस्या ला खतम करा। मैं नइ जानव स्काई वाक में का रेंगही, भूत-प्रेत रेंगही, गाड़ी-घोड़ा रेंगही या कुत्ता-बिल्ली रेंगही, लेकिन आप समस्या ल दूर करौ।

श्री राजेश मूणत :- जय सियाराम, जय यादव, जय माधव। और किसी को कुछ कहना है तो सब बोलिये, फिर मैं बोलूंगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट। रामकुमार जी, पिछले पांच साल आपकी सरकार रही है, उसमें भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। जैसे ही आपकी सरकार बनी तो उन्होंने दो चीजों की घोषणा की। उन्होंने एक बिलासपुर का सिवरेज के मामले में और दूसरा रायपुर का स्काई वॉक के मामले में एक समिति गठन किया, उसके बाद में उसका पांच साल तक कोई निर्णय नहीं कर पाये। उन्होंने उस समिति का जिसको अध्यक्ष बनाया था, वह समय जो विधायक थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसका आपको जानकारी है? उसमें आपको क्या जानकारी है?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन डेढ़ साल म काय कर दारे हौ?

श्री धरमलाल कौशिक :- स्काई वॉक वाले समिति में आपके एक विधायक उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन डेढ़ साल म काय कर दारे हौ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि जो स्काई वॉक बना रहे हैं वह सही है और वह बनना चाहिए। आपके ही विधायक ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- समस्या को आप लोग पैदा करें और उसको हल हम लोग करें और आप लोग सिर्फ मलाई खायें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार में मेरे ही सीट पर श्री सत्यनारायण शर्मा जी बैठा करते थे। वे सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उनकी अध्यक्षता में दो कमेटी बनी थी। स्काई वॉक के लिए एक कमेटी बनी थी और शराब कैसे बंद करना है, उसके लिए उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करना था। वह अध्ययन करते-करते अभी घर में अध्ययन कर रहे हैं और वह अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दिये हैं कि शराब कैसे बंद करना है?

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सब ब्रांड का टेस्ट भी करना था।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ, उसमें टेस्ट करने का भी एक नियम था। वह पीते नहीं हैं तो आदमी टेस्ट करा कर दखने ले जाते थे। आप लोग ऐसा कमेटी बनाकर जनता को कब तक दिग्भ्रमित करेंगे? कुल मिलाकर हमको अच्छा लगेगा तो बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो तोड़वा देंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमको अच्छा लगेगा तो हम दारू बंद करेंगे और हमको अच्छा नहीं लगेगा तो दारू बंद नहीं करेंगे। आपको क्या कहना है? हम लोग गंगाजल उठाकर कसम तो नहीं खाये हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कुछ नहीं कहना है, आने वाला समय कहेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह हमारे ऊपर छोड़िये, हमको जो अच्छा दिखेगा, वह हम करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ये धरती म बड़े से बड़े पहलवान जन्म ले हे। राजा कंश, रावण, कुंभकरण जन्म ले हे, ओखर घमंड नई टूटिस त तुमन अऊ हमन कोन होवत हन, साहेब। यह शरीर के भरोसा नई रहय त घमंड के का भरोसा रही? आप चिंत मत करौ, तुमन आने वाला समय जरूर बता दिही।

श्री रामविचार नेताम :- भाई, मैं तोर से एक बात पूछत हौं। सभापति जी, मैं रामकुमार जी की बहुत चिंता करता हूं, लेकिन उनसे यह पूछना चाहता हूं कि माननीय धर्मजीत सिंह जी उस दिन बता रहे थे कि आप हर तीन महीने में इंजेक्शन लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वो वाला विभाग है। (हंसी) क्या वह सही बात है?

श्री रामकुमार यादव :- मुख्यमंत्री जी हर मोर गुरू बबा हे। मोर बारे में ओला कुछ भी भड़का हौ ता ओ हर नई भड़कय। ओ हर मोर गुरू बबा हे। आप भोरहा म मत रइहौ।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय सभापति महोदय, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो नेता लोग नहीं हैं उनको भी आप लोग बताईयेगा कि आज मूणत जी फिर इस हाऊस में बोले। स्काई वॉक को

लेकर मन में जो कंफ्यूजन था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को एक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आवेदन देता है, उसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी लिखते हैं कि रिपोर्ट दर्ज की जाये। वह वहां से मेरे पास 10 मिनट बाद ही आ जाता है। मैंने उनसे कहा कि यदि नैतिकता है और वाकई में वह दमदार नेता है तो मैं मांग करता हूं कि कोई भी रिटायर्ड जज से स्काई वॉक की जांच करा लें। फिर मैंने कहा कि आपके पास पूरे पी.डब्ल्यू.डी. की फाईलें होंगी? जो मेरा पी.एस. रहा है, वह आपका सी.एस. है, ई.इन.सी. भी वही हैं, आप जांच कर लीजिये तो उन्होंने लिखा कि ई.ओ.डब्ल्यू. जांच करेगी। ई.ओ.डब्ल्यू. जांच किया और ई.ओ.डब्ल्यू. ने क्लीन चीट दे दी कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आपकी सरकार के समय 3 कमेटियां बनीं। एक कमेटी नहीं, 3 कमेटियां बनीं। एक इंजीनियर की कमेटी, एक सर्वे की कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी, इन तीनों कमेटियों ने सर्वे को सही और उसके ऊपर निर्णय किया, उसके बाद भी कुछ बचा हो तो कांग्रेस विधायक दल की एक कमेटी बना लो । सभापति महोदय, राजनीति करता हूँ, शुचिता की राजनीति करता हूँ, दमदारी से राजनीति करता हूँ, पीठ के नीचे वार करके राजनीति नहीं करता हूँ, यह ध्यान रखना । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ और लिखित में देता हूँ कि मैं राजनीति करने आया हूँ, जिसकी अध्यक्षता में चाहते हो, जांच कर लो । यदि आप में नैतिकता है तो जांच कर लो । सभापति महोदय, मैं कहता हूँ कि विधायकों की जांच कमेटी बना दो, कांग्रेस में ताकत है, मैं मांग करता हूँ । सभापति महोदय, अवैध दारू, फर्जी दारू, एक दुकान में दो गल्ला, अवैध दारू का वितरण, अवैध होलोग्राम, यदि ताकत है तो विधायक दल से जांच की मांग करो, क्या नैतिकता की बात करेंगे ...।

श्री रामकुमार यादव :- ताकत तो बहुत हे साहब, कांग्रेस ला ललकारौ मत तुम, बहुत ताकत हे । आपके द्वारा इस प्रकार से ललकारना अच्छी बात थोड़ी हे । आप कांग्रेस के ताकत देखे नइ हव । जहां दुनिया हार जाती है वहां कांग्रेस खड़ा होता है ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी ।

श्री दलेश्वर साहू :- आपकी इतनी बढ़िया योग्यता है तो पार्टी ने आपका ख्याल क्यों नहीं किया, इतने सीनियर मंत्री थे और किसी विभाग में बिठा देते ?

श्री राजेश मूणत :- कोई बात नहीं, आपने प्रशंसा की है, उसके लिये धन्यवाद। आप तो हमारे पुराने साथी हो । विधान सभा आपकी रहती है और लोक सभा में सहयोग करते हो । (मेजों की थपथपाहट) सब तो अपने ही भाई हैं । सभापति महोदय, मैंने कहा कि मैं आरोप-प्रत्यारोप पर नहीं जाऊंगा । जब, आरोप-प्रत्यारोप में जाऊंगा तो अच्छे से बात करूंगा । आपने स्काई वॉक के बारे में जानकारी चाही है तो मैंने उसका उत्तर दिया, लेकिन एक विजन के साथ में कोई अच्छा काम कर रहा है तो आभार भी व्यक्त करना चाहिये, उसे धन्यवाद भी देना चाहिये और इसीलिए छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 का संकल्प लेकर चल रहा है । सभापति महोदय, यह छोटा राज्य है, खुशहाल राज्य है, प्रगतिशील राज्य

है, इस राज्य की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी है । सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा एकात्म परिसर बना हुआ है और पहले से तय था कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य मूर्ति लगेगी । मेरा आग्रह है कि यदि बजट में प्रावधान नहीं है तो उसे सहयोग करें । अटल जी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर यह कार्य होना चाहिये । सभापति महोदय, हालांकि यह पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन कमिटमेंट को भाजपा पूर्ण करती है । हमने मोदी जी के कार्यकाल में कमिटमेंट किया और विष्णु देव साय जी की सरकार अपने कार्यकाल में इसे पूर्ण करेगी, हमारी यह सोच है । सभापति महोदय, मैं उसके लिये आग्रह करना चाहता हूँ कि शहर के विकास के लिये, विजन को पूरा करने के लिये, प्रशासन के द्वारा जो काम चल रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ । सभापति महोदय, हमारी सरकार ने शहर के विकास के लिये पहली किश्त में 800 करोड़ रूपये देना आरंभ कर दिया है । चाहे वह कृषि हो या विद्युतीकरण की बात हो, सरकार ने अपनी दूरदर्शिता को बजट भाषण में उल्लेख किया है । सभापति महोदय, राजनीति आयेगी और जायेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ यहीं रहेगा । छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति और उन्नति हो, यह हम सब का है, माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जी ने बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के लिये बहुत सारी चीजें लेकर आये हैं, कुछ योजनायें बंद की गई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, जहां तक श्रम कल्याण विभाग की बात है, इसमें पिछले 5 साल का कार्यकाल देख लें, जो काम के लिये हमारी गरीब बहनें जाती थी, उसे साईकिल दी गई थी, 35 साल से ऊपर की बहनों को हम सिलाई मशीन देते थे, हमारे चावड़ी पर रहने वाले भाई उनको गरम भोजन दिया जाता था, आपने तो उसे पूरा बंद कर दिया था । सभापति महोदय, सरकार के श्रम कल्याण बोर्ड में एक-एक पैसा उनकी मजदूरी से काटकर आता है, आपके कार्यकाल के 5 सालों में एक ही कार्यक्रम हुआ है । 5 साल में एक ही कार्यक्रम हुआ, खाली नेता को खुश करने के लिए 10 करोड़ समथिंग खर्च हुआ है । आप 8 करोड़ रूपए खर्च होने की बात कर रहे थे । यहां तो खाली एक कार्यक्रम में 10 करोड़ रूपए खर्च हुए । आपने क्या किया ? कुछ चीजें सरकार के ध्यान में आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आती है तो सरकार उस आधार पर तत्काल निर्णय करती है और उस निर्णय के आधार पर उसको इंम्लीमेंट करने का काम आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत देर से सब लोगों ने सब बात की है । इस विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के डेव्हलपमेंट को आगे पहुंचाने के लिए आप सबका योगदान इस प्रदेश की 3 करोड़ जनता का अभिनंदन, वंदन, इसमें 90 विधायकों का सहयोग, स्नेह, प्यार, जाति, वर्ग, समाज से ऊपर उठकर आओ विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में साथ में हम सब छत्तीसगढ़ का विकास करें । इसी आशा

और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सदन को सूचना

"सदस्य परिचय, छत्तीसगढ़ विधान सभा (षष्ठम)" का वितरण

सभापति महोदया :- षष्ठम विधान सभा के माननीय सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों कर केन्द्रित प्रकाशन "सदस्य परिचय, छत्तीसगढ़ विधान सभा (षष्ठम)" की प्रति समस्त माननीय सदस्यों को सूचना कार्यालय से वितरित की जा रही है ।

कृपया आप सभी अपनी प्रति प्राप्त करें ।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति जी, मैं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) के विरोध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हम आपको पैसा क्यों देंगे ?

श्री राजेश मूणत :- पैसा नहीं दोगे तो क्षेत्र में कुछ नहीं चाहिए न, यह आज मना कर दो ।

श्री दलेश्वर साहू :- आगे बात करेंगे ।

श्री राजेश मूणत :- आज आप मना कर दो न कि हमें पैसा भी नहीं चाहिए और हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं चाहिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- आपको क्यों देंगे, इसी पर तो बात कर रहे हैं ।

श्री राजेश मूणत :- फिर आखिरी में मांग मत करना कि ये कर दो ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपने राजस्व मद में 13,598 करोड़, 71 लाख, 34 हजार रूपए में प्रावधान किया है । आपने पूंजी मद में 5249 करोड़, 26 लाख, 54 हजार रूपए रखा है । संचित निधि पर आपका भारित होगा । आप क्यों खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी उल्लेख करेंगे । 14 करोड़, 14 लाख, 54 हजार, 119 रूपए को आपको कुछ विभागों में एक सीमा में बांधकर रखा गया है, इसके अलावा आप ज्यादा खर्च नहीं करोगे । संचित निधि पर भारित होगा । आप कुल 19,762 करोड़, 12 लाख, 42 हजार, 523 रूपए मांग रहे हैं तो हम आपको क्यों देंगे ? इतने आसान तरीके से हम आपको नहीं देंगे ।

सभापति महोदय, इस बजट के बारे में मैंने पूंजीगत व्यय का बताया, जिसमें पूंजीगत व्यय में सामान्य सेवा भी है, सामाजिक सेवा भी है और आर्थिक सेवाएं हैं । अब आपने सामाजिक सेवाओं की भी परिभाषा दी है । शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, परिवार, जलपूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, पोषण आहार, सूचना प्रसारण एवं अन्य । आपने इसको पूंजीगत व्यय में बांधकर रखा है । आपने उस क्राईटेरिया में घटक बनाया है । आर्थिक सेवाओं में कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन, सामान्य, आर्थिक, विज्ञान और प्रोद्योगिक संचार। यह पूंजीगत का है। आपने सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं में प्रावधान किया है । अब राजस्व में आपने 4 घटक बनाए हैं, उसमें भी आर्थिक सेवाओं में भी खर्च कर रहे हैं। कृषि से संबंधित ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान प्रौद्योगिक, सामान्य आर्थिक सेवाएं । आर्थिक सेवाओं में राजस्व विभाग में भी खर्च करेंगे । अब सामाजिक में भी चलेंगे । राजस्व विभाग में सामाजिक दृष्टिकोण से भी खर्च करने का प्रावधान आपके बजट में है । शिक्षा, खेल, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास, श्रम और रोजगार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक सुरक्षा कल्याण और दैवीय विपत्ति आपदाओं के संबंध में राहत, सूचना और प्रसारण एवं अन्य। इसके अलावा राज्य में दो भागों में पूंजीगत व्यय और इसके अलावा आपने सामान्य में दो भागों में बांट रखा है। केंद्र सरकार से सहायक अनुदान, केंद्रीय रूप में प्रायोजित योजनाएं, वित्त आयोग का अनुदान, राज्य को अन्य अंतरण अनुदान, यह आपका ढाचा है, यह आपके घटक हैं।

सभापति महोदय, जब हम पूरे प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं, गरीब जनता के जीवकोपार्जन के लिये योजना बनाते हैं और हमने हर वर्ग के लिये बजट का प्रावधान रखा है। वित्त मंत्री जी ने इस विनियोग विधेयक के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजने की अनुमति के लिये मांग की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां 70 प्रतिशत धान किसानों के खेतों में हैं। वे उसी की खेती करते हैं और उससे अपना जीवकोपार्जन करते हैं। उनके बारे में हमारी क्या सोच है ? हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए ? उसके लिये बजट का प्रावधान कैसे होना चाहिए ? हमने आपको यह जो बजट दिया, उसके लिये आपकी क्या सोच रही ? धान विक्रय करने वाले किसान को 3119 लाख 18 हजार रूपये भुगतान नहीं हो पाया है, तो हम आपको बजट क्यों देंगे ? जब आपने उस समय भी बजट मांगा तो हमने दिया। परंतु इसमें हम बजट कैसे देंगे ? आपको यह पेमेंट करना है और आपको ऋण की भी अदायगी करनी है और उसको आपने बजट में लाया है तो आप देंगे ही क्योंकि जो कर्जा है, उस कर्ज की अदायगी तो करनी पड़ेगी। आप वर्ष 2024-25 की स्थिति में उपार्जन केंद्रों से 49 लाख 73 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं। अब जब आप उसका उठाव नहीं कर पायेंगे तो आपके बजट का alignment बिगड़ेगा।

कैसे बिगड़ेगा वह मैं आपको बताता हूं। आपने लगभग 122 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग करवायी है, जिसमें आपको राज्य पुल में 13 लाख 34 हजार मीट्रिक टन धान देना है और केंद्रीय पुल में 70 लाख मीट्रिक टन धान जमा करना है। आपके पास 40 लाख मीट्रिक टन धान शेष है। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप धान बेचने का नियम बना रहे हैं। आपकी बेचने की मंशा है। आप 40 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी करेंगे। केंद्र ने अतिशेष चावल को केंद्रीय पुल में लेने से इंकार कर दिया तो मैं सोचता हूं कि जब आप ट्रिपल इंजन और चार इंजन की बात करते हैं, तो आपका स्वाभिमान कहां है ? आप जो बार-बार ट्रिपल इंजन कहते हैं, तो आप जब केंद्रीय पुल में इस चावल को भेजेंगे, तब हम मानेंगे कि आपकी जो नीति और नियम है, हम उसके लिये आपको सम्मान से देखेंगे। यदि आपने नीलामी कर दी तो निश्चित रूप से आपका alignment बिगड़ेगा। आप कल्पना करिये कि आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे ?

सभापति महोदय, अब चूंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 जनवरी, 2024 से वर्ष 2025 की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में 46 प्रकरण दर्ज हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में 2,400 प्रकरण हैं, आप उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में 384 प्रकरण निराकृत हैं, आप उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। आपके न्यायालयीन प्रक्रिया में 723 प्रकरण हैं, जो उपभोक्ता में गबन किया गया है, जो भ्रष्टाचारी किया गया है, यह प्रकरण उसी के हैं और आपका नियंत्रण नहीं है। यदि ऐसे ही यह प्रकरण लंबित हो तो कैसे बनेगा ? हम आपको किस वजह से पैसे देंगे ? दूसरा, नागरिक आपूर्ति निगम में जनवरी, 2024 से 2025 के आवंटन अनुसार चना उपलब्ध नहीं है। आपकी निष्क्रियता और हठधर्मिता के कारण वर्ष 2025 में कृषि विभाग द्वारा किसानों को समर्थन मूल्य में चना उपलब्ध नहीं कराया गया, तो हम आपको पैसे क्यों देंगे ? आपके पास पैसा था । किसानों को समर्थन मूल्य में चना खरीद कर देना, यह कितना सरल काम था, पर आप इस सरल काम को भी नहीं कर पायें। आपको क्यों पैसा दें? यहां पर हम इसलिए विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। आप इतने आसान तरीके से पैसे मांग रहे हैं। आप बचत स्टॉक का दुरूपयोग करने वाले राशन दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर पायें। आर.सी.सी. वसूली की कार्यवाही, राजस्व प्रकरण में प्रक्रियाधीन है। उपभोक्ता प्रकरण में स्टे वेकेट कराने के लिए आप न्यायालय में Urgent hearing की प्रार्थना तो कर सकते थे, आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं मार्कफेड पर कहना चाहूंगा। आपका 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में मार्कफेड के राजस्व, सरकार की हानि हुई, प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त व्यय मद में राशि 31 हजार 542.106 करोड़ रूपये लेनदारी के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा 15 हजार 186.90, 1 करोड़ के माध्यम से भुगतान किया गया है। 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में 16 हजार 395.205 करोड़ रूपये, आपको मार्कफेड में पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास राशि है या नहीं यह आपको सोचना पड़ेगा। एक पीडीएस चावल अन्न खाद्यान्न संबंधी जांच, मतलब वित्तीय वर्ष 2023-

2024 में भारी भ्रष्टाचार हुआ था। आपकी केन्द्र सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भारत सरकार की उप सचिव श्री एस.आर. मीणा, श्री संतोष कुमार पाण्डे अपर सचिव का जांच दल गठित हुआ। आज तक उस जांच दल ने राज्य शासन को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया है। क्या आपने भ्रष्टाचार करने के लिए जांच कमेटी बैठायी ? भारत सरकार के एक उप सचिव श्री पुण्डिर हैं। आज तक उनके द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया और आप कार्यवाही नहीं करेंगे और पैसा मांगते जाएंगे तो कैसे बनेगा? कृषि विभाग का तो हाल बेहाल है, उस पर चर्चा करूंगा। मैं यह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पढ़ रहा था। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट स्वयं पढ़ें। उनके कृषि विभाग के 4-5 घटक हैं, जिसमें कृषि और उद्यानिकी है उसमें बहुत सारे और हैं। मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आप विनियोग में पैसा मांग रहे हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे ? उसी के साथ अनुसूचित जाति का भी है। यहां अनुसूचित जाति के लिए राशि आयी थी, आप उस पैसे को थोड़ा सा भी खर्च नहीं कर पायें। अगर एकाध प्रतिशत होता या दो प्रतिशत होता तो हम कहते कि इतना ही प्रतिशत है आपको किसी कारण समस्या होगी। लेकिन एक विधायक यह सोचता है कि अगर थोड़ा बहुत राशि होती तो ठीक है, लेकिन आप लोग 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रूपये खर्च करते हो ..। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय दलेश्वर साहू जी बहुत सीनियर विधायक हैं। अभी आप यहां पर जितना बोल रहे हैं उतना माननीय भूपेश जी बोलकर चले गये। इसमें आप कोई नई चीज बोलिए। आप वही चीज बोल रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो यहां पर मांग संख्या सहित अपनी बातों को बताऊंगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, उन्होंने भी मांग संख्या के सहित अपनी बात बतायी। आप कुछ तो नई चीज बोलिए। आप वही चीज रिपिट कर रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप यह बताईये। अनुसूचित जाति उपयोजना अच्छी चीज पर बोल रहा हूँ। मैं उसमें आऊंगा। मैं आपके लिए भी बोलूंगा। जब मैं ऊर्जा में आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। आपने जो प्रश्न लगाया था आपकी सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना की बात कहना चाहूंगा। आप इस विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में एक रक्ति भर खर्च नहीं कर पाये हो। आपको केवल कोरा घण्टाल के लिए पैसा देंगे। आप अपने बजट को खुद पढिये। विधायक लोग तरसते हैं। मुझे यह पैसा मिल जाता, वह पैसा मिल जाता। आप अनाबद्ध जैसी राशि को, तीन-तीन योजनाओं की राशि खर्च नहीं कर पाये। बैगा जाति, कमजोर जाति के लिए आपने पैसा

लाया। बिहोर, पहाड़ी, कमार, अबूझमाड़, पांडो, मुरिया जनजाति हैं, आपने एक मुरिया विकास अभिकरण भी चालू किया है। पर उनके पैसे का थोड़ा सा भी उपयोग समय पर करते तो बजट में पैसा देने को बनता कि चलो गरीब तबके के लिये आपने सोच बनाई है। आप केन्द्र सरकार से पैसा भी लाये हैं पर आपने उसकी समीक्षा नहीं कर पाई और आप बजट में पैसा मांगने चले हैं, यह कैसे संभव है ? पिछड़ी जाति, जनजाति के संवर्द्धन के लिये पैसा लाये हैं, इनके लिए भी पैसा आप समय पर खर्च नहीं कर पाये। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में दवा सहित, मोबाईल मेडिकल यूनिट में 4 करोड़ 82 लाख 220 रुपये खर्च नहीं कर पाये। आप स्वास्थ्य जैसे विषय में खर्च करते, वनांचल में जीने वाले हमारे गरीब तबके के लोगों को कितना भला होता। आप को किसलिये पैसा देंगे? यह पैसा बचा हुआ है, आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत विभाग में घर-घर आदिवासी संस्कृति के संवर्द्धन के लिये आपके पास 800 करोड़ रुपये था, 473 करोड़ रुपये खर्च कर पाये। क्या खाली पैसे को जाम करने के लिए आपको पैसा देंगे? ठीक है, आपके पास बहुमत है, आप बजट पास कर लेंगे। पर हम अपनी बात रखेंगे, अपने विपक्ष की भूमिका निभायेंगे और आपके कान खोलने का प्रयास करेंगे। आपको चिंतन करने में मजबूर कर देंगे। यह बात कहां से आ रही है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कम से कम इस बात की आपको जानकारी होगी। विशेष आदिवासी पिछड़े समूह का पैसा जीरो, जीरो है, एक रत्ती भर खर्च नहीं किये हैं। आप लोग भी इस पर ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास के लिये, अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स के पैसा देना है। आपने तो भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं कर पाये हैं, आपको किसलिए पैसा देंगे ? आप पोर्टल तो खोल लेते, देना या नहीं देना, अलग बात है। जब आप पोर्टल ही नहीं खोल पाओगे तो आप कैसे बच्चों के खातें में पैसा जमा करेंगे। वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान, यह सम्मान पाया, वो सम्मान पाया। वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान 2023 में नहीं दे पाये, उसका बजट भी शेष पड़ा हुआ है। सभापति महोदय, हम इतना भी नहीं बोलेंगे। 2023-24 में व्यय जीरो-जीरो दिखा रहा है। आपकी सरकार थी, एक आदमी को सम्मानित कर देना था। किसी आदिवासी को, किसी सामाजिक दृष्टिकोण में काम करने एक अच्छे व्यक्ति को सम्मानित कर देना था। उसके लिए भी आपके पास समय नहीं है। आप केवल महतारी वंदन योजना में सिमटकर रह गये हैं। अब ऊर्जा विभाग में आता हूं। राजेश मूणत जी, मैं आपको एक शब्द बोलूंगा।

श्री राजेश मूणत :- क्या है कि आज कल बाबा रामदेव की दवाई में ऊर्जा ज्यादा है। सभापति महोदय, पहले दोपहर में 2 बजे समाचार आता था, उसको धीमी का समाचार कहा जाता था।

श्री दलेश्वर साहू :- आप मेरे को बोल रहे हैं। मैं भाषणबाजी तो कर नहीं सकता, तथ्यात्मक बात बोलने में तो कोई हिचक नहीं होगी। आपको याद होगा आने 2023 में एक प्रश्न लगाया था। गारेपेलमा सेक्टर के कोयला खदान के संबंध में था। जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा प्रश्न लगाता है तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। मेरा मुख्यमंत्री जी भी प्रश्न ग्राह्य हुआ था, तीसरा नंबर में था। मैंने उसी परपज को

लेकर विद्युत विभाग की तीनों ट्रांसमिशन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन को लेकर प्रश्न लगाया था। आप यह तीनों कंपनी के संबंध में आप विभागीय को जवाब पढ़ना, शायद आप पढ़े होंगे, यदि उसको निकालकर बस्ता में डाल दिये होंगे तो नहीं मालूम, कोयला ट्रांसपोर्टिंग को लेकर आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं सत्य बात बोल रहा हूं। उस समय आपका शासन था, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, साहब। आपने पूछा कि एक निविदा में इतने रुपये रेट फिक्स है तो आप डबल पैसा देकर उसका परिवहन क्यों करा रहे हैं ? यह आपका प्रश्न था । आपके पास जवाब आया कि हम समय-समय पर विभाग के ऊपर के जो बड़े अधिकारी हैं उनके आधार पर यह निर्णय लेने का अधिकार है और उसका निर्णय लिया तथा क्रय नियम बना रहे हैं ।

समय :

4.00 बजे

यह शब्द है कि क्रय नियम बना रहे हैं, यह आपके उत्तर में आया है । साल भर पहले जब मैंने उसी ट्रांसमिशन कंपनी के ऊपर लेनदेन के ऊपर लगाया तो चूंकि मंत्री जी के ऊपर बार-बार छींट आता था कि छत्तीसगढ़ क्रय नियम का पालन नहीं होता । ठीक है, हमने मान लिया लेकिन आप अभी साल भर तक क्रय नियम नहीं बना पाये । मैं तो सोचता हूं कि भारतमाला से ज्यादा अगर कोई करप्ट घोटाला हुआ होगा तो शायद यह 3 कंपनियों में सिर्फ लेनदेन और सामग्री क्रय में चूंकि यह मेरा अपना एक अनुभव बोला है । जैसे मैंने कुछ सीनियर लोगों का और कुछ विधायक लोगों का भी चूंकि जब मैंने उसका प्रश्न और उत्तर पूछा तो आप अभी तक छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम का तो पालन कर ही नहीं रहे हैं । जो अधिकारी बैठे हैं, निदेशक, अध्यक्ष जो भी हैं उसने समय-समय पर जो लिख दिया वह सो निहाल । आपका कंट्रोल, यही अगर ऊर्जा विभाग किसी मंत्री के हाथ में होता, आपके हाथ में होता तो थोड़ा समीक्षा करने में एक अच्छा होता और अधिकारी के ऊपर एक दबाव बनता लेकिन बेलगाम है, बेलगाम । मैं तो सोचता हूं कि जब दूसरे भ्रष्टाचारी का आलम निकलेगा तब भारतमाला तो कहीं एक कोंटे में रहेगा, यह तीनों कंपनियों के लेनदेन के मामले में चूंकि मैं तो सूचना के अधिकार में लगाउंगा कि आपने किस ढंग से लिया, क्या किया तो यह हाल है तो फिर हम आपको कैसे पैसा देंगे ? ठीक है, आपका एक कंपनी नियम है । कंपनी अगर गांव में एक पान ठेला भी चलाता है न तो वह नियम-कानून से बंधा रहता है । एक होटल चलाने वाला व्ययक्ति यदि वहां खाद्य अधिकारी जाता है तो...।

श्री अजय चंद्राकर :- दलेश्वर जी, भाषण करने की बजाय आप यह बताईये कि आपको क्या तकलीफ है ? माननीय विष्णुदेव साय जी सब तकलीफ दूर कर देंगे। आप समझ रहे हैं, आप कहां इधर-उधर में पड़े हैं । आपके लोग तो सुनने के लिये हैं नहीं । क्या तकलीफ है, आप वह बोलो न भई ।

श्री दलेश्वर साहू :- तकलीफ नहीं । मैं इतना ही चाहता हूं कि आप यह जो पैसा मांग रहे हैं न, हम आपको इसे बेदर्दी से खर्चा करने के लिये नहीं देंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह बताईये कि क्या तकलीफ है ? सब करवा देंगे । कोई चिंता नहीं है ।

श्री दलेश्वर साहू :- आप नियम बनाईये, कानून बनाईये । आप कानून के दायरे में चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आपको पैसा देना है ?

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, आप कुछ भी बनायेंगे और बैठे रहेंगे । आप इस छत्तीसगढ़ भण्डार नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- डोंगरगांव में पैसा देंगे कि नहीं देंगे ?

श्री दलेश्वर साहू :- हम ले लेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं लेना है ।

श्री दलेश्वर साहू :- हम ले लेंगे । जहां लेना होगा तो ले लेंगे और नहीं लेंगे तो विकास के ऊपर भी कोई मायने नहीं रखता ।

श्री अजय चंद्राकर :- बजट पारित नहीं करेंगे तो कैसे ले लेंगे ? इसलिये आप बजट को पारित करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- आपकी तो मजबूरी है, आप उसका पालन करेंगे लेकिन हम आपको चेतायेंगे, आपको जतायेंगे । आपको चिंतन कराने में मजबूर करेंगे । आप एक-बार घुसिए तो सही । आप तीनों कंपनियों में घुसकर तो देखिये । भारतमाला से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार का आलम है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बजट को पारित करिये फिर जितना पैसा चाहिए, हम डोंगरगांव के लिये दे देंगे । आप कोई चिंता मत करिए ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं आर.डी.एस.एस. के बारे में फिर से कह रहा हूं । मैं परसों भी बोला था और आज भी बोलूंगा । यह आर.डी.एस.एस. कितनी शानदार योजना है और यह योजना भारत सरकार से आप ही लोग लाये हैं । यह पूरे प्रदेश लेवल का है, मैंने तो राजनांदगांव की समीक्षा की थी । सारे विधायकों के पास आर.डी.एस.एस. का चूंकि आज आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं, जुलाई में आपका समाप्त हो जायेगा और आपका कितने लाख का बजट है । आपके पास 35 हजार करोड़ पैसा है । केवल 2 महीने शेष हैं और आपने 4 परसेंट, 5 परसेंट और 7 परसेंट खर्च किया है तो आप कैसे वोल्टेज की समस्या को दूर कर लेंगे ? आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उसकी समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप पैसा मांगे चले जा रहे हैं और भण्डार क्रय नियम का बिना पालन किये, कुछ भी पैसा अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं क्या हम आपको इसीलिये पैसा देंगे ? आप क्रय नियम दिखाईये तब हम मानेंगे कि आपका विद्युत खर्चा आपके छत्तीसगढ़ के अधीन है । ऊर्जा विभाग में किसी को बड़े अधिकारी के रूप में या अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है तो किसी टेक्निकल आदमी को ही बैठाया जाता है, किसी सामान्य आदमी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है लेकिन क्या भ्रष्टाचार करने के लिये ही बनाया जाता है ? यह दुखद घटना है, यह हठधर्मिता है और मैं सोचता हूं कि सरकार के लिए बहुत

दुखदायी घटना है। मैं पूरे विधायकों से, पूरी सदन से निवेदन करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि एक बार RDSS की समीक्षा कर लेना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस RDSS का फुल नाम भी बता देता हूं जोकि Revamped Distribution Sector Scheme है। 35,000 करोड़ का मामला है, प्रदेश का कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- और कुछ है?

श्री दलेश्वर साहू :- और है। अभी तो बोलेंगे । पंचायत विभाग के मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी, आपके विभाग में बोलना चाहूंगा, आप सुने या न सुनें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय :- 20 मिनट हो गये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- ये बैठे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। महात्मा गांधी भारत स्वच्छ मिशन। उस दिन मैं बोल लिया था, जल्दबाजी में बैठिए, बैठिए बोलें तो मैं कुछ शब्दों को बोल भी नहीं पाया था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपका विभाग है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आपका लक्ष्य 10,507 था, आपने 5,640 किया। आपका लगभग 5400 बचा हुआ है। आप तरल अपशिष्ट प्रबंधन में खर्चा नहीं कर पाए हो। समुदायिक स्वास्थ्य परिसर में आपका पैसा है, आप खर्च नहीं कर पाए। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय पर खर्च नहीं कर पा रहे हो। आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में खर्चा नहीं कर पाए हो। आप फीकल स्लज मैनेजमेंट में खर्च नहीं कर पा रहे हो। ये अलग-अलग घटक में है। वर्ष 2023, 2024 और वर्ष 2024 का भी आपका वही बुरा हाल है? आपका 58 ,53, 33, 31 हर एक घटक का लक्ष्य के विरूद्ध शेष है तो ये पंचायत विभाग का है। आपने प्रधानमंत्री आवास में बहुत बढ़िया चर्चा की। आपका बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण भी रहा, पर हमने पैसे के बारे में टोका-टाकी की तो आपकी पैसे की उपलब्धता में आपका प्रस्तुतिकरण नगण्य था, समझ में नहीं आया। अभी समय है, जब आएंगे तो समीक्षा करेंगे, जुलाई में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका 18 लाख का वचन था, आपने कर लिया, पर मैं सोचता हूं कि शायद पैसे की कमी पड़ेगी और इस बजट में फिर से आपको कहीं न कहीं से व्यवस्था करानी पड़ेगी। वह आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिगर में ज्यादा जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। पर मुझे जहां तक मालूम है कि आपके पास पैसा नहीं है। पी.एम. जनमन योजना, उसकी भी जब समीक्षा करेंगे, तभी पैसा मांगोगे। यह तो भारत सरकार का है, आपने अच्छी योजना लायी है । ट्रिपल इंजन की सरकार को देखने का अवसर मिला, मोदी जी की जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की सरकार है कि मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं, शायद उस कल्पना से दिए होंगे, पर आप उस कल्पना को साकार नहीं कर पा रहे हो। जब उनको पता चलेगा, हम लोग पत्र लिखेंगे कि आपने इतना पैसा भेजा है, समय में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरी किश्त, तीसरी किश्त नहीं मिलेगी, वह भी नियम कानून से बंधा हुआ है। जब तक आप यूटिलाइजेशन उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजेंगे तो आपको किश्त भी नहीं भेजेंगे। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा आपने तो पैसा ला लिया, पर जब दूसरी और तीसरी किश्त की बात होगी तो आपको देने

वाला कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। सरकार नियम कानून से बंधी हुई है। मुख्यमंत्री समग्र विकास के बारे में चर्चा हुई। आपने राजनांदगांव विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ थोड़ा बहुत दिया है और 4 मिनी स्टेडियम दिये हैं, वह भी डॉ. रमन सिंह को दिये हैं, किसी विधायक को नहीं दिये हैं। पर आपने अपने बजटीय भाषण में आश्वस्त किया है कि आपको सभी योजना का लाभ मिलेगा।

श्री राजेश मूणत :- दलेश्वर भाई, एक बात बताता हूं। वर्ष 2018 के अंदर राजनांदगांव का स्टेडियम बना था। नया दिग्विजय सिंह स्टेडियम बना न। 5 साल पहले वर्ष 2018 में उद्घाटन हुआ और उसके बाद में वर्ष 2024 के अंदर कार्यक्रम हुआ, 5 साल उस स्टेडियम में कुछ नहीं किया।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने स्टेडियम की बात कर दी, इसलिए मुझे याद है। मुझे बोलने दीजिए। मूणत जी, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर सुनना। मूणत, जब वह स्टेडियम बन रहा था तो ई.ई. रिकवरी निकालता है, एसडीओ और इंजीनियर के ऊपर । देखिए, मैं नई बात बोल रहा हूं । समयलाल नाम का ई.ई. था, फाउंडेशन को लेकर 40-50 लाख की रिकवरी निकालता है कि आपने गलत ढंग से फाउंडेशन करके ठेकेदार को पैसा दे दिया । देखो, यह ई.ई. कहता है, किसके ऊपर रिकवरी निकालता है, एक एसडीओ और इंजीनियर के ऊपर । वह ई.ई. बहुत परेशान रहता है कि देखो एक ई.ई. के पत्र को एसडीओ, इंजीनियर नकारते हुए, मजे के साथ ईएनसी से मिलता है । हमारा संभाग दो भाग में बंटा हुआ था, एक राजनांदगांव और एक खैरागढ़ । मैं सत्यता बोल रहा हूं, मुझे याद है ।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा एक बता बताओ । मैंने केवल इतना पूछा और आपने कहा स्टेडियम । वह तो यह बताते हैं कि वहां गेंहू उगा था, गेंहू खरीदकर लाया, उसके बाद आटा पिसाने गया था, फिर लाइट चली गई, फिर बाद में वहां से गेंहू लेकर आया, आटा बन गया, घर पहुंचा तो घर के अंदर गैस खत्म हो गई थी, फिर गैस लेने गया फिर रोटी बनी । इतनी बात बता रहे हो, मैंने पूछा पांच साल में उस स्टेडियम का उपयोग क्यों नहीं कर पाए, यह बताओ ?

श्री दलेश्वर साहू :- आपने स्टेडियम की बात छेड़ी, इसलिए मैं बोल रहा हूं । मूणत जी, मेरी बात सुनो । आपने तो पैसा दिया क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका था । मुझे बोलने दीजिए, आपने मुझे छेड़ा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- जवाब देकर समाप्त करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- खैरागढ़ के ई.ई. को ।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, आपको कौन छेड़ सकता है, यह बताओ ?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं बहुत टेक्नीकल बात कर रहा हूं ।

श्री राजेश मूणत :- वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उनको छेड़ा ।

श्री दलेश्वर साहू :- अरे कितनी हास्यास्पद बाद है, इसको तो सुनो आप । राजनांदगांव का ई.ई. रिकवरी निकालता है एसडीओ और इंजीनियर के ऊपर । ईएनसी आदेश देता है खैरागढ़ के ई.ई. को

जाओ और मूल्यांकन, सत्यापन करके उसको नस्तीबद्ध कर दो कितनी विडम्बना है । अब ईएनसी के आदेश का तो ई.ई. को पालन करना पड़ेगा । वह गया और उनकी रिकवरी को समाप्त कर दिया । एक ई.ई. के आदेश को दूसरे ई.ई. ने समाप्त कर दिया, यह हाल है । फिर वह ई.ई. मेरे पास रोते आया, वह न्याय मांगने आया । हालांकि यह बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन आपने छेड़ दिया इसलिए बोलूंगा । मैंने कहा कि मैं विधान सभा में लगाऊंगा, विधान सभा में कहीं न कहीं न्याय तो मिलता है, दबाव तो बनता है । पीछे पीछे वह एसडीओ मिलना चाहा तो मैंने कहा कि मैं जिसको वचन देता हूं उस वचन का पालन करता हूं और मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने उस पर क्या कार्रवाई की।

श्री राजेश मूणत :- यह कब का है ?

श्री दलेश्वर साहू :- मैं सन् बता दूंगा । कार्रवाई का भी बता दूंगा ।

श्री राजेश मूणत :- अरे मेरे भाई, 2018 में स्टेडियम का लोकार्पण हुआ, 2023 तक आप लोग उसमें एक कार्यक्रम नहीं कर पाए ।

श्री दलेश्वर साहू :- मूणत जी, लीपापोती मत करो । मैं इतना लेवल पर बात कर रहा हूं और आप उसको कोंटे में डाल रहे हो । मैं 2013 का विधायक हूं, 2013 में मैं विधायक बन गया था । एक-एक चीज पर नजर रहती थी और मैं डॉ. रमन सिंह जी का पड़ोसी विधायक हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन सरीके नो हन, हम सच्चा काम करने वाला हन ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- देखो, जब कोई विधान सभा में गलत जवाब देते हैं तो प्रश्न संदर्भ समिति में जाता है, आपको सब नियम पता है । मेरे पांच-सात मामले समिति में लगे और मैं जब कार्रवाई कराता हूं तभी सांस लेता हूं । ऐसा नहीं है कि कोई आए तो सेटिंग कर लिये, विधान सभा में उठाए ।

श्री राजेश मूणत :- ये सेटिंग क्या होती है, मैं समझ नहीं पाया ?

श्री दलेश्वर साहू :- विधान सभा का रिकॉर्ड बताएगा । प्रश्न एवं संदर्भ समिति की पुस्तक मंगाइए और देखिए कि दलेश्वर साहू जी ने क्या किया है ।

श्री राजेश मूणत :- अरे भाई, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तभी तो आप वहां से जीत रहे हो । बार-बार कहते हो सेटिंग कर लेते हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- वह आप लोगों में चलता है ।

श्री राजेश मूणत :- आप सिर्फ लोक सभा में सेटिंग करते हो ।

श्री रामकुमार यादव :- सेटिंग के परिभाषा, चुनाव मा सेटिंग करके जीतथो, वही सेटिंग हे ।

श्री दलेश्वर साहू :- आपने कोयला खदान के परिवहन के संबंध में प्रश्न लगाया, आपको जो जवाब मिला उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं । अभी कर लो, आगे इस पर समीक्षा करो, नियम का पालन करवा दो ।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी समाप्त करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, बस ये लॉस्ट है। आपने मनरेगा में 2 करोड़ 76 लाख 99 हजार रूपए का पेमेंट नहीं किया है, आपका पुराना रिकॉर्ड है, ये आपकी एलाईमेंट खराब करेगा, आपके नीचले विभाग ने आपको जानकारी दी है या नहीं दी है, ये पता नहीं, आपने उस स्तर का बजट शामिल नहीं किया है। आप लोग सक्षम हैं, फिर से अनुपूरक बजट में शामिल कर लेंगे, जो सत्य है, वह मैं आपको बता रहा हूं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क के उपर भी चर्चा हुई, मैं उसमें दोबारा बोलना नहीं चाहता। आपका 1262 सड़क नवीनीकरण करने का है और आपने 175 सड़क स्वीकृत की है, आपके पास पैसा ही नहीं है, हम लोग इस बजट को और गंभीरतापूर्वक देखेंगे, मैं समझता हूं कि आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए फिर से पैसा लाना पड़ेगा। प्रभारी मंत्री जी, मैं आपका बजट भाषण बहुत गंभीरता से सुन रहा था। इसमें और बसाहटों को जोड़ने का काम करना है, ये पहले समय का है, शायद 500, 1000 का क्राइटेरिया था, उसको आपने कम कर दिया, इसलिए आपको बधाई देता हूं, इससे निश्चित रूप से हमारे जो छोटे-छोटे गांव कस्बे हैं, उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिस दिन स्वीकृति होगी, धरातल पर उतरेगा, हम उस दिन मानेंगे। आपने उस दिन भाषण में इसके बारे में चर्चा की, हमने उसको बहुत गंभीरतापूर्वक सुना। मैंने मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात बताई, आपने उसको सुना, मैं उसको दोबारा नहीं बोलना चाहता।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना, इतनी शानदार कल्पना थी, उसमें शौचालय बनेंगे, यात्री प्रतिक्षालय बनेंगे, लेवीवाय बनेगा, शायद पानी की भी सुविधा का साधन था। आज आप मुख्यमंत्री सड़क योजना की स्थिति देख लीजिए, इसकी रिपेरिंग नहीं करा पा रहे हैं, आपने इसमें एक रूपए भी बजट नहीं रखा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरूआत डॉ. रमन सिंह जी ने की थी। ये शानदार कल्पना थी, आज उसका क्या हश्र हो गया है ? आप उसकी एक बार समीक्षा जरूर कीजिए। जब आप मुख्यमंत्री सड़क योजना की भूमिका पढ़ेंगे तो किसी भी आदमी को लगेगा कि इसको फिर से बनाना चाहिए, उसका फिर से जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, उसको फिर से लागू करने की जरूरत है। उसमें कितना फायदा हुआ नहीं हुआ, अलग बात है। मैं समझता हूं कि इतना होने के बाद कल्पना साकार नहीं हुआ, धरातल पर नहीं उतरा, वह खाने का साधन बन गया।

सभापति महोदय :- दलेश्वर जी, समाप्त करिए।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आपने महतारी वंदन योजना में 3971 हितग्राहियों को अभी तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है, आपने उसके लिए बजट मांगा है, बजट मांगने से कुछ नहीं होगा। उनको भुगतान नहीं होने की समीक्षा भी हुई, हम लोगों ने प्रश्न लगाया था, प्रश्न लगाने के बाद उसमें तकनीकी दृष्टिकोण से या जो ऑनलाईन सिस्टम है, उसमें भी मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे

थे, जब वह पात्र है, पात्र होने के बाद सिस्टम को सुधारने में कितना समय लगता है, आपके दिमाग में ही वायरस लगा हुआ है, आप उस कंडीशन को कैसे सुधारोगे ? यह दो दिन का काम है, अगर अधिकारी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आपने 3971 पात्र हितग्राही को अब तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है और आप महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए आपको किस आधार पर पैसा देंगे ? आप पहले इनका निराकरण करिए। मैं पुलिस विभाग में भी बोल सकता था लेकिन मैंने उस दिन मंत्री जी को जवाब दे दिया था। मैंने शिक्षा विभाग के बारे में भी बात की। हम आपको किस हिसाब से पैसा देंगे ? आपकी 2783 प्राथमिक पाठशाला जर्जर है, आपकी 947 पूर्व माध्यमिक पाठशाला जर्जर है, पाठशालाओं की कंडीशन बहुत खराब है।

श्री धरमलाल कौशिक :- विधायक जी सुनिए न, तैं कथस कि कंडीशन बहुत खराब हे, पूरा देश भर में तुंहर कंडीशन बहुत खराब हे, ओला कतका सुधारिहा। अउ ओ सुधरने वाला नई हे, तेखरे सेती कहे हे कि तैं विरोध मत कर अउ चुपचाप मांग कर ले।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं तो आपको सिर्फ चिंतन मनन करने के लिए बोल रहा हूं। आप तो पैसा ले जाओगे, स्वीकृति कराओगे, वह तो आपका हक है, आपके पास बहुमत है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरमलाल कौशिक भैया, प्रदेश में आपकी जितनी स्थिति होनी चाहिए, वास्तव में खराब कर दी है, ये गलत हुआ है।

श्री रामकुमार यादव :- तोर स्थिति ला देख के मोला रोवासी लागथे ग। तै हमर बिलासपुर जिला के अस, तोर स्थिति ला देख के मोला गुण गुण के रोवासी लागत हे। (हंसी) तैं ऐती रतेस ते ओती हावस। मैं ओखरे खातिर कथव, मेहनत करे मुर्गी, अउ अंडा खाए फकीर। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदया, मेरा केवल लास्ट निवेदन है। अब मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। मैं थोड़ा कुपोषण की बात करूंगा। जब कोई बात आती है कि हमने यहां पर ऐसा किया।

सभापति महोदया :- आप समाप्त करेंगे। आपको आधे घंटे से ऊपर हो गये।

श्री दलेश्वर साहू :- कुपोषण की समस्या मुख्यमंत्री जी के इलाके में ज्यादा है। मैडम जी, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। आप मुख्यमंत्री जी के इलाके को संभाल लीजिए। आप बाकी विधान सभा क्षेत्र डोंगरगांव को संभालेंगी, राजनांदगांव को संभालेंगी, बस्तर को संभालेंगी तो कम से कम सरगुजा को संभालियेगा। आप कहां से आती हैं ? मैडम जी सरगुजा से आती हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- कोन हा ?

श्री दलेश्वर साहू :- महिला एवं बाल विकास मंत्री जी।

सभापति महोदया :- दलेश्वर जी, आप समाप्त करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- एहा सरगुजा ले आथे।

श्री दलेश्वर साहू :- मैडम जी, तै तोरे इलाका के पइसा ला संभाल ले, तब तोला समझ में आही। तै समीक्षा करबे अउ देखबे कि मोर इलाका में कतका कुपोषण हे, तेला। आप कृषि में डी.ए.पी. खाद का वितरण नहीं कर पा रहे हो। वह तो मैंने प्रश्न लगाया तो मेरे इलाके में पहुंच गया। मैंने तत्काल जैसे ही ध्यानाकर्षण लगाया तो 24 घण्टे में पहुंच जाता है। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि कम से कम ध्यानाकर्षण ग्राह्य हो या न हो, लेकिन वह एक बहुत अच्छा माध्यम रहता है कि तत्काल इतना मीट्रिक टन खाद सभी समितियों में चला गया। मैंने सारी 5-10 जगहों में पेयजल के ऊपर ध्यानाकर्षण लगाया था। हरकत किये बिना, मांगे बिना यह संभव नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अधिकारी तो इसको समझेंगे ही। आप लोग न समझे तो न समझे, लेकिन वह इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं कि कहां पर गलती की गई है, उसको जताने की जरूरत है।

सभापति महोदया :- दलेश्वर जी, आप समाप्त करेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- मैडम जी, हम आपके आदेश का पालन कर लेते हैं और समाप्त कर देते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, तोर नाम हा धरम से जुड़े हे ता ते धरम के रस्ता में चलबे अउ धरम के गोठ ला गोठियाबे। धरम के रस्ता ला छोड़ के कहिबे ता फेर सीनियर के कुछु महत्व होना चाहिए न। भैया, ते एखर ध्यान रखबे।

सभापति महोदया :- आप बस बार-बार मत उठियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- तै हा उठबे मत, बइठे रहिबे।

श्री रामकुमार यादव :- मैं मड़िया सकत हो या नहीं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, हमारे युवा वित्त मंत्री माननीय ओ.पी. चौधरी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उस विनियोग पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। आप पिछले साल जो बजट लेकर आये थे तो ज्ञान का बजट लेकर आये थे और इस बार जो बजट लेकर आये हैं तो गति का बजट लेकर आये हैं। पिछले समय का ज्ञान और इस बार की गति, दोनों ने मिलकर कर दी, कांग्रेस की दुर्गति। (मेजों की थपथपाहट) आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चार इंजन की बात कर रहे हैं तो यह जो चार इंजन की बात कर रहे हैं तो उसमें ज्ञान और गति का प्रभाव है कि सवा साल के अंदर हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार से काम किया गया है। जिस प्रकार से यहां के किसानों के लिए, महतारियों के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम किया गया है, आज उसी का परिणाम है कि जब नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए और त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव संपन्न हुए तो उस चुनाव के परिणाम ने यह बता दिया कि विष्णु देव जी की सरकार केवल चल ही नहीं

रही है, बल्कि सरपट गति से दौड़ रही है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे सवा साल का जो आकलन किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अजय चंद्राकर जी ने पूरा डाटा दिया है, इसलिए मैं डाटा नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल एक-एक लाइन में बात करूंगा।

माननीय सभापति महोदया, जब हम आकलन करते हैं तो हमारे वर्ष 2024-2025 के पिछले बजट और वर्ष 2025-2026 के इस बजट में हम कहां पर खड़े हुए हैं? हम कहां पर खड़े हुए हैं, यह इसलिए बताना आवश्यक है कि जब हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो वह मौजूदा कीमतों पर 6 लाख, 35 हजार, 917 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जब हम वर्ष 2024-2025 और वर्ष 2025-2026 के बजट की तुलना करते हैं तो हमारे वर्ष 2025-2026 के बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) जब हम इस बजट में 1 लाख 65 हजार करोड़ रूपये प्रावधान करने की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार खुद की आर्थिक स्थिति कैसी है। जब हम खुद के राजस्व की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और उसमें हम कहां पर खड़े हैं। मैं जब इस विषय पर बात करना चाहता हूं तो यह बताना चाहता हूं कि हमारे कुल 1 लाख 65 हजार करोड़ रूपये के बजट में हमारे राज्य का राजस्व 54 प्रतिशत है और केन्द्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि 45 प्रतिशत है। निश्चित रूप से जितनी राशि केन्द्र से मिल रही है, उससे ज्यादा राशि खुद राज्य सरकार का राजस्व है। उस दृष्टिकोण से यहां बजट रखा गया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में जी.एस.डी.पी. की मौजूदा स्थिति में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रूपए होने का अनुमान है। यदि हम वर्ष 2023-24 से तुलना करेंगे तो 9.4 प्रतिशत की वृद्धि है। हम देखेंगे 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. वर्ष 2023-24 की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 1,33,488 रूपए होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से आगे निकल गई है। बाकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो अलग-अलग विभाग के लिए राशि का प्रावधान किया है, मैं उसको देख रहा था कि लगभग 12 विभागों के लिए जो राशि का प्रावधान किया है, इन 12 विभागों में पिछले वर्ष जो राशि का प्रावधान किया था, उसकी तुलना में इस वर्ष उससे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) ऐसे समय में, जब हम किसानों को अंतर की राशि दे रहे हैं, हम महतारी वंदन योजना में राशि दे रहे हैं, भूमिहीन कृषक को राशि दे रहे हैं, यदि आप इस राशि को मिलायेंगे तो करीब-करीब 20 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा राशि है। इन सबमें 20 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा राशि का प्रावधान किए जाने के बावजूद, इतनी राशि का प्रावधान किए जाने के बाद भी जो 26,341 करोड़ रूपये पूंजीगत परिव्यय किया जाना प्रस्तावित है।

मुझे ऐसा लगता है कि जो पूंजीगत व्यय होना है, हम उसमें सबसे ऊंचे अंक पर पहुंचे है। कभी भी इतना ऊंचा नहीं रहा है। पूंजीगत व्यय में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है, जिससे परिसम्पत्तियों का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होना संभावित है।

सभापति महोदय, मैंने आपको अभी कुल राजस्व प्राप्तियों के बारे में बताया कि केन्द्र सरकार से कितना केन्द्रांश होता है और खुद राज्य का कितनी राजस्व प्राप्तियां हैं। इसके बाद कहना चाहूंगा कि राज्य की जी.एस.डी.पी. में खुद का कर राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत जी.एस.टी. है और इसको लेकर जो तरह-तरह की बातें हो रही थी। हम इस सदन में जी.एस.टी. की बातों को लेकर विभिन्न समयों में अलग-अलग चर्चाएं कर चुके हैं। पक्ष-विपक्ष के द्वारा जी.एस.टी. की भ्रान्तियों को लेकर, उससे होना वाला फायदा क्या है, उससे होने वाला नुकसान क्या है, इन सारी चीजों पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन चर्चा करने के बाद मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारे राज्य का खुद का कर राजस्व सबसे बड़ा स्त्रोत 34 प्रतिशत हिस्सा यहीं से होने का अनुमान है। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आय में कितनी वृद्धि हो रही है। वर्ष 2024-2025 के संशोधित अनुमान से 10 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। जो बिक्री कर है, जो वैट कर है, जिससे हमें राजस्व की प्राप्ति होनी है, उसको वर्ष 2024-2025 के संधोशित अनुमान से अनुमानित करेंगे तो 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। साथ ही राजस्व उत्पाद शुल्क से वर्ष 2025-2026 में हमारी जो राजस्व की प्राप्ति होनी है, उसको वर्ष 2024-2025 के संशोधित अनुमान से अनुमानित करेंगे तो 19 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहां एक तरफ हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए आय के क्या स्त्रोत हैं, हम आय के स्त्रोत में कैसे वृद्धि कर रहे हैं, उसमें हम एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। इसके माध्यम से हमारी राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारे व्यय हैं, उसको हम किस तरीके से भरपाई कर रहे हैं, यह मैं आपको आंकड़े के माध्यम से बताना चाह रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- कौशिक जी, एक मिनट। आप बहुत अच्छा बोलत हौ। माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- आप बार-बार मत उठा कीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- हमर वित्त मंत्री जी बइठे हे, ओ हर बहुत वरिष्ठ हे, ज्ञानी हे। मंत्री जी तो हमर कलेक्टर साहब भी रिहीस हे। मैं ज्यादा कुछ नई जानव, लेकिन मैं चौधरी साहब जइसे एक झन पढ़े-लिखे आदमी ल पूछे कि छत्तीसगढ़ म अभी तक कतना रूपये के कर्जा हावय? ता ओ हर मोला कर्जा ल बताइस। मैं ओखर से पूछे कि छत्तीसगढ़ के जनसंख्या कतना हे? ता ओ हर कहिस कि इहां लगभग 3 करोड़ के जनसंख्या हे। मैं ओला पूछे कि ओ 3 करोड़ जनसंख्या में बांट दिहा त कतना कन कर्जा होवत हे? मोला सदन ल बताते हुए अत्यंत दु:ख होवत हे, सदन के ऊपर म बइठे आदमी मन देखत भी होही ऊहूं मन के मुड़ म 43,000 रूपये के कर्जा हावय। मतलब कोई लइका अभी भी जन्म ही

ता ओखर 43,000 रूपये के कर्जा रही। ये कर्जा म तुमन बूड़ोत हौ। जे कर्जा ल हमन पांच साल म ले रहे हन, वाह रे मोर चौथ इंजन के सरकार हो, ओ कर्जा ल तुमन डेढ़ साल म ले देहे हौ अऊ दारू भट्ठी ल खोलत हौ। अब आप बात करौ।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, आप पिछले समय भी विधायक रहे हैं। जब आप पिछले समय विधायक थे तो डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा जो 15 सालों में कर्जा लिया गया था ..।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही बताने के लिए वित्त मंत्री जी को भी और कोई नहीं मिला क्या? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा पिछले 15 सालों में कर्ज लिया गया था, उससे ज्यादा आप लोगों ने एक साल में ले लिया था। यदि प्रदेश को किसी ने डूबाने का काम किया है तो पूर्ववर्ती क्रांग्रेस की सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने बिना सोचे-समझे और बिना नीति के कर्जा लेकर खर्चा किया, उसके कारण से छत्तीसगढ़ डूबी। माननीय सभापति महोदय, यदि हम इस बजट में हमारे मुख्य क्षेत्रों में हमारे राज्य की व्यय की तुलना की बात करें। मैं थोड़ा सा तुलना करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में अलग-अलग मद में हमने कितना व्यय किया है और अन्य राज्यों की इसमें क्या स्थिति है? वित्तीय वर्ष 2025-2026 में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए इस बजट के कुल व्यय का 16.2 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अन्य राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए जो औसत आबंटन है वह लगभग 15 प्रतिशत के आसपास है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में औसत आबंटन 6.2 प्रतिशत अधिक है। सड़कें एवं पुल मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में छत्तीसगढ़ में सड़कें एवं पुल में व्यय के लिए 5.1 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। अन्य राज्यों में सड़कें एवं पुल के लिए औसत आबंटन 4.3 प्रितशत अधिक है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-2026 में छत्तीसगढ़ में कृषि के लिए अपने व्यय में 16.3 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2024-2025 द्वारा अन्य राज्यों द्वारा कृषि के औसत आबंटन से 6.3 प्रतिशत काफी अधिक है। इससे सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। मैं केवल पूर्ववर्ती सरकार की बात नही करता हूँ । सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश का आधार कृषि है, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसानों और कृषि के लिये हमारी सरकार के द्वारा जो बजट प्रावधान किये गये हैं, जब हम अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो वह 6.3 प्रतिशत में थे और हमारी सरकार 16.3 प्रतिशत में है । सभापति महोदय, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी छलांग लगाये हैं । सभापति महोदय, वर्ष 2025-2026 में आवास के लिये अपने व्यय का 5.6 प्रतिशत आवंटित किया गया है और वर्ष 2024-2025 में अन्य राज्यों द्वारा आवास के लिये औसत आवंटन की बात करें तो 1.3 प्रतिशत है । सभापति महोदय, आज पूरे हिन्दुस्तान में अन्य राज्यों की जो स्थिति है और विभिन्न सेक्टर में जो बजट दिये गये हैं,

उस बजट के मुकाबले हम छत्तीसगढ़ में कहां पर खड़े हैं, यह स्पष्ट परिलक्षित होता है । सभापति महोदय, मैं तीन बातें रखना चाहता हूँ, आज हम विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं और विनियोग हमारा पारित हो जायेगा और सरकार को खर्च करने के लिये राशि मिल जायेगी, लेकिन सरकार को जो राशि मिलेगी, उसे कैसे खर्च करें, यह भी महत्वपूर्ण विषय है । सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने और हम लोगों ने इस बात को सदन में रखा है कि बजट प्रावधान के बावजूद राशि खर्च क्यों नहीं हो पा रही है? सभापति महोदय, गुड गर्वनेंस के माध्यम से यह व्यवस्था की जा रही है, ई-आफिस से हमारे फाईल की जो गति है, हमारा मूवमेंट है कि हमारी फाईल कहीं पर न रूके, हमारी फाईल तेज गति के साथ में बढ़नी चाहिये, इसके लिये ऑनलाईन तरीके से फाईल का निपटारा हो । सभापति महोदय, इसके तहत जवाबदारी तय की जा रही है, यदि विलंब हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, विलंब क्यों हुआ है, इसमें किसी प्रकार की गुंजाईश न रहे, यहां तक मुख्यमंत्री का आफिस भी ई-आफिस से जुड़ा हुआ है, ताकि सरकार के विकास की गाड़ी सरपट दौड़े और इसके लिये ई-आफिस प्रणाली अपनाई गई है । मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । सभापति महोदय, हम जब बजट में सड़क पास करे, पुल-पुलिया पास करें, हम बिल्डिंग पास किये, उसका एक समयावधि होता है,उस समयावधि में कार्य पूर्ण होना चाहिये, यदि उस समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो बाद में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है और निर्धारित राशि से अधिक राशि में हमारे निर्माण कार्य पूर्ण होते हैं और इसके लिये सरकार के द्वारा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है कि हम करप्शन को कैसे रोक सकते हैं, यदि कार्य में विलंब हो रहे हैं तो उसे जल्दी कैसे करें ? सभापति महोदय, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के द्वारा लगातार चेक किया जाता है और वह निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होने चाहिये, जिससे भ्रष्ट्राचार की गुंजाईश न रहे । सभापति महोदय, हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हमारी सरकार केवल जीरो टॉलरेंस की बात नहीं कर रही है, बल्कि इस सवा साल में हमने जनता के बीच में विश्वास अर्जित किया है । हमने जीरो टॉलरेंस प्रशासन चलाकर दिखाया है, यह इस बात का प्रमाण है और इसके लिये अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, इसका लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से मिलेगा । इसके साथ ही साथ सरकारी खरीदी में भी किसके द्वारा खरीदी की जानी चाहिए, उसको निर्धारित किया गया है, वह केन्द्र सरकार का जेम पोर्टल है । खरीदी में किसी प्रकार से लापरवाही न हो, उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाईश खतम हो । बहुत सारे सुधार हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा सुगम ऐप के माध्यम से किया गया है । वित्त मंत्री जी ने सुगम ऐप लाकर हमारे जो फर्जी रजिस्ट्री होती थी, आप देखेंगे कि एक जमीन की तीन बार रजिस्ट्री हो गई। एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री किया, दूसरे व्यक्ति ने रजिस्ट्री किया, तीसरे व्यक्ति ने रजिस्ट्री किया और रजिस्ट्री करने के बाद हमारे किसान परेशान हैं कि जमीन मैंने खरीद ली है, लेकिन जमीन खरीदने के बाद में जमीन

उनके पास में नहीं है, वह रजिस्ट्री होकर दूसरे के पास में चली गई । इन सारी प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए सुगम ऐप की मदद ली जा रही है । उसके साथ ही साथ में हम पेपर लेश की ओर बढ़ रहे हैं । यह बात बार-बार उठाई जाती है, जब हमारे वित्त मंत्री जी टेबलेट के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया तो कहा गया कि यह नियम नहीं है कि टेबलेट के माध्यम से बजट प्रस्तुत करें । अभी तक पेपर के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया है । आज केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पेपर लेश की तरफ बढ़ रही है । जब हमारे देश की लोकसभा पेपर लेश की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया पेपर लेश की तरफ बढ़ रही है तो हमारे वित्त मंत्री जी ने तय किया कि हम छत्तीसगढ़ की विधान सभा को भी पेपर लेश की तरफ ले जाएंगे और यह बहुत सारी पुस्तिका पड़ी है, उससे मुक्ति मिलेगी ।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन पेपर ला देखके मत पढ़ौ न । पेपर ला देखके पढ़ेथे अउ पेपर लेश कहाथे । हिम्मत हे तो तुमन बिना पेपर ला देखे बोल के बतावव।

श्री उमेश पटेल :- पेपर लेश बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले व्यवस्था बना लीजिए । उसके बाद पेपर लेश कर लीजिए, कौन मना कर रहा है । प्रश्न इसीलिए उठ रहा है कि व्यवस्था नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री जी ने दो बजट पेपर लेश प्रस्तुत किया ।

श्री उमेश पटेल :- यहां कोई आरोप तो नहीं लगा रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम महंत जी को धन्यवाद देते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- विधान सभा की व्यवस्था होती है । आप उसकी व्यवस्था बना लीजिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मेरी बात सुन लीजिए । हम महंत जी को धन्यवाद देते हैं । जब वे स्पीकर थे तो छत्तीसगढ़ की विधान सभा में पहली बार प्रश्न ऑनलाईन लिया गया था । आपको भी जानकारी है, पिछली बार आप भी सदस्य रहे हैं । पहले हम प्रश्न आफ लाईन लगाते थे, लेकिन महंत जी के समय से हमने ऑनलाईन प्रश्न देना शुरू किया है ।

श्री उमेश पटेल :- आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं । आपने यह कहा कि कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अभी भी उठाते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- प्रश्न इसलिए उठता है कि व्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष जी उसकी व्यवस्था बना देंगे, वह हो जाएगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- जब हम ऑनलाईन की तरफ बढ़ रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- वैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब हम नई विधान सभा जाएंगे तो वह सबके लिए उपलब्ध रहेगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- नई विधान सभा की बात नहीं है । इसी विधान सभा में हम लोगों को अपने प्रश्न जमा करने के लिए विधान सभा में आने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- यह व्यवस्था बनी न, वैसी व्यवस्था सदस्यों के लिए भी बना लीजिए कि आप सिर्फ पेपर से ही बोल सकते हैं, यह व्यवस्था है, उसको हटा दीजिए । यहां पर टेबलेट, मोबाईल उपयोग करने की आजादी हो ।

श्री धरम लाल कौशिक :- हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- पहले आप व्यवस्था बनवा लीजिए । आप दोनों अलग-अलग बातें कर रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं अलग-अलग बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- व्यवस्था बना लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन सिर्फ भाषण दे सकत हे । हम 2047 में शुरू करेंगे, कहिथे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- जब महंत जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने ऑनलाईन प्रश्न शुरू किया था ।

श्री उमेश पटेल :- वह व्यवस्था सबके लिए था, एक-एक विधायक के लिए था। वह व्यवस्था है । वैसे ही व्यवस्था सबके लिए बना दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- कब बबा मरहि त कब बरा चाबबो, तुमन के तो अईसे हे । 25 साल बाद होही ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति जी, जब चरण दास महंत जी स्पीकर थे, तब उन्होंने यह व्यवस्था करवाई और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे युवा वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी ने किया है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल :- आप फिर से गलत बोल रहे हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- वित्त मंत्री जी के द्वारा यहां पर पेपर लेश बजट प्रस्तुत किया गया है ।

श्री उमेश पटेल :- पेपर लेश की महिला मंडल मत करिए, उसके लिए व्यवस्था बना दीजिए । मैं यही कह रहा हूं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- व्यवस्था बनाई जा रही है ।

श्री उमेश पटेल :- नहीं बनाई जा रही है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- व्यवस्था बनाई जा रही है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कर रहा हूं कि आप यहां के परम्पराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं । व्यवस्था बनाईए, उसके बाद बात करिए ।

सभापति महोदया :- उमेश जी, आप बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- विधान सभा को जितना हानि आप लोगों ने पहुंचाया है, उतना आजतक किसी ने नहीं पहुंचाया है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप लोग कभी सुधर नहीं सकते । आप परम्परा की बात करते हो ।

श्री उमेश पटेल :- आप यहां के परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। व्यवस्था बनाइए। (व्यवधान)

सभापति महोदया :- रामकुमार जी बैठ जाइए, आप बार-बार उठकर मत बोलिए। उमेश जी बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक:- आप लोग कभी सुधर नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- [xx] (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक:- आप परंपरा की बात करते हैं। हम पहले आकर प्रश्न जमा करते थे और उसके बाद हमने ऑनलाईन शुरू किया, तो आप परंपरा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था सबके लिए है। जो व्यवस्था सबके लिए है, वह व्यवस्था हुई। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- जब कोई नई व्यवस्था बनाओगे, तो कुछ परंपराएं टूटेंगी तो कुछ नई परंपराएं लागू भी होंगी और हमारी सरकार के द्वारा ये नई परंपरा बनाई जा रही है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यहां क्या एक आदमी के लिए व्यवस्था बनेगी? अगर व्यवस्था बनेगी, तो सारे विधायकों के लिए व्यवस्था बनेगी। एक आदमी के लिए व्यवस्था थोड़ी बनेगी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- भाई, कोई व्यवस्था बनाए तब ना, खाली ऐसी ही थोड़ी व्यवस्था बन जाही। 8 रुपए स्क्वेयर फीट बोली लगथे बिलासपुर जिला मा। का बात करथव महाराज जी? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय डॉ. चरण दास महंत जी का ये बार-बार उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, वह सारे विधायकों के लिए थी और सभी विधायकों के लिए व्यवस्था बनी थी। यहां परंपरा ये है कि मोबाईल, टेबलेट का बिना इस्तेमाल किए हमें बोलना है। या तो वे व्यवस्था बना लें कि यहां टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, वह सबके लिए ओपन हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि नई विधान सभा में जायेंगे, तब ये व्यवस्था लागू करेंगे लेकिन आप जो महिमा मंडन कर रहे हैं, वह गलत है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय सभापति महोदया, जब मैंने पिछली बार और इस बार टेबलेट पर यहां बजट प्रस्तुत किया, तो सम्माननीय स्पीकर महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली थी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है और आज हम सब लोग विनियोग पर चर्चा कर रहे हैं। हम पारदर्शिता लाने के लिए सब काम कर रहे हैं। पारदर्शिता में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर डी.एम.एफ.(खनिज न्यास निधि) का बहुत नाम चला। खनिज न्यास निधि का किस प्रकार से आपने दुरुपयोग किया, उसे आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो [xx] की आप बात करने हैं ना, खनिज निधि का यदि किसी ने [xx] किया है, तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया है। (शेम-शेम की आवाज)

श्री ओ.पी.चौधरी :- और उससे पहले? उससे पहले स्वीमिंग पूल, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट ये किसके शासनकाल में हुआ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, 15 साल हमारी सरकार रही और डी.एम.एफ. को लेकर हमारे एक अधिकारी जेल गए हों, तो आप बता दो? लेकिन आपकी सरकार आई, ये मामला इसलिए प्रमाणित है कि आपके अधिकारी और आप लोगों ने किस प्रकार से दुरुपयोग किया है, तो आज उसका परिणाम सामने है कि डी.एम.एफ. का इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि कोई जेल में बंद है तो कोई बेल में है। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, आप भी जांच करवा लीजिए, आपके भी बहुत से लोग चले जायेंगे, क्योंकि मेरे बालोद जिला में गौण खनिज का मामला प्रकाश में है। (व्यवधान) ये मैंने जांच के लिए दिया है, आज तक जांच नहीं हुई, गौण खनिज के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जब आचार संहिता लगी थी, तो बगैर भौतिक सत्यापन के वहां सोलर लाईट लगा दी गई। वहां क्रेडा के नियमों का सरासर उल्लंघन हुआ है। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- आज उससे ज्यादा हो रहा है। कंबल ढ़ाककर घी पी रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ करना है? कंबल ढांककर 40 परसेंट। 40 परसेंट का उजागर हुआ है।।(व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, चलो मैं बता रहा हूं। मैं आपको केवल एक उदाहरण बता रहा हूं कि आपने डीएमएफ में क्या किया और हमने डी.एम.एफ. में क्या किया। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- किसको कहते हैं 40 परसेंट?

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, बइठे हे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, ये लोग डीएमएफ में क्या किये हैं, वह यहां नहीं बल्कि पूरी दिल्ली और देश में चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ को किसी ने बदनाम किया और छत्तीसगढ़ में करप्सन की पहचान बनाई, तो वह कांग्रेस की सरकार ने बनाई। (शेम-शेम की आवाज) लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या किया। जो डीएमएफ की खनिज निधि है, आपने उसका [xx] किया और हम दंतेवाड़ा में 250 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कालेज बनवा रहे हैं। हम

ये डी.एम.एफ. का उपयोग कर रहे हैं ताकि वह वहां रहने वाले बच्चों के काम आए, वहां हमारे डॉक्टर बनकर निकलें। हमारा पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, जो नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्र हैं, हम ऐसे क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज बनाकर उस डी.एम.एफ. की राशि का उपयोग करना चाहते हैं। हम उसको जनहित के मुद्दे पर लगाना चाहते हैं।

श्री राजेश मूणत :- लखेश्वर भाई, आप सीनियर विधायक हैं और बस्तर से आते हैं। आप बस्तर की राजनीति से परिपक्व हैं। आप एक उदाहरण दीजिये कि बस्तर के आदिवासियों के हित में कांग्रेस पार्टी ने तब से लेकर आज तक कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो ? कांग्रेस पार्टी ने पूरे बस्तर में कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट भी लाया हो तो बता दीजिये। चाहे वह प्रयास संस्था हो, चाहे जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे दंतेवाड़ा का हो, चाहे सुकमा, बीजापुर, जिले का निर्माण हो, आप एक सिंगल काम बताईये, जो कांग्रेस पार्टी ने किया हो ?

श्री लखेश्वर बघेल :- अलग से बता देंगे। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदया, यह जो प्रश्न करते हैं फिर मंत्री जी बोलते हैं कि मैं आपको बता दूंगा, वैसे ही आप दोनों बैठकर मत पूछ लेना।

माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो वर्थ डिपार्टमेंट है, जैसे पी.डब्ल्यू.डी. हो गया, पी.एच.ई. हो गया, जल संसाधन हो गया और भी ऐसे अन्य विभाग हैं, जहां पर हमारे हैण्ड्स बढ़ने चाहिए, हमारे संसाधन बढ़ने चाहिए, जिसके अभाव में हमारे काम प्रभावित होते हैं, जिसके कारण लागत भी बढ़ती है, उसमें अधिक समय लगते हैं और जिसके कारण हमारे कई कार्य अपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा और उसके बाद इन तीनों डिपार्टमेंट में हमने एक साल में 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की अनुमति दी है और उसके लिए बजट में 9500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) निश्चित रूप से इनकी नियुक्ति हो जाने के बाद काम की गति बढ़ेगी और उसके बाद उसका रिजल्ट भी हम सब के सामने दिखाई देगा। इसी प्रकार से ग्राम सड़क योजना के लिए 850 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, हम देख रहे हैं कि हमारी जो एप्रोच रोड है, जो गांव से जुड़ी हई नहीं है, इसके साथ ही वहां पर हमारे जो मजरे टोले हैं और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, उन स्थानों के लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है। हम ग्राम सड़क योजना के तहत उनको जोड़ सके और सुनियोजित रूप से उसका विकास हो सके। मजरे टोले में विद्युतीकरण करने का, उनको सड़कों के माध्यम से जोड़ने का, वहां पानी पहुंचाने का, इस प्रकार से विभिन्न विभागों के माध्यम से बजट में प्रावधान किया गया है। हम समाज के अंतिम छोर में, प्रदेश के अंतिम सिरा में बसने वाले लोगों तक खुशहाली पहुंचा सके, हम वहां सुविधाएं पहुंचा सके और उसके लिये हमारे जो काम प्रारंभ हुए हैं, उसमें निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएं और आशाएं रही हैं और आज वह दिखने लगा है कि उनकी आकाक्षाएं भी पूरी होने वाली है।

इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में बसें नहीं चल रही है, जहां पर गाड़ियों का अभाव है, जहां के लोग कभी बसों में बैठे नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री बस योजना शुरू की जा रही है। जहां लोगों ने कभी फोन में बात नहीं की है, वहां पर मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरू की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमारे समाज के विकास का मापदण्ड क्या होना चाहिए। उसका मापदण्ड समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का विकास है और इसके लिये मैं हमारे मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देव साय जी को और हमारे युवा वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिये, विकास की कड़ी को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिये सारे प्रयत्न किये गये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे के संबंध में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मेट्रो का जो सर्वे करा रहे हैं, वह रायपुर से दुर्ग तक करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बिलासपुर जुड़ना चाहिए। क्योंकि उसमें बिलासपुर नहीं जुड़ेगा तो यह आपकी परियोजना अधूरी है। इसलिए आप जो मैट्रो के लिए सर्वे करवा रहे हैं, आप इसकी राशि बढ़ायें। मैं आपसे यह मांग भी कर रहा हूँ, उस अंचल के लिए जिस अंचल से आप आते हैं। यह जो मैट्रो का सर्वे है, यह रायपुर से दुर्ग नहीं, बल्कि बिलासपुर से रायपुर और दुर्ग तक जुड़ना चाहिए और आज आप इस सर्वे के लिए राशि की घोषणा करेंगे। जब उसका डी.पी.आर. बन जाएगा तो उसमें अलग से देखेंगे कि बाद में कितनी राशि प्रावधान करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ सर्वे हो जाए तो मुझे यह लगता है कि इसका लाभ मिलेगा और उसमें आप समुचित रूप से तीन संभागों को जोड़ पायेंगे। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, आप इन तीनों संभागों को जोड़ने में सफल होंगे। आप लोग भी समर्थन करेंगे? जो इधर बैठे है, सब लोग समर्थन करेंगे।

माननीय सभापति महोदया, मैं नई उद्योग नीति पर कहना चाहूंगा। यहां जो नई उद्योग नीति लायी गयी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। इस नई उद्योग नीति के माध्यम से हमारे यहां पर लोग आएंगे और यहां आकर एम.ओ.यू. करेंगे। फिर एम.ओ.यू. करने के बाद, यहां पर अपने संयंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ। यहां पर उद्योग मंत्री भी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने भी उद्योग नीति लायी थी।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदया, माननीय धरम जी, उस समय आप नेता प्रतिपक्ष रहे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने इस बात को उठाया था।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदया, उस समय एम.ओ.यू. हुए, वह कैसे हुए थे? मैं बता रहा हूँ कि एक बार उन सब का परीक्षण जरूर करवा लीजिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, जब आपने एम.ओ.यू. किया तब आप लोगों ने कहा कि इससे इतने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय राजेश मूणत भईया, आज आपको क्या हुआ है? आप आपने कुछ तो अलग खाया है?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, जब एम.ओ.यू. भी हो जाए तो एम.ओ.यू. होने के बाद हमारे यहां कितने उद्योग आ रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार देने के लिए एम.ओ.यू. किया है और वास्तव में यहां पर कितने संयंत्र लगे हैं ? उसमें कितना उत्पादन शुरू हुआ ? उसमें हमारे लोगों को कितना रोजगार मिला ? मैं यह समझता हूँ कि जो पिछला एम.ओ.यू. हुआ है उसे देखकर, आज हमें नये सिरे से उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

श्री राजेश मूणत :- आप बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, उस समय जो एम.ओ.यू. करने वाले Director थे, वह अभी अंदर कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जरा उनका भी ध्यान रखना। भाई ऐसा एम.ओ.यू. न करें कि किसी को अंदर जाना पड़े।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ कला कौशल के बारे में कहना चाहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि आपके कोण्डागांव, जगदलपुर, चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर की बात करते हैं। जहां हमारे नये-नये अलग-अलग उत्पाद होते हैं। हम कोसे की साड़ी को देखें, जो हमारे इस प्रदेश की पहचान है। आपके यहां बेल मेटल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, रायगढ़ में जो काम हो रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो बैम्बू के काम हैं, टेराकोटा का काम है, हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं और हमारी सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इन उत्पादों को कैसे बाजार मिले। हम इन उत्पादों को बाजार तक कैसे ले जा सकें ? उसके लिए इस बजट में जो प्रावधान रखे गये हैं और उसके लिए जो व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा नया रायपुर में National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना करने का निर्णय किया गया है ताकि इन कलाकृतियों का भी आधुनिक तकनीक से सृजन हो, जैसा आज यह लोग चाह रहे हैं। उसके अनुरूप उसका सृजन किया जा सके और उसका सृजन करने के बाद उसका काम प्रारंभ कर सकें। आपने यहां पर बहुत सारे कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे महाविद्यालयों, फिजियोथैरेपी की बात की है। हमारे प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें उन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा जो अभी तक वंचित रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, आपने एक बहुत अच्छा किया है। यहां 25000/- रूपये तक जी.एस.टी. को लेकर, जिनका 10 सालों तक मामला लंबित रहा। यह मामले लंबित होने के कारण उनका निपटान नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण वह ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे।

समय
5.00 बजे

माननीय सभापति महोदया, उसमे कोई बहुत ज्यादा लागत की नहीं, बहुत रिबेट देने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो तकलीफ में थे, उसका जो निर्णय लिये हैं और एक झटके में उसको खत्म करके बहुत लोगों को सुविधा दिये हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। जब आप समीक्षा करेंगे तो इसी प्रकार से निर्णय होगा। आप जैसे वित्त मंत्री बैठेंगे तो इस प्रकार के निर्णय आयेंगे। इस प्रकार के निर्णय लेने से जो अधिकांश समय कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, उनको उससे मुक्ति मिली है। हम बिजली की बात कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जी को चिंता है।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- कौशिक जी, एक मिनट। विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण हेतु सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित है। चूंकि विनियोग विधेयक पर चर्चा जारी है। अत: विनियोग विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक के पारण का कार्य किया जायेगा। मैं समझती हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। हम यह चिंता करते है कि हमारी बिजली की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े। आज हमारे प्रदेश में 2100, 2200 यूनिट उपभोग की क्षमता छत्तीसगढ़ के लोगों की है और उसके लिए हमको नये पॉवर प्लाण्ट बनाने की आवश्यकता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे थे कि 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के पॉवर प्लाण्ट हैं और 20, 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन के पॉवर प्लाण्ट बनाने की आवश्यकता क्यों ? यही बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक जितनी सरकारें और मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उन्होंने बिजली के उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहे हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल में 400 मेगावाट बिजली की क्षमता कम हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता के ऊपर में यह प्रश्नचिन्ह है कि जिनके कार्यकाल में 400 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता कम हुई है। नहीं तो हर मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि मेगावाट की क्षमता बढ़नी चाहिए। आज प्रदेश में नये उद्योग आ रहे हैं। जहां

किसानो के 73 हजार पंप के कनेक्शन थे, आज 5 लाख से ऊपर पंप के कनेक्शन हो गये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बिजली के बारे में जो भी बोल रहे हैं, सब सहमत हैं। पिछली बार जब आप इधर नेता प्रतिपक्ष थे, आप हर समय इस बात को लाते थे कि किसानों को स्थाई कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। आप एकात बार तो बोलिये कि किसानों को स्थाई कनेक्शन दिया जाये। आप उधर जाते ही किसानों के बारे में बोलना छोड़ दिये। स्थाई कनेक्शन की बात बताईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बजट को पढ़े नहीं हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं बजट को पढा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप यह बताईये कि कितने का प्रावधान किये हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- महासमुंद जिले में 1500 स्थाई पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी स्थाई कनेक्शन के लिये कितने रुपये का प्रावधान किये हैं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बजट का प्रावधान कर देने से समस्या का हल नहीं है। आप धरातल में बताईये। मेरे केवल एक जिला में 1500 स्थाई पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको बता रहा हूं, आप तो बता नहीं पाये। हमारी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता दी है। आप केवल इसलिए पंप कनेक्शन नहीं दे रहे थे कि 1 लाख रुपये कहां से लायेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप गुमराह कर रहे हैं। आप महासमुंद जिले में चलिये 1500 स्थाई पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी हमारी सरकार के द्वारा अधूरे पंप के कनेक्शन को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है और हमारे पंप के कनेक्शन लगेंगे। हम कम बिजली की बात नहीं करते, हम उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम 20 हजार मेगावाट कैसे बढ़ा सकें, हम उस चिंता में लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- द्वारिकाधीश यादव जी, आपके पास पुन्नूलाल मोहले जैसे कोई आदमी नहीं है जो क्षमता बढ़ा सके।

श्री धरमलाल कौशिक :- किसानो के पंप कनेक्शन देने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ठीक है, आप 50 करोड़ रुपये करवाईये, आप किसानों का मेगावाट बढ़ा रहे हैं, बिजली उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसानों के लिये 6-6 घंटे लाईट गोल रहती है। आप क्षेत्र में जाकर देखिये, कितनी बात होती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो बिजली उत्पादन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने बिजली बिल का रेट बढ़ा दिया, आप बहुत ज्यादा उत्पादन कीजिए, लेकिन हमारी जनता को सुविधा दीजिए न। आप बिजली बिल कम कीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो बिजली बिल बढ़ा है न, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आपको भी कि स्मार्ट मीटर लगाने का एग्रीमेंट किसने किया है? किसको काम दिये हैं और सारा जो किया हुआ है, आज बिजली बिल बढ़ाने की बात कर रहे हैं । यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, पूर्व मुख्यमंत्री ने बिजली बिल हाफ किया था । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- इनके द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया, यह उसके कारण है । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप कम कर दीजिये न । आपकी सरकार है, आप कम कर दीजिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल हाफ किया था । आपके लोगों ने चीटिंग करके, मीटर रीडर लोगों ने चीटिंग की है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जो एग्रीमेंट किया है आपको उसकी तारीख निकालकर देखना चाहिए कि एग्रीमेंट कब का है । संगीता जी आप पिछली बार भी विधायक रही हैं, आप थोड़ा सा एग्रीमेंट की कॉपी सूचना के अधिकार में नहीं तो आप विधानसभा में प्रश्न लगाना कि उसका एग्रीमेंट किसने किया, किस तरीख को एग्रीमेंट हुआ है । उस एग्रीमेंट की शर्तें क्या-क्या हैं और उस एग्रीमेंट के एवज में क्या लिया गया है, आप उसको भी थोड़ा देख लेना । उसके कारण आज आप जो बोल रहे हैं न, चूंकि उस समय हमने मना किया था कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए तब वहां बैठे हुए जो मुख्यमयंत्री थे उनके द्वारा एग्रीमेंट करने का काम किया गया था । आप बोल रही हैं कि यहां पर 3 घंटे बिजली नहीं है, 7 घंटे बिजली नहीं है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 7 घंटे बंद रहता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- कितने घंटे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 7 घंटे भी बंद रहता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलो, 7 घंटे बंद है तो बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए ? आप बताओ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं । मैं तो पूछ रहा हूं कि बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसको बढ़ाना चाहिए लेकिन कम नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कौशिक जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह सुविधा तो पहले भी थी, पहले लाईट बंद नहीं होती थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तेलंगाना में आपकी सरकार है ।

श्री उमेश पटेल :- तेलंगाना में पहुंच गये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बता रहा हूं न, मैं यहीं से जोड़ रहा हूं । वह 8 हजार करोड़ रूपये...।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये न । वह मोदी जी के प्रोजेक्ट स्मार्ट मीटर को भी वह यहां क्रिटिसाईज कर रहा है, आप समझ लीजिये कि क्या-क्या हो रहा है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तेलंगाना ने 8 हजार करोड़ रूपये हमारे छत्तीसगढ़ का बिजली का बिल नहीं दिया है तो 6 घंटे बंद है, 3 घंटे बंद है ।

श्री उमेश पटेल :- तो आप उसको मांगिए न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको पैसा दिलवाईए ।

श्री उमेश पटेल :- हम क्या दिलवायेंगे, सरकार उधर की है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तब तो यहां बिजली देंगे ।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, 43 मिनट हो गये हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदया, मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

श्री उमेश पटेल :- आप समझ लीजियेगा कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की योजना है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो बिजली बिल की बात कर रहे हैं न, हम तो उसको रोककर रखे थे कि उसको रोको ।

श्री राजेश मूणत :- उमेश जी, क्या है कि धरम जी को 4-5 लोग मिलकर भी नहीं घेर पाओगे ।

श्री उमेश पटेल :- भैया वह इतने सीनियर आदमी हैं कि उसको पूरा सदन मिलकर नहीं घेर सकता है । आप कहां लगे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननी सभापति महोदया, मैं आपको एक-एक लाईन में बता देता हूं कि जो अच्छे काम हुए हैं और इस बजट में प्रावधान रखे हैं । मैं मुख्यमंत्री परिवहन योजना की बात की । मोबाईल टावर की बात की और इसके साथ में एक अच्छा काम कि हमारे जो शहर हैं, हमारे चाहे वह नगर पंचायत हो, नगरपालिका हो, चाहे हमारे नगर-निगम हों । ऐसे जो क्षेत्र है, आसानी के साथ में हम उसमें कैसे पहुंच सकें उसके लिए फोर लाईन और फोर लाईन के साथ में बाईपास रिंगरोड बनाने की व्यवस्था यह बजट में जो प्रावधान कर रहे हैं । गृह प्रवेश सम्मान योजना, निर्धारित समय में अपने घर बनाएं और घर बनाकर के उसमें प्रवेश करें । आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि अपने घर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए लेकिन हमारे पंचायत मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गरीब आदमी अपने घर में प्रवेश करेगा उनको उनका सम्मान करेंगे और उसके लिए सम्मान के लिए

राशि की व्यवस्था की गई है । गवर्नेंस फेलोशिप IIT और IIM के छात्रों को फेलोशिप देने का प्रावधान । सियार केयर योजना कि हमारे जो सियान हैं उनके केयर करने के लिए जिला में उनकी व्यवस्था की जा रही है । सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना । यह माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और इस योजना के अंतर्गत कि आपको मुफ्त में कैसे बिजली पहुंचायी जा सके, इसके साथ में अटल सिंचाई योजना । एस.एस.आई.पी. का क्रिन्वायन, नयी स्टार्टअप नीति और इसके साथ में बहुत समय से यह मांग चल रही थी कि डी.ए. को लेकर बार-बार मांग की जाती थी । आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो डी.ए. दिया जा रहा है उसके बराबर 53 परसेंट हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) साईंस सिटी, आप बड़े शहरों में साईंस सिटी बना रहे हैं । वित्तमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप रायपुर में साईंस सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस तर्ज पर आप संभाग एरिया को भी चिन्हांकित कीजिये, मैं अभी जिले की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे 5 संभाग हैं तो रायपुर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगदलपुर में अच्छा काम कर रहे हैं, अब इसके अलावा जो बचे हुए संभाग हैं, वहां भी साइंस सिटी के लिए आप काम करेंगे तो वहां के छात्रों को भी और वहां के लोगों को भी देखने को अवसर प्राप्त होगा। मैं एंटी नारकोटिक्स एक्ट के बारे में कहना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जो व्यसन है, इस व्यसन से हम यहां के युवाओं को कैसे हम बचा सकें। उसमें केवल शराब की बात नहीं है, बल्कि शराब के साथ में अन्य जो सिरप से लेकर बाकी चीजों का उपयोग करते हैं। यह निश्चित रूप से एक बेहद चिंता का विषय है। यदि युवा रास्ता भटक जाये और भटक कर गलत दिशा में चला जाये, हम कितना भी विकास करेंगे, उसका लाभ होने वाला नहीं है। हमारे युवा सकारात्मक दिशा में जाये और हम नशा के क्षेत्र से उनको उबार कर ले जायें, इसके लिए भी हमको कार्य योजना बनाने की जरूरत है और अगर हम यह कार्य योजना बनायेंगे तो हमें निश्चित रूप से से लाभ मिलेगा। हमारे एस.ओ.जी., एंटी नारकोटिक्स में तीन नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मैं बहुत सारी बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता। आज जिन पदों की जरूरत नहीं है और जिन नए पदों का सृजन करना है या जो खाली हैं, उनको फिल-अप करना है, उस तरफ मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि यहां पर अस्थाई रूप से काम करने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, उनकी लगभग आधी उम्र बीत गयी है। पिछले समय जब डॉ. रमन सिंह की सरकार बनी, उस सरकार में हमने कुछ विभागों जैसे पी.डब्ल्यू.डी., वन विभाग और विभागों के जो लोग 12 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे थे, उनकी नियमितीकरण करने का काम किया गया था। मैं समझता हूं कि इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए और जो लोग बहुत समय से अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उन अनियमित लोगों की नियमितीकरण भी हमारे लिए आवश्यक है। उस दिशा में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाह रही हूं, सचिव लोग भी नियमितीकरण के लिए बैठे हुए हैं, उनका भी शासकीयकरण कर लीजिए। निवेदन है कि आप सबका करवा रहे हैं तो उनका भी करवा लीजिए, सुन लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं धान के विषय में बोलना चाहता हूं। हम धान का 3100 रूपये दे रहे हैं। आज जो लोग दूसरी फसल ले रहे थे, वे भी धान की तरफ आकर्षित हो गए। यह जो बोझ है, वह आने वाले समय में भी बढ़ने वाला है। धान की एवज में हमारा विकल्प क्या हो सकता है? क्योंकि आप यह देखिए कि अभी हम 3100 रूपये में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में 3100 से बढ़ न जाए। इसलिए अभी से हमको विकल्प तलाशने की और ढूंढने की आवश्यकता है कि धान की एवज में हम दूसरी फसल क्या लें, जिससे धान के उत्पादन के साथ में हमारी अन्य चीजों का भी उत्पादन बढ़े। मैं उसके लिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिससे किसानों को नुकसान भी न हो और हम धान को छोड़कर अन्य फसल की तरफ भी जायें। मैं एक सियान सदन की बात करना चाहता हूं कि जो हमारे छोटी नगर पंचायत, नगर पालिका है, में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक लोगों के लिए एक सियान सदन की स्थापना होनी चाहिए। हम नालंदा परिसर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सब जगह नालंदा परिसर बनाना संभव नहीं है। आपने 17 जगह को चिन्हांकित किया है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अभी जो 17 जगह चिन्हांकित किये हैं, उसको आप जिले तक ले जाने में सामर्थ्यवान हैं, ले जाएंगे, लेकिन हमारे जो छोटे नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहां नालंदा परिसर न हो, लेकिन एक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए। उस लाइब्रेरी की स्थापना के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप एक लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि सवा साल के अंदर में इस बजट के माध्यम से मैंने बात की कि लोगों की जो उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों को आपने पूरा करने का काम किया और उसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया तो निश्चित ही आने वाले समय में प्रदेश के विकास की गति बढ़ेगी । आपने गति नाम भी दिया है । वह गति दिखाई भी देने लगी है, उसके लिए मैं आपको और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । मैं चार पंक्तियां कहकर अपनी बात को विराम देता हूं - गति का बजट है, साहब यह गति का बजट है एक नई सुबह लाता है, विकास की राहें हर क्षेत्र में खोलता है, हर किसी के जीवन में खुशियों की बहार और एक समृद्ध भविष्य का संचार करता है । आपको बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

सदन को सूचना

भारतीय प्रबंध संस्थान आई.आई.एम. द्वारा माननीय सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

सभापति महोदय :- भारतीय प्रबंध संस्थान आई.आई.एम. अटल नगर रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों हेतु शनिवार दिनांक 22 मार्च एवं रविवार दिनांक 23 मार्च, 2025 को दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है । पत्रक भाग-दो द्वारा कार्यक्रम की सूचना दी गई है । आप समस्त माननीय सदस्यों से पुन: आग्रह है कि कृपया प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हों ।

समय
5.17 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- अध्यक्ष महोदय, आप विशेष अनुमति देकर, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दे दीजिए । मेरा नाम नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो एक ही विषय पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है। अभी मुझे बाहर पता चला है कि छत्तीसगढ़ की बहादुर पुलिस ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है। (मेजो की थपथपाहट) बार-बार बस्तर की करते हैं ना कि बस्तर से इतना प्रेम क्यों है ? बस्तर से इसलिए प्रेम है कि इतनी खूबसूरत जगह को बदसूरत बनाकर रखने वाले लोगों को विष्णुदेव साय और विजय शर्मा की सरकार के द्वारा खत्म किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की एक मांग रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय भी मैं आपकी कृपा से वहीं था और आज भी मेरा नाम नहीं है इसलिए मैं आपसे अनुमति लेकर दो मिनट बोलना चाहता हूं । माननीय वित्त मंत्री जी, बिलासपुर एक बहुत बड़ा उभरता हुआ शहर है, जहां न्यायधानी है । वहां हमारे एयरपोर्ट की समस्या अभी भी बहुत विकराल रूप में खड़ी है । यह सही है कि थ्री-सी एयरपोर्ट का लायसेंस वहां मिल चुका है, लेकिन इसको फोर-सी केटेगरी एयरपोर्ट की मान्यता दिलाने के लिए वहां के सेना के 1200 एकड़ जमीन में से ढाई या तीन सौ एकड़ जमीन हमें रक्षा विभाग से वापस चाहिए । उसके लिए सरकार की तरफ से पहल भी की गई है । मैं चाहता हूं कि वह जमीन रक्षा विभाग से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाए ताकि वहां पर बड़ा बोईंग विमान उतर सके । बोईंग विमान जब तक नहीं उतरेगा तब तक उस एयरपोर्ट का जो जनता के लिए उपयोग होना है, बहुत हद तक हम नहीं कर

पाएंगे । अभी छोटे-मोटे फ्लाइट चल रहे हैं । अभी छोटे-मोटे फ्लाइट चल रहे हैं, इलाहाबाद, जबलपुर और घूम फिरकर दिल्ली तक । वहां पर अभी जब थ्री-सी एयरपोर्ट है तो उसका भी प्लेन समर शेड्यूल, विंटर शूड्यूल होता है उसमें आप थोड़ा हस्तक्षेप करें और वहां से भी अच्छे शहरों के लिए छोटी फ्लाइट चलवाइएगा जो एटीआर की फ्लाइट होती है, वह चलना चाहिए, बैंगलोर चलना चाहिए, पुणे चलना चाहिए, बनारस चलना चाहिए । वह तो करेंगे ही लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए कम से कम 100 करोड़ रूपए का प्रावधान आपको इसमें करना चाहिए ताकि वहां पर हवाई अड्डे में प्लेन उड़ाने के लिए जो भी आवश्यक सुविधा हो, वहां हम उपलब्ध करा सकें । मेरी जानकारी में अभी शायद 10 करोड़ रूपए का प्रावधान है । इसे बढ़ाकर बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान करेंगे और आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके हमारे बिलासपुर के लोगों को भी रायपुर की ही तर्ज बड़े-बड़े महानगरों से जोड़कर वहां इस सुविधा को दें। हमारे सैकड़ों साथी वहां पर कई साल से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आंदोलन की महत्ता को सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार वहां की जनता को सुविधा देगी तो हमारी सरकार का नाम होगा। वित्त मंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर पहल करेंगे। मैं अबिकापुर का भी बोल रहा हूं। जगदलपुर एयरपोर्ट का भी है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर तो टॉप प्रियारिटी में है, जगदलपुर से शुरू होगा तभी तो बिलासपुर, अंबिकापुर जाएगा। बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर को जोड़िए। बिलासपुर में 4सी एयरपोर्ट की संभावना है, आपके यहां अभी 4सी एयरपोर्ट की स्थिति नहीं है, बिलासपुर को 4सी एयरपोर्ट करना चाहिए। गृहमंत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी पुलिस ने आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। (मेजों की थपथपाहट) उसके लिए इस प्रदेश की जनता और इस विधान सभा की तरफ से बहादुर जवानों के शौर्य को सलाम करते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, हम लोग यहां रोज आकर इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धि बताते हैं, फिर भी आप लोग ये गड़बड़, वो गड़बड़ मत बोलिए। जल्दी से सब प्रस्ताव पास कर दीजिए, मंत्री जी को पावर दीजिए, जल्दी से खर्चा करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आज विनियोग विधेयक में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आपसे पहले यह कहना चाहूंगी कि हम जनता के विश्वास पर जीतकर सदस्य या मंत्री बनकर छत्तीसगढ़ के इस सदन में उपस्थित हुए हैं। हमको छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता करनी चाहिए और बजट को ऐसा तैयार करना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाए। परंतु मैं यहां बजट भाषण सुन रही थी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम एक साल के बजट को विश्वास वर्ष के रूप में जनादेशपरब मनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करते हैं। कहां जनादेश दिख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में GYAN का अर्थ बताया था, GYAN में उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को केन्द्र बिन्दु बनाकर बजट पेश की थी और

अभी GATI को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने GATI में बजट पेश की है। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगी कि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इन्होंने किसानों को एकमुश्त राशि देने का वादा किया था, किसान एकमुश्त राशि के इंतजार में कर्ज में डूब गए, किसान सालभर इंतजार करते रह गए, किसान शुरूआत से निंदाई, कोड़ाई, बीज बोने से लेकर उनको सोसायटी तक धान ले जाते तक कर्ज लेना पड़ा। उसके बाद जब पैसे देने की बात आई तो एकमुश्त की राशि दो किस्त में बंट गई, वह भी अंतर की राशि में मिला। पहले चुनाव है करके अंतर की राशि दी, उसके बाद मूल राशि दी, ऐसी कई जगहों पर किसानों के साथ [xx] हुआ। आज भी आप बजट को उठाकर देख लीजिए, किसानों के लिए कोई भी विशेष बजट का प्रावधान नहीं दिख रहा है जिसमें किसान अपनी आय को दुगुना कर सकें। अभी मेरा एक प्रश्न लगा था, उसमें भी आपने बजट में कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, युवा। बजट में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, आपने पिछले बजट में भी और इस साल के बजट में भी युवाओं के रोजगार के लिए ऐसी कोई तात्कालिक प्रबंध नहीं किया गया है, उसमें खास उल्लेख नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार में जो सहायक शिक्षक की भर्ती हुई थी, आपने उनको भी बेरोजगार कर दिया, आपने उनके लिए भी बजट में राशि नहीं रखी। आज भी शिक्षकों की भर्ती लंबित है। आप रोजगार दे रहे हैं या छीन रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, आपने नारी की बात की है। आपने पिछले बजट में महतारी वंदन के लिए 3 हजार करोड़ रूपए का बजट रखा था, इस साल के बजट में 5500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। परंतु सभी विवाहित महिलाओं को राशि नहीं मिल रही है। उसमें वृद्ध पेंशन और निराश्रित पेंशन में 500 रूपए अंतर की राशि है करके कांट दिया जा रहा है। कई ऐसी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, एकदम निराश्रित हैं, उनकी सूची में नाम नहीं है , इसलिए उसकी राशि नहीं मिलती है। न उनको महतारी वंदन योजना की राशि मिलती है और न ही पेंशन की राशि मिलती है। उनको क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनका नाम वर्ष 2002 और वर्ष 2011 की सूची में नहीं है। यदि जनगणना नहीं होगी तो सूची में उनका नाम कैसे आएगा? यह हमारी नारियों के साथ भी एक तरह का [xx] है। गरीब की बात होती है। जो लोग असहाय हैं, उनको पेंशन ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास की बात होती है तो आवास में यदि देखा जाए तो आज हम लोग 18 लाख-18 लाख आवास सुनकर थक गये हैं, लेकिन आवास निर्माण कब होगा? अभी भी केवल 6 या 7 लोगों के लिए आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत होते हैं। एक पंचायत में बहुत लंबी-लंबी लिस्ट मंगवा ली जाती है और कई लोगों के लिस्ट से नाम गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों का घर बनता है, जिनके पास पक्का घर हो। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि पहले आवास योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती थी, वह 1 लाख, 50 हजार रूपये की राशि मिलती थी और अब उसकी राशि को काटकर 1 लाख, 20 हजार रूपये कर दिया गया है। वहीं पर सीमेंट और छड़ के रेट बढ़ा दिये गये हैं

जबकि गरीबों को तो आपको सुविधा देनी चाहिए। लेकिन आपने तो उसमें कटौती कर दी है तो वह आवास कैसे बनाएंगे? फिर उसके लिए वह कर्ज लेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आप आवास की सुविधा दे रहे हैं या लोगों को लूट रहे हैं? क्योंकि एक तरह से तो वह कर्जा ही ले रहे हैं। 1 लाख रूपये में कोई घर कैसे बना सकता है?

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि यदि आप आवास निर्माण में उनको पूरा सहयोग करते और गृह प्रवेश करवाते तो वह भी ज्यादा अच्छे से खुश होकर गृह प्रवेश करते और उनको भी सहायता मिलती और उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता। मैंने आपको ज्ञान के बारे में तो पूरा बता ही दिया है। अभी सभी जगहों पर मैंने पोस्टर में प्रगति की बात देखी है तो यह प्रगति है या दुर्गति है, इसके लिए इस साल के बजट प्रावधान में इन्होंने एक पंक्ती रखी है। जिसमें उन्होंने कहा था कि :-

कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में,

पूछ उन परिंदों से, जिनके घर नहीं होते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जिनके घर नहीं होते हैं और जिनके यहां बिजली भी नहीं होती है तो उनका क्या होगा? वह तो और अंधेरे में रह रहे हैं। मैंने पिछले बजट में भी ऐसे कई उदाहरण दिये थे। कटेमा में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस बजट में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है जबकि मैंने उसको बजट में रखा था और बताया था कि वहां पर यह स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं। आप बोलते हैं कि हम पानी की सुविधा दे रहे हैं। हर जगह जब स्रोत नहीं था तो आपने पाइप बिछवा दी और पानी टंकी बन गयी। उसके बाद सड़कों की खुदाई हो गई। सी.सी. रोड की खुदाई कर दी गई और वहां पर पूरी पाइप फटने के कारण हम लोगों को कई बीमारियों को भी झेलना पड़ा और बहुत सारी बीमारियां फैलीं। स्रोत नहीं होने के कारण हमको बोर खुदाई करनी पड़ती है। बोर खुदाई हो गई, लेकिन बोर लाइट के बिना कैसे चालू होगा? बिजली में लो वोल्टेज की समस्या है। हमारी संगीता दीदी बता रही थी कि 5 घण्टे तक लाइट गोल रहती है। 5 घण्टे तक लाइट ऑफ, सुबह भी लाइट गोल और रात में भी लाइट गोल होगी तो फिर आज जनता पानी पीने के लिए तरस रही है। अभी तो गर्मी के दिन की शुरूआत हुई है। मैं यह समझ नहीं पाई कि ऐसी स्थितियों में आप आम जनता की क्या गति करेंगे या दुर्गति करेंगे?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि वर्ष 2025 और वर्ष 2026 के अनुमानित बजट में 2 हजार 804 करोड़ रूपये राजस्व अधिव्यय अनुमानित है जबकि सकल वित्तीय घाटा 22 हजार 900 करोड़ रूपये अनुमानित है। राज्य में इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से 19 प्रतिशत, परिवहन से 17 प्रतिशत, आबकारी से 21 प्रतिशत तथा जी.एस.टी. से आय में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। आप शिक्षा, रोजगार और गरीबी के लिए बजट का बहुत कम उपयोग क्यों कर रहे हैं?

जबकि शिक्षा के क्षेत्र में हमको लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा की ओर आपका कोई ध्यान नहीं है। न ही कहीं पर स्कूलों की मरम्मत हो रही है और न ही बजट में बिल्डिंग के उन्नयन की कोई बात रखी गई है और तो और वातावरण तथा पर्यावरण को बचाने के लिए भी किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसकी बजाय सिर्फ शराब दुकानें बढ़ रही हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार में 1 अप्रैल 2025 से होने वाली नई शराब नीति के तहत 67 नये शराब दुकानें खोलने की घोषणा की गई है। इन नई दुकानें खुलने के साथ ही राज्य में शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 714 हो जायेगी। इससे सरकार को अनुमानित राजस्व प्राप्तियां लगभग 12,500 करोड़ रूपए बताया गया है। वर्तमान सरकार, जब पिछली बार विपक्ष में थी, तब शराबबंदी को लेकर आये दिन धरना-प्रदर्शन करती थी और आज सत्ता में आने के बाद फिर वही शराब की नदियां बहा रहे हैं। वहीं अगर शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया होता तो युवओं को भी प्रोत्साहन मिलता। लेकिन रोजगार का अवसर कम और युवाओं के लिए शराब की दुकानें ज्यादा खोली जा रही है। सिर्फ राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को नशे में डुबाया जा रहा है। नई दुकानों की उपलब्धता से शराब की खपत बढ़ेगी और शराब की बढ़ती खपत के कारण घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटना और अन्य अपराधों में वृद्धि होगी। शराब की बढ़ती उपलब्धता के कारण युवा एवं नाबालिग युवती शराब के प्रति आकर्षित होते जायेंगे, जिसके कारण उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। शराब के अधिक सेवन के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी। जैसे लीवर, हृदय रोग एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, जिसके कारण अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। सरकार एक ओर राज्य को नशा मुक्त करने के लिए प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केन्द्र खोलने जा रही है। अभी आदरणीय सदस्य बता रहे थे कि नशा मुक्ति के लिए कई तरह की बात कर रहे थे। नशा से मुक्ति कैसे करायेंगे ? आप एक तरफ नशा के लिए दुकानें खोल रहे हैं, उनको जगह-जगह बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति की बात करते हैं। यह डबल इंजन की सरकार का यह डबल गेम मुझे समझ में नहीं आई। आपने सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानें खोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हर्षिता जी, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष जी, मेरा पूरा भाषण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- काफी हो गया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, और भी बात है, जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर सरकार के राजस्व के अलावा पूंजीगत व्यय को देखे तो वह बहुत कम है। सरकार को यहां व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों पर सोचना चाहिए। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि सड़कों का जाल बिछ रहा है या पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक, धार्मिक स्थितियों को सुधारा जा रहा है। लेकिन अभी तक उसमें कोई नई नीति नजर नहीं आई है। उद्योग नीति की बात करें तो बजट में बड़े उद्योगों के लिए कोई सोच ही नहीं है। अगर बड़े उद्योगों में देखा जाये तो राजनांदगांव

बी.एन.सी. मिल बंद है। अध्यक्ष महोदय, जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय बंद हो चुका था। अगर हम उसको सुचारू रूप से चालू करें और बड़ी उद्योग नीति का लाभ मिले तो वहां की जनता और आसपास के ग्रामीण अंचल के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। परन्तु बजट में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। प्रयोगशाला टेक्निनिशयन और प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती के एक साल पहले लिए विज्ञापन निकाला गया था। परन्तु एक साल बीत जाने के बाद भी न तो परीक्षा आयोजित की जा सकी है और न ही परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई विभाग द्वारा कोई पहल किया गया है। विभाग द्वारा परीक्षा नहीं लिए जा सकने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना की पर्याप्त व्यवस्था किए बगैर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। जिससे सहायक प्राध्यापकों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सरकार बनने के तुरन्त बाद महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की कमी को देखते हुए 2019 में भर्ती आयोजित की गई थी। उसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सहायक प्राध्यपकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि सहायक शिक्षकों को हटाने से बहुत नुकसान हुआ है। फिर से उनको वापस ले लेना चाहिए, ताकि उनका रोजगार भी बना रहे और जहां शिक्षकों की कमी है, वह पूरी की जा सके।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये।

सभा द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, विनियोग तुलनात्मक रूप से शोध, कर परीक्षण का एक नया आयाम होता है, जिससे हम छत्तीसगढ़ में अच्छे से अच्छा सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से कार्यों को कर सकें, क्रियान्वयन कर सकें। लेकिन यहां पर जिस प्रकार से विश्वास की कमी नजर आ रही है और बजट का प्रावाधान खाली दिख रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी दुर्गति दिख रही है, मैं, आपसे उसके लिए निवेदन करना चाहूंगी कि उसको व्यवस्थित किया जाए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण और समाज कल्याण में शराब को लेकर जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है या सामाजिक गतिविधियां बिगड़ रही है, उसको सुधारा जाये। महिला होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि इस तरह से हो रहे

अपराध को रोका जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री किरण देव जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधियेक के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो यह बजट पेश किया गया है, वह निश्चित रूप से आने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के सुनहरे कल की ओर इंगित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के नये दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। इस सरकार में कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं। आज जब मैं इस विनियोग विधियेक की चर्चा में आपके अनुमति से हिस्सा ले रहा हूं तो मैंने दोनों ही पक्ष के पूर्व के वरिष्ठ सदस्यों को भी सुना, उसमें से कई विद्वान, ऐसे कई वक्ता भी हैं, जिनका सभी विषयों पर समान रूप से अधिकार है। यह देश प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सरकारों के कार्यों का मूल्यांकन जनता करती है, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरी है, जनता ही श्रेष्ठ है इसीलिए विगत सवा साल में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाकर इस छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने की दिशा में क्रियान्यवन प्रारंभ किया है, जनता ने उसका आर्शीवाद भी दिया है क्योंकि क्षेत्र विशेष में नीचे तक की इकाई है। यदि हम हमारे बस्तर से सरगुजा तक की बात करें तो इसका प्रमाण-पत्र जनता ने विगत तीनों चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है। जनता को मूल्यांकन करने का अधिकार है और विपक्ष को आलोचना का अधिकार है, लेकिन जहां तक बजट का विषय है तो जनता के द्वारा इस सर्वव्यापी बजट की प्रशंसा चारों ओर हो रही है। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। विगत दिनों इस बजट के विषय पर विभिन्न विभागों के लिए जो अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई, उस पर मैं आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में विभाग से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। यह विषय बार-बार आता रहा है और मैं यह लगातार सुन रहा था कि डबल इंजन की सरकार, फिर तीन इंजन की सरकार, फिर चार इंजन की सरकार। निश्चित रूप से चाहे केन्द्र की सरकर हो या चाहे राज्य की सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं जो गांव, गरीब, किसान, सभी धर्म, समाज, जाति, सब वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उसमें से लगभग सभी योजनाएं पिछले पांच वर्षों में बाधित हुई थी, उसका जनता तक लाभ नहीं मिल रहा था। वह हितग्राही जिसे उसका लाभ मिलकर वे लाभार्थी के रूप में परिवर्तित होने वाले थे, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तेजी के साथ डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक मिल रहा है। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। केन्द्र सरकार व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की

जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या अभी विष्णु देव साय जी की राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इस ओर मैं जरूर इंगित करना चाहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ कोई विशेष जाति, विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि इसका लाभ सभी को मिल रहा है, जिसका परिणाम जनता ने प्रमाण-पत्र के रूप में हमें इन चारों चुनाव में दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारा यह छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मैं सीधे-सीधे स्वरूप में कुछ विभागों की ओर कहूंगा, जैसे लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग का विषय है । सभापति महोदय, विधान सभा के प्रश्नकाल में भी पानी की समस्या को लेकर सवाल उठाये गये हैं, सरकार ने इसमें 4500 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 40 लाख परिवारों के घरों में नल-कनेक्शन पहले से लग चुका है, जब पानी का विषय आता है और इस पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता जाहिर की है कि जल स्तर कम हो रहा है, मैंने अनुदान पर केदार कश्यप जी को धन्यवाद ज्ञापित किया था कि हमारी जगदलपुर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी है, इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई तो तीन दिन के भीतर इंद्रावती नदी का जल छोड़ दिया गया और उसका जल स्तर बढ़ गया ।

अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से अपनी कहना चाहूँगा कि आज से 10 वर्ष पूर्व नगरीय निकाय क्षेत्र में महापौर की दृष्टि से मुझे भी कार्य करने का अवसर मिला है, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्ष में चाहे वहां के सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य हो, चाहे वह बुनियादी सुविधाओं की बात हो, भूपेश सरकार पूरी तरह से फेल हुई । आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को अभी रायपुर में इस विषय को लेकर बधाई दूँगा कि 750 सीटर सर्वसुविधायुक्त लायब्रेरी का निर्माण होने जा रहा है, वैसे नालंदा का भी विषय पूर्व में आ चुका है । छत्तीसगढ़ में नालंदा अपने आप में एक अद्भुत योजना है, हमारे 13 नगरीय निकायों में हाईटेक लायब्रेरी के लिये 148 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, उसके लिये भी माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, हम लोग बस्तर से आते हैं, नीलकंठ टेकाम जी का विशेष रूप से यह क्षेत्र रहा है, केशकाल से विधायक हैं, हमारे बस्तर से लखेश्वर बघेल जी और अन्य सभी विधायक आते हैं, 5 साल तक जो केशकाल की दुर्दशा थी उसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है । अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी इतना सुंदर बना हुआ है कि लोग वहां पर्यटन की दृष्टि से विडियोग्राफी कर रहे हैं, केशकाल के बारे में हमारे विधायकों ने सदन में कई बार मामला उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी की थी, लेकिन हमारी सरकार के आते ही केशकाल घाटी का मनोरम दृश्य सामने आया है । मैं इसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बघेल जी, ठीक तो बोल रहे हैं ना हमारे अध्यक्ष जी ? साहब, एक दिन नहीं बोले हैं कि केशकाल घाटी बहुत अच्छा बन गया है ।

डॉ.चरणदास महंत :- माननीय धर्मजीत सिंह जी, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ । केशकाल घाटी बहुत सुंदर बना है, वहां हम साल भर से गये नहीं है, उसके बाद भी बहुत सुंदर बना है । इसमें सरकार का क्या योगदान है ? गिट्टी सप्लाई किया है, रेत सप्लाई किया है, श्रमिक सप्लाई किया है कि खुद खड़े होकर देखे हैं ?

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि केशकाल की घाटी बहुत अच्छा बना है, वास्तव में अच्छा बना है, लेकिन मेरे क्षेत्र की पूरी सड़क खराब कर दिये । विश्रामपुरी से होकर नगरी सिहावा से होकर ओव्हर लोडेड गाड़ियां जा रही है, मैं चाहती हूँ कि उधर का भी सड़क केशकाल घाटी जैसे बन जाये ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि उसके लिये भी बजट में प्रोविजन हो गया है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं । अध्यक्ष जी, मैं आपको टोकता नहीं हूं, न टोकना चाहता हूं । आप बहुत अच्छा केशकाल घाटी बना रहे हैं, सड़क अच्छा बना रहे हैं, वहां रेल्वे की लाईन चली जाएगी, प्लेन उतरने लगेगा, मगर ये काम आप वहां की जनता के लिए कर रहे हैं या किसी को बुलाया है, उसके लिए कर रहे हैं या किसी को बस्तर सौंपना है, उसके लिए कर रहे हैं या किसी को बस्तर को थाली में परोसना है, उसके लिए कर रहे हैं या किसी को खनिज के ठेके देने हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं । कुछ तो बता दीजिए। हमारी जनता जो वहां गांव में रहती है, जो आज भी भूख मरती है । आप सबके निरीक्षण और हम सबके कहने के बाद ही उनके लिए कर रहे हैं ? इतने-इतने उद्योग उनके लिए खोल रहे हैं । आप उनको काम दोगे, वे काम करेंगे, पसीना बहाएंगे, तनख्वाह दोगे इसलिए वहां काम होगा । बाकी तो समझ रहे हैं कि किसके लिए होगा।

अध्यक्ष महोदय :- महंत जी, आपको भी आज बोलना है ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि जल्दी-जल्दी खतम करें तो मैं बोलूं ।

श्री किरण देव :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्य हो गया । मुझ जैसे पहली बार सदन में आये सदस्य की बात को इतने वरिष्ठ सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा की गई टिप्पणी से मैं वास्तव में धन्य हो गया।

डॉ. चरण दास महंत :- देखिए, आप हमारे नेता नहीं हैं, आप हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं, घर वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, यार भी हैं । आपके बड़े भाई भी हैं, उसके भी बड़े भाई भी ।

श्री किरण देव :- धन्यवाद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी । अध्यक्ष महोदय, मैं

इस विषय को इसलिए ले रहा हूं कि मैंने एक उदाहरण के रूप में अपनी बात रखी है। वास्तव में जगदलपुर से रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करने वाला मुख्य मार्ग है। मैं इसकी महत्ता के बारे में कहना चाहता हूं । यह मार्ग वर्षों से उपेक्षित पड़ा था और उतनी ही तेजी के साथ इसमें काम किया गया है, मैंने उसकी प्रशंसा की है। स्वाभाविक रूप से जब ऐसा काम होता है तो जनता भी इसकी प्रशंसा करती है । लोक निर्माण विभाग का विषय है । हमारे 31 हजार करोड़ से सड़कों का, राजमार्गों के निर्माण की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य मद से 899 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया । सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केन्द्रीय सड़क निधि से 1204 करोड़ रूपए के 17 कार्य स्वीकृत किए गए हैं । मैं आदरणीय नितिन गड़करी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री जी के लगातार प्रयासों के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यह बहुत बड़ी योजना थी । समग्र विकास के लिए मार्गों का सुदृढ़ीकरण करके मार्गों का गांव तक पहुंचना, नीचे तक पहुंचना और अच्छे से निर्माण होना किसी भी राज्य के विकास की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एशियन डेव्हपलमेंट बैंक द्वारा 3370 करोड़ रूपए की 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं और छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हपलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए 5784 करोड़ की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है । हम सभी इस बात को मानते हैं । अगर हम बस्तर, सरगुजा की बात करें या हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वहां पर सड़कों के निर्माण की है क्योंकि विकास सड़कों के माध्यम से ही वहां तक पहुंचेगा । बस्तर के विषय को मैं विशेष रूप से इंगित करूंगा क्योंकि वह ऐसा क्षेत्र है, जो मुख्य धारा से निरंतर कई वर्षों से कई जगहों से छूटा हुआ था । हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लगातार प्रयत्नों से वहां पर बहुत तेजी से शांति का माहौल एवं वातावरण निर्मित हो रहा है । उसके कारण भी इन सड़कों का काम तेज गति से बढ़ेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग के संबंध में भी कहना चाहता हूं। इस बजट में ऊर्जा विभाग के लिए 1274 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और लगभग 43.50 लाख उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक की खपत पर आधे दाम पर बिजली उपलब्ध कराने की बात है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवद देता हूं । छत्तीसगढ़ में 25000 मेगावाट उत्पादन जल सौर और ताप ऊर्जा से आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से बढ़ेगी । उसी के साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि 3 हार्स पॉवर तक के सिंचाई पम्पों पर प्रतिवर्ष 6000 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रावधानित करने की दिशा से इसमें सम्मिलित किया गया है । पॉच हार्स पावर तक सिंचाई पम्प पर प्रतिवर्ष 7500 यूनिट नि:शुल्क बिजली का प्रावधान है । आने वाले समय में किसानों को इससे बहुत लाभ मिलेगा । सौर ऊर्जा

को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज आधारित 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट आप ही के राजनांदगांव जिले में स्थापित हो रहा है और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनांतर्गत 1 लाख 30 हजार घरेलू उपभोक्ताओं के क्षतों पर सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को इंगित करना चाहूंगा कि शासकीय सेवाओं की भर्ती की आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पशुपालन विभाग में गौपालन के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज पर एवं 2 से 3 लाख तक के ऋण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खासकर वनवासी क्षेत्रों में इसकी बहुत आवश्यकता है। मछली पालन की दृष्टि से ग्रामीण तालाबों के प्रति हेक्टेयर औसत 4017 किलोग्राम और सिंचाई जलाशयों में भी इसी प्रकार है। आज सुबह ही आपका एक विषय आया था कि 240 किलोग्राम मत्स्य का उत्पादन, जो कि समग्र देश के औसत उत्पादन से भी अधिक है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन की दृष्टि से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई व कोरबा में ई-बस सेवा की शुरुआत का निर्णय लिया गया है और ऐसे 240 ई-बसों की शुरुआत के लिए जो प्रावधानित किया गया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण रेल विभाग है। अभी जिस प्रकार से विमानन विभाग की बात कर रहे थे, तो जब डबल इंजन सरकार की बात होती है तब मैं इस विषय को रखना बहुत आवश्यक समझता हूं कि प्रदेश में रेल्वे नेटवर्क के विस्तार के लिए 38378 करोड़ रुपए की लागत की 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं एवं 1672 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग स्टेशनों के पुर्नविकास के साथ 32 अमृत रेल्वे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के बजट में केन्द्र सरकार द्वारा रेल के आधुनिकीकरण एवं रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 6925 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये अपने आपमें डबल इंजन की सरकार के फायदे को बताता है क्योंकि बार बार डबल इंजन और त्रिपल इंजन की सरकार का विषय आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का अभिवादन, अभिनंदन कि हमारे बस्तर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बस्तर पंडुम करने जा रहे हैं। जैसा कि बीच में हमारे वरिष्ठ सदस्य धरम लाल कौशिक जी ने बस्तर ओलंपिक का विषय रखा था, तो मैं आपके माध्यम से बस्तर पंडुम का विषय सदन में रखना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कभी भी इस दिशा में सोचा नहीं गया। बस्तर पंडुम हमारे बस्तर की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, प्राकृतिक

सौन्दर्य और बस्तर में विभिन्न प्रकार के जो खान-पान, वाद्य यंत्र एवं नृत्य हैं, जिनके प्रति पूरे देश में एक ललक रहती है कि बस्तर क्या चीज़ है क्योंकि बस्तर के 26-26 किलोमीटर में वहां की जनजातियां, भाषा, बोली बदलती हैं, तो उसको लेकर अभी जो वर्तमान में बस्तर पंडुम का कार्य हो रहा है, तो बस्तर पंडुम के इस निर्णय के लिए, इस कार्य योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके लिए आपने जो प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन का एक विषय बार-बार सदन में आता है। मैं बिना किसी के ऊपर टिप्पणी किए कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी की चिन्ता और आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से इस योजना को संचालित किया जा रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है। टिप्पणी आती है कि किसी एक की कहीं कमी हो रही है, कहीं किसी एक का नाम छूट रहा है, कहीं किसी जगह पांच का नाम, कहीं किसी जगह 07 का नाम छूट रहा है लेकिन 1 हजार रुपए प्रति महीना किसी वंचित एवं गरीब परिवार की महिला को संबल प्रदान करने के लिए क्या ताकत रखता होगा? क्योंकि 500 रुपए वाला काम पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, लगातार आदरणीय वित्त मंत्री जी से मैं कहता भी हूं और आदरणीय अजय चन्द्राकर जी ने भी बार-बार इस बात को कहा है कि यह नौजवान वित्त मंत्री जी न जाने किस प्रकार से इसको प्रावधानित करते हैं कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन की राशि भेजने का काम करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। मैं इसके लिये आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और आपने इस वित्तीय वर्ष में इसको बढ़ाकर 5500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, इसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जबकि इसी प्रकार की जो योजनाएं हैं। जैसे मैं यहां पर कर्नाटक और झारखण्ड की बात करूं तो ऐसी योजनाओं को वहां भी लॉन्च किया गया लेकिन अभी मैंने टी.व्ही. में कुछ 10-15 दिनों पहले वहां के मुख्यमंत्री जी को कहते हुए सुना कि हमने जिसकी घोषणा की है, हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम अपने वार्षिक बजट से बाहर जाकर इन योजनाओं को प्रावधानित कर सके इसलिए वह योजना वहां पर बंद पड़ी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ लगातार 10 महीनों से हमारी बहनों को मिल रहा है, इसके लिये मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अभिनंदन के पात्र है। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना का एक लाभ और है। मैं महतारी वंदन पर थोड़ा सा और समय लूंगा। इसके अंतर्गत जो शक्ति ऋण योजना है, वह ग्रामीण बैंक व कुछ अन्य बैंकों द्वारा हमारी माताओं और बहनों को इसी से संबद्ध होकर 25 हजार के आस-पास का बैंकों के माध्यम से जो ऋण है, उसकी भी सुविधा मिल रही है। इसलिए यह निश्चित रूप से सुखद परिवर्तन है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी कई योजनाओं पर वित्त मंत्री जी ने लगातार संज्ञान लिया है। मैं हमारे पर्यटन विभाग पर बोलना चाहूंगा । मैं हमारे बस्तर क्षेत्र से आता हूं इसलिए जब मैं बात करता हूं तो बस्तर का एक विषय जरूर रखना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी आदरणीय मंत्री जी की अनुदान मांगों पर इस विषय को रखा था कि एक निर्णय लिया गया है और वह लगातार चल रहा है। उसमें बसों के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है। हमारे प्रभु राम जी के जन्म स्थल, अयोध्या जी जाने के लिए 12 कोच वाली स्पेशल ट्रेन की सेवा से साल भर में हमारे 20 हजार श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिये भी मैं अभिनंदन करूंगा । (मेजों की थपथपाहट) जब हमारे बस्तर की बात आती है, तो यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इसकी जितनी तारीफ होनी चाहिए, इसकी जितनी प्रशंसा होनी चाहिए, उतनी हो नहीं रही है। वह क्षेत्र हमारे जगदलपुर विधान सभा के अंतर्गत ही आता है। मैंने पिछले बजट में भी इस बात को रखा था और धन्यवाद दिया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे कुटुमसर को तो सभी जानते हैं परंतु घुड़मारास की विशेषता यह है कि उसका संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन में 60 देशों में से 20 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से हमारे देश में से एक मात्र गांव घुड़मारास है, जो घुरवा जनजाति को जो पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, यह अपने आप में अद्भुत है। (मेजों की थपथपाहट) उसको बढ़ाने के रूप में टूरिज्म विलेज के रूप में चुना गया है, उसके लिये धन्यवाद। धर्मस्व के क्षेत्र में यह काम लगभग पिछले 5 वर्षों में बंद हो चुके थे। वित्त मंत्री जी ने कुदरगढ़, चंद्रहासिनी, महामाया, बम्लेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर के लिये 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है, उसके लिये भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ हमारे खनिज की दृष्टि से एक विषय लगातार उठ रहा था। छत्तसीगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां लिथियम ब्लॉक का ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटन हुआ है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की अनुदान मांगों पर धन्यवाद नहीं दे सका था। लेकिन जिस तरीके से मेकाहारा और सिम्स हॉस्पिटल में भवन के विस्तार के लिये बजट में प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष महोदय, उसके तहत मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि अब धीर-धीरे यह स्थिति आयी है कि विशाखापट्टनम से 3 पेशेंट्स ऐसे रहे, जिनको वहां से 18 दिन भर्ती रहने के बाद मेकाहारा में इलाज कराते हुए ठीक करके जगदलपुर ले गये। उसके लिये 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हे, मैं उसके लिये भी माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना के लिये 1526 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिये भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बस्तर में निरंतर पिछले सवा साल, डेढ़ साल में और मैं इस बात पर भी यकीन करूंगा कि जब आप मुख्यमंत्री थे, उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एम्स और मेडिकल कॉलेजों में हमारे बस्तर में भी स्व. बलीराम कश्यप जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खुला है, इसके अतिरिक्त इस बजट में नैच्युरोपैथी की दृष्टि से और फिजियोथैरेपी की

दृष्टि से आपने वहां पर ऐसे अस्पताल भवन के निर्माण को प्रस्तावित किया है , मैं उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। इस तरीके से आज इस सदन में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस विनियोग विधेयक का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे इस विनियोग विधेयक के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए समय प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

समय
6.00 बजे

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हमने रजत वर्ष में प्रवेश किया है। इस रजत वर्ष में हम इन 24 वर्षों का आंकलन करें कि छत्तीसगढ़ की इस 24 सालों की यात्रा में हमने क्या पाया और क्या खोया ? तो हमारे सामने दोनों पहलू आएंगे। छत्तीसगढ़ में इन 24 वर्षों में बहुत से ऐसे अच्छे पहलू हैं, जो इस छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और हम सबने देखा है। इस छत्तीसगढ़ के इन 24 वर्षों में ऐसे बहुत से बुरे पहलू भी हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और हम सब ने भी देखा है। इन 24 सालों की यात्रा में 8 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 16 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अगर आज हम छत्तीसगढ़ का आंकलन करते हैं, जो इस प्रदेश के अच्छे पहलू हैं जिसमें यहां संपत्तियों का निर्माण, छत्तीसगढ़ की तरक्की, बहुत से पैरामीटर हैं। आज देश में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम स्थापित हुआ तो हम यह पायेंगे कि वह सारे अच्छे पहलू जिसकी आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा होती है तो वह केवल और केवल 16 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होती है, जिसका आपने 15 सालों तक नेतृत्व किया है। एक साल इन्होंने किया और अभी हमने रजत वर्ष में प्रवेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो दूसरा पहलू है जहां एक तरफ देश में Development, नये-नये नवाचार की चर्चा होती है, यह आपके नेतृत्व में उन 16 वर्षों में स्थापित किया। छत्तीसगढ़ का जो

दूसरा पहलू, बुरा पहलू है, जिनका नाम भी पूरे देश में हुआ, अगर उसको स्थापित करने का काम भी किसी ने किया है तो 8 सालों में इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। आज जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के Development की बात आती है तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम आता है हमारी बहुत सी नीतियां ऐसी हैं, जिसकी प्रशंसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसकी प्रशंसा 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने की, जिसकी प्रशंसा आर.बी.आई. ने की। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में यह जो घोटाले, ई.डी. और भ्रष्टाचार, यह इन 8 सालों की प्रक्रियाएं हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम रजत वर्ष में जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी का यह सौभाग्य है कि उनके पास इन 24 सालों का अनुभव है, उसमें अच्छे अनुभव भी हैं और बुरे अनुभव भी हैं। इस रजत वर्ष में आवश्यकता है, जो कहना चाहिए कि इस प्रदेश के विकास में जो चूक हुई है। यह हो सकता है कि इनसे 90 प्रतिशत चूक हुई हो और हमसे 10 प्रतिशत चूक हुई हो, मैं उस विषय में नही जाना चाहता हूँ। उन उन सारी चूकों को ठीक करते हुए, रजत वर्ष में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को और आगे कैसे ले जाएं। हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी की विकसित भारत 2047 की कल्पना है। हमारी इस सरकार की यह प्राथमिकता है, जिसका विजन डॉक्यूमेंट भी बना है- "विकसित 2047 का छत्तीसगढ़।" जब हम 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं तो हमसे जो चूक हुई हैं या जो हमसे गलतियां हुई हैं। मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे अनुभव का लाभ लेते हुए हम सारी चीज को दूर करते हुए इसको विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में परिवर्तित करें। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय छत्तीसगढ़ के लोन के ऊपर आता है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको बंटवारे में 7 हजार करोड़ रुपये मिला था जब मध्यप्रदेश के साथ बंटवारा हुआ। 03 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की आपके नेतृत्व की सरकार रही। हमने 2018 में 44 हजार करोड़ रुपये में ऋण को छोड़ा था। कुछ ऋण कांग्रेस के समय में हुआ, कुछ ऋण अपनी सरकार ने सवा साल में लिया, मै उस विषय में नहीं जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का यह सौभाग्य है कि खासकर वित्तीय मामले में छत्तीसगढ़ की नींव बड़ी मजबूत रखी गई। इस वित्तीय मामले में जो नींव रखी गई, वह आपके नेतृत्व में रखी गई और उसी का परिणाम है कि आज वित्तीय प्रबंध के जो सारे पैरामीटर हैं, वह देश के अग्रणी राज्य में छत्तीसगढ़ को खड़ा करता है। उसका सबसे कारण है कि उसकी नींव बहुत मजबूत रखी इसलिए आज एक मजबूत इमारत पूरे देश में छत्तीसगढ़ की दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं चर्चा करना चाहूंगा, आपके, हमारे समय में 18 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. का लोन था, कल भी वित्त मंत्री बता रहे थे कि वह 19 से 20 प्रतिशत है। मैं उस लोन में नहीं जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि आप और हम एक बार प्लानिंग कमीशन में गये थे जब मोनटेक सिंह आहलूवालिया उपाध्यक्ष हुआ करते थे। जब सवेरे अधिकारियों के साथ बैठे तो मोनटेक सिंह आहलूवालिया जी ने कहा कि आप लोगों की लोन लेने की क्षमता तो बहुत है,

आप लोन क्यों नहीं लेते, प्लान क्यों नहीं बढ़ाते ? छत्तीसगढ़ जल्दी डेव्हलप हो जायेगा। जब आप और मै गये और मोनटेक सिंह आहलूवालिया जी के साथ बैठे तो हमने तर्क-वितर्क किया। यह बात सही है कि हमारी लोन लेने की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि जी.एस.डी.पी. के बहुत कम लोन है। लेकिन अगर हम प्लान बना लें, हमारी खर्च करने की क्षमता ही नहीं है, हमारे पास वह संसाधन ही नहीं है, हमारे पास वह मेनपावर नहीं है तो क्या हम भ्रष्टाचार के लिये लोन लें ? हमने लोन लेने से मना कर दिया। उसी का परिणाम है कि अगर उस समय हम इस प्रवृत्ति में जाते कि हमारी लोन लेने की इतनी पात्रता है और लोन लेते तो आज यह जो छत्तीसगढ़ की इतनी बुलंद इमारत दिखाई देती है, आज यह दिखाई नहीं देती। उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आपके नेतृत्व की सरकार को जाता है जिसने वित्तीय व्यवस्था को मजबूत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने लोन लिया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। वह जी.एस.डी.पी. के अंतर्गत है और आज भी है। लेकिन यह प्रश्न जरूर उठता है कि आपने 5 साल के अंदर लोन लिया, वह पैसा छत्तीसगढ में दिखाई नहीं देता, संपत्तियों का निर्माण इस छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर अगर मैं इस 5 साल की बातचीत करूं, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज उनको बहुत से पैरामीटर देखने की आवश्यकता है। यह बजट आय और व्यय के हिसाब से बनता है। इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी देयतायें हैं। ठीक है, जब हम बजट बनाते हैं, बजट में आय-व्यय होता है और जो साल का बजट होता है, यह अनुमानित होता है। फाईनल बजट तो जब ए.जी. की रिपोर्ट आ जाती है, डेढ़ साल के बाद आती है। कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने 2022 की रिपोर्ट फाईनल पब्लिश की है। उस समय सारे वास्तविक आंकड़ें आते हैं कि हम revenue plus में हैं, हम fiscal depreciate में कहां खड़े हैं ? यह बजट अनुमान है, उसके बाद अनुपूरक बजट आते हैं। लेकिन रिसीप्ट पेमेंट में सब दिखाई देता है। अगर किसी का बाकी पेमेंट छोड़ दें, हम खुश हो सकते हैं कि हमारे पैरामीटर ये हैं, लेकिन वह पेमेंट कहां से आयेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत से बैकलॉग को हमने फुल किया है लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी आज भी बहुत सा बैकलॉग अगर आप अध्ययन करेंगे तो वह आपके सामने है और जब आप उस बैकलॉग को भरने की कोशिश करेंगे तो आपने यह जो बजट बनाया है उसमें कहीं न कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाउंगा कि 1300 करोड़ रूपये केवल नगरीय निकाय के बिजली बिल का बकाया है । अगर आज वह 1300 करोड़ रुपया बिजली बिल का जाता है तो नगरीय निकाय का बजट जीरो, यह स्थिति किसने लाई ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को नहीं कह रहा हूं उनको तो एक साल हुआ है, उनको तो जो विरासत में मिला है उसको समझते-समझते समाधान करते-करते आज भी अगर इस स्थिति में पहुंचे हैं तो यह उनकी योग्यता के कारण पहुंचे हैं । (मेजों की थपथपाहट) लेकिन 5 साल में इन्होंने जो देयताएं खड़ी की

हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा उदाहरण आयुष्मान का देना चाहूंगा कि आयुष्मान का कितना बिल बाकी है, आज 1200 करोड़ रुपये आज डॉक्टरों का बाकी है जिसके कारण इलाज नहीं होता । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज हम सारी देयताओं का हिसाब करें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 से 6 हजार करोड़ रुपया ऐसा है, जो सारे विभागों को कहीं न कहीं देना है कि अगर आप 5-6 हजार करोड़ रूपया बैकलॉग में एडजस्ट करोगे तो सारा बजट जो हमको डवलपमेंट का दिखाई देता है, वह दिखाई नहीं देगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है । यह तो खड़ी करके चले गए और अब चूंकि सरकार हमारी है, सारा निपटारा भी हमको करना है तो माननीय वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान दीजिए । हमको राजस्व बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस विषय में भी आउंगा कि राजस्व कैसे बढ़ सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा हमारे PSUs हैं, हमारे अंतर्गत काम करते हैं, उनके लोन का या उनके घाटे का जिक्र इसमें नहीं आता । अगर वह खड़ी होती है उसमें हमारी स्टेट गारंटी है ।

माननीय अध्यक्ष महोद, कल ही विषय आया । एक आवास पर्यावरण का आया, मैंने आर.डी.ए. का विषय उठाया, मैंने हाऊसिंग बोर्ड का विषय उठाया । माननीय मंत्री जी नया रायपुर के बारे में बता रहे थे कि एन.पी.ए. हो गया, जितने भी PSUs हैं, अगर मैं मार्केटिंग फेडरेशन की बातचीत करूं । हम जो लॉस होता है उसको कितना पैसा कंपनसेट करते हैं ? लेकिन अगर आप फाईनल ऑडिट करेंगे तो आपके ऊपर कितनी लॉयबिलिटी खड़ी होगी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह छत्तीसगढ़ के लिए विचारणीय प्रश्न है और मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, उनको तो जो करना था, वह करके चले गए । यह सब हमको करना है, विकास भी करना है, यह जो सारे फाईनेंस के पैरामीटर हैं उसको भी ठीक करना है इसलिए मैं कुछ बातें जो फाईनेंस के लिए ज़रूरी है । इस प्रदेश का जो 25 साल का अनुभव रहा है वह आज रिफार्म मांगता है और रजत जयंती में हमारा कर्तव्य बनता है कि उन रिफार्म को करते हुए हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ें और बढ़ेंगे क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है । हम निश्चित रूप से बढ़ेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है, मैंने PSUs के बारे में कहा । आपको याद होगा कि वर्ष 2005-06 में एक साल ऐसा रहा जिसमें धान खरीदी में जीरो घाटा रहा, पूरे छत्तीसगढ़ का हम इतिहास उठाएंगे एक से लेकर आज 24 साल तक एक साल ऐसा रहा जो धान खरीदी में जीरो रहा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में वह सारी रणनीति बनाकर आज आवश्यकता है फिर से सारी चीजों की समीक्षा करने की क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मार्च तक का ब्याज देती है । मार्च तक के सारे खर्चे देती है उसके बाद अगर कस्टम मिलिंग नहीं होती, उसके बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वह सीधा हमारे खाते में आते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की है कि इन सारे PSUs के बारे में समीक्षा करके एक-एक घाटे को दूर करने की नहीं तो यह विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना है मुझे उसकी राह में बाधा दिखाई देती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कुछ कमियां चूंकि वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, बजट बनता है, 20 परसेंट तक की आर.ई. ठीक है, होता है, एस.ओ.आर. घटते हैं, बढ़ते हैं, रेट आते हैं लेकिन उसके बाद आज अगर हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हंड्रेड-हंड्रेड परसेंट लागत बढ़ रही है, आज बढ़ी हुई 100 रूपये की चीज 3 साल के बाद आर.ई. आती है 300 रूपये की , 20 प्रतिशत से ज्यादा अगर आर.ई. गई तो नया टेंडर करना पड़ता है। अगर हम उसका अप्रूवल भी दे देंगे, फिर से नया टेंडर होगा, फिर लागत बढ़ेगी। ये सारे वर्क डिपार्टमेंट में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कौन लोग यह डिजाइन बना रहे हैं? कौन लोग यह कर रहे हैं? इन सारी चीजों में कड़ाई करने की जरूरत है कि जिससे समय विलंब न हो। 20 प्रतिशत बढ़ सकता है, 30 प्रतिशत बढ़ सकता है, 100-100 प्रतिशत? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर का उदाहरण देना चाहूंगा। एक ऑडिटोरियम था। आपके हमारे समय में प्रांरभ हुआ। हमने चालू करवाया। 5 साल में मालूम नहीं, जितना हुआ था, उसकी केवल नींव बनी है। पेपर में रोज आता है और उसके बाद सारा पैसा खत्म। उसके बाद अभी आर.ई. आई। मैं धन्यवाद देता हूं कि वित्त मंत्री जी ने आर.ई. के बाद स्वीकृति दे दी, लेकिन आज उसका फिर से नया टेंडर होगा।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, अग्रवाल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे चर्चा करने दीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं यह कह रहा हूं कि आप जब नगरीय प्रशासन मंत्री रहे तो आपने पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति की। आपके कार्यकाल में क्यों नहीं बन पाया? थोड़ा सा यह भी बता दीजिए।

श्री अमर अग्रवाल :- हां, मैं बता दूंगा। वह भी बता दूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- आप लेट की बात कर रहे हैं।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं बता दूंगा। भाई, आप क्यों चिड़ रहे हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहा हूं।

श्री दलेश्वर साहू :- अग्रवाल जी, मैं तो ज्ञान अर्जन करना चाह रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- नहीं-नहीं, ज्ञान अर्जन नहीं है, आप लोगों को बैठे-बैठे अपने पाप याद आते हैं, इसलिए उचकते हो।

श्री दलेश्वर साहू :- अग्रवाल जी, आपने मेरे लिए भी डोंगरगांव में स्वीकृति प्रदान की, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। शायद आपके इलाके का है, आपने बना लिया होगा तो आपने क्या उपाय किया, उसे मैं जानना चाह रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- आप अलग से आ जाना, मैं उसे बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उसमें आर.ई. हो गयी। फिर से नया टेंडर करना पड़ेगा, जिसका टेंडर वर्ष 2018 में हुआ, वर्ष 2024 चल

रहा है, वह वर्ष 2030 तक पूरा होगा। क्या छत्तीसगढ़ में हम इसी गति से काम करते रहे? क्या छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा? मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा। अगर हम इस बजट में अगर देखें तो कैपिटल में हमने काफी 26 प्रतिशत से बढ़ोत्तरी के साथ काम किया है। संपत्ति का निर्माण हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? संपत्ति बनाना बहुत आसान है। उसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है? मैं बिलासपुर स्टेट ट्रेनिंग की बात करना चाहूंगा। बिलासपुर स्टेट ट्रेनिंग का डेढ़ सौ से पौन दो सौ करोड़ रूपये लगा है और मैं ऐसा मानता हूं कि सेंट्रल इंडिया में उससे अच्छा स्टेट ट्रेनिंग सेंटर आपके नेतृत्व में जो बनना प्रारंभ हुआ, बनकर आज रेडी है, आज उसकी हालत क्या है? आज अगर हम वहां जाते हैं तो मुझे ही कई बार दुख होता है कि किस कल्पना के साथ हमने इस स्टेडियम को बनाया, हमारी कल्पना थी कि हमने इसको बनाया और आज उसका हाल क्या है? इस प्रदेश में और कई चीजें आ गई हैं। मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए कह रहा हूं कि मैं पुराने अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं, कोई इसमें आपने किया या सरकार ने ऐसा किया, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। हमारे यहां सीपत में 100 बिस्तर का अस्पताल बना। परसो ही फोटो छपी कि उसमें मवेशी रहते हैं। हम संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। जरूरत है, उसका आंकलन करना चाहिए। जहां हम सब हेल्थ सेंटर नहीं खोल सकते, वहां हम बिल्डिंग बनाकर 100-100 बिस्तर का अस्पताल खोल रहे हैं। हमारे पास मैन पावर नहीं हैं और बाद में उस संपत्ति का होता क्या है? आज ये सारी बातें विचार करने की हैं कि सेटअप के साथ आज स्टेट ट्रेनिंग सेंटर है, खेल विभाग के पास है। संपत्ति बन गई और पी.डब्ल्यू.डी. बोलता है कि हैण्ड ओव्हर ले लो। खेल-कूद विभाग बोलता है कि मेरे पास सेटअप नहीं है। मेरे पास चलाने के संसाधन नहीं हैं। बारीकी के साथ इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। आज वित्त विभाग का काम है, वह ठीक है। देखिए, मैं भी विधायक हूं, दूसरे भी विधायक हैं। हम वित्त मंत्री जी के पास जाते हैं, सहृदयता से मुख्यमंत्री जी कर देते हैं, विभागीय मंत्री जी कर देते हैं। उनको धन्यवाद है। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे? आप बिल्डिंग तो बनवा लेंगे, जब उसको आप चला नहीं पाएंगे तो हम ये जो संपत्ति बढ़ा रहे हैं, अपने कार्यकाल में भी आया था। 300 बिस्तर के अस्पताल बने हैं। सेटअप नहीं, सेटअप अप्रूव कर दिए। नौकरी निकालो इक्विपमेंट को कोई मिलता नहीं, फिर उसके बाद उसकी उपयोगिता तलाशी गई तो उसका उपयोग नर्सिंग कॉलेज में किया गया । अध्यक्ष महोदय, बजट से पहले इन सारी बातें पर विचार होना चाहिए । ठीक है जन प्रतिनिधियों की मांगें आती हैं, करना पड़ता है और करना भी चाहिए । लेकिन कहीं न कहीं तो हमको उसका असेसमेंट करना पड़ेगा कि इस सम्पत्ति की छत्तीसगढ़ में आगे क्या उपयोगिता है ? बिना सेटअप के इस सम्पत्ति को हम रखेंगे कैसे ? यह हमारे लिए बहुत जरूरी है । आज अजय जी कह रहे थे कि अमर जी वित्त मंत्री थे तो उस समय से यह चला आ रहा है कि ए.ए. देरी से मिलता है, सही है होती होगी । वित्त विभाग के बहुत से नियम है, कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाउंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है कि हम ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं करते

कि स्क्रूटनाइज्ड कोई चीज है, यह वित्त विभाग में प्रावधान है कि पहले से सारा एस्टीमेट बन जाए, लैंड हो जाए, सारा कुछ हो जाए, स्क्रूटनाइज्ड आइटम्स अगर बजट में होंगे तो उसके लिए ए.ए. की जरूरत नहीं है । आज छत्तीसगढ़ में जरूरत है कि स्क्रूटनाइज्ड आइटम्स ही बजट में आएं । अगर वर्क डिपार्टमेंट को कह देंगे तो साल भर काम करेंगे । आज जरूरत है कि बजट में केवल स्क्रूटनाइज्ड आइटम्स का ही समावेश हो और उसके बाद कोई ए.ए. की जरूरत नहीं है । अजय जी बोले इसलिए मुझे ध्यान आ गया तो मैं समाधान ढूंढने लग गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नहीं, प्रदेश का ।

श्री अमर अग्रवाल :- हां प्रदेश के, लेकिन विषय आपने उठाया । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से देखेंगे हम जो सम्पत्ति बना रहे हैं वे चलेंगी कैसे, उनका सेटअप कैसे होगा ? सम्पत्ति बनाने के बाद उसकी उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस रजत वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं, जब हमारे अनुभव अच्छे नहीं हैं तो इन अनुभवों को देखकर हमें आगे जाने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ बातों के लिए इशारा किया । मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, आप एक बार समीक्षा करिये कि इस प्रदेश में कितने अधूरे काम हैं, जिनका ए.ए. देना है, जिनको रिवाइज़ करना है, कोई भारत सरकार की योजना थी उन्होंने बंद कर दी, वे अधूरी हैं । अध्यक्ष महोदय, हम नई सम्पत्ति खड़ी कर रहे हैं । लेकिन जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, यदि उनको पूरा नहीं करेंगे तो वो नेशनल लॉस है, छत्तीसगढ़ का लॉस है । आपको याद हो 2003 में जब हमारी सरकार आई तो उस सरकार के बहुत से अधूरे काम थे । मैं शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम का जिक्र करना चाहूंगा । यह जो क्रिकेट स्टेडियम था, एक सोसायटी बना दिया, सोसायटी को नियम के विरूद्ध दे दिया, हम चाहते तो उस समय केस कर सकते थे, हम चाहते तो उसको अनियमितताओं में बदल सकते थे । ठीक है प्रक्रिया में त्रुटि हुई होगी लेकिन हमने आपके नेतृत्व में उसका रास्ता निकाला और आज वह शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम देश की शान है (मेजो की थपथपाहट) । सरकार की कार्य पद्धति होनी चाहिए । ऐसे ही एक बार अजय चन्द्राकर जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उस समय भारत निर्माण गौरव योजना चलती थी, केन्द्र सरकार ने बीच में बंद कर दिया । बहुत से काम अधूरे रह गए, हमारी सरकार का पहला बजट है हमने कहा कि इस बार हम न्यू आइटम में ध्यान नहीं देंगे, पुराने जितने काम हैं उनको पूर्ण करने के लिए न्यू आइटम को नहीं लिया और सारे पुराने काम हमने करके दिया और सारी सम्पत्तियों को व्यवस्थित करके दिया । आज भी मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप समीक्षा करिये, आप न्यू आइटम मत करिये, एक साल बाद हो जाएगा । लेकिन नई सम्पत्ति हम बनाते हैं और पुरानी को छोड़ देते हैं । माननीय वित्त मंत्री जी, आप भी समझते हैं कि जो विभाग है उनकी रूचि नए काम में हैं पुराने कामों में नहीं है, उसके कारण जो भी हैं, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता । करिए एक बार समीक्षा और दृढ़ संकल्प के साथ हम इसको पूरा करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष

महोदय, मैंने पहले ही कहा कि आज हमको राजस्व की जरूरत है। हमारे नेशनल हाईवे बहुत अच्छे बने, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और इस देश के परिवहन मंत्री गडकरी जी का धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे के मामले में बहुत समृद्ध है, हमने बहुत से स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे स्टेट हाईवे हैं, अभी इस बजट में कुछ प्रावधान किया है। शहरों के चारों तरफ रिंग रोड बनाएंगे, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मध्य प्रदेश में जाईए, वहां रोड कार्पोरेशन बना है, जो काम नेशनल हाईवे करती है, हम BOT बेस पर सड़क बना लें। अध्यक्ष महोदय, हमने आपके नेतृत्व में सड़क कार्पोरेशन बनाया है। (मेजों की थपथपहाट) लेकिन इनकी सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया, मैं उस विषय में जाना भी नहीं चाहता। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे 24 साल के अच्छे और बुरे अनुभव हैं, बुरे अनुभव किसने किया है, मैं उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता। क्या हम एक सड़क बना सकें ? अगर मान लीजिए BOT में सफल नहीं हैं तो BJF है, उसका जो गैप है, हम उसके आधार पर कर सकते हैं। इस विकसित छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जो स्टेट हाईवे हैं, हम उसको कैसे समृद्ध करें ? क्योंकि आकार भी बढ़ाना है, जब आकार बढ़ाना है तो हम केवल स्टेट फंड के भरोसे नहीं रह सकते, हम PPP मॉडल में कैसे जा सकते हैं, हम BJF देकर कैसे जा सकते हैं, हम BJF मॉडल की बात करते हैं, हम PPP मॉडल की बात करते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। मैं कोई दोषारोपण भी नहीं करता लेकिन हमारे अनुभव हैं, हमको विकसित की तरफ जाना है, हमारे लिए आज ये विचारणीय प्रश्न है। हमारी जो चूक है, हम उसको कैस दुरूस्त करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा DMF है, कन्वर्जेंस है। बहुत सी योजना कन्वर्जेंस के माध्यम से हुई है। DMF एक ऐसा शब्द हो गया, मेरे ख्याल से हर विधायक के पास 10 आदमी आ जाते हैं, कलेक्टर को बोल दीजिए कि DMF में मेरा ये काम स्वीकृत कर दें। DMF की परिभाषा ही यही हो गई है। जो पाता है वह DMF की बात करता है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। सेंट्रल गनर्वमेंट में गाईडलाईन बना दी।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके सुझाव में एक सुझाव दे दीजिए कि जिन जिलों में DMF नहीं है, उसके लिए कुछ राशि का इंतजाम कर दें।

श्री अमर अग्रवाल :- मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जो कहूंगा रजत वर्ष के समीक्षा के बाद हमको क्या करना चाहिए, मैं उसी विषय पर चर्चा करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, DMF के नार्म्स बदल गये, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। केन्द्र की सरकार ने इसको CAG के अंदर शामिल कर दिया। इब इसमें रोक लगेगी लेकिन नार्म्स को बदल दिया। अब स्थिति क्या है ? अब स्थिति ये है कि वहां खर्च हो ही नहीं सकता। वहां DMF का पैसा हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास एक ही उपाय है, DMF के उस इलाके में जो हमारा

स्टेट प्लान है, उसको कट करके सारा पैसा उधर डायवर्ट करना। मैं जानता हूं, आपको वहां दिक्कत जाएगी, हमारा जो TSP प्लान है, हमारा जो SSP प्लान है, उसका उल्लंघन करना बहुत कठिन है लेकिन हमको केन्द्र सरकार से बात करके इसका रास्ता निकालना पड़ेगा या तो DMF का दायरा बढ़वाना पड़ेगा या हमारे जो TSP, SSP के प्लान हैं, वह DMF से फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन इसका भी कहीं न कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो CSR फंड है, उसका हम कन्वर्जेंस के मामले में क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी इस बता का जिक्र किया था कि जिस प्रकार से आकांक्षी जिले के हेल्थ के पैरामीटर, एजुकेशन के पैरामीटर का मूल्यांकन हुआ, उस पैरामीटर को हमको डिस्ट्रिक्ट में बनाकर एक लंबी योजना के साथ काम करने की जरूरत है जिसके बारे में आज अजय जी समावेशी विकास की बात कर रहे थे। वह समावेशी विकास तभी संभव है, जब आगे से बजट निर्धारण हो तो उस प्राथमिकता के आधार पर हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा सुझाव देना चाहूंगा, हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं , टेण्डर की खामियां हैं। जमीन ही नहीं है और टेण्डर हो जाते हैं तो बिना लैण्ड के वह पहले हो जाये। उसके बिना बजट में आप कोई आइटम मत लीजिए, नहीं तो टेण्डर हो जाते हैं और लागत बढ़ती रहती है। उसी की स्वीकृति मिले, जिसकी प्रारंभिक सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाए। मैं मानता हूं कि यह बहुत कठिन काम है। वास्तव में वित्त मंत्री इसीलिए अलोकप्रिय भी होता है क्योंकि सीधी बात है कि जिसको आप न कहेंगे, वह नाराज भी होगा। इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं। मैंने 3 साल में जो महसूस किया है, मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूं। वित्त मंत्री जी, हमको कहीं न कहीं इन सारे reforms पर जाना पड़ेगा। यदि हम नहीं गये तो हम जिस विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उसमें दिक्कत जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा। जब CAG की रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत सी अनियमितताएं सामने आती हैं। वह PAC में जाता है। माननीय चरण दास जी उसके अध्यक्ष हैं और मैं भी उसका सदस्य हूं। 7-7 साल, 8-8 साल से बैकलॉग चल रहा है। जब तक अधिकारी रिटायर हो जाते हैं और उसकी पेंशन रूक जाती है। मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब यह ऑडिट रिपोर्ट आती है तो CAG की रिपोर्ट में जाने से पहले उसकी एक कॉपी वित्त मंत्री को आती है। आप उन अफसरों को बुलाइये। कम से कम इससे भविष्य के लिए रोक लगेगी। PAC में जो होगा, वह होगा। विधान सभा में जो होगा, वह होगा। आपका कर्तव्य है कि आप उन अफसरों को बुलाइये और पूछिये कि इसमें अनियमितता कैसे चल रही है? यदि आप starting point में उसको दबाने का काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं कमी आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मैं गलत नहीं हूं। हमारे यहां वर्ष 2008-2009 में भारत सरकार ने outcome budget को प्रारंभ किया कि हमारा जो बजट है, उसके परिणाम क्या होंगे? outcome

budget में संख्या तो आ जाती है कि इसके परिणाम क्या होंगे? लेकिन आज इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारा जो बजट था, outcome में हमने जो लक्ष्य रखे थे, उसकी कितनी पूर्ति हुई है? उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं? आज यह comparison करना बहुत आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने के लिए बहुत से विषय हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट का नाम गति रखा है। उनकी गति के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा बजट दिया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार में मोदी जी ने यह जो गति अभियान शुरू किया है, उसमें जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें integrated रहता है। लैण्ड का issue है, पर्यावरण का issue है और बहुत से internal department के विषय हैं। उसको CS करते हैं। हमारे यहां परंपरा है कि जो internal department है, उसकी CM समीक्षा करते हैं। लेकिन CS की भी अपनी एक मर्यादा है। यदि मंत्री कहीं अड़ जाएं और नहीं माने तो वह प्रोजेक्ट डिले होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार केन्द्र की सरकार ने यह जो गति करके internal department की कमेटी बनायी है, उसी प्रकार प्रदेश में भी आप एक कमेटी बनाइये और 100 करोड़ रूपये से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि हम टाइम में कर जाएं और internal department की CM अध्यक्षता कर लें, आप अध्यक्षता कर लें। जिसके पास जो विभाग हो, उसके मंत्री को शामिल कर लें, उसके अधिकारियों को शामिल कर लें। यदि within a limit उनके clearance कर लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वह सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। कुलमिलाकर आज मैंने छत्तीसगढ़ के अनुभव महसूस किए हैं व जनता के अनुभव महसूस किए हैं। हमको रजत वर्ष से ऊपर जाना है। मैंने उन बातों की तरफ ध्यान दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे ऊर्जावान, दूरदर्शिता से कार्य करने की क्षमता वित्त मंत्री जी में है और मेरे इन सुझावों पर आप अमल करेंगे। इससे इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी पार्टी की सरकार में यह विकसित छत्तीसगढ़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे दोनों पक्षों के सदस्यों में काफी लंबी बहस हुई है। माननीय मंत्री जी, आपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका कुछ-कुछ विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी आप नहीं थे, आपके अध्यक्ष महोदय किरण देव जी ने आपकी तरीफ की है। अभी शायद किरण देव नहीं हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- बैठे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- वित्त मंत्री जी चले गये। सर, क्या मैं आपत्ति दर्ज करा सकता हूं कि जब मैं बोलने के लिए उठता हूं तो वित्त मंत्री पानी पीने चले जाते हैं। कभी चाय पीने जाते हैं, कभी पानी पीने जाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब आप बोलने खड़े होते हो तो प्यास लग जाती है तो क्या करेंगे ? अब थोड़ा सा पानी पीने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री राजेश मूणत :- जब आप बोलने खड़े होते हैं तो पड़ोस वाले इधर-उधर चले जाते हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- भईया, मैं तो ऐसा कुछ बोलता ही नहीं हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है कि दूसरे लोगों से काम चला लीजये न।

डॉ. चरण दास महंत :- किससे काम चलाऊ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- इसी तरफ से किसी को पकड़कर काम चला लीजिये।

डॉ. चरण दास महंत :- यहां न विद्वान सदस्य चन्द्राकर जी बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपको सुने बगैर नहीं रह सकता।

डॉ. चरण दास महंत :- न हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी यहां बैठते हैं। मैं तो आपकी प्रशंसा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप ही लोग नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष के भाषण में नहीं रहे तो फिर विधान सभा आने का क्या मतलब ?

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं वित्त मंत्री जी को सुनाने जा रहा था, इसलिए दोनों वित्त मंत्री गायब हैं। किसे सुनाऊं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बाजू वाले भी वित्त मंत्री थे, वह भी गायब हैं, जिसमें आज खूब बात हुई है।

डॉ. चरण दास महंत :- भाई, वह वित्त मंत्री के साथ-साथ मुख्यमंत्री थे। जब से आप लोग बैठे हो, तब से उसी तरफ ईशारा कर-करके, कर-करके, कर-करके उसे बैठने ही नहीं देते हो। जो कुछ हुआ है, पिछले 5 साल में हुआ है। नमस्कार सर, (श्री किरण देव, सदस्य के सभा कक्ष में आने पर) आप विलंब से आ रहे हैं। मैं तो अभी शुरू ही नहीं हुआ हूं। जब मैं शुरू होता हूं तो आपके वित्त मंत्री जी पानी पीने जाते हैं। वह आ गए।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- पानी भी पीने नहीं देंगे ?

डॉ. चरण दास महंत :- आप पानी पीओ, जो पीना चाहे वह पीओ। मैं तो यह कह रहा था कि मैं किरण देव का भाषण बहुत अच्छे से सुन रहा था। उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। वर्तमान में पूर्व वित्त मंत्री अमर जी भाषण कर रहे थे, वह भी कुछ-कुछ प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वह भी

पुराने खरसियन हैं, रायगढ़ियन हैं इसलिए, मगर नहीं कर पा रहे थे। हमारे विद्वान अजय जी का भाषण पूर्णत: सुन चुका हूं, मैं अपनी बात आपकी प्रशंसा से शुरू करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कभी जांजगीर में कलेक्टर हुआ करते थे। मुझे बताया गया कि आप छत्तीसगढ़ के आदमी हैं तो खुशी हुई। फिर बताया गया कि आप खरसिया के आदमी हैं, तो खुशी हुई। फिर पता लगा कि आप खरसिया के अंदर गांव के हैं तो और खुशी हुई कि गवंहिया आ गया। उस समय आप अपनी सोच से वहां के बहुत सारे छात्रों को सैनिक बनने के लिए भेजते थे। कितने भेजे हुए लोग आपकी प्रशंसा किये है या नहीं किये हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको फोन पर कहा कि और अच्छे लड़कों को भेजिये। मैं यह जानना चाहता हूं आप जहां जाते हैं, वहां सैनिक बनाने के लिए, बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए कुछ करते हैं। तो आज यहां पर जो सड़कों में घूम रहे हैं, हमारे बच्चें, आपके बच्चें, छत्तीसगढ़ के बच्चें छोटी-छोटी मांगों को लेकर घूम रहे हैं। पंचायत सचिव की मांगों को बजट में क्यों शामिल नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है ? यहां बहुत सारे पंचायत सचिव बैठे हुए हैं, रोज हड़ताल कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। सहकारी संस्थाओं के 20 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 60-70 हजार लोग अनिनियमित नौकरी से परेशान हैं। बी.एड. के अभी 2,650 लोगों की नौकरी चली गई। आज वे लोग सड़कों पर बैठे हैं। तो क्या इनके प्रति आपकी कोई जवाबदारी बनती है या नहीं बनती ? बनती होगी न, या वह 8 साल वाले हैं ? जैसा कि अभी अमर जी बता रहे थे कि इस प्रदेश में 8 साल कांग्रेस की सरकार रही और 16 साल भा.ज.पा. का रहा। तो आप इस तरह से बांट कर चलेंगे कि 8 साल वाले हैं इसलिए इनका काम नहीं करना है, 16 साल वाले हैं तो इनका काम करना है। हमारे-आपके ही तो बच्चें हैं। मैं इनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे उस पर ध्यान दें और उनके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालें। सर, पूरी बात है गई है और समय भी ज्यादा हो गया है। आज जरूरत से ज्यादा बहुत लंबे-लंबे भाषण आए हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं ऐसा समझता हूं कि वह वित्त विभाग के असलियत से थोड़ा सा हटकर बात कर रहे थे और मैं वही कहूंगा जो आपके किताबों में लिखा है, मैं बाहर से बात करता ही नहीं हूं। मैंने अभी जो बात किया है, वह अलग बात है। आपने यह छिपाने का प्रयास किया है कि आपने बजट में जितनी राशि स्वीकृत की है, उसको धरातल पर आने के लिए या उसमें काम होने के लिए कितने महीने लगेंगे? जैसा कि अमर अग्रवाल जी बोल रहे थे कि आप लोग बिना स्वीकृति के काम नहीं कर पाते हैं। अब आपने प्रस्तुत तो कर दिया, लेकिन अभी वह विभाग से जाएगा, वह वित्तीय व्यवस्था चेक करेंगे, आबंटन जारी करेंगे, फिर उसकी स्वीकृति होगी। आप यह राशि कब तक जारी कर पायेंगे? आपको यह राशि जारी करने में कितने महीने लगेंगे? वह राशि हमको धरातल पर कब दिखने लगेगा? इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि इसी तरीके से जब कोई योजना का सर्वेक्षण होता है, डी.पी.आर. बनता है तो बनते-बनते महीनों गुजर जाते हैं और वह अभी तक नहीं आता। जैसे मैं कहूं कि आपने स्वच्छ भारत

मिशन में 400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इसमें आपने 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था, जो आज भी आपके पास है और आपने दिसंबर, 2024 तक इस बजट का एक रूपये भी खर्च नहीं किया है। यह मेरा आरोप नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी स्वच्छ भारत मिशन में 400 करोड़ रूपये स्वीकृत किया है और पिछला 200 करोड़ रूपये बचा हुआ है और वर्ष 2024 के बजट में आपने एक रूपये भी खर्च नहीं किया है तो इसका क्या अर्थ होता है? आप अभी जो 147 करोड़ रूपये खर्च कर रहे हैं, वह वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 की बची हुई राशि है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजियेगा, मैं अपने आप को संशोधन कर लूंगा, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, नालंदा परिसर निर्माण हेतु पिछले साल आपने 148 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा था। पूरे साल में आपने 50 प्रतिशत की राशि भी खर्च नहीं किया। अभी आप उसके लिए 17 करोड़ रूपये और दे रहे हैं, जबकि आपका पिछला पैसा खर्च नहीं हुआ है तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप बजट की राशि बढ़ाना चाहते हैं या उसमें से खर्च करना चाहते हैं? फूड पार्कों की स्थापना के लिए आपने 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। यह सभी बात आपकी किताब है, यह मैं नहीं बोल रहा हूं। पिछले साल के 50 करोड़ की राशि में से अभी तक सिर्फ 45 प्रतिशत खर्च हुआ है। सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के लिए आपने 75 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। पिछले साल के 26 करोड़ रूपये का आधा पैसा भी अभी तक न तो खर्च हो पाया है, न कुद निर्माण दिख रहा है। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसका अभी तक सिर्फ सर्वेक्षण चल रहा है, डी.पी.आर. चल रहा है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहां महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री जी बैठी हैं। इस विभाग में 146 करोड़ रूपये की केन्द्र प्रवर्तित 11 योजनाएं हैं और इस वित्तीय वर्ष में आपने उन 11 योजनाओं में एक रूपये भी खर्च नहीं किया है। मैडम, आपको यह पता है? यह सब बजट आप बढ़ा-बढ़ा कर दिखा रहे हैं और आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? मैं फिर से उस बात पर आता हूं। आदरणीय अमर जी आ गये हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो आपके जमाने की ऑडिटोरियम, बिलासपुर की बात की है। आपने ही कही है न कि 20 प्रतिशत खर्चा नहीं हुआ है ..।

श्री अमर अग्रवाल :- स्टेट ट्रेनिंग सेंटर और आडिटोरियम दोनों की बात की है।

डॉ. चरणदास महंत :- जी ।

श्री अमर अग्रवाल :- स्टेट ट्रेनिंग सेंटर और बिलासपुर के आडिटोरियम उसी की बात की है ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आपने स्टेडियम की भी बात कही है, आपने ट्रेनिंग सेंटर की भी बात कही है, 8 साल हो गये हैं या 6 साल हो गये हैं, पैसा स्वीकृत हो गया, काम हो गया और 20 परशेंट हुआ है, बाकी नहीं हुआ । इसमें 8 साल वाले की जवाबदारी बनती है कि इसमें आपकी भी जवाबदारी बनती है ?

श्री अमर अग्रवाल :- आप उसे तोड़-मरोडकर मत बोलिये, सुनिये मैने कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया है, मेरा जो 25 साल का अनुभव है, हमसे ज्यादा बुरा अनुभव आप लोगों का है, वह विषय आया है । मैं तो कोई पॉलिटिकल भाषण किया नहीं है ? आप मेरे को एक चीज बताईये कि वर्ष 2017 में उसका टेंडर हुआ, आप तोड़-मरोड़कर 8 साल मत करिये, यहां 5 साल के बाद किसकी सरकार थी, उसका क्यों आर.ई. नहीं दिये ? देखिये, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ । आप उसको तोड़-तोड़ कर 8 साल मत बोलिये । हमने वर्ष 2017 में टेंडर किया, उसके बाद 5 साल आपकी सरकार रही है, उसके बाद वह पूरा नहीं हुआ है, मैंने इस सरकार को सारे विषय को कहा है कि उसे क्या करना चाहिये ? जो काम आपका है, वह मैं कर रहा था ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आप प्रदेश के विख्यात वित्त मंत्री रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते थे, मैं तो आपकी प्रशंसा में कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो दर्द छिपा है, मैं उस दर्द को बयां करना चाहता था ।

श्री अमर अग्रवाल :- आपने 8 साल वाला विषय उठाया है, मैंने इसलिये बोला है । हम तो आपके सुनने के लिये बैठे हैं, आप आदरणीय हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मेरे को इसी में एक शेर याद आ गया-

श्री अजय चन्द्राकर :- शेर को बाद में सुनाईयेगा, दर्द क्या छिपा है, इसको पहले बताईये ?

डॉ.चरणदास महंत :- सुन लीजिए । मरशफी नाम के एक शायर हैं ।

मरशफी हम तो समझे थे कि होगा कोई सीने में दर्द
मगर तेरे दिल में तो काम बड़े रफू का निकला

अध्यक्ष महोदय, आप इतना सा दर्द समझ रहे हो और काम वाला रफू वाला हो गया है । रफू समझते हो ना, मैं आपकी तारीफ में यह कर रहा था कि जिस तरह से आपने विद्वतापूर्वक सभी बातें कही है, आपने गलती से मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम भी ले लिया, जो हमारे पार्टी के थे । आपने कहा कि 1300 करोड़ नगरीय निकाय का बिल बकाया है और 1200 करोड़ आयुष्मान का बिल बकाया है तो मैं इन बातों को इसीलिए कह रहा था कि आपके बजट बन रहे हैं, बजट में राशि आ रही है, बजट में खर्च की व्यवस्था नहीं दिख रही है या खर्च हो रहा है तो एक साल, डेढ़ साल बाद हो रहा है तो उसको सुनियोजित तरीके से काम होना चाहिये । यह आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ और हम दोनों साथ-साथ ही रहे हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- खेद के साथ बोल दीजिए कि हमसे जो गलती हो गयी है, उसे आप सुधार लो । थोड़ा सा खेद के साथ, बड़े दिल के साथ बोलो कि हमारी सरकार से गलती हो गई है, अब आप सुधार दो, निश्चित रूप से सुधार आयेगा, लेकिन थोड़ा सा खेद के साथ । गलतियां होती है, गलती

मानने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा खेद के साथ बोल दो कि हमारी जो गलती हुई है, अब आप ठीक करें । हम पक्का ठीक करेंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- वह तो करना ही पड़ेगा । आप जाओगे कहां ? 8 साल और 16 साल का मामला है, कोई गलती हुई तो सुधारोगे, कुछ अच्छा हुआ है तो प्रशंसा भी करेंगे, नहीं सुधारोगे तो कहां जाओगे ? आप तो मंत्री हो । अभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी, हमारे सदस्य भी, आपके सदस्य भी, सिर्फ एक ही बात करते हैं कि वह भी गलती से शायद इस बात को समझ गये कि उनको उलाहना दे रहा हूँ ।

समय
6.48 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुई)

डॉ. चरणदास महंत :- सॉरी मैडम, माफ कीजिएगा आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा बोले, उसको क्लियर कीजिए । आप आसंदी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज क्यों हो रहा है ? आप यह बताईये । आपको बताना चाहिये । आप नेता प्रतिपक्ष हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदया, भईया सुन ना । हम दोनों गुड़ाखूबाज हैं । (हंसी) आपको पता है ?

श्री अमर अग्रवाल :- उसमें शरमाने की क्या बात है ?

डॉ. चरणदास महंत :- हम नहीं शरमा रहे हैं, बता रहा हूँ कि यह शरमा रहे हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- जब आप दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री थे, तब भी आपके साथ बाथरूप चले जाते थे । इच्छा है तो चलो, अभी भी चले जाते हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं यह बोल रहा था कि अध्यक्ष महोदय होते तो मैं उनको बताता कि ...।

श्री अमर अग्रवाल :- उसमें शरमाने की क्या बात है ?

डॉ. चरणदास महंत :- हम उनको बताते कि हम दोनों ...।

श्री अमर अग्रवाल :- अरे बाबा, जब आपको अध्यक्ष बनाये तो आपके साथी हैं, सामूहिक नेतृत्व वाले उन लोगों ने सोनिया गांधी जी से शिकायत किये थे कि गुड़ाखू करके पड़ा रहता है । शिकायत किये थे कि नहीं किये थे, यह सत्य है या नहीं है ।

डॉ. चरण दास महंत :- सही है, आप सत्य हैं ।

श्री अमर अग्रवाल :- सत्य है या नहीं, यह बता दीजिए ।

डॉ. चरण दास महंत :- सत्य तो है, बता तो रहा हूं । (हंसी) मैं तो यह बता रहा हूं, बता रहा था ।

श्री अमर अग्रवाल :- आप आधी-अधूरी बात मत बोला कीजिए, आप यह बोलिए कि आपके साथी

आपको अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए गए थे । उनको और कुछ तो मिला नहीं । आप सज्जन आदमी हो, शरीफ़ आदमी हो, काम वाले हो तो बोले थे कि यह आदमी गुड़ाखू पीकर धुत्त रहता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- लता जी आसंदी पर आ गई हैं इसलिए अचानक उनको अपना फ्लो रोकना पड़ा है ।

डॉ. चरण दास महंत :- ऐसा नहीं है । अगर माननीय अध्यक्ष महोदय आसंदी पर होते तो मैं उनके सामने बिना लज्जा के बोल देता कि मैं और अमर जी दोनों साथ वाशरूम जाते थे, मगर इनके सामने नहीं बोल पा रहा हूं । यही तो बोला, और कुछ थोड़ी बोल रहा हूं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नशा करते-करते आप यहां आ गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, वाशरूम से आगे की सीमा दोनों ने साथ-साथ तो नहीं लांघी हैं न ।

डॉ. चरण दास महंत :- ना, कभी नहीं ।

श्री अमर अग्रवाल :- उसके बारे में विस्तृत चर्चा करना हो तो आगे का साथ फिर अजय के साथ रहेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको भी जानता हूं, अजय जी को भी जानता हूं। आप सब लोग बहुत होशियार लोग हैं । मैं यही कह रहा था कि आप यह कहते हैं कि आपने 5 साल में यह किया, 5 साल में वो किया, 5 साल में ऐसे बजट पास किया। आपके कार्यकाल के 14 महीने निकल गए । मैं वित्त मंत्री जी को कह रहा हूं कि आपके कार्यकाल के 14 महीने निकल गए 15 महीने निकलने वाले हैं, 16 महीने निकलने वाले हैं । यह कह-कहकर आप कितने दिन बचोगे । कुछ तो उदाहरण प्रस्तुत करिए कि हम दूसरी बार आये हैं, हमने पहले महीने में ये किया, तीसरे महीने में ये किया, चौथे महीने में ये किया, पॉचवे महीने में ये किया । आपकी तरफ से जो भी खड़ा होता है, वह कहता है कि आपने पॉच साल में यही किया, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ तो करो ।

सभापति महोदया, आपका हर व्यक्ति धीरे से अमृतकाल विजन, 2047 का उदाहरण दे देता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अमृतकाल विजन को इस टेबल में रखा है ? वित्त मंत्री जी, मैं पूछ रहा हूं, उप मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं, सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी भी हैं । आप 2047, 2047, 2047 कर रहे हैं । 2047 के विजन डाक्यूमेंट को क्या आपने विधान सभा के पटल पर रखा है, फिर किस बात पर वहां पर जाने की बात कर रहे हैं । हवा में कोई रास्ता बनाएगा, आप उसको पटल पर रखिए न । जो रास्ता हमको भी पसंद होगा, हम भी 2047 तक उसमें चलेंगे, हम में से बहुत सारे लोग ऊपर चले जाएंगे, 2047 तक बहुत कम लोग बचेंगे । हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे विधायकों को पता होना चाहिए, साथियों को पता होना चाहिए । आप इस बात का ध्यान रखिए।

सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ में कृषि, खनिज, वन हमारी सबसे बड़ी सम्पदा है और अगर हमने इसको अच्छे ढंग से बचा लिया तो निश्चित रूप से हमारा रजत जयंती वर्ष और बेहतर ढंग से मनेगा । जिस तरह आप किसी की बुराई नहीं करते, मैं भी किसी की बुराई करने में विश्वास नहीं रखता । यह बात सिर्फ अजय जी रखते हैं । अभी मैंने कहा था कि 40 लाख मेट्रिक टन को बाजार में बेचने जा रहे हो तो क्या मिलेगा ? मैंने कहा कि आपने 100 लाख टन उत्पादन दिखाया है और उपार्जन 145 लाख टन दिखा रहे हो । आपको बुरा लग गया, कृषि मंत्री जी ने होशियारी से ईशारा कर दिया तो कम्प्यूटर में फटाफट कोष्ठक में लिखाकर आ गया कि यह धान नहीं चांवल है । कृषि मंत्री जी, क्या हम चांवल बोते हैं ? क्या हमारे यहां चांवल उत्पादित होता है या धान उत्पादित होता है ? आप के ही लिखे हुए को मैंने पढ़ा था, कोई बाहर से लाकर तो नहीं पढ़ा था । आप कुछ मत कहिए, मैं उसमें नहीं सुन रहा हूं । कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए । आपको एक और रिकार्ड बताता हूं । कल माननीय मुख्यमंत्री जी खनिज विभाग में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी ।

श्री रामविचार नेताम :- सभापति महोदय, भारत सरकार हमसे चांवल ही खरीदती है । हमारे सरकार की जिम्मेदारी धान खरीदने की ही होती है । हम धान खरीदकर मिलिंग करने के बाद भारत सरकार के एफसीआई को चावल देते हैं। इसलिए उनका जो आंकड़ा दिया जाता है, वह चावल का ही दिया जाता है। उन आंकड़ों को आप धान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतना चावल है तो उसका धान कितना होगा।

डॉ. चरण दास महंत :- आप नाराज मत होइए ना। धान से भूंसा भी निकलता है और भूँसा से नीचे कोढ़ा भी निकलता है और उस कोढ़े से तेल भी निकलता है, तो आपने उत्पादन में कोढ़े का क्यों नहीं लिखा? आपने भूँसे का क्यों नहीं लिखा? आपने तेल का क्यों नहीं लिखा? उत्पादन धान हुआ है, तो हुआ है और गलती हो गई तो हुई है। मैंने कुछ अधिकारियों से पूछा कि भईया ये धान उत्पादन 100 लाख टन लिखा है और हमारे यहां 145 लाख टन खरीद रहे हैं, दूसरे साल धान का उत्पादन 110 लाख टन हुआ है और आप 149 लाख टन खरीद रहे हैं तो जो 45 लाख टन और 49 लाख टन है, ये कहां के धान हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं या उड़ीसा के हो सकते हैं या महाराष्ट्र के हो सकते हैं? शंका तो सभी करते हैं ना। आप भी पांच साल वालों में ऐसे ही शंका करते रहे। हम भी आप पर शंका कर रहे हैं, आप इस पर नाराज मत होइए।

सभापति महोदय, चलिए खनिज पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुख्य मंत्री जी का विभाग है। मैंने कल भी बताया कि आपके रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2023-24 की अपेक्षा वर्ष 2024-25 में जो खनन के काम हुए हैं, वह मात्र 15% हैं। कल आप शायद उस समय नहीं थे। अब इसमें आप लोग कोई टोकिएगा मत, मैं सीधे-सीधे आरोप लगा रहा हूं कि वन संपदा का जितनी तेजी से आपके अधिकारी दोहन कर रहे हैं, वे जितना दोहन कर रहे हैं, उतना पुनर्निमाण करने में आपका कोई योगदान नहीं दिख

रहा है, बल्कि आप हमारे रोजगार करने वाले श्रमिकों के मनरेगा के काम को 100 का 39 कार्यदिवस कर दिए हैं। आपने अपने पंजीकृत श्रमिकों के नाम काट दिए हैं और गरीबों का भी रोजगार छीन रहे हैं। जैसे यहां नौकरी करने वालों का रोजगार छीना, आपने 3300 शिक्षकों का रोजगार छीना। आज एक गरीब तो बेचारा पसीना निकाल-निकालकर खाता है, उसका भी रोजगार आप छीन रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। इसे विनियोग में कहना चाहिए या आपके यहां चाय पीकर कहना चाहिए, आप उसको समझिए, फिर बताइएगा।

सभापति महोदय, अगर आपके आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूं तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी के पिछले वर्ष में 17.09 थी, जो कि इस साल घटकर 16.80 है। कम घटा है। ठीक है? मंत्री जी, कहीं गलती हो जाएगी तो बताइएगा, हम गणित नहीं पढ़े हैं। उद्योग, खनन, विनिर्माण और विद्युत जलपूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी पिछले वर्ष 48.03 थी, जो इस बार घटकर 47% हो गई है। ये भी मेरे ख्याल से ठीक ही होगा? सेवा के क्षेत्र में हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर भाव में 10.43 थी, अब वह प्रतिशत घटकर 8.54 हो गया है। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव से क्षेत्रवार प्रतिशत दर के अनुसार उद्योग क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2023-24 में आपके 10.16% थी, जो कि अब घटकर वर्ष 2024-25 में 9.00% हो गई है। सेवा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में 13.57% थी, जो कि अब घटकर 13% से कम हुई है और 0.10% कम हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मूल्यवर्धन वर्ष 2023-24 में 11.05 था, वह घटकर अब 10.00 हो गया है।

समय:

7.00 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में पिछले वर्ष 2024-25 में 11.60 था, वह अभी घटकर 10.8 हो गया है। और क्या बताऊं, क्या कुछ ज्यादा कहूं ? एक तरफ आप किसानों के बहुत बड़े हिमायती है। दूसरी तरफ आपने हमारे किसानों की ऋण माफी योजना बंद कर दी है। आप किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की बात करते हैं, आपने उसमें भी कटौती कर दी। वर्ष 2023-24 में सितंबर, 2023 तक बात करें तो 15 लाख 23 हजार किसानों को 7 हजार 40 लाख करोड़ रूपये का आपने ऋण वितरण किया है। जबकि वर्ष 2024-25 में 15 लाख 21 हजार किसनों को 6 हजार 937 करोड़ 39 रूपये का ऋण दिया है। अब आप इन दोनों की गति की तुलना अपनी गति से कर लीजिये। या अमर जी जो केंद्र की गति बता रहे हैं, उससे तुलना कर लीजिये। हम लोगों को समझाईयेगा, हमको समझ में नहीं आता है। आपका पूंजीगत व्यय की बात आप कर ही रहे थे। आपने किया है, फिर आप नाराज मत हो जाना। इस साल आपने पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि की है। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं परंतु आपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो पूंजीगत राशि 50 प्रतिशत

भी खर्च नहीं कर पाये, वह रखा हुआ है और कहा रखा है यह पता नहीं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ? आपने इसको अपनेभाषण में बताया नहीं। आप नक्सलवाद की बात करते हैं, चलिये हम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सैनिक, हम उनको बधाई देते हैं। ललेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे आम आदमियो की मृत्यु हो जा रही है, पिछले साल लगभग 64 आम नागरिक मरे हैं, जिनमें 3 जनप्रतिनिधि भी हैं। अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। मैं इधर मग्न हो गया था। जिसमें 3 जनप्रतिनिधि भी है, 1 व्यवसाय भी है और 60 गरीब शामिल है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब इधर मुंह कर लेता हूं, अभी तक मेरा मुंह उधर था। सरकार ने अपने बजट में सहकार से समृद्धि का बहुत बड़ा नारा दिया है। मैं पिछले दिनों ही जो शक्कर के कारखाने बंद हो रहे हैं, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया था। आपके क्षेत्र का मामला था, धर्मजीत सिंह जी के क्षेत्र का मामला था, सूरजपुर का मामला था, भोरमदेव का मामला था, बालोद का मामला था। यह बंद करने की साजिश हो रही है। आप एक साजिश रचने जा रहे हैं, आपके लोग रचने जा रहे हैं। वह लोग जो साजिश रच रहे हैं, वह किसके कहने से रच रहे हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। मगर आपकी नीयत इसमें साफ दिखाई नहीं दे रही है। मैंने धर्मजीत सिंह जी से पूछा था, विधान सभा के बाहर कि भैया, यह जो सिरा बन रहा है, जिसका आप लोग गन्ने से गुड़ भी बनाते हैं, उसमें सिरा ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो यह सिरा का और कुछ उपयोग होता है क्या ? उन्होंने बताया कि शराब बनाने में बहुत अच्छा उपयोग होता है और बहुत सस्ता आता है। सस्ती शराब भी मिलती है और गली-गली बिक भी जाता है। सिरा को राब कहते हैं और राब से गुड़ाखू भी बनता है। बाजू वाले भैया को पता होगा। यह एक साजिश है जो आपके द्वारा हो रही है। आप इसे आरोप समझते हैं तो समझ लीजिये। मगर आप इसकी गति को गुजरात की तरह लगा रहे हैं कि वहां से व्यापारी आये और हमारे शक्कर मिलों को खरीदे, गुड़ मिलों को खरीदे और हम सब थोड़ा फुर्सत पा जाये कि हमको काम न करना पड़े। यह बात अगर है तो बहुत गलत बात है। सतत् विकास, लक्ष्य की श्रेणी में भारत का स्थान 71वें स्थान पर है और छत्तीसगढ़ का वर्ष 2023 में 64वें स्थान पर था और वर्ष 2024 में घटकर 67वें में आ गया, यह आपके विकास का मापदण्ड है, जो आपके माननीय वित्त मंत्री जी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यालय व्यय में हो रही बढ़ोत्तरी, वर्ष 2023-24 में 992 करोड़ 11 लाख से बढ़कर वर्ष 2025-26 में जो अनुमान लगाया है। वह 1769 करोड़ 54 लाख रूपये हो जाएगा। इस सरकारी खर्चे में नियंत्रण करने कौन आएंगे? यह जवाबदारी माननीय वित्त मंत्री जी की है या पूरे मंत्रिमण्डल की है? मगर जो वृद्धि हो रही है, वह 11 प्रतिशत से भी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसमें आपको और हमको चिंतित तो होना ही चाहिए। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा फूड सब्सीडी का है, बी.पी.एल. हितग्राहियों को चावल वितरण किया जा रहा है। आपने अभी बताया। केन्द्र सरकार वर्ष 2011 की बी.पी.एल. सूची को मानने को फिरहाल तैयार नहीं है। इस दिशा में कुछ प्रयास होना चाहिए, क्योंकि यह गरीबों से सीधा जुड़ा हुआ

मामला है। चावल सब्सीडी के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि यह केन्द्र से भी जुड़ा है, डबल इंजन से भी जुड़ा है। आप इसका निपटान जल्दी कर दीजिए। जब हम इसमें वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं। फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ जैसे आप लोग दोहराते हैं जब यहां गड्ढे पाटने की बात होती है तो यह गड्ढा 5 सालों में ही हुआ था, उसके पहले गड्ढा नहीं था। यहां पर एक भी शब्द ऐसा नहीं आता कि उसके पहले भी 15 सालों तक शासन में थे। उसमें कुछ हुआ होगा। उस समय भी बड़े-बड़े काम हुए थे। अब बात नहीं आ रही है। खैर, माननीय अध्यक्ष महोदय आप आसंदी पर बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जब कोविड के समय हमारी सरकार थी तो हमें भी इस डबल इंजन की सरकार ने गारण्टी दी थी और यह कहा था कि आपको Compensation मिलेगा, इन्होंने अपने सरकार का Compensation बनाकर भेजा, वह भी नहीं मिला और आज भी Compensation नहीं मिलेगा। आपको ही Compensation भरना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में पिछली सरकार ने 70 हजार 473 करोड़ रूपये का ऋण लिया है और केन्द्र सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु प्राप्त विशेष सहायता और जी.एस.टी. की राशि, जिसमें सम्मिलित है। अगर हम उसको घटा भी दें तो यह 43 हजार करोड़ रूपये का होता है। इस एक वर्ष में 37 हजार करोड़ रूपये का ऋण ले लेना। यह कहां की वित्तीय व्यवस्था है ? जिसकी चाहते हैं कि हम आपकी प्रशंसा करें। आदरणीय वित्त मंत्री जी आप बताईयेगा कि बजट का क्या हश्र होगा, कैसे होगा ? क्या हम अनुमान लगाएं? यह रजत जयंती वर्ष में आप सबको और हम सबको सोचना है। आप लोगों ने आय का एक प्रमुख स्त्रोत बना लिया है कि यहां पर प्रमुख स्त्रोत केवल आबकारी विभाग है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। जिसके बारे में हर रोज कोई न कोई हमारी सरकार को गाली देता है। आज आपके जमाने में इतने सारे सूखे नशे बढ़ गये हैं। शायद 50 रूपये में एक छोटी सी इतनी बड़ी पत्ती आती है, शायद उसको खाने में पानी-वानी नहीं लगता है। मैंने तो उसे नहीं देखा है। ऐसा कहते हैं कि वह दवाई खाने के उसको कोई पुलिस वाला मारे, आम आदमी मारे, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। उसने इतनी छोटी सी गोली खाली तो। उसके बाद जो उसके शरीर में एक विषैले पदार्थ के कारण, उसका दिमाग खराब होता है उसमें उसको चाकू गोद-गोद कर मारने में खुशी होती है। आज यही सब नशे के कारण हैं यहां बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, चलते-चलते लड़कियों की ईज्जत लूटी जा रही है, जगह-जगह खूनी संघष हो रहे हैं। यहां लूट, खसोट, डकैती, आपके जिले में यह अपराध बढ़ रहे हैं। उसमें रायपुर नंबर वन है, बिलासपुर नंबर 2 पर है और भिलाई नंबर 3 पर है। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप नई पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं ? आपको नई पीढ़ी कैसे याद करे ? आप तो बड़े अच्छे ढंग से याद कर रहे हैं कि इनका 8 सालों का कार्यकाल था और हमारा 16 सालों का कार्यकाल रहा। तब इन 16 सालों के बाद जो यहां आएंगे वह आपको किस नाम से याद करें ? आप यह जरूर बताईयेगा ? हमें आपकी नियत पर संदेह है। अगर हमें संदेह नहीं है तो आप बहुत बड़े ए.आई. तकनीकी ज्ञान के जानकार हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपके तंत्र को इस ए.आई. में लगाईये। आप कहीं

खोजिए, कोई तांत्रिक हो तो आप तांत्रिक को भी खोज लीजिए, कोई तंत्र खोजे, मंत्र खोजें । मगर इन लोगों को ठीक करने के लिए आप कोई बात करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आपका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से विरोध करना चाहा नहीं है, न कभी चाहूंगा और मैं न करता हूँ। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। आपके जो सरकारी ग्रंथ किताबों के रूप में हैं, खैर उसको बोल चुका हूं, उनको नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, वह हमारे मित्र हैं। मंत्री बनने से पहले पेड़ों की कटाई हुई, हमारे पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, पेड़ काटने वाले थे, हमारे हसदेव जंगल के पेड़ कट भी गये। उसमें ठेका भी हो गया, कोयला भी निकलने लग गया और उसका दुष्प्रभाव वहां के हसदेव मिनीमाता बांध में पड़ने भी लगा। सिल्ट भी होने लगा, पानी कम होने लगा। वहां के कलेक्टर हमारे किसानों को नोटिस भी देने लगे यदि यहां रबी के फसल में पानी लोगो तो हम आपको अंदर कर देंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर यह धारा लग जायेगी। इस बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज आपने बड़ी कृपा की कि जब मेरा ध्यानाकर्षण आया था तो आपने जैव विविधता के मामले को जो कि आपने पढ़ा है, रचा है, सुना है, बैठक की है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक मीटिंग करने के लिए बात कही। इससे हम सबको खुशी होगी। इस तरह से पेड़ की कटाई के मामले में हमारी biodiversity भी खराब हो रही है। मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण से सोचा जाये, न कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा जाये। अंत मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अनुपूरक को जोड़ दें तो मेरे ख्याल से इनकी 180 हजार करोड़ रुपये का बन रहा है। अगर वसूली का देखें तो दिसंबर तक 93,860 करोड़ रुपये ही वसूली हुई है। अगर आप वसूली नहीं कर पायेंगे, कर्ज में दबते रहेंगे, कर्ज के लदान से लदते रहेंगे, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि बजट आय-व्यय की व्यवस्था है। मैं यही चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप सुनिश्चित करें। आपने मेरी बातों को सुना तो है, ध्यान देंगे तो मुझे खुशी होगी। यदि ध्यान नहीं देंगे तो हम आने वाले वर्षों में आपकी बुराई करेंगे। इसी बात को कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आज के इस विनियोग विधेयक की चर्चा में भाग लेने वाले हमारे सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विपक्ष की ओर से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी, दलेश्वर साहू जी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी ने चर्चा में भाग लिया। मैं उन पांचों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सत्तापक्ष की ओर से आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, राजेश मूणत जी, धरमलाल कौशिक जी, किरण देव जी, अमर अग्रवाल जी और बीच में कुछ अपना विषय आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने भी रखा था। उन 6 लोगों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष की ओर से शुरूआत भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की और उन्होंने कुछ बातें रखीं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे, उस समय इस बात को लेकर उन्होंने विषय बनाने का दुष्प्रयास किया। मेरे को 3 अप्रैल 2021 की तारीख याद आ रही थी। 3 अप्रैल 2021 की तारीख थी और सुकमा, बीजापुर के बार्डर पर हमारे 22 जवानों की शहादत हुई थी, माओवादियों ने 22 जवानों को शहीद कर दिया था। 3 अप्रैल 2021 को टी.व्ही. में शाम को उस घटना का प्रसारण हो रहा था, दिख रहा था कि 22 जवानों की कैसे शहादत हुई। नीचे में पट्टी में न्यूज चल रही थी। उसी समय टेलीविजन पर दृश्य आ रहे थे कि असम के गोवाहाटी में हमारे उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रोड शो कर रहे हैं। 4 बजे के आसपास 22 जवानों के शहादत की न्यूज चल चल रही थी और टेलीविजन के उसी फ्रेम में पट्टी में लिखा जा रहा था कि 22 जवानों की शहादत हो गई, माओवादियों ने अटैक कर दिया और उसी में टेलीविजन में प्रसारण हो रहा था कि असम के गोवाहाटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हंसते हुए रोड शो कर रहे थे इस घटना के 2 घंटे के बाद और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से...।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आसाम-गोवाहाटी में रोड शो का प्रोग्राम रहा होगा । वह चाहते तो हेलीकॉप्टर से भी यहां नहीं पहुंच सकते थे, वह चाहते तो हेलीकॉप्टर से भी नहीं पहुंच सकते थे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- हंसते हुए रोड शो तो नहीं कर सकते थे न, नहीं कर चाहिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं यह नहीं कह रहा हूं । आप इसको एक-बार और बोल चुके हैं, मेरे सुनने में ही शायद इसी सत्र में और पिछले सत्र में भी बोले होंगे तो ऐसे क्यों बहाना बनाते हो यार ? कुछ अच्छा बहाना बनाओ ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस बात को बोल रहा हूं और अगर आप टेलीविजन के रिकॉर्ड देखेंगे, न्यूज चैनल के रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें पट्टी में चल रहा है कि 22 जवानों की शहादत हुई और उसी फ्रेम पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनीतिक रोड शो करते हुए, हंसते हुए आपको दिखाई दे देंगे । आप अगर चैनलों के वीडियो मंगाएं तो यह साक्ष्य के रूप में दिखाई दे देगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी के नेतृत्व में जब नक्सलवाद पर कठोर प्रहार हो रहा है और आज मैं बहुत हर्ष के साथ सदन के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि 22 माओवादियों का शव आज बरामद हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) 22 जवानों की उस दिन शहादत हुई थी और पहले चरण में ही 22 शव आज माओवादियों के प्राप्त हुए हैं और अब 30 तक वह संख्या पहुंच गई है । (मेजों की थपथपाहट) वह समय था जब इस तरह की शहादत हमारे, चूंकि वह 3 अप्रेल 2021 का दिन था, जिस दिन हमारे जवानों की

शहादत हुई थी और आज हमारे जवानों ने 22 और 22 से बढ़ते हुए 30 माओवादियों को अगर मार गिराया है और उस घटना के बारे में, हमारे जवानों से बात करने के लिए, हमारे पुलिस बलों का हौसला अफज़ाई करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अपने से बाहर जाकर चैम्बर में उन जवानों की अगर हौसला अफज़ाई कर रहे थे तो यहां वही पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नहीं बैठने पर राजनीतिक विषय बना रहे थे । (शेम-शेम की आवाज) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से निश्चित रूप से मैं ह कहना चाहता हूं कि माओवादियों के खिलाफ जो हमारे संघर्ष हैं, उसको नुकसान पहुंचता है । यह वह लोग हैं जो एयर स्ट्राईक का और सर्जिकल स्ट्राईक का भी सबूत मांगने का दुष्प्रयास करते हैं । (शेम-शेम की आवाज) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर तरह-तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबकी ऊर्जा को सामने लाते हुए प्रदेश के विकास में काम करने पर विश्वास करती है । वित्त मंत्री के रूप में या गृहमंत्री के रूप में या PWD minister के रूप में या Health minister के रूप में हमारे साथी जो काम करते हैं, हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसे सब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष केबिनेट में एक presentation के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जब सबकी सर्वानुमति-सर्वसम्मति से जब विषय निर्धारित हो जाता है तब हमारा कोई भी विभाग उस विषय में आगे बढ़ता है । आज एक आदिवासी बेटा को अगर हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने अगर छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने मुख्यमंत्री के रूप में पाई है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वह सहन नहीं होता है । यह आदिवासी विरोधी लोग हैं इसलिए आदिवासी विरोधी हैं कि इनको आज़ादी के बाद लगभग मैं गिन रहा था 56 सालों का समय मिला था भारत देश के राष्ट्रपति बनाने का, भारत देश के संविधान के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी भाई या बहन को बैठाने का लेकिन 56 साल के भारत देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस को जो मौका मिला, उन 56 सालों में एक भी बार किसी आदिवासी भाई को या आदिवासी बहन को कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का काम नहीं किया । (शेम-शेम की आवाज) अगर भारतीय जनता पार्टी में नरेन्द्र मोदी जी को अवसर मिलता है तो पहले राष्ट्रपति के रूप में वे एस.सी. समाज से एक व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाते हैं। (मेजों की थथपाहट) दोबारा जब उनको मौका मिलता है..।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी, आपके पहले हम लोग राष्ट्रपति बना चुके हैं। नारायणन साहब को याद करिए, हम लोग पहले राष्ट्रपति बना चुके हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- और जब दोबारा मौका मिलता है तो एक आदिवासी बहन को हमारी पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाते हैं। (मेजों की थपथपाहट) अभी कुछ महीने पहले पूरे देश ने देखा, जब राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, तो इटली की महारानी ने बयान दिया दैट पूअर लेडी। दैट पूअर लेडी कहकर उन्होंने राष्ट्रपति महोदया का अपमान करने का काम किया। (शेम-

शेम की आवाज) आदिवासी समाज के प्रति, आदिवासी बहन के प्रति या छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री के रूप में सुशासन देने के लिए जो प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं, उनके प्रति इटली की महारानी के बयानों से या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बयानों से साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से इनकी आदिवासी विरोधी सोच है। नफरती झलकती है।

डॉ. चरणदास महंत :- और अमेरिका से इतने लोग हथकड़ी पहनाकर और इधर बेड़ी बांधकर यहां अमेरिका से भेजे जाते हैं, तब आपको [XX][7] नहीं आती।

श्री ओ.पी. चौधरी :- तो क्या इटली की महारानी को यह अधिकार मिल जाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई एक आदिवासी व्यक्ति को पूअर लेडी बोलें। इटली की महारानी को क्या यह अधिकार मिल जाता है?

डॉ. चरणदास महंत :- आप लोग हर बात को, भाषा को बदल-बदल कर इस तरह से बात करते हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वह आपकी महारानी हो सकती है। देश ने उनको महारानी स्वीकार नहीं किया है।

डॉ. चरणदास महंत :- अगर [XX] शब्द गलत है तो आप काट सकते हैं। गलती से निकल गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने [XX] शब्द का उपयोग किया है, अगर वह भाषा गलत हो तो आप उसे निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, देख लेते हैं।

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, अब इटली से क्या संबंध हैं, ये तो आप जानते हैं। अब इटली वाली कौन सी महारानी क्या बोल रही है, यह तो आप लोग ज्यादा जानते हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अमेरिका का संबंध आप लोग से है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, इटली से कांग्रेस का क्या संबंध है? कांग्रेस पार्टी का इटली से क्या संबंध है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय वित्त मंत्री जी, विनियोग में बोलिए न। आप विनियोग में बोलिए न।

श्री राजेश मूणत :- आप इटली के नाम पर इतने परेशान क्यों होते हो?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप जारी रखिए।

डॉ. चरणदास महंत :- आप लोग अपने नेता की 108 की माला की तरह जप करते हैं तो हम लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं होती। हम लोग अपने नेता की कोई बात करते हैं तो आप लोगों को चिढ़ हो जाती है।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इनकी नेता देश के पहले सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक आदिवासी बेटी को दैट पूअर लेडी बोलती हैं, उस बात से हमें समस्या है। इटली की महारानी से हमें सीधे कोई समस्या नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- पूअर लेडी, किन अर्थों में कहा था? क्या आपने इसे सुना है?

श्री ओ.पी. चौधरी :- पूरे देश ने देखा।

डॉ. चरणदास महंत :- देखा होगा। आप उल्टे-सीधे..।

श्री ओ.पी. चौधरी :- पूरा देश इसका विश्लेषण कर रहा है और इसीलिए आप लोग वहां पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- यहां आने को मजबूर नहीं हुए हैं। आपने राहुल जी के भाषण को भी उसी तरीके से आलू से सोना निकाला था और द पूअर लेडी को भी आपने उसी अंदाज में, आपके ए.आई. ने या जो भी आपका तंत्र हो, उससे बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आपके कहने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, मगर ऐसी बात मत करो। बहुत पढ़े-लिखे हो, आप तो आई.ए.एस. हो।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति ला आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी करे हे। आप मन हमेशा रोके के काम करे हावौ। का बात करथौ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आना चाहूंगा कि आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और उसी के अनुसरण में हमारे छत्तीसगढ़ में हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। कल रात को मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था तो मैं साउथ कोरिया का उदाहरण पढ़ रहा था। उस पर मैं देख रहा था कि जब भारत देश आजाद हुआ, लगभग उसी दौरान साउथ कोरिया आजाद हुआ तो वे लोग एक्सपोजर टूर में थे कि कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, उसको लेकर साउथ कोरिया के लोग भारत देश देखने के लिए आये थे कि कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग जब भी देश के विकास की बात करते हैं तो सामान्यत: बोल दिया जाता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए विकास करने में दिक्कत आती है। साउथ कोरिया का जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या है, वह भारत देश से भी ज्यादा है। जितने भी सामाजिक आर्थिक सूचकांक आजादी के समय वर्ष 1945, वर्ष 1947 के समय साउथ कोरिया के थे, वह भारत से बहुत खराब थे। उनकी राजधानी सियोल की हालत दिल्ली से ज्यादा खराब थी और इसलिए वे भारत देश आये थे कि कैसे देश को विकास करने की दिशा में आगे बढ़े। वे एक्सपोजर टूर करने आये थे। लेकिन उनकी लीडरशिप मजबूत रही, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। वहां पार्क नाम का एक प्रेसीडेंट हुआ उसने बड़े विज़न के साथ काम किया और 1945 से लेकर 2025 तक लगभग 80 साल की इस विकास यात्रा में साऊथ कोरिया की अर्थव्यवस्था एक लाख

गुना बढ़ी । वहीं हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था लगभग 2000 गुना ही बढ़ पाई । आज साऊथ कोरिया जैसा देश विकास के सोपानों को छू रहा है । वह 80 के दशक में ही बहुत जल्दी विकसित राष्ट्र बन गया । एक साऊथ कोरिया का ही उदाहरण नहीं है । इसी तरह से सिंगापुर का उदाहरण है, इसी तरह से जापान का उदाहरण है । 1970 से 1995 तक उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम धमाके हुए थे । उसके बाद राष्ट्र का पुनर्निमाण उन्होंने 1970 से 95 तक करते हुए एक नए सोपान को छुआ । उस मामले में हम कहीं न कहीं पीछे रह गए । इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोल रहा हूं । अभी छत्तीसगढ़ के विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है । माननीय मंत्री जी, हमें साऊथ कोरिया जाने की कोई जरूरत नहीं है । आप बड़े पढ़े लिखे माने जाते हैं, आपको याद होगा आपका जो पहला बजट भाषण चला था ।

श्री रामकुमार यादव :- हिरोशिमा नागासाकी के बम के बारूद ला हमला का करना हे भई ।

डॉ. चरणदास महंत :- बजट भाषण चला था तो उस बजट भाषण में मेरे लड़के ने बताया कि आपने 100 बार नरेन्द्र मोदी जी का नाम लिया था, 100 बार उस बजट भाषण में है, मैं खोजकर लाकर आपको बता दूंगा और आपने हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री जी का नाम मात्र 50 सा 60 बार लिया था । तो इसका अर्थ क्या होता है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े पूरी तरह से गलत हैं । हालांकि नरेन्द्र मोदी जी हमारे..।

डॉ. चरणदास महंत :- ये रिकॉर्डेड है, लाकर दिखा दूंगा ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आप दिखा दीजिए, सदन के समक्ष कल प्रस्तुत कर दीजिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं मेरे बेटे को बताता हूं (हंसी) ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- फंसवाएगा आपका बेटा आपको कहीं, ऐसा लग रहा है (हंसी) ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं । हमने नरेन्द्र मोदी जी का नाम लिया है, वे हमारे प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं । लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम हमने ज्यादा बार लिया है (मेजो की थपथपाहट) । हमने दोनों का नाम लिया है ।

श्री रामकुमार यादव :- मुख्यमंत्री जी, तू रथस ता गुणगान करत हे, तु नइ राहस ता आने ताने गोठियाथे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सबको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो तुम्हारा टिकिट काट देंगे, ऐसा बोले हैं क्या यार ? सबको डिस्टर्ब करते हो और इसी शर्त पर तुमको टिकिट दिये थे कि पूरे पांच साल डिस्टर्ब करना है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इनका तो टिकिट महंत जी ही काटेंगे । ये पूरी तरह से महंत जी के साथ नहीं है । तुम्हारा टिकिट तो महंत जी ही काटेंगे याद रखना ।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय नेता जी, हमको मालूम नहीं था कि आपका बेटा इतना होनहार है, आपने बेटे का जिक्र किया ।

डौ. चरणदास महंत :- मैं बेटे की होनहारी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- हम भी चाहते हैं कि इस विधान सभा में होनहार लोग आएं, आप घोषणा कर दो कि अगला चुनाव आप नहीं लड़ोगे, अपने बेटे को लड़ाओगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप निर्विरोध कर दो मैं लड़वा दूंगा ।

श्री अमर अग्रवाल :- अरे वो टिकिट तो आपको देने देगा जब ना, आपका पड़ोसी । आप तो इसी बार दो टिकिट चाह रहे थे ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने साऊथ कोरिया का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि देश और दुनिया में इस प्रकार के इंस्पेरेशन हैं जो अच्छे विकास मॉडल एडॉप्ट करके आगे बढ़े और वहां पर वीजीएप स्कीम से जिस तरह से देश विकासशील से विकसित बना था । वैसे नरेन्द्र मोदी जी कोरोना के बीच पीएलआई स्कीम लेकर आए और आज मैं सदन में ऐलान करना चाहता हूं कि आज से 20 साल, 30 साल बाद विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने का इतिहास लिखा जाएगा तो नरेन्द्र मोदी जी के कोरोना के समय उठाए गए पीएलआई स्कीम को इसी तरह से याद किया जाएगा जैसे साऊथ कोरिया की विजिएप स्कीम को याद कर रहे हैं (मेजो की थपथपाहट) । मैं इसलिए जिक्र कर रहा था । अध्यक्ष महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर है जिसको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट घोषणा कर रहे हैं कि 5.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी । यह नरेन्द्र मोदी जी की लीडरशिप है जिसमें 2014 से 2024 तक भारत की इकोनॉमी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है (मेजो की थपथपाहट) । 2004 में यूपीए की सरकर आई, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार आई तब भारत देश की अर्थव्यवस्था दसवें नम्बर की अथ्व्यवस्था थी और 2014 तक 10 साल तक यूपीए की सरकार रही और भारत दसवें नम्बर की अर्थव्यवस्था बना रहा । उसको मोदी जी ने 2014 से 2024 के बीच एक नया छलांग लगाते हुए 10वें स्थान से आगे बढ़ाते हुए 5वें स्थान तक पहुंचाने का काम किया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इन 10 सालों की प्रक्रिया में हमें गुलाम बनाकर रखने वाले ब्रिटेन देश को भी पीछे छोड़ने का काम किया। मोदी जी ने ऐलान किया है कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को जर्मनी और जापान को छोड़ते हुए तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचाएगी। (मेजों की थपथपाहट) जब भारत की इतनी बड़ी विकास की यात्रा चल रही है तो ऐसी स्थिति में 2047 तक नरेन्द्र मोदी जी के लीडरशीप में अमृतकाल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो काम चल रहा है, उसमें हम कहीं पीछे न रह जाएं, ये हमारी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है, इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी समझते हैं और इसलिए

उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़ अंजोर विजन@2047 हमारी स्ट्रेटजी बनकर तैयार है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे इतना ही अनुरोध कर रहा था कि जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, उसको यहां रखवा देते। हम भी उसमें चर्चा करते।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इसको बनाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से सबसे चर्चा की। हमारे सभी सम्माननीय विधायकों से चर्चा की, चाहे वे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। हमने सबको चिट्ठी लिखकर उनके सुझाव आमंत्रित किए। सभी के सुझावों पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा चुका है। हम उसको बहुत जल्द जनता को और सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी उसकी प्रति समर्पित करेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- आप सिर्फ उसको भाजपाईयों तक ही सीमित रखना चाहते हैं ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- बिल्कुल नहीं।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने हम लोगों से पूछा ही नहीं। हमारे किसी भी विधायक को विजन डॉक्यूमेंट के बारे में कोई पत्र नहीं आया। किसी से सुझाव नहीं मांगे गये।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आप बोल दीजिए कि मैंने पत्र नहीं लिखा है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने पत्र लिखा होगा, उसको कहां डाला ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- सर, सब लोग नहीं मिला है बोल दीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो बोल रहा हूं।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आपके कितने सारे साथी बताए हैं कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए आपकी चिट्ठी मिली। इसी सदन के रिकॉर्ड में बताए हैं आप चेक करा लीजिए।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने मुझे नहीं मिला बोला। बहुत सारे साथियों को नहीं मिला।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आप तो सबसे पूछ रहे थे।

डॉ. चरणदास महंत :- या तो ये विजन डॉक्यूमेंट समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। एक मीटिंग बुला लेते, चाय नाश्ते के साथ समझा देते।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, विजन डॉक्यूमेंट बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की बात करते हैं तो अनेक विपक्ष के साथी उपहास उड़ाने का दुष्प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जब तक हमारा लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर सकते। ये नारे पे नारे लगाते रहे, लेकिन हम वास्तव में विकास करके दिखाना चाहते हैं। अगर अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में ये निर्णय लेती है कि हम देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद, माओवाद को समाप्त करेंगे तो

उसकी डेडलाईन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिक्लियर करती है। (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा लगाए थे। लेकिन आज भी किस तरह के हालात है। नरेन्द्र मोदी जी के इन 10 सालों में जिस तरीके से गरीबी उन्मूलन के काम हुए, जिस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाया गया, उस चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो दशकों तक गरीब गरीबी में ही पलते रहे। ये 1970 से नारा लगा रहे हैं। अगर हम माओवाद को समाप्त करने की बात करते हैं, हम डेडलाईन भी देते हैं कि मार्च, 2026 तक हम माओवाद को समाप्त करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस तरह की सोच के साथ, इस तरह के विचार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं देख रहा था, हमारे विपक्ष के अनेक साथी बोल रहे थे कि गुजरात मॉडल क्या है ? गुजरात मॉडल में ये है, गुजरात मॉडल में वो है, गुजरात मॉडल का जवाब गुजरात और देश की जनता लगातार देती आ रही है। देश ने नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीन बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, ये गुजरात मॉडल है। (मेजों की थपथपाहट) लोकतंत्र में जनता से बड़ी कसौटी और कोई दूसरी कसौटी नहीं होती है। आप गुजरात के अंदर जाकर देखें, गुजरात के चुनाव परिणामों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। वर्ष 1995 से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार है। सन् 1995 से वर्ष 2022 में 27 सालों के बाद जब गुजरात में चुनाव होते हैं तो 182 में से 156 सीट गुजरात मॉडल को गुजरात की जनता देती है। (मेजों की थपथपाहट) आजाद भारत के इतिहास में और पूरे गुजरात राज्य के इतिहास में सबसे कम सीट 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गयी तो 27 साल बाद इनको 182 में से 17 सीट मिली है। यह गुजरात मॉडल है।

श्री रामकुमार यादव :- आप एक समय याद करो भारतीय जनता पार्टी के मात्र दू ठन सीट रीहिस हे। एक ठन कोंटा में रहाए। आप ए बात ला काबर भूलत हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- वित्त मंत्री जी, दिल्ली में शून्य मिला है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- गुजरात में भी शून्य मिला है।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिल्ली में तीसरी बार शून्य मिला है। रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- हां, बताओ जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- यदि आप गुजरात जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि आटो में बैठोगे और कहीं नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो वह लोग बीच रास्ते में उतार देते हैं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- आप संभल कर जाना।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मतलब, धर्मजीत भैया, आप बोलकर देख चुके हैं। आपको अनुभव है। आप जो बात बता रहे हैं, वह आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है ?

श्री रामकुमार यादव :- नहीं-नहीं, पहिली ए कांग्रेस में रीहिस हे ता ऐला आटो ले उतार दे रीहिस हे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कांग्रेस में था, मैं भाजपा में था। मैं गुजरात नहीं गया हूं। मेरे पास एक व्यक्ति आया और मुझे बोला कि वहां पर मैं नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे ही बोल दिया था तो वह आटो रोककर मुझे बोले कि उतर नीचे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। (हंसी) इसलिए

श्री रामकुमार यादव :- मैं कहेव कि ओ समय कांग्रेस में रहे हव ता चिन डारे रीहिस हे। (हंसी)

श्री केदार कश्यप :- इनको प्लेन से उतारा जाएगा। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात मॉडल, नरेन्द्र मोदी जी का नेतृत्व आजाद भारत का एकमात्र नेतृत्व है, जिसकी यदि हम सन् 2001 से सन् 2025 तक बात करे तो लगातार 24 सालों तक जनता ने उसको चुना है। 24 साल तक वह राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री या देश के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री रहे हैं। इन लोगों को इसी बात की पीड़ा होती है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बार ज्ञान का बजट प्रस्तुत किया था। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी उसकी कई तरह से आलोचना कर रहे थे। हर्षिता जी भी उसकी आलोचना कर रही थी। ज्ञान में पहला बिंदु गरीब का है। जिस तरह से इन्होंने 5 वर्षों तक आवास को छीना था तो गरीब विरोधी होने का उससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर आवास योजना के हितग्राहियों को आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया कि उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शब्द और प्रधानमंत्री शब्द लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब इनकी सरकार थी और यह योजना चलाते थे तो उस समय इन्होंने इंदिरा आवास योजना नाम रखा था और परिवार के चरणों में जाकर नाम रखा था। इनको परिवार की चापलूसी करते हुए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास की शुरूआत भी कांग्रेस वालों ने और कांग्रेस की सरकार ने ही इंदिरा आवास से की थी तो गरीबी को हटाने के लिए गरीबी उन्मूलन की शुरूआत कांग्रेस की ही सरकार ने की है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुभाष चंद्र बोस आवास नाम भी तो रख सकते थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 1 गांव में 5 से ज्यादा नहीं बनते थे।

श्री दलेश्वर साहू :- भाई साहब, अटल समरसता भवन क्या है ?

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- मैंने वह भी कहा कि पहले उसके लिए 1 लाख 50 हजार रूपये दिये जाते थे और आज उसको कम करके 1 लाख 20 हजार रूपये कर दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आप छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में कहीं पर भी एकाध इंदिरा आवास दिखा सकती हैं? क्या आप डोंगरगढ़ में दिखा सकती हैं? चलिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- है। वह अभी भी चल रही है। वहां पर आपकी अटल आवास योजना चल रही है। वह भी जर्जर हो गई है, लेकिन उसके लिए भी आज तक राशि नहीं मिली है।

श्री दलेश्वर साहू :- आज भी लोग आपके प्रधानमंत्री आवास को इंदिरा आवास ही बोलते हैं। वह योजना इतनी पॉपुलर है। उनको आज भी समझ नहीं है कि वह किसका आवास है। लोग उसको इंदिरा आवास ही बोलते हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको परिवार के चरणों में चापलूसी करते हुए इंदिरा आवास शब्द नाम स्वीकार था। लेकिन देश के सर्वोच्च कार्यपालिक संवैधानिक पद प्रधानमंत्री आवास शब्द नाम स्वीकार्य नहीं है। मैं इस बात की आपत्ति ले रहा हूं। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- पहले दूसरा आवास, फिर अटल आवास और फिर प्रधानमंत्री आवास नाम अब हुआ है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [xx] शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है। वह हमारी आस्था हो सकती है। लेकिन मंत्री जी, यह [xx] शब्द अच्छा नहीं है। आप इतने विद्वान हैं। [xx] शब्द इतना हल्का है। [xx] शब्द अच्छा नहीं है। यह शब्द ठीक नहीं है कि हम [xx] हैं। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- आपने अटल समरसता भवन नाम क्यों रखा है ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गांव-गांव में जो अटल चौक बने हैं, वह किसके नाम से बने हैं ? गांव-गांव में ग्राम पंचायतों में अटल चौक बने हैं तो वह किसके नाम से बने हैं ? वह किसकी स्वामी भक्ति है ? वह किसके चरणों की भक्ति है ? आप यह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल चौक नाम क्यों है? गांव-गांव में ग्राम पंचायतों में आपने जो चौक बनाये गये हैं, उनका नाम अटल चौक क्यों रखा गया है ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप पहले कलेक्टर रहे हव ता बढ़िया रहे हव। जब ले आप भारतीय जनता पार्टी में गेहो, तब ले तुंहर शब्द आने हो गेहे। आप ए [xx] शब्द ला बताओ कि कइसने हे तेला ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है कि एक एरोप्लेन में मिट्ठू और बंदर दोनों यात्रा कर रहे थे। (हंसी) बार-बार वह मिट्ठू एयर होस्टेस को बुलाने वाले लाइट को बजा देता था तो बंदर बोला कि यह क्या है ? तो वह बोला कि मैं इस बटन को दबाता हूं तो एयर होस्टेस आती है तो मजा आता है। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- भाई, आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो हम सुनते थोड़ी न रहेंगे। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आप बोले तो ठीक और हम लोग बोले तो गलत। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सबसे ज्यादा आप बोलथो। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बंदर थोड़ी न मानने लगा। एयर होस्टेस पायलेट को बताई तो पायलेट ने कहा कि इन दोनों को प्लेन से बाहर फेंक दो। मिट्ठू बोला कि मुझे तो उड़ने आता है, तेरे को आता है

? बंदर बोला कि नहीं आता, तब मिट्ठू बोलता है कि फिर मजा लेने का शौक क्यों करता है। आप लोग ऐसा शौक मत करो। (हंसी) मोदी जी को उड़ना आता है, मोदी जी को सब प्रकार की कला मालूम है और आप लोगों को एक ही कला मालूम है- मजा लेना है, मजा लेना है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उड़ना आता है, हम लोगों को भी उड़ना आता है।

श्री राम कुमार यादव :- कांग्रेस पार्टी मा कोई डरने वाला नइ हे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, योजना की शुरूआत कांग्रेस ने की थी, उसको ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। असली मजा आप ले रहे हो।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- असत्य की बुलन्दी में जो ईमारत खड़े किए हैं, असत्य की बुनियाद तो गिरना ही है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बस इतना ही फर्क है कि आप कोशिश कर रहे हो।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, असली मजा खुद ले रहे हैं। जो कभी कांग्रेस में रहते हैं कभी भा.ज.पा. में चले जाते हैं।

श्री प्रबोध कुमार मिंज :- राम कुमार जी, इतना बढिया उदाहरण दिए हैं। आप ऊंगली मत किया करो।

श्री राम कुमार यादव :- मोर रखिइया हे, ओखर रहत मैं डरने वाला नइ हव।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों ने इन्दिरा आवास योजना की बहुत चर्चा किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि 2002 से लेकर 2015 तक इन्दिरा आवास योजना लगभग 14 साल चली। इन 14 सालों में इन्होंने कुल मात्र 5 लाख 39 हजार आवास बनाये थे। ये इन्दिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। कच्चा मकान बनाये थे, 5 लाख 39 हजार आवास बनाये थे। आज हम 2 साल, 3 साल के अंदर 18 लाख आवास बनाने की बात करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

श्री राम कुमार यादव :- एक साल तीन महीना मा 1लाख 65 हजार 120 आवास बने हे। 16 लाख आवास कैसे बनही तेला बतावा ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक साल में 13 लाख रोजगार पंजीकृत गरीब मजदूरों के नाम काटे हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आवास योजना की बात कर लो, मुद्दे से मत भटकाओ। सुनने की हिम्मत रखो।

श्री राम कुमार यादव :- एक साल तीन महीने में 1लाख 65 हजार 120 आवास बने हे। 16 लाख आवास कैसे बनही तेला बतावा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आपने आवास के निर्माण में राशि की कमी क्यों की है ? यह तो बता दीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 5 साल तक 18 लाख गरीबों के आवास छीनने वाले लोगों को आज सच्चाई और सत्य सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पहले 1 लाख 50 हजार मिलता था, लेकिन आज 1 लाख 20 हजार क्यों कर दिया गया, यह तो बता दीजिये ? आज तो आपकी सरकार है। आपकी केन्द्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, आपने उसके बाद राशि क्यों कम कर दिया ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 42 हजार रूपये तब भी मिलता था और 1 लाख 42 हजार आज भी मिलता है। उसमें नरेगा का कम्पोनेंट अलग होता है। (मेजों की थपथपाहट) 1 लाख 20 हजार सीधा मिलता है, बाकी नरेगा और स्वच्छता कम्पोनेंट मिलता है।

गृह मंत्री (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो यह है कि जब कल भी चर्चा हो रही थी तो कुंवर सिंह निषाद जी ने कहा कि 15 हजार महिलाएं अपहृत हो गईं। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब से लेकर आज तक पूरी गणना की गई थी, वह कोई आकड़ा नहीं था। जब मैंने बताया तो आप नहीं थे, आप उस समय निकल गये थे। अभी आपने फिर कहा कि 13 लाख ऐसे लोग हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। इसमें 4 लाख की संख्या है। 4 लाख नाम कटे, ढाई लाख नाम नये जुड़े। नाम कटने के विभिन्न कारण हैं। चाहे शादी हो गई है, चाहे मृत हो गए हैं, ऐसे सारे कारण हैं। तो वह भी आकड़ा गडबड़ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे व्यवस्था अवश्य चाहिए कि पलायन और बहिर्गमन में फर्क होना चाहिए। जब सत्य सुनना है तो बैठना पड़ेगा, ये पलायन कर जा रहे हैं। जब मैं उस दिन 18 लाख की कथा कह रहा था तो भी पूर्व मुख्यमंत्री जी पलायन कर गये। वह बात को नहीं सुने। जब माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार बनी तब 9 लाख 33 हजार आवास पूर्ण थे, उसके बाद पूरे के पूरे 18 लाख आवास माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में ही लगभग 13 लाख 80 हजार कुछ फिगर था, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप कन्टीन्यू करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने जो 18 लाख कथा सुनाई थी, मैं उस समय सदन में मौजूद था, मैं उस पूरी कथा को दोहराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ए.सी.सी. सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, आप बिना इन्टरप्शन के सुनिये कि 18 लाख आवास कहां

से आता है। कल 18 लाख आवास कैसे बना, हम इसको कैसे दिखायेंगे, सुनिये। सुनने की हिम्मत रखिये। सन् 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में 6 लाख 99 हजार 439 आवास शेष थे। आप जोड़ते जाईये। आवास प्लस वर्ष 2016 की सूची में ..।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप धीरे भी बोल सकते हैं। (हंसी)

एक माननीय सदस्य :- सर, हम लोगों चमका रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, वह आपा खो रहे हैं। आप अपना आपा संभालिये। आप इतने बड़े मंत्री हैं, आप थोड़ा धैर्यता से जवाब दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- आप काम में जोर दीजिये, आवाज में जोर मत दीजिये। चौधरी साहब, आप काम में जोर दीजिये, आप तो अच्छे आदमी हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- आप धैर्यता के साथ जवाब दीजिये, टेक्निकल जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए, जिस प्रकारे वे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आराम से जवाब सुनिये।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष जी आप लोगों को संरक्षण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सबको पूरे संरक्षण है। मंत्री जी, आप चालू करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, ए.सी.सी.सी., सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 439 आवास शेष है। (धीरे-धीरे बोलने पर) (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, बने बोलत हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अब प्यार से सुनिये, भाई।

श्री दलेश्वर साहू :- हव, सुनत हौ, सुनत हौ।

अध्यक्ष महोदय :- भाई, सुन लीजिये। अब आराम से सुनिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 आवास प्लस के अंतर्गत 8 लाख 19 हजार 919 आवास है। (मेजों की थपथपाहट) जो अपूर्ण आवास थे, बीच में जिनको एक किस्त, दो किस्त देकर छोड़कर चले गये, उसके अंतर्गत 2 लाख 46 हजार 215 आवास है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर एक योजना चलाये, जिसमें ए.सी.सी.सी. के लिस्ट को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसका निर्माण यू.पी.ए. सरकार ने किया था और इन्होंने वर्ष 2016 के आवास प्लस को भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 47 हजार 90 आवास के लिए केवल 25-25 या 30-30 हजार रूपये का पहला किस्त दिये थे। हम इन तीनों को ही जोड़ दें तो 18 लाख से ऊपर का आवास होता है (मेजों की थपथपाहट) और यह किसी भी डेटा में जोड़ कर देख लें, जिसके अंतर्गत 25 हजार जनमन के आवास और 15 हजार नक्सल प्रभावितों के आवास (मेजों की थपथपाहट) जो

अतिरिक्त भारत सरकार ने जोड़ा है, उसको यह लोग नहीं जोड़ते हैं। हमने 18 लाख से अधिक आवास बनाने का संकल्प लिया था। जब हम विपक्ष में थे तब मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन चलाते हुए हम लोग विधान सभा का घेराव करने आये थे, वहां हमारे बीच बम फोड़ रहे थे। उस समय हमारे अरूण साव जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने उन हितग्राहियों के चरण पखारे थे, उस दिन भी वह संकल्प लिये थे और जब सम्माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी बनी और पहला केबिनेट की मीटिंग हुई तब उन्होंने पहला संकल्प के रूप में 18 लाख आवास के फाईल पर दस्तखत किया था। (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने शहरी क्षेत्रों को छोड़ कर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में 18 लाख आवास बनाने का संकल्प लिया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप कृपा करके रामकुमार जी को दो आवास जरूर दे देना। रामकुमार जी, आप दो आवास ले लेना। मंत्री जी, एक आवास रामकुमार यादव और एक आवास यादव रामकुमार, ऐसा करके दो आवास दे देना। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिए आवास से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता है। उनके साथ पांच साल कैसे धोखा हुआ था और हमारी सरकार किस समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, उसका मैंने ब्यौरा प्रस्तुत किया। मैं किसानों के विषय में बताना चाहूंगा कि किसानों के संबंध में सदन को गुमराह करने के दृष्टिकोण से विपक्ष के द्वारा तरह-तरह की बातें कही जाती है। मैंने कई बार आंकड़ा प्रस्तुत किया है और आज फिर प्रस्तुत करना चाहता हूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में 5,627 करोड़ रूपये इन्होंने चार किस्तों के रूप में प्रदान किया, वर्ष 2020 में इन्होंने 5,553 करोड़ रूपये चार किस्तों को मिलाकर प्रदान किया और हम लोगों ने पिछले बार एक ही साल में 13,320 करोड़ रूपये अंतर की राशि एक साथ प्रदान की है। (मेजों की थपथपाहट) इस बार 31 जनवरी को धान खरीदी की तारीख समाप्त हुई और मात्र सात दिनों बाद 07 फरवरी की तारीख आई, उस दिन मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फोन किया कि आज मैंने भाषण में बोला है कि आज हमको पैसा भेज देंगे, उसकी क्या स्थिति है, वह आप पता करिये तो मैंने बैंक में फोन लगाया तो बैंक वालों ने कहा कि अंतर की राशि हमको 12,000 करोड़ रूपये अंतर की राशि मिल गई है, लेकिन यह राशि इतनी बड़ी है कि इसको कम्प्यूटर एक दिन में प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसमें दो दिन का समय लगेगा। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विष्णु देव साय जी के सवा साल के कार्यकाल में किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि हमने अंतरित करने का काम किया है , उसका भी ब्यौरा चाहिये तो सम्माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे ।(मेजों की थपथपाहट) यह किसानों की बात हुई है । अध्यक्ष महोदय, जब महतारी वंदन योजना की बात होती है तो हमारे विपक्ष के साथी तरह-तरह की बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथियों को निवेदन करना चाहूँगा कि वह अपने जन-घोषणा पत्र 2018 को खोलकर देखें, उसकी

प्रति को निकालें, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माताओं और बहनों को प्रति माह 500 रूपये की राशि प्रदान की जायेगी । अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल का 5 साल का समय बीत गया है, इन्होंने एक भी महीना पांच रूपये देने का काम नहीं कर पाये ।(शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) आज बात करते हैं कि उसको कम मिल गया और उसको ज्यादा मिल गया, इस तरह की बातें करते हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह बात सदन के समक्ष रखना चाहूँगा कि हमारी माताओं और बहनों के लिये देश के विभिन्न राज्यों में जितनी भी योजनायें चल रही है, उसमें सर्वाधिक कवरेज परशेंटेज की दृष्टि से किसी राज्य में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है, जहां महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हम 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 सालों में 5 रूपया का भी भुगतान नहीं दिया है, आज उनको किसी भी प्रकार का सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं बनता है । (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हम ज्ञान के लिये समर्पित होकर काम कर रहे हैं, युवाओं की दृष्टि से भर्ती पर भी तरह-तरह की बातें आक्षेप के रूप में इस सदन को गुमराह करने के लिये रखी गयी है । आज माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी बोल रहे थे कि देश की सभी सरकारें मानती है कि सरकारी नौकरी के अलावा अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजन करके ही हम युवाओं में विश्वास अर्जित कर सकते हैं । हम दोनों दृष्टि से कार्य कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आज भारत के युवाओं की मांग देश और दुनिया में बढ़ रही है । जर्मन चांसलर ने अभी मोदी जी के साथ एक एम.ओ.यू. किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 लाख युवाओं की आवश्यकता बताई है । अध्यक्ष महोदय, आज पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष है, कोरिया की औसत आयु 50 वर्ष है, जर्मनी की औसत आयु आज 47 वर्ष है, चीन की औसत आयु आज 40 वर्ष है, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है, आज इन परिस्थितियों में भारत युवा देश है, जिसकी औसत आयु मात्र 28 वर्ष है, छत्तीसगढ़ और भी युवा प्रदेश है, जिसकी औसत आयु मात्र 24 वर्ष है । अध्यक्ष महोदय, हम इन डेमोग्राफिक कंडिशन्स का लाभ लेने के लिये, बेहतर अवसर दिलाने के लिये, कौशल विकास की दृष्टि से इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थानों की स्थापना आपके कार्यकाल में हुई है, चाहे आई.आई.एम. की बात करें, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे एन.आई.टी. की बात करें, चाहे ट्रिपल आई.टी. की बात करें, चाहे सीपेड की बात करें, आज आप सभी को पता है कि इस बजट में निफ्ट के नाम से एक नये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर स्किल प्रदान करते हुये देश और दुनिया में उभरते हुये मांग के अनुसार बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिये 12 नवीन नर्सिंग कॉलेज और 6 नये फिजियोथेरेपी कॉलेज का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. और पॉलिटेक्नीक को

बेहतर करने के लिये, समयानुकूल बनाने के लिये, आज के समय की डिमांड को पूरा कर सकें, युवाओं में स्किल डेवलप करने के लिये, स्किल को बेहतर करने के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सर्विस सेक्टर में फोकस करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है । हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई उद्योग नीति लेकर आई है, नई उद्योग नीति में पहला जो बिन्दु निर्धारित किया गया है, जो इंसेंटिव है, जो छूट है, जो सब्सीडी है, उनको निवेश के आधार पर न देकर रोजगार सृजन के आधार पर दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, पहले जो छूट दी जाती थी, वह छूट रहता था कि 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो यह छूट मिलेगी, 2000 करोड़ से ज्यादा निवेश करेंगे तो यह छूट मिलेगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय उद्योग मंत्री जी ने जो रणनीति को बदलने हुये निर्धारित किया कि अगर 1 हजार लोगों को रोजगार देंगे तो ये-ये छूट मिलेगी, 2000 लोगों को रोजगार देंगे तो ये-ये छूट मिलेगी । इस तरह से उद्योग नीति को पूरी तरह से रोजगार सृजन पर केन्द्रित बनाया है । इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे, लेबर इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग के अनेक अवसर पैदा होंगे, सर्विस सेक्टर में टूरिजम को इंडस्ट्री का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने इन सवा सालों के बीच में किया है । हम बस्तर और सरगुजा के लिए होम स्टे पॉलिसी लेकर आये हैं । इन सबसे निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बहुत तेजी से पैदा होंगे। इसके अलावा हमारी सरकार इस सदन में आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के मामले में भी पिछली सरकार ने 5 सालों में जो भर्तियां की हैं, उससे बहुत ज्यादा भर्ती इन 5 सालों के कार्यकाल में हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाएगी (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सवा साल की अवधि में 19 विभागों में लगभग 10 हजार नये पदों को स्वीकृति देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है और इस दृष्टिकोण से आने वाले 4 सालों में उनके 5 साल और हमारे 5 सालों की कोई तुलना करेगा, वह स्पष्ट रूप से पाएगा कि कांग्रेस के पिछले 5 सालों की तुलना में हम कहीं अधिक और बेहतर रोजगार देकर दिखाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञान की इस परिकल्पना को हमें अगर साकार करना है, अगर हमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण को सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास जरूरी है । जब आर्थिक विकास होगा, तभी हम कल्याणकारी योजनाओं को *Sustainable* तरीके से आने वाले भविष्य में भी चला पाएंगे। इस बात को समझते हुए नई आर्थिक रणनीति बनाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गति की अवधारणा के साथ इस बजट को हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, जिसमें गर्वनेंस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, टेक्नालॉजी पर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमारी सरकार का पूरा फोकस है । ज्ञान का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए गति हमारी स्पष्ट रणनीति है और उस रणनीति के माध्यम से हम तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करेंगे । हम गर्वनेंस प्रोवाईड करेंगे और जब तीव्र आर्थिक विकास

होगा और जब बेहतर गर्वनेंस होगा तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा । इसका उदाहरण पिछले सवा सालों में भी हमने करके दिखाया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि चाहे हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी ग्रोथ की दृष्टि से पूरे देश में छत्तीसगढ़ आज बेस्ट परफार्मिंग थ्री स्टेट में है । जो पंजीयन शुल्क है, उसमें लगभग 20 प्रतिशत का ग्रोथ इन सवा सालों में हुआ है । कई सारे रिफार्म हमने इंट्रोड्यूस किये, उनके रिजल्ट आने में कुछ महीनों का समय लगा । अभी कई महीने ऐसे आते हैं, जिसमें 60-65 परसेंट का भी ग्रोथ आता है । चाहे ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू की बात करें, चाहे एक्साईज़ रेवेन्यू की बात करें, सबमें ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हो रही है । (मेजों की थपथपाहट) जो सुशासन और तीव्र आर्थिक विकास की हमारी आर्थिक रणनीति के कारण संभव हो पा रहा है और यही कारण है कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 2018 में विपक्षी पार्टी की सरकार थी, उस समय बजट में जितने बर्डन थे, उन बर्डन के अलावा अनेक बर्डन हम पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए आये हैं । उस समय 2526 रूपए में धान की खरीदी होती थी, उसकी जगह में हम 3100 रूपए में धान की खरीदी कर रहे हैं । इनके कार्यकाल में प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी होती थी, उसके स्थान पर हम 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं । इससे हमारे बजट पर लगभग 9 हजार करोड़ रूपए का व्यय भार बढ़ा है । हम महतारी वंदन योजना के नाम से नई योजना लेकर आये हैं । उसमें 8000 करोड़ का अतिरिक्त बजट पर हमारा भार बढ़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछली सरकार के द्वारा आखिरी के दो-तीन सालों में कोई बजट खर्च नहीं किया जा रहा था, उसमें 8500 करोड़ रूपए का बजट भार हम पर बढ़ा है । भूमिहीन कृषक मजदूर साथियों को पहले 7000 रूपए दिया जाता था, हम उसे 10 हजार रूपए दे रहे हैं । उससे हमारा व्यय भार बढ़ा है । हमने दो साल का बोनस इन सवा सालों में दिया है, उससे व्यय भार बढ़ा है । लगभग 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त बजटीय भार बढ़ा है, उसके बाद भी आदरणीय विष्णु देव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमारे सुशासन की सरकार सारे कार्यों को अंजाम दे पा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं समझा कि आप समाप्त कर रहे हैं । समाप्त करने के थोड़ा पहले बताईएगा ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी । अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट का साईज 01 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का था। हमारे विपक्ष के अनेक साथियों ने कहा कि ये खर्च नहीं हुआ, वो खर्च नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन तृतीय अनुपूरक लेकर आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था कि पिछले गड्ढों को पाटने में इस बार हमारा 10-12-13 हजार करोड़ खर्च होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह रखना चाहता हूं कि 01 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का खर्च हम इस बार भी करने जा रहे हैं। मार्च

का जब फिगर आएगा, तो 01 लाख 47 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, ये बेरोजगारी भत्ते की बहुत बातें करते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी स्कीम है, और ये बंद हो गई, बंद हो गई करके सदन में चिल्लाते रहते हैं। आपके माध्यम से मैं सम्माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि किस तरह से बेरोजगारी भत्ता के नाम पर लोगों के साथ धोखा किया गया। मैं उस बेरोजगारी भत्ते के पूरे डेटा आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं, जिसके बारे में ये बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनघोषणा पत्र 2018 में इन्होंने कहा था कि 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करेंगे। सिम्पल मैथेमेटिक्स है कि एक साल में 2500 रुपए के हिसाब से हम 10 लाख युवाओं की गणना करते हैं, तो 2500 करोड़ रुपए होता है और पांच सालों में जो बजटीय प्रावधान होने चाहिए थे, उसकी हम गणना करते हैं अर्थात् 2500X5 करते हैं तो पांच सालों के लिए 12500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होता है। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पांच सालों में कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर साढ़े बारह हजार करोड़ की जगह पर मात्र 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। (शेम-शेम की आवाज) अगर ये ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का जो वायदा किए थे, वह ये देना चाहते तो इनको 12500 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन ये 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किए और चुनाव से ठीक पहले चंद युवाओं को देने का काम किए और इन्होंने टोटल जो बेरोजगारी भत्ता बांटा है, वह चुनाव वर्ष में 01 अप्रैल, 2023 से बांटना चालू किया और अप्रैल से नवंबर तक इन्होंने 249 करोड़ 99 लाख 90 हजार रुपए ही बांटा। इतना ही रुपया बांटा।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, ओमा करोना काल रहिस, याद करा कि करोना काल रहिस। करोना काल के बावजूद भी छत्तीसगढ़ ला कतका सवांरे के काम करे रहेन। अऊ नरेन्द्र मोदी जी ह ता खाली थाली पीटो, घंटी बजाओ। खाली घंटी बजवावत रहय।

श्री ओ. पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ता पर कितना बड़ा धोखा इन्होंने किया और अभी भी सदन में बात रखते रहते हैं, जबकि 12.5 हजार करोड़ की जगह में 249 करोड़ रुपए का पेमेंट किए हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, आप बेरोजगारी भत्ते के ऊपर बोल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार नरेन्द्र मोदी जी की उपलब्धि को आप करीबन-करीबन आधा-पौन घंटा बताए हैं। हर साल 02 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, उसमें भी आप थोड़ा सा बताइए?

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब जी, तू बढ़िया साहेब रहेव, ओति गेव तब ले अइसने रिठागे हो।

श्री ओ. पी. चौधरी :- तोर टिकट नई कटय, बात करबो नेता प्रतिपक्ष ले।

श्री केदार कश्यप :- तोला वैक्सीन लगे हे कि नई लगे हे, बता? नहीं लगे हे त रामविचार जी ने कहा कि लगवाओगे क्या।

श्री रामकुमार यादव :- मोला तकलीफ हे, तूमन मोर कान में पिरात रहेव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट था, उससे फोटो कैसे गायब हो गया?

श्री रामकुमार यादव :- ये बहुत अच्छा आदमी रहिसे जब कलेक्टर रहिसे तब, जब ले तुम्हर मेर गीस तब से रिठागे वो।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामविचार नेताम जी, तब से आपके लिए चिन्तित हैं कि इनको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है और नहीं तो पशु चिकित्सालय वाला इंजेक्शन लगवायेंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उस सर्टिफिकेट में फोटो हुआ करता था, वह फोटो कैसे गायब हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेण मूणत :- नेता जी, रायपुर के कई चौराहों पर एक बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी कि छत्तीसगढ़ के 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया। बढ़िया चमकता हुआ चेहरा रूहानी। उसी समय पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय धरम लाल कौशिक जी ने विधान सभा में प्रश्न उठाया तो सरकार का उत्तर आया कि खाली लगभग 19 हजार लोगों को रोजगार दिया और दूसरे दिन आपने कहा कि नहीं तो उसको कालिक पोत देंगे और वह होर्डिंग उतारनी पड़ी। आप यह काम तो मत करते।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, इसी पवित्र सदन में पिछले बजट सत्र में 34 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात हुई थी और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इसकी प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गयी है लेकिन अभी तक उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे ? आपको 1 घण्टा हो चुका है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं 20 मिनट और लूंगा।

श्री प्रबोध मिंज :- अभी ज्ञान पर भाषण चल रहा है, गति पर नहीं आये हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- जल्दी कर देवव नहीं तो हमर दुर्गति हो जाही बबा।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया गति बढ़ाये (हंसी) और मुद्दे पर रहे, बाकी विषय छोड़िये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत टोकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जी ने धान खरीदी पर बहुत सारी बातें गलत तरीके से रखकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ यह प्रमाणित करना चाहता हूं कि इनके 5 सालों में जो धान खरीदी हुई, वह नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र की सरकार के कारण हो पायी। मैं इस बात को सदन में कुछ आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्रीय पुल का चावल का कोटा था, वह वर्ष 2018-19 में 24 लाख मीट्रिक टन था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2019-20 में चावल का कोटा 28 लाख मीट्रिक टन रहा, वर्ष 2020-21 में चावल का कोटा 24 लाख

मीट्रिक टन रहा, वर्ष 2021-22 में चावल का कोटा 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। 24 लाख से ढाई गुना बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन किया गया। (मेजों की थपथपाहट) इसमें ढाई गुना की वृद्धि की गयी। 61 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात् 93 लाख मीट्रिक टन धान होता है। इन्होंने जो टोटल धान खरीदी की थी, वह 95 लाख मीट्रिक टन की थी। यदि यह धान खरीदी कर पाये तो केंद्र की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के कारण कर पाये और आज इन्हें सदन में नरेन्द्र मोदी जी को, केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इनको मोदी जी का नाम लेने में आपत्ति होती है। यह कहते हैं कि वह हमको धान खरीदी करने नहीं दे रहे थे। अगर नरेन्द्र मोदी जी की केंद्र की सरकार 24 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को ढाई गुना बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन नहीं की होती तो यह धान खरीदी को पूरा नहीं कर पाते।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, रेशियो देखिये ना, उस समय कितनी धान खरीदी होती थी और बाद में कितनी हुई, उस रेशियो को देखिये।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी, हानि की क्षतिपूर्ति कौन करता है ? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है ? और आपकी केंद्र सरकार कितने सालों से उसका निर्धारण नहीं कर पा रही है ? आपकी केंद्र की सरकार वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 से इसका निर्धारण नहीं कर पा रही है। इनके बारे में भी आप चर्चा करिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो हमारा बजट है, वह गति का बजट है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला बजट है, जिसमें हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से 10 नई योजनाएं, 20 नए संस्थान और 30 नए बड़े आर्थिक, प्रशासनिक सुधार introduce किये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है जो सोच पाती है कि वनांचलों में, दूर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टॉवर नहीं होने से डिजिटल डिवाईड पैदा हो सकता है। जब डिजिटल डिवाईड पैदा होता है तो आज के जमाने में एक गरीब आदमी के लिये यह सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस बात को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ अगर हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर योजना लेकर आते हैं, तो यह विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने वाला कदम है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, जो दूरांचल के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वह यातायात सुगम नहीं हो पाते। वहां बसें नहीं चल पाती क्योंकि बस ऑपरेटर के लिये प्रॉफिटेबल नहीं होता है। उसके लिये यदि VGF (Viability Gap Funding) के प्रावधान के तहत अंदरूनी क्षेत्रों में भी बस चलाने की सोच रखते हैं तो यह हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का परिणाम है। इसके लिये हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना लेकर आये हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- यदि आपको इतनी ही चिंता है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिये हमारे उस मंत्री जी को पैसा दे दीजिये। अभी वह 1200 कुछ सड़कों की बराबरी करने में है, उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। वह ग्रामीण विकास कहां से करेंगे ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस तरह की अलग-अलग 10 नई योजनाएं लेकर आयी है। इसमें इस तरह की संवेदनशील परियोजनाएं भी हैं। इसके अलावा एक बड़े विजन के साथ नदियों को जोड़ने की योजना, स्टेट कैपिटल रिजन बनाने की योजना या मेट्रो के सर्वे करने जैसी योजनाएं हमारे इस बजट में शामिल है। 10 नई योजनाओं के साथ 20 नए संस्थान, चाहे वह नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे फिजियोथैरेपी कॉलेज हो, चाहे NIFT हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से 30 बड़े-बड़े कदम इस बजट में समाहित हैं, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में ई-फाईल का जिक्र किया। हमारे सभी मंत्रिगण ई-फाईल के माध्यम से इसमें काम कर रहे हैं। यहां पूरी फाईलों का निपटान ई-फाईल व्यवस्था के तहत डिजिटल तरीके से किया जाना प्रारंभ हो चुका है। अलग-अलग प्रकार के Reforms को हमारी सरकार बहुत तेजी से लागू कर रही है। चाहे मैं अटल मॉनिटरिंग डेसबोर्ड की बात करूं। चाहे पंजीयन में सुगम एप की बात करूं या मैं ब्रैप की बात करूं, चाहे लैण्ड रिकॉर्ड के Digitalization की बात करूं। चाहे ऑटो म्यूटेशन की बात करूं। चाहे एस.एन.ए. स्पर्श की बात करूं। इस तरह के 30 बड़े Reforms को हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं वित्तीय रूप से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार वित्तीय अनुशासन के सारे नार्म्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। जब हम बात करते हैं कि वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जो डेट होता है जो ऋण होता है, उसका जी.एस.डी.पी. के रेश्यों में Calculation होता है कि टोटल जी.डी.पी. कितना है उसके विरूद्ध कितना ऋण है, उसका प्रतिशत। फाईनेंस कमिशन का मानना है, वित्त आयोग का यह मानना है कि वह 25 प्रतिशत के नीचे होना चाहिए। हम अभी 19 प्रतिशत के आसपास हैं। हम 25 प्रतिशत से Well Below रहते हुए, हम वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। मैं तेलंगाना राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा जहां पर यह रेश्यो 25 प्रतिशत पहुंच चुका है, जो कांग्रेस शासित राज्य है। मैं झारखण्ड का जिक्र करूंगा जहां कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, वह 25 प्रतिशत से आगे बढ़कर 28 प्रतिशत पहुंच चुका है। मैं हिमाचल प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा जहां कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है। वह 25 प्रतिशत से बहुत आगे बढ़ते हुए 35 प्रतिशत पर पहुंच गये हैं। मैं पंजाब का जिक्र करना चाहूंगा जहां इनके इंडी के दोस्त लोगों की सरकार है वहां 25 प्रतिशत से बहुत ऊपर 42 प्रतिशत जा चुका है।

श्री दलेश्वर साहू :- आप कमजोरियां ढूढंने में समय मत गवाईये। आप आगे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, एला उहू दिन कहे रहेव, आप के घाव कहिहौ ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आप लोग कैसे संचालित कर रहे हैं देश में जहां-जहां रूल कर रहे हैं। मैं उसको बता रहा हूँ और यहां पर बोलने से कुछ थोड़ी होता है। तेलंगाना को कैसे चला रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दे तो मैं तेलंगाना के ..।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, तेलंगाना में कलेक्टर ऑफिस हा नहीं जलत हे। आप जवव पता कर लेव कोनो जले हो ही ता।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का वीडियो, यदि आप यहां पर बोले तो मैं सदन में उसका वीडियो दिखवा दूं। जिसमें उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया कि यहां कोई पैसा-वैसा नहीं है। मैं 500 करोड़ रूपये भी महीने का कैपिटल Expenditure(पूंजीगत व्यय) कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। राजदीप सरदेसाई को नेशनल टेलिविजन पर इंटरव्यू देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि मैं कोई चीज छुपाना नहीं चाहता। मैं अंदर कुछ बात करूं और भाषण में कुछ बात करूं, मैं यह नहीं करना चाहता। इनके मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया। इस तरह के हालात इनके कांग्रेस शासित राज्यों के हैं। यहां बात करने से कुछ थोड़ी होता है। हम इस तरह के कामों को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रह हैं। हमारा जो पूरा Development है वह Reforms Oriented Development चल रहा है। हमने इस बार पूरा प्रयास किया कि Reforms टैक्सेशन में कैसे लागू हों, चाहे वह जी.एस.टी. हो, चाहे वह पंजीयन हो, हम सब जगह Reform लेकर आ रहे हैं। आज भी हम लोग पंजीयन में एक बड़ा एक्ट उसके संबंध में लाने जा रहे हैं। ई-वे बिल की जो सीमा थी उसको 50 हजार रूपये से बढ़ाकर, 1 लाख रूपये कर दिया गया है। इससे 54 प्रतिशत ई-वे बिल जनरेट होना बंद हो जाएगा। इससे 26 प्रतिशत व्यापारियों को ई-वे बिल भरना नहीं पड़ेगा। इसी तरह 10 साल पुराने जो वैट के केसस थे, इंट्री टैक्स के केसस थे जिसमें 25000/- रूपये तक का जो उनकी देनदारी थी, उसको हमने एक झटके में समाप्त कर दिया। इससे हमारे 40 हजार व्यवसायियों को सीधा लाभ होगा और 62 हजार केस एक साथ समाप्त होंगे। हमने बल्क डीजल में 23 प्रतिशत से घटाकर, 17 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। जो आयात गुजरात और उत्तर प्रदेश से होता था, वह इससे बंद होगा और इसके कारण हमारा राजस्व 227 करोड़ रूपये बढ़ने जा रहा है। हम लोगों ने इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं, इतने सारे कैपेक्स के बीच में पेट्रोल के दाम को एक रूपये कम करने का निर्णय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लिया है। इसके पीछे सुशासन का Confidence है। इसके पीछे Reform का Confidence है। इसके अलावा मैं विशेष रूप से पेंशन फण्ड का जिक्र करना चाहूंगा । हमारे आदरणीय हमारे अमर अग्रवाल जी ने बहुत सारे Reformative प्वाईंट्स पर बहुत विस्तार से चर्चा की। मैं उनके अनुभवों के आधार पर, हमारी सरकार में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे बिन्दु रखें हैं । उन्होंने पिछले दिनों विभागीय चर्चा के दौरान पेंशन फंड का जिक्र किया था। जब हम पेंशन

फंड की बात करते हैं, इनकी सरकार ने N.P.S. की जगह में O.P.S. को reintroduce किया। इसके पीछे कर्मचारियों का हित करने की इनकी कोई मंशा नहीं थी। इनकी मंशा थी कि हर महीने N.P.S. में सरकार के योगदान का जो पैसा देना पड़ता है, वह न देना पड़े। वर्ष 2004 से 2020 तक जो सरकार ने government contribution का 19 हजार करोड़ रुपये जो पैसा किया था, उस पर इनकी गिद्ध दृष्टि थी। यह आज की liability को टालकर भविष्य की liability के रूप में उसे धकेलना चाहते थे, इसलिए इन्होंने N.P.S. की जगह में O.P.S. को पुन: introduce किया। आज भविष्य की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ का वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमने पेंशन फंड का एलान इस बजट में किया है। पेंशन फंड की व्यवस्था करने वाले, उसके लिए एक्ट लाने वाले, उसके लिए इस बजट में 456 करोड़ रुपये का प्रावधान करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य होगा। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, किसी ने नहीं बोला था, किसी R.B.I. की गाईडलाईन में नहीं है, कोई F.R.B.M. के एक्ट में नहीं है, वित्त मंत्रालय की किसी गाईडलाईन में नहीं है कि पेंशन फंड बनाना है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे कैबिनेट की मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है कि हम छत्तीसगढ़ का बेहतर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित करें। हम Growth and Stability fund लेकर आये हैं ताकि छत्तीसगढ़ मे जो माईनिंग की रॉयल्टी से अप, डॉउन होता है, उसको कवर किया सके और दुनिया में Growth opportunities को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम Growth and Stability fund भी लेकर आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो Consolidated Sinking Fund होता है, उसमें कुल जो ऋण रहता है, उसका 5 प्रतिशत जमा करना होता है, उसमें हम लगभग साढ़े 7 प्रतिशत जमा किये हैं और देश के बेस्ट 3 राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज की तारीख में शुमार है। इनके कांग्रेस शासित राज्यों की हालत देखेंगे तो वहां पर भी बहुत खराब स्थिति आपको दिखाई देगी। इस तरह के हम वित्तीय अनुशासन के भी विषय लगातार रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की भविष्य में दिक्कतें न हों। इन सारे बिन्दुओं को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं कि वह बहुत बार बोले कि भारतमाला प्रोजेक्ट की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। मैं देख रहा था, कल सोशल मीडिया में आ रहा था, इनके प्रभारी जी बैठक लेने आये थे, इन्होंने तय किया है कि सेन्ट्रल एजेसिंयो के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करेंगे। यह कैसी दोहरी राजनीति है, इसका जवाब जरूर नेता प्रतिपक्ष जी दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर सेन्ट्रल एजेंसियों में भरोसा है या नहीं है ? वह सदन में आ करके सी.बी.आई. जांच की मांग करते हैं और पार्टी कार्यालय में जाकर सी.बी.आई. के खिलाफ धरना, प्रदर्शन करने की बात करते हैं। यह दोहरी राजनीति नहीं चल सकती।

श्री राजेश मूणत :- जैसे आपसे उस दिन अरूण साव जी से पूछा था कि हां या ना। आज आप इस पर कह दें हां या ना।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उमेश पटेल जी, आज चर्चा में बात कर रहे थे कि खरसिया का कोई रेलवे ओवरब्रिज पास नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं वर्ष 1990 से 35 साल तक उनका परिवार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह स्वयं पिछले 11 सालों से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले 05 साल की सरकार में वह स्वयं कैबिनेट मंत्री रहे और 05 साल तक कैबिनेट मंत्री रहने के बाद वह हमारी सत्ता पार्टी को सवा साल में सवाल पूछते हैं कि यह कैसे स्वीकृति नहीं हो पा रही है? इसका जवाब उनको सदन को, जनता को देना चाहिए। पिछले 05 साल के आखिरी 5वें साल में इन्होंने हजारों करोड़ के ए.एस. बजटीय प्रावधान कर दिये। हजारों करोड़ रुपये के ए.एस ऐसे ही दे दिये। उसको लोगों को दिखाने के लिए टेंडर कर दिये। अभी कागज लेकर घूमते रहते हैं। सत्ता तो चली गई, जनता ने नकार दिया, अब उसको लेकर घूमते रहते हैं, बजट में आ गया था, बजट में आ गया था, टेंडर हो गया था। ऐसा वाला टेंडर चाहिए, ऐसी वाली स्वीकृति चाहिए तो हम भी 5वें साल में इनको 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपये का दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जनता को गुमराह करना है, अगर दिखाने के लिए ए.एस. दिया जाता है, दिखाने के लिए टेंडर किया जाता है तो 5 साल तक आखिर इन्होंने क्यों नहीं किया ? इस बात का जवाब इनको जनता को देना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सदस्यों ने बहुत चूंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमारे उप मुख्यमंत्री जी पिछले सवा साल से नींद नहीं आती, हमारी रोज बात होती है । बिना बजट के, बिना पैसा के इन्होंने सैकड़ों करोड़ का, हजार करोड़ से ऊपर का टेंडर कर दिया, Security Deposit का, S.D. का पेमेंट कर दिया। ठेकेदार का जो S.D. जमा था उसका पेमेंट कर दिया । अगर हम चर्चा करें जो आदरणीय अमर अग्रवाल जी बहुत सिद्दत के साथ उठा रहे थे कि कहां-कहां लॉयबिलिटी कितनी पेंडिंग है । वह बोल रहे थे कि अगर विभिन्न विभागों को मिला लें तो 4-5 हजार करोड़ का हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे । मैंने पिछली बार भी बताया था और मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि जो अलग-अलग देयता हैं, आप जो बजट लोन छोड़कर गए थे, जो लोन का रिकॉर्ड होता है जिसमें उसकी गणना नहीं होती है उसके अंतर्गत मैंने जो गणना की थी तो 34,970 करोड़ रुपए की गणना आई है । ऐसा ही हर जगह है, चाहे वह चना का पेमेंट हो, चना, नमक, गुड़ के पेमेंट की बहुत बात कर रहे थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि तृतीय अनुपूरक में, तीसरे सप्लीमेंट्री में हमने इनके समय का भी चना का, गुड़ का सबका भुगतान अभी सुनिश्चित किया है ताकि आगे आने वाले समय में दिक्कत न आए । माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ अस्पतालों का पेमेंट हो, चाहे पी.डी.एस. डीलर मार्जिन का पेमेंट हो, चाहे मार्कफेड का पेमेंट हो, चाहे Energy department के पेमेंट हों, चाहे नान के पेमेंट हों, सभी 34,970 करोड़ रुपए की देयता,

आप बजट लोन के रूप में छोड़कर गए हैं और यहां पर किस नैतिकता के साथ सवाल करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार रिफॉर्म्स (reforms) के साथ काम करेगी, हितग्राहियों के लिए समर्पित होकर काम करेगी और हमारे कई सदस्यों ने कुछ विषय रखे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आदरणीय धर्मजीत जी ने हवाई जहाज बिलासपुर के बारे में कहा है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बिलासपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे उपमुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अमर अग्रवाल जी का, धर्मजीत जी का, सुशांत जी का चूंकि वह सबका क्षेत्र है वहां पर जो भी जरूरत होगी उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह समर्पित है लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि वह वॉयबिलिटी (viability) नहीं बैठ पाता । वहां पर number of Passenger बढ़ाइए, मैं धर्मजीत जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब नंबर बढ़ेगा तो अपने आप हम चीजों को आगे बढ़ा पायेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जो 50 सीट से कम और हंड्रेड परसेंट नहीं होने से...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टेक्निकल बात है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी वॉयबिलिटी (viability) की बात बता देता हूं । एक मिनट ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस सीट भर के कारण कितना करोड़ रूपये हर्जाना दे रहे हैं इस पर भी चर्चा कर लो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वहां हमारे जो एयर स्ट्रिप है । आप उसमें बोईंग विमान नहीं ला सकते, हम लोग दिल्ली जाने के लिये यहां आते हैं और यहां से हम लोग जाते हैं, यदि पैसेंजर का देखेंगे तो हमारा एयर स्ट्रिप मतलब आज जो 40 परसेंट पैसेंजर हैं वह बिलासपुर से हैं, 60 परसेंट रायपुर संभाग का पूरा बस्तर से है तो 40 परसेंट हमारा बिलासपुर संभाग से है और केवल वहां पर जब तक आप एयर स्ट्रिप को नहीं बढ़ायेंगे तब तक वह दिक्कत आयेगी इसीलिये हम लोग बोल रहे हैं कि सेना के पास वह जमीन है ।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, कोरातरई वाला ला ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, सेना से जमीन लेने के बाद जब हम रनवे को बढ़ायेंगे और रनवे बढ़ाकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वॉयबिलिटी (viability) भी मिलेगी और वहां के लोगों को हमारे दिल्ली से लेकर कलकत्ता और मुंबई से लेकर के यात्रा में सुविधा भी मिलेगी, पैसेंजर की संख्या भी बढ़ेगी लेकिन जब तक हमारा रनवे न बढ़े तब तक

जो फोर-सी की बात आई और उसके साथ में यह जो नाईट लैंडिंग के हैं वह भी लगभग-लगभग प्रक्रिया पूर्ण हो गई है । हम कभी भी नाईट लैंडिंग शुरू कर सकते हैं उस स्थिति में आ गए हैं । लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो उस स्थिति में हैं । मैं समझता हूं कि उसमें यदि थोड़ी बहुत बजट की आवश्यकता है । आप बजट बढ़ाएंगे तो यहां का pressure भी कम होगा और बिलासपुर संभाग में आप भी हैं, उसमें अंबिकापुर के लोग भी हैं । सारे लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी इसलिए आप राशि की घोषणा भी करें और आप उसकी राशि बढ़ाएं ताकि लोगों को हवाई सुविधा मिल सके।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, वहां पर मामला थ्री सी और फोर सी में अटका है। वर्तमान में थ्री सी एयरपोर्ट की क्षमता है, छोटी-छोटी फ्लाइट्स चल रही हैं। हमारे यहां बिलासपुर से इलाहाबाद का फ्लाइट खुल जाती है । लेकिन कोई बड़े शहर की फ्लाइट अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो उसमें लोग जरूर जाएंगे। सेना को जमीन हमारी ही सरकार ने आपके समय में दिया था। वहां पर 1200 एकड़ का उनका कुछ कैंप बनना था, उसमें वे 250 एकड़ देने के लिए तैयार भी हो गये हैं और सरकार की तरफ से पैसा भी उसके लिए जमा कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा उसको हाई लेवल ऑफिसर्स की बैठक लेकर देखें कि वह मामला कैसे सुलझ सकता है? अगर वह 250 एकड़ जमीन मिलेगा तो एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बढ़ेगी और तभी उसमें बोइंग उतर सकेगा। कोशिश अभी करेंगे तभी तो आगे होगा न। कृपा कर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब जी..।

श्री अमर अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जमीन वापसी का लेटर आ गया था। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा पैसा भी जमा हो गया, लेकिन पुराने रेट और नए रेट को लेकर राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय में कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। अगर इसका समाधान हो जाए, वह बजटेड है। रेट का समाधान हो जाए तो बाकी सारी चीजें अपने आप आगे बढ़ जाएंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है माननीय वित्त मंत्री जी..।

श्री रामविचार नेताम :- अब आपको क्या चाहिए?

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनते जाइए न।

श्री अमर अग्रवाल :- इनको कुरूद में हवाई पट्टी बनवानी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मुझको तो मुंगेली में हवाई पट्टी बनवानी है।

क्या होता है, आप सस्ते में छूट रहे हैं। विनियोग की अब तक एक परंपरा रही है। हम जितने भी गैर ट्रेजरी बेंच के सदस्य होते थे, अपने-अपने विषय में बात करते थे और उसकी घोषणाएं होती थीं। जो

सरकार की ओर से संभव हो, वे घोषणाएं होती थीं, आपको मालूम है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। आपने एक भी घोषणा किसी सदस्य की मांग पर नहीं की तो ये परंपरा टूट जाएगी। जो विनियोग की परंपरा है, वह टूट जाएगी। मैं आपको एक-दो चीज बता देता हूं ताकि परंपरा मत टूटे। एक तो मैंने आपको एक कागज दिया है, जिसको सुधारने की घोषणा कर दीजिए। दूसरा काइंड्स की घोषणा मत कीजिए, हमारी कुछ दो-तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, मेन बजट में किन्हीं कारणों से आपने छोड़ दी, जिसको मैंने आपको अवगत कराया तो इतना ही बोल दीजिए कि उसको अनुपूरक प्रथम में हम ला देंगे। वह दो-तीन चीजें आपको मालूम है। तो विनियोग की परंपरा कायम रहेगी, वित्त मंत्री का भाषण हो रहा है, ये लगेगा, हम सबको महसूस होगा तो कृपा कर दोनों विषय में आप कुछ बोल दीजिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग में..।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 झन बोल रहे हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्यों नहीं बोलेंगे। आपको हमारी बात में हर समय क्या आपत्ति रहती है? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- गुस्सा मत भई।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- तो एयरपोर्ट की जो व्यवस्था है, माननीय अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री ने कहा है कि उसमें केंद्र सरकार की राशि रिवाइज करने की विसंगति है। रिवाइज हो जाएगा और कम से कम इतने लोग जब हम बोल रहे हैं, आप भी वहीं के संभाग से हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक और जैसा मेरे से ज्यादा जलते हैं कौन? अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं मुंगेली में ही एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, आप बैठिए। आप भी बैठिए।

श्री पुन्नूलाल महोदय :- माननीय..।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। बहुत चर्चा हो गई।

श्री पुन्नूलाल महोदय :- मैंने मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बोला था।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा बैठिए, माननीय मंत्री जी, फिर से पूछ रहा हूं कि आप कितना समय लेंगे? 5 विधेयकों पर चर्चा बाकी है और मुझे आज ही पूरा करना है। इसलिए कृपया जितनी जल्दी हो सके, समाप्त करें।

श्री ओ.पी. चौधरी :-माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े 6 घंटा सुनाये हैं तो एक डेढ़ घंटा सुनाना बनता है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मेरा लगभग खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- खत्म करिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आदरणीय राजेश मूणत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी थी..।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सब महत्वपूर्ण है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- नवा रायपुर अटल नगर की बात रखी थी, उसमें अटल अटल जी की प्रतिमा की बात रखी थी। इस बजट में अटल स्मारक और अटल जी की प्रतिमा के लिए ऑलरेडी प्रावधान है। उसमें राशि बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ा लेंगे। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने हॉस्पिटल संबंधी बात रखी है और एयरपोर्ट संबंधी बात रखी है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम बिन्दुओं को रखेंगे और जरूरत अनुसार प्रथम अनुपूरक में या सी.एफ. एडवांस के माध्यम से करेंगे।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, हमारे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेट्रो को बिलासपुर तक करा दीजिए न।

श्री ओ.पी.चौधरी :- आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष विषयों को रखेंगे और जो उचित रहेगा उसको अनुपूरक या सी.एफ. के माध्यम से करेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- मंत्री जी हमारे राजनांदगांव के डॉ. रमन सिंह के मेडिकल कॉलेज में सी.टी. स्केन मशीन नहीं है, उसके लिए व्यवस्था करा दीजिए ताकि वहां के मरीजों को सुविधा हो जाए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- लगना चालू हो गया है दलेश्वर जी ।

श्री प्रबोध मिंज :- दलेश्वर जी, आप तो विरोध में बात कर रहे थे, अभी मांग कर रहे हैं ।

श्री दलेश्वर साहू :- जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो हमारे अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के इंस्ट्रूमेंट को तो चालू करवा दो । बड़ी बड़ी बात करने से क्या होगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- फिटिंग चालू है भाई, पांच साल में आप लोग नहीं खरीद पाए ।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं छोटी सी सीटी स्केन मशीन की बात कर रहा हूं । साल भर से बंद पड़ी हुई है, कम से कम उनके लिए तो व्यवस्था करा दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं 25 तारीख को जा रहा हूं, आइए आपको दिखाउंगा ।

श्री दलेश्वर साहू :- साल भर से बंद पड़ी हुई है, कम से कम उनके लिए तो व्यवस्था करा दीजिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो भी विषय हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और आवश्यकतानुसार अनुपूरक बजट में लाएंगे । केवल चार पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा -

जहां दाई कौशल्या के शक्ति हे अउ मा करमा के भक्ति हे,

बबा घासी के तप हे, संत वल्लभ के जप हे,

जहां वीर नारायण के बलिदानी के कहानी हे,

महाराज भंजदेव के सच्चाई के बानी हे,

महाराज चक्रधर के साज हे,

खैरागढ़ वाली रानी इंद्रा के आवाज हे,

पंडित सुंदरलाल के मया हे, ददा खूबचंद के दया हे,

अइसे हमर छत्तीसगढ़ महान ला, जय जोहार अउ नमन करत हौं ।

और कांग्रेस को इन पंक्तियों से समस्या होती है तो हो, हम तो सुनाएंगे क्योंकि कविता से हमको ताकत मिलती है, हमारे पूर्वजों से हमको ताकत मिलती है । ये असत्य छत्तीसगढ़ियावाद के ढोंग करने वालों को परेशानी हो तो हो । जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ (मेजो की थपथपाहट) ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय वित्त मंत्री जी ने मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछा है तो मेरा जवाब देने का तो बनता ही है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी सीधा सीधा दे दीजिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय वित्त मंत्री जी, आपने मुझसे कहा है कि सीबीआई पर इनको भरोसा कैसे हो गया ? ये बार-बार भारत माला के प्रकरण को सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं । मैं आज भी चाहता हूं, कल भी चाहता हूं और परसों भी चाहूंगा । आप लोग सीबीआई जांच नहीं करेंगे तो मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के पास जाऊंगा । आपके हमारे मंत्री हैं गडकरी जी, उनके पास जाऊंगा । उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसी बात से डर रही है और सीबीआई जांच नहीं करा रही । मैंने कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा । पिछले लोग, पिछली सरकार ने सीबीआई की जांच यहां नहीं कराई तो आप लोग तो कलेक्ट कर रहे हैं ना कि कौन कौन सी जांच सीबीआई के लायक है । मैं एक जांच आपको दे रहा हूं, यह जांच सीबीआई के लायक है करा लो । इसमें आपको क्या आपत्ति है ? मूणत जी, क्या आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है क्योंकि आपका केस ही चार-पांच साल से चल रहा है ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- तो फिर विरोध मत करिये न सर, जुलूस क्यों निकलवाना चाह रहे हैं, कल तो आपने निर्णय लिया है ।

डॉ. चरणदास महंत :- जब आपको भरोसा है, और मैं भरोसा करने लग गया हूं तो आपको क्या तकलीफ है ?

श्री राजेश मूणत :- नेता जी, मुझे तो ई.डी. पर भी पूरा भरोसा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- जो भी केन्द्रीय जांच करने वाले यहां हैं, हमको सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि व्यक्तिगत् राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर जांच न करें । हम उसका विरोध करेंगे, उसके लिए हड़ताल करेंगे, उसके लिए प्रदर्शन करेंगे । ठीक है, चौधरी साहब कोई आपत्ति हो तो बता दीजिए । सर, अब मैं एकाध मिनट बात कर लूं । इन्होंने जो विनियोग

प्रस्तुत करते समय लच्छेदार भाषण दिया है । पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं क्योंकि आपकी 15 साल की सरकार थी और उस समय राज्य पर 41 हजार करोड़ का ऋण भार था, अगर यह सही है तो ठीक है अन्यथा क्षमा करते हुए सही आंकड़ा बता दो । जब पांच साल के लिए हमारी सरकार आई तो हमने 41 के बजाय 43 हजार करोड़ लिया, ठीक है ।

डॉ. चरणदास महंत :- हम कहां बोल रहे हैं। हमारी सरकार आई तो हमने 5 साल में 43 हजार करोड़ रूपए का ऋण लिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें आप 41 हजार करोड़ बता रहे हैं, उसमें 8 हजार करोड़ रूपए आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल का है। डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल का नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- महराज, इतना विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बुराई करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अमर अग्रवाल :- 43 हजार करोड़ में मध्यप्रदेश से जो बंटवारा हुआ, उसमें 7 हजार करोड़ शामिल है।

डॉ. चरणदास महंत :- मध्यप्रदेश का शामिल है, जोगी जी का शामिल है, सबका शामिल है।

श्री अमर अग्रवाल :- सबका शामिल है। सबका मिलाकर 18 साल में 43 हजार करोड़ है।

डॉ. चरणदास महंत :- भाई मैं तो बोल रहा हूं जब इनकी सरकार ने छोड़ा तब छत्तीसगढ़ पर 41 हजार करोड़ का ऋण था। ठीक है।

श्री अमर अग्रवाल :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, इतना ही तो बोल रहा हूं। 5 साल में हमने 43 हजार करोड़ रूपए और लिया। अब मेरी गणित सही है तो वर्ष 2023 में ये ऋण 84 हजार करोड़ हो गया, ठीक है। 43 हजार करोड़ और 41 हजार करोड़ मिला के 84 हजार करोड़ होगे न ग सीनियर आदमी। विष्णुदेव जी की सरकार ने एक साल में 34 हजार करोड़ ऋण लिया, ये गलत है ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- गलत है।

डॉ. चरणदास महंत :- कितना लिया ?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय।

डॉ. चरणदास महंत :- सिर्फ संख्या बताईए न।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. लोन को और एच.सी.ए. लोन को माईनस करके हमारा लोन लगभग 1 लाख करोड़ पहुंचा है। जो वित्त आयोग के FRBM के RBI नार्म्स में नहीं माने जाते, ये उनको जोड़ करके बात करते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- हमने बता दिया हमें गणित नहीं आती, आप वित्त मंत्री हो, आप जोड़िए न।

श्री ओ.पी.चौधरी :- जी.एस.टी. लोन और एच.सी.ए. लोन को छोड़कर हमारा लोन लगभग 1 लाख करोड़ तक पहुंचा है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए ठीक है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, उसमें हमने किसानों के खातों में पिछले सीजन में 13320 करोड़ रूपए, इस सीजन में 12 हजार करोड़ रूपए, महतारी वंदन में 8 हजार करोड़ रूपए, पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना का 6500 करोड़ रूपए, हम इस साल उसमें 8500 करोड़ रूपए देने जा रहे हैं, दो साल का बोनस 3716 करोड़ रूपए, जितने लोन लिए हैं उससे कई गुना ज्यादा हमने छत्तीसगढ़ की जनता के वेलफेयर में कल्याण किया है। (मेजों की थपथपाहट) उसके बाद GSDP के जो नार्म्स हैं, FRBM के जो नार्म्स हैं, हम उसका अक्षरश: पालन कर रहे हैं। हम पेंशन फंड भी बना रहे हैं। ग्रोथ इन-स्टेबिलिटी फंड भी बना रहे हैं, कंसोलिटेटेड सिंकिंग फंड भी बना रहे हैं, हम एक रूपये पेट्रोल में भी माफ कर रहे हैं, वैट के पुराने टैक्सेस को भी खत्म कर रहे हैं, बल्क डीजल को 23 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत में ला रहे हैं, वेलफेयर स्कीम भी कर रहे हैं, इस बार कैपेक्स का 26 हजार करोड़ का प्रावधान किए हैं, पिछले साल कैपेक्स कम हो जाएगा करके बात कर रहे थे, जब मार्च का डेटा आएगा, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, कैपेक्स में पिछले वित्तीय वर्ष में पहले छमाही में पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, उसके कारण हमको भारत सरकार से 1051 करोड़ रूपए इंसेंटिव मिला है, इस वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वृद्धि कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में फिर 10 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर की वृद्धि करेंगे। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रहे हैं, पूंजीगत व्यय भी बढ़ा रहे हैं, वेलफेयर के कामों को भी कर रहे हैं। हम मोदी जी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, इस समग्र चीजों को करते हुए जितना लोन ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हम छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए खर्च कर रहे हैं। इसमें किसी को आपत्ति हो तो होए, जनादेश हमारे पक्ष में है।

डॉ. चरणदास महंत :- वेरी गुड। मैंने 41 हजार करोड़ और 43 हजार करोड़ जोड़कर 84 हजार करोड़ बताया था, अब उसमें विष्णुदेव जी की सरकार ने जितना लोन लिया है या मान लो है, उसको जोड़ करके बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए...।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए विनियोग की चर्चा पूरी हो चुकी है। जवाब पूरा आ चुका है और जवाब आने के बाद यदि किसी को कोई विषय एक लाईन में बोलना है तो बोलिए।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही लाईन में बोल देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अब डिबेट संभव नहीं है। विनियोग की पूरी चर्चा के बाद कभी डिबेट नहीं होती।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अब इसके उपर न सवाल होगा न जवाब होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है। मैंने प्रतिक्रिया दे दी कि मुझे सी.बी.आई. की जांच चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बस ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी प्रतिक्रिया विनियोग पर दे रहा हूं। आज छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति कितना लोन है, ये अगर बता सकें तो बता देना। प्रदेश में कितना भार है बता देना। मैंने सुना है कि आप फिर से 28 हजार करोड़ रूपए का लोन लेने वाले हो। अगर यह सही है तो बता देना ? आज आपके माननीय मोदी जी के देश में रहने वाले हर इंसान पर कितना ऋण का भार है, आप वह बता देना?

अध्यक्ष महोदय :- ये सारी बातें आपकी चर्चा में क्यों नहीं आईं? चलिये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वसम्मत के विषय रहते हैं। इसको तो आप हां या नहीं में पारित करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- यदि मंत्री जी इसमें कुछ बोलना चाहे तो बोल दें।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सर्वसम्मत के विषय रहते हैं, इसलिए इसमें क्या बोलना। रामकुमार जी को इसमें कुछ बोलना हो तो वह बोल दे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972, क्रमांक-7, सन् 1973 को संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को अधिनियम में शामिल किये जाने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 सितम्बर, 2020 में प्रकाशन उपरांत कुटुम्ब पेंशन की वर्तमान राशि 25,000 रूपये प्रतिमाह है। अत: मेरा इसमें आग्रह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक, 2025 में अनुसूची के सरल क्रमांक-8 (क) की धारा-(छ) के (ख) में कुटुम्ब पेंशन की राशि 25,000 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर राशि रूपये 40,000 रूपये प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया जाये। अत: मेरा पूरे सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, क्या उनके परिवार को मिलेगा? मैं आपसे सिर्फ जानकारी लेना चाहता हूं। आप यह स्पष्ट कर दें कि यदि उनके परिवार में कोई शासकीय सेवक है, जैसा कि आप लोगों का नियम है कि उसके परिवार में यदि कोई शासकीय सेवक है तो उनकी अनुकम्पा

नियुक्ति नहीं हो सकती है तो क्या विधायक के घर में यदि कोई और शासकीय सेवक है तो उसकी पत्नी को या पति को आपके यह 40,000 रूपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरी भी एक शंका है। आप बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। पहले जवाब तो आ जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- ते का भइसी-भइसा के नाम लिख के जाबे, तेन ला मिलही ? हर में खड़े होथस। ते भइसी-भइसा के नाम लिख के जाबे का ? (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि वह पूछ नहीं पा रहे हैं तो मैं पूछ देता हूं कि यदि वह व्यक्ति अविवाहित मर जाता है तो उसका पेंशन किसको मिलेगा ?

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, एकदम सही बात है। मान लो कि अगर कोई बिहाव नइ करे हे, ओखर पत्नि नइ हे, ओखर परिवार नइ हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार, एक मिनट, मेरी बात सुन लो, फिर बोलना। मान लो अभी दुर्भाग्य से कुछ हो गया तो किसको मिलेगा, इतनी बात है न ?

श्री राम कुमार यादव :- ओही बात हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- शादी कर लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।

श्री राम कुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय जी, मान लो कोई शादी नइ करे हे। मान लो ओखर कोई परवरिश करत हे, कोई देखभाल करत हे, ओला गोदनामा ले हे, तो ओहू ला स्पष्ट कर देहा।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- अगर तोर कोई प्रेमी हो नाम लिखवा दे, ओला मिल जाही (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वह तो आपके में आयेगा। कौन नामिनी रहेगा, यहीं तय हो जाये।

श्री राम कुमार यादव :- लड़ाई झगड़ा हो जाही, 5 ठन हे त 5 झन हो जाही, लड़ाई झगड़ा हो जाही।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा है, उसके तहत ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव जी, पुन्नू लाल की बात मत करो, दो के बाद तीसरे के लिए भी तैयार हैं। समझे ? तुम एक के लिए तैयार नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(5) छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025)

उप मुख्य मंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

श्री धरम लाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा संशोधन है, उस संशोधन के साथ स्वीकार करना है। इसमें लोक परिसर में किसी के द्वारा कब्जा किया गया या अनराधिकृत रूप से लाभ कमाने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए सक्षम अधिकारी एवं अपील अधिकारी इसके लिए, इसमें पहले यह था कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है और उसका प्रकाशन किया जाता है। प्रकाशन करने के बाद यदि वह अधिकारी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद फिर से राजपत्र प्रकाशित करना पड़ता है। उसमें कठिनाईयां आती

है उसको देखते हुए इसमें एक छोटा सा संशोधन है। धारा 3 में और धारा 9 में संशोधन किया गया है। संशोधन का मूल उद्देश्य केवल इतना है कि मूल अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा प्रतिस्थापित की जाए :- " राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा या संभागीय आयुक्त (राजस्व) सामान्य आदेश द्वारा कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। " कुल मिलाकर धारा 3 में भी यही सक्षम अधिकारी और अपीलीय अधिकारी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बार-बार नोटिफिकेशन होता है, उसके कारण प्रक्रिया में विलम्ब होता है। यह संभव ही नहीं हो पाता क्योंकि कोई नियुक्त होता है तो बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इसमें सामान्य अधिसूचना के बजाय संभागीय आयुक्त के सामान्य आदेश, इतना ही महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, इसलिए इसको संशोधित करते हुए स्वीकार किया जाये। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको संशोधन के साथ में स्वीकार करना चाहिए।

समय :
8:50 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

पूर्व से जारी (श्री धरमलाल कौशिक) :- इसलिए इसमें सामान्य अधिसूचना के बजाय संभागीय आयुक्त के श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय सभापति महोदय, जहां तक छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 अधिनियम में संशोधन करने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह पास हो या न हो, लेकिन मैं अपनी बात तो रख सकता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, तैं हर बिना नाम पुकारे रखत हस।

श्री दलेश्वर साहू :- ऐसा क्या। क्या मैं नहीं बोल सकता?

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलिये-बोलिये।

सभापति महोदय :- आप दो मिनट में बोलिये।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से गलत आर्डर हो सकता है, अपील की संख्या बढ़ेगी। मूल संहिता में कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी के रूप में थे, लेकिन अब संशोधन के बाद कलेक्टर की जगह जो सक्षम प्राधिकारी होंगे। साहब, यदि गलत आदमी की नियुक्ति हो जाये, उसके कारण हो सकता है कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने का संभावना बढ़ जाये। फिर मान लीजिये कि जहां वह निर्णय नहीं लेता है तो अपील में फिर उसी के पास जाएगा, लेकिन अपील कलेक्टर के पास ही करना होगा। इसलिए मूल संहिता से कलेक्टर को हटाकर इस संशोधन से अपीलीय अधिकारी बनाया जा रहा है, इससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इससे हो सकता है कि यदि हम अपने मन-पसंद आदमी को वहां पर पदस्थापना कर दें और हम जो एक उद्देश्य के लिए इसमें संशोधन करा रहे हैं, कहीं वह गलत

दिशा में न चले जाये, यह मेरा मानना है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साहब, यदि आप किसी चीज को सरलीकरण करेंगे तो आप उसकी प्रतिक्रिया को भी तो देखेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसके उद्देश्य और कारण को समझ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं वही कह रहा हूं। ठीक है। मैं आपके उद्देश्य को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप इसका साईड इफेक्ट को तो देखेंगे। यदि आप किसी को सरलता से बैठा दिये और उसको राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ता है। इसलिए यदि किसी यदि साधारण आदमी को बैठायेंगे तो निश्चित रूप से इससे साईड इफेक्ट पड़ने की संभावना रहेगी। यह मेरी अपनी बात है, बाकी जैसे भी हो।

सभापति महोदय :- ठीक है। माननीय मंत्री जी।

समय :
8:52 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की इस चिंता के संदर्भ में मैं उनको थोड़ा स्पष्टीकरण जरूर देना चाहता हूं, वह यह है कि लोक परिसर (बेदखली) के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, उसके लिए बार-बार गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती थी। वह जो होते थे, वह डिप्टी कलेक्टर या उससे अनिम्न श्रेणी के लोग होते थे, जो बेदखली के लिए प्राधिकृत होते थे। तो जो डिप्टी कलेक्टर या उससे अनिम्न श्रेणी के लोग होते थे, उनके स्थानांतरण आदि के कारण बार-बार गजट नोटिफिकेशन करने की दिक्कत आती थी, कोर्ट में चैलेंज भी आ जाता था। पहला विषय, प्राधिकृत अधिकारियों के लिए यह निर्धारित किया जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन के साथ-साथ जो अपीलीय अधिकारी हैं, उनका भी जो प्रशासनिक आदेश है वह मान्य होगा। दूसरा विषय, अपीलीय अधिकारी वह होंगे जो धारा-9 के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय अधिकारी कौन होंगे? अपीलीय अधिकारी के लिए भी यही प्रावधान था, इसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन होता था, उसको भी न करके, जो कलेक्टर या उससे अनिम्न स्तर के लोग होंगे, गजट नोटिफिकेशन के साथ-साथ प्रशासनिक आदेश से भी यह संभव हो पाएगा। न कलेक्टर के नीचे से कुछ हो रहा है, न डिप्टी कलेक्टर के नीचे से कुछ हो रहा है। अपीलीय अधिकारी अब भी कलेक्टर हैं और बेदखली के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी डिप्टी कलेक्टर या उससे अनिम्न श्रेणी के लोग हैं। सिर्फ प्रक्रिया बदल रही है और वह भी पुरानी प्रक्रिया यथावत् है। एक और प्रक्रिया जोड़ी जा रही है कि उसमें प्रशासनिक आदेश के माध्यम से किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -छत्तीसगढ़ लोक परिसन (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ लोक परिसन (बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 6 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025(क्रमांक 7 सन् 2025)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- भारसाधक सदस्य को इस विषय पर कुछ बोलना है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसको भी सर्वसम्मति से पारित करवा दीजिए । सदस्य वेतन भत्ता है ।

श्री दलेश्वर साहू :- इसको थोड़ा सा टेक्नीकल भाषा को सरल करते हुये कर देंगे तो समझ में आ जायेगा, उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं । इनको सरलता से परिभाषित कर दें ।

श्री केदार कश्यप :- ते जगन्नाथ जाबे, भुवनेश्वर जाबे । भुवनेश्वर से जगन्नाथ कामा जाबे ? उही ला जोड़ही ।

एक माननीय सदस्य :- ठीक है ना रे भई, बता मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :-सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाये गये, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन 1973) को और संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 के अधिनियम में शामिल किये जाने हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के लिये रेल, हवाई यात्रा के ऊपरांत गंतव्य स्थान तक जाने के लिये सड़क मार्ग से यात्रा कर बोर्डिंग करते हैं, उसमें सड़क मार्ग से की गई यात्रा को भी बोर्डिंग के साथ राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है । वर्तमान में रेल एवं वायु यात्रा उपरांत गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा का प्रावधान नहीं था, उसका इसमें प्रावधान किया गया है । अब इसमें रेल, वायु यात्रा और बोर्डिंग सहित के स्थान पर रेल एवं वायु यात्रा बोर्डिंग सहित रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट से गंतव्य स्थान तक सड़क मार्ग से की गई यात्रा प्रतिस्थापित करने का इसमें प्रस्ताव है । सदन से आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो सब के लिये सुविधा है ना ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि-छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान सभासदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 7 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

समय :-

9:00 बजे

(7) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । अमर जी ।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक लाया है क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन स्टाम्प का जो बिल है, इसमें जो बैंक गारंटी है, वह बहुत पुराना है । अब समय के साथ बढ़ते हुए शहरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण में आवश्यक हो जाता है क्योंकि बैंक गारंटी भी रजिस्टर्ड होती है तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रभार शुल्क है, उसके लिए तो बहुत स्पष्ट प्रावधान था, जिसके कारण परेशानियां हो रही थीं । उसके अनुच्छेद 1 में अब ये प्रावधान करके बैंक गारंटी का प्रावधान ला रहे हैं, उससे काफी सुविधा मिलेगी और इसमें स्पष्ट प्रावधान हो जाएंगे तो बैंक गारंटी जो देते हैं, वे रजिस्टर्ड की श्रेणी में आ जाएंगे । इससे सबको लाभ होगा इसलिए यह संशोधन है और बहुत छोटा संशोधन है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री ओ. पी. चौधरी :- संक्षिप्त में बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय । 1908 में एक्ट बना था और इसमें टोटल 93 सेक्शन्श हैं, उस समय जब 1908 में एक्ट बना था, उस समय कोई डिजीटल टेक्नालॉजी, कोई ऑनलाईन प्रक्रिया यह सब नहीं था तो अब इन सारी प्रक्रियाओं को हम ऐप के माध्यम से डिजीटल ट्रांजेक्शन इंश्योर करने के लिए, आधार फीडिंग करने के लिए, व्यवस्थाओं को बदल रहे हैं, ट्रांसपरेंसी ला रहे हैं तो 32 अलग-अलग जगहों में संशोधन की जरूरत पड़ रही है । इससे प्रक्रिया

ट्रांसपरेंट होगी, जमीन की इंलीगल खरीद-बिक्री रूकेगी और ये सारी चीजें होंगी तो इस दृष्टिकोण से हमको अनेक जगहों पर, इंलीगल कालोनी को कंट्रोल करने की दृष्टि से कई जगह अक्षांश, देशांतर को लेने की दृष्टि से हमको कुछ संशोधनों की जरूरत पड़ रही है । 1908 के समय किस तरह की मानसिकता थी, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा । जैसे दत्तक विलेख होता है, किसी को बच्चा एडाप्ट करना है, दत्तक लेना हो तो उसमें केवल पुत्र लिखा हुआ है । उस जमाने में लोग शायद सोचते नहीं थे कि पुत्री को भी गोद लिया जा सकता है । उसमें पुत्र की जगह हम संतान कर रहे हैं । इस इस तरह के जो समय के साथ 100 सालों में बदलाव हुए हैं तो इन सबको सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन हम लोग लाए हैं। मैं सम्माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्रेसिव रिफार्म्स के लिए जरूरी हैं इसलिए सम्माननीय सदन इसे पारित करे ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 8 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(8) छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी):- अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको ज्ञात ही है कि कोई भी राशि जब तक इस विधान सभा से पारित नहीं हो जाती, उसका हम आहरण नहीं कर सकते। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में लगभग चार माह लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसे खर्च आ जाते हैं, जिसका बजटीय प्रावधान नहीं होता। न्यू आईटम्स भी होते हैं या मैचिंग ग्रांट भी होता है, तो उसके लिए सी.एफ. एडवांश (आकस्मिक निधि) का यह प्रावधान शुरू से है। जब हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उस समय हमारे बजट का आकार 5735 करोड़ था और तब सी.एफ. एडवांश के लिए 40 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2015 में ही हम सबने इसको संशोधित किया और इसे 100 करोड़ किया। आज माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उसमें सी.एफ. एडवांश का 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाए हैं, जो कि उचित है। उसका कारण है कि कई बार दो सत्रों के बीच में समय लगता है। क्योंकि केन्द्र सरकार की पहले जो सेन्ट्रल स्कीम्स आतीं थीं, तो पैसा आ जाता था, तो धीर-धीरे भी खर्च होता था लेकिन जब से पी.एफ.एम.एफ. (पब्लिक फाईनेंस मैनेजमेंट फंड) आया है, उसके माध्यम से ऑनलाईन होता है, तो जैसे ही जिस दिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट पैसा डाल देगी, तो अगर उसके एक निश्चित सीमा के अंदर, 07 दिन या 10 दिन के अंदर यदि हम उसके मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं देंगे, तो उसमें इन्ट्रेस्ट कैल्कुलेट होता है। तो इसलिए क्योंकि कई बार बड़ी राशि भी आती है, इसलिए ये सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी लाए हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही आवश्यक है और इसलिए इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी):- अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 11 सन् 2025) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(रात्रि 9 बजकर 09 मिनट पर विधान सभा शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन 30, शक सम्वत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 20 मार्च, 2025